हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

15 जून, 2005

खण्ड–2, अंक–4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 15 जून, 2005

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4) 1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4) 19
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(4) 20
जांच आयोग की नियुक्ति	(4) 21
वाक आउट	(4) 22
वर्ष 2005–2006 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(4) 22

मूल्य : 128

	पृष्ठ संख्या
सदन की बैठक का समय बढ़ाना	(4) 40
वर्ष 2005–2006 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(4) 41
बैठक का समय बढ़ाना	(4) 59
वर्ष 2005–2006 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(4) 60
वर्ष 2005–2006 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(4) 67
बैठक का समय बढ़ाना	(4) 114
वर्ष 2005–2006 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(4) 114

HUS/LCS/7

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 15, जून, 2005

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार एच०एस० चट्ठा) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल जवाब होंगे।

Payments made to AGs.

***14 Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state the year-wise details of the payments made by the State Government to the Advocate Generals Haryana during the year 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 and 2004-2005 ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : The year wise details of the payments made by the State Government to the Advocate Generals, Haryana during the year 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 and 2004-2005 is given below :—

Sr. No.	Year	Amount
1	2000-2001	26,90,927.00
2	2001-2002	8,83,515.00
3	2002-2003	7,84,328.00
4	2003-2004	18,60,667.00
5	2004-2005	15,12,101.00
	Total	**77,31,538.00**

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जानकारी उन्होंने सदन के पटल पर रखी है वह दर्शाती है कि काफी पैसा स्टेट एक्सचैकर से एडवोकेट जनरल आफिस को गया है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एडवोकेट जनरल नियुक्त करते हैं उनको तनख्वाह और दूसरी फैसीलिटीज सरकार की तरफ से क्या-क्या दी जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो ब्यौरा दिया है इसमें जो पैसा सरकार ने दिया है क्या इस पैसे के अलावा बोर्डज और कारपोरेशंज ने भी एडवोकेट जनरल को पैसा दिया है अगर दिया है तो कितना दिया है ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सारी डिटेल पता करके माननीय सदस्य को बता देंगे।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतनी डिस्पैरिटी है कि एक साल में तो 26 लाख 90 हजार रुपये की पेमेंट की गई और वर्ष 2002-2003 में 7 लाख 84 हजार। कोई मुकदमें तो कम नहीं हुए होंगे और कोर्ट भी कम नहीं हुए, ज्यादा भी नहीं हुए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जजिज की 40 पोस्टें हैं जो मन्जूर हैं जिनमें से 28 से 30 जजिज से ज्यादा कमी भी नहीं रहे होंगे उनके कोर्ट्स में अगर एडवोकेट जनरल के आदमी भी लगाये जायें तो 30 से ज्यादा आदमी नहीं बनते। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस समय एडवोकेट जनरल आफिस में कितने लोग लगे हुए थे, उनकी क्या स्ट्रैन्थ थी और टोटल स्ट्रैन्थ क्या है जो एप्रूवड है कि इतने लगने चाहिए।

Shri Bhupinder Singh Hooda : This is not a part of the question

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो एडवोकेट जनरल को पैसा सरकार ने दिया और जो पैसा बोर्ड और कारपोरेशंज ने दिया उसके बारे में तो मुख्य मंत्री जी पता करके बता देंगे। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, एडवोकेट जनरल के होते हुए भी पिछली सरकार ने न जाने देश के कितने जाने-पहचाने वकीलों से सम्पर्क करके सरकार के बोर्ड और कारपोरेशंज के केसिज के बारे में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने के लिए उनसे पूछते रहे और जिन राजनीतिक लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज किए गये और उनको तंग करने के लिए नुकसान पहुचाने के लिए प्राईवेट वकीलों को ए,प्वोज किया गया तो इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जानकारी दें कि कितने प्राईवेट वकील थे और कितना पैसा दिया ।

Mr. Speaker: Mr. Dalal I would infrom you that your question is confined to AG's Office, not office of the Assistant Advocate General, not office of the Deputy Advocate General, not office of the Sr. Advocate General. You ask only about Advocate General.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, एडवोकेट जनरल के होते हुए प्राईवेट एडवोकेट एन्गेज किये क्या वजह थी कितना पैसा प्राईवेट एडवोकेट्स को दिया गया।

Shri Bhupinder Singh Hooda : Although this is not a part of the question अगर फिर भी जानना चाहते हैं तो हम डिटेल इनके पास भेज देंगे।

Bus Route Permits

***13. Shri Dharam Pal Singh Malik :** Will the Minister for Transport be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that some Transport Co-operative Societies were granted route permits for plying of buses in the Haryana State during the year 1994 to 1996 ; if so, the details thereof; and

(b) whether the said societies are still operating on the said routes, if not, the reasons thereon ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes, Sir. 974 Co-operative Transport Societies were granted route permits for plying of buses in the State of Haryana during the year 1994 to 1996. Details of such Societies are laid down on the table of the House at Annexure 'A'.

(b) Yes, Sir but some of them have changed their routes keeping in view the viability constraints.

Annexure 'A'

Sr. No.	District	Number of permits granted	Number of permits trans-ferred	Number of permits received on transfer	Number of permits cancelled	Total number of permits as at present	Number of permits surren-dered/ deposited/ impounded by bank	Number of societies operating
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ambala	37	-	5	-	42	3	39
2.	Bhiwani	68	8	-	-	60	4	56
3.	Faridabad	75	7	-	-	68	46	22
4.	Fatehabad	61	-	10	-	71	6	65
5.	Gurgaon	46	3	-	-	43	9	34
6.	Hisar	37	-	23	1	59	-	59
7.	Jhajjar (B.garh)	67	-	-	-	67	12	55
8.	Jind	27	-	10	-	37	1	36
9.	Kaithal	56	-	1	-	57	-	57
10.	Karnal	52	-	1	-	53	2	51
11.	Kurukshetra	20	-	-	-	20	6	14
12.	Narnaul	22	8	-	-	14	4	10
13.	Panchkula	8	-	-	-	8	4	4
14.	Panipat	29	-	-	1	28	4	24
15.	Rohtak	59	-	1	-	60	3	57
16.	Rewari	42	-	-	1	41	9	32
17.	Sirsa	156	8	-	-	148	24	124
18.	Sonepat	75	11	-	42	22	4	18
19.	Yamuna Nagar	37	6	-	-	31	5	26
	Total	974	51	51	45	929	146	783

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, टोटल 974 परमिट दिए गए जिसमें से सारी स्टेट में 45 कैंसिल हुए और उन 45 में से 42 सोनीपत जिले के कैंसिल हुए, सिर्फ 3 परमिट बाकी सारे हरियाणा स्टेट के कैंसिल हुए। मंत्री महोदय बताएं कि ऐसे क्या कारण थे कि सोनीपत के 42 परमिट कैंसिल किए गए और वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब किया गया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि टोटल टैक्स तकरीबन 8 करोड़ 70 लाख पैंण्डिंग था उसमें मैक्सीमम एरियर्ज हैं, 42 जो इनके परमिट कैंसिल किए हैं इन्होंने टैक्स नहीं भरा, उसी वजह से इनके परमिट कैंसिल किए गए, इनको बकायदा नोटिस भी दिया गया, अखबारों में भी एड दी गई, इनसे कहा गया कि आप एरियर्ज भर दो। जब परमिट कैंसिल किए गए तब भी अखबारों में एड दी गई। इनके परमिट कैंसिल होने का मूल कारण यही है कि इन्होंने पैसैंजर टैक्स नहीं भरा और रोड टैक्स नहीं भरा।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, ये परमिट पंजाब कोआप्रेटिव सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत दिए गए और इस एक्ट के तहत जो ट्रांसपोर्ट सोसायटीज रजिस्टर्ड हुई चाहे कोई भी सोसायटी हो चाहे वह ट्रांसपोर्ट सोसायटी हो, हाउसिंग सोसायटी हो या कोई दूसरी सोसायटी हो, अगर एक्ट के मुताबिक वह काम नहीं करती तो उस सोसायटी की कमेटी को सस्पैंड करके इन्कवायरी करके वहां एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया जा सकता है। इन केसिज में ये परमिट सीधे कैंसिल कर दिए और उन रूटस पर इतना बुरा हाल है कि थ्री व्हीलर्ज और जीपें चलती हैं, वे रूटस किसी दूसरे को भी नहीं दिए गए और वहां बहुत बुरा हाल है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो ऐसी सोसायटीज हैं वे लिकविडेशन में गई या उन पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए या फिर उनकी लेटैस्ट लीगल पोजीशन क्या है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन रैमेडी उसके लिए यह है कि हमारे 2 ट्रिब्यूनल हैं। एक अम्बाला में है और दूसरा हिसार में । वे वहां जाकर अपील कर सकते हैं और वह अपना फैसला दे देगा। उसके बावजूद भी हम सभ्यैथैटिक एटीट्यूड ले सकते हैं अगर ये अपने एरियर्ज भर दें क्योंकि वे अनएम्पलायड यूथ्स हैं। अगर वे रूट वायबल बनते हैं तो हम इन परमिट्स को रैस्टोर करने बारे सोच सकते हैं, क्योंकि एरियर्ज भी बहुत ज्यादा हैं।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, उन सोसायटीज का क्या हुआ, क्या उन पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए गए या उनकी इन्कवायरी हुई।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि ये परमिट ही कैंसिल हो गए हैं । अब ये सोसायटीज ट्रिब्यूनल में अपील कर सकती हैं।

Opening of I.T.Is.

***64. Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open. I.T.Is in every Constituency of the State particularly in Narnaund ?

Education Minister (Sh. Phool Chand Mullana) : No, Sir.

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार ने जितने वायदे किए हैं उनको पूरा कैसे करेगी। मेरी तो केवल यह मांग है कि हर कांस्टीच्यूएंसी में एक कालेज और ITI होना चाहिए। आज का मेरा प्रश्न तो अपनी कंस्टीच्यूएंसी में ITI खोलने के बारे में है, पर्टीकुलरली नारनौंद में कोई कालेज नहीं है इसलिए वहां कोई कालेज खोला जाए। ITI में पढ़ने के लिए नारनौंद से सुबह बच्चे अपने घरों से निकलते हैं और रात को 8 बजे वापिस आते हैं। अध्यक्ष महोदय, बच्चों को चार-चार घंटे तो सफर करने में ही लग जाते हैं। यदि हर हल्के में ITI और कालेज खोल दिए जायें तो सरकार का ट्रांस्पोर्ट का पैसा भी बचेगा और बच्चों का समय भी बचेगा तथा वे अच्छी पढाई भी कर सकेंगे। (विघ्न) सरकार ने अभी हर हल्के में ITI और कालेज खोलने के बारे में नहीं सोचा है तो मेरी हुड्डा साहब से प्रार्थना है और कल उन्होंने कहा भी था कि नारनौंद की तो सारी मांगे मान ली जावेंगी। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि नारनौंद में तो ITI बनाई जाये।

श्री फूलचंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ऐसा कोई मापदण्ड नहीं है कि हर हल्के में ITI या कालेज खोला जाये। जहां तक मेरे साथी नारनौंद की बात कर रहे हैं नारनौंद से हांसी 20 कि०मी० की दूरी पर है और 20 कि०मी० का सफर तय करने में 30 से 45 मिनट ही लगते हैं। जहां तक मेरे साथी कह रहे थे कि सरकार का ट्रांसपोर्ट का पैसा बचेगा मैं बताना चाहूंगा कि सरकार को तो सवारियां आने जाने से आमदन होती है। हांसी नारनौंद के नजदीक है और हांसी में जो ITI है उसमें दाखिले की भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने जो वायदे किये हैं उनको पूरा करने के लिए हम पर्याप्त कदम उठा रहे हैं और पूरा करेंगे। हमारी सरकार ITIs में जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसको इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान दे रही है। हमारे मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने श्री नवीन जिंदल, एम०पी० की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो देखेगी कि ITIs की ट्रेनिंग को किस तरह से सुचारू रुप से चलाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सारे हरियाणा प्रदेश के इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग और एजूकेशन की तरफ पूरा ध्यान दे रही है कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं भी ITI विभाग का काफी अच्छा वजीर रहा हूं। 1991 से 1996 के दौरान जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय हमने 40 के करीब वोकेशनल इन्स्टीच्यूट खड़े किये थे और उनमें 80 हजार पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कर दी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 8-10 सालों में वह तादाद कम होती-होती शायद इतनी कम हो गई कि कई वोकेशनल इन्स्टीच्यूट इन्होंने बंद कर दिए। करनाल जिले में भलाह गांव में हमने 80 लाख रुपये की लागत से ITI बनाई थी जिसमें 10 ट्रेड थे लेकिन अब शायद उसमें 3 ट्रेड ही रह गये हैं और सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है मैं चाहूंगा कि इस ओर सरकार ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, अब मुलाना साहब एजूकेशन मिनिस्टर हैं। ये बड़े काबिल और पढ़े लिखे हैं और हमारी सरकार की भावना भी अच्छी है, जो त्रुटियां पिछली सरकार के समय में हुई हैं हमें आशा है उनको ये दूर करेंगे और गांव के लैवल पर भी तकनीकी शिक्षा की ट्रेनिंग दी जाये ताकि जो गांव में रहने वाले युवक इधर-उधर आवारागर्दी करते हैं उन्हें छोटा-मोटा रोजगार मिल सके।

श्री फूलचंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने क्या-क्या किया वह तो मान साहब अच्छी तरह जानते हैं। पिछली सरकार की कहानी तो रमलू की कहानी है। गांव में एक ताई ने रमलू को कहा कि रमलू मेरी चक्की राह दे, रमलू चक्की राइने लगा और उससे चक्की टूट गई। चक्की टूटने के बाद रमलू जल्दी से खड़ा होकर भागने लगा तो ऊपर छिक्के में दूध रखा था उसका सिर छिक्के को लगा और दूध गिर गया। रमलू और जल्दी से ताई के घर से बाहर निकलने लगा तो दरवाजे में ताई से टक्करा गया और ताई गिर गई। ताई ने रमलू से कहा, अरे रमलू मैं तन्ने के रो लूं। रमलू ने ताई को कहा कि ताई तू मन्ने कित-कित रोवगी आगे-आगे देख, के हो रहा सै। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने भी हर क्षेत्र में नाश कर रखा है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र को ले लें। जहां तक ITIs में ट्रेनिंग को सुधारने की बात है इस बारे में मैंने अभी बताया था कि मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी हमारे एम०पी० श्री नवीन जिंदल की अध्यक्षता में बनाई है। This Committee will see that how to run the Institutions properly. सरकार का पूरा ध्यान है इन संस्थाओं को इम्प्रूव किया जायेगा और इनमें स्टाफ भी पूरा किया जायेगा तथा बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं हमारी सरकार का ध्यान यह भी है कि जो बच्चे इन संस्थाओं में ट्रेनिंग लेंगे उनको एडजैस्ट किया जायेगा और कई ITIs को तो बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रिज ने एडोप्ट भी किया है जिनमें मारूति उद्योग, जिंदल स्टील ग्रुप, हीरो होंडा आदि कंपनीज हैं। इनके अतिरिक्त चार और बड़ी कंपनीज ने भी कुछ ITIs को एडोप्ट किया है जिनमें चक्कूमैक्स, एसकोर्ट, फैबरीक इण्डिया और जेसीबी इण्डिया कंपनीज हैं। ये कंपनीयां हमारी ITIs को एडोप्ट करेंगी और बच्चों को ट्रेनिंग भी देंगे और उन्हें जॉब भी देंगे।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : स्पीकर सर, यह जो आई०टी०आई० विभाग है यह मेरे पास भी रहा है और हमने कुण्ड मण्डी के अन्दर एक बहुत ही अच्छी आई०टी०आई०, की शुरूआत की थी। यह इसलिए की थी कि बावल एक ग्रोथ सैंटर है और वहां पर बड़ी से बड़ी इण्डस्ट्री लगी हुई है और बच्चों को उनसे तालमेल करके वही ट्रेड दी जानी चाहिए जो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार ठीक होती है। दुर्भाग्य की बात है कि 10 साल पहले एक स्वर्गीय मन्त्री जी ने उसका नींव पत्थर रखा था लेकिन वह आई०टी०आई० दो ट्रेड से शुरू हुई थी वह वैसे की वैसी ही है। उस आई०टी०आई० के लिए गांव वालो ने कम से कम 20 किल्ले जमीन फ्री दी थी लेकिन आज तक उसकी चारदिवारी नही बनी है और न उसमें दूसरी सुविधाएं हैं।

श्री अध्यक्ष : मैडम दस साल पहले तो आप खुद मन्त्री थीं और आपका अपना राज था।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : स्पीकर सर, उस आई०टी०आई० की शुरूआत उसी समय हुई थी। आप कह सकते हैं कि मैं मन्त्री थी इसलिए मैंने शुरूआत कर ली और शुरूआत करने के बाद उसको पूरा करना उसके बाद जो सरकार बनी थी उसका धर्म था। उस आई०टी०आई० को पूरा किया जाना चाहिए था क्योंकि यह मेरे अकेले की बात नहीं है यह सारे इलाके की बात है और वहां के बच्चों के भविष्य की बात है।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय बहन जी ने कहा है कि वहां पर काम शुरू किया था लेकिन हमारे पास ऐसी कोई इत्तलाह नहीं है लेकिन ये जो भी कहेंगी सरकार द्वारा उस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि मेरे हल्के हसनपुर के अन्दर एक भी आई०टी०आई० या पोलिटैक्निक कॉलेज नहीं है। 1988 में चौधरी देवी लाल की सरकार द्वारा एक आई०टी०आई० मन्जूर की गई थी। लेकिन चौटाला साहब की सरकार ने उसको वापिस ले लिया। उस आई०टी०आई० के लिए नौ एकड़ जमीन भी ऐक्वायर कर ली गई थी। चौटाला साहब की सरकार ने उस आई०टी०आई० को खत्म कर दिया और वह जमीन भी मिनि सैक्रेटेरियेट के लिए दूसरे महकमें को ट्रांसफर कर दी है। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद जिले में इण्डस्ट्री बहुत ज्यादा हैं और वहां पर आई०टी०आई० का होना बहुत जरूरी है। मेरा ऐरिया सबसे पिछड़ा हुआ ऐरिया है और हसनपुर से पलवल 35 किलोमीटर है और हथीन 45 किलोमीटर है। हमारे ऐरिया के बच्चे वहां पर जा नहीं सकते हैं। किसी भी आई०टी०आई० के लिए हम पंचायत की जमीन देने के लिए भी तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अगर हम आवश्यकता के अनुसार सरकार को जमीन उपलब्ध करवा दें तो क्या आप हमारे हल्के में आई०टी०आई० खोलने के बारे में विचार करेंगे ?

Shri Phool Chand Mullana : Sir, Hodel is a part of Faridabad District. In Faridabad we have two ITIs. Other ITIs are in Ballabgarh, Mewla Maharajpur and Palwal. पलवल और हसनपुर की विसिनिटी कोई 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां पर आई०टी०आई० की आवश्यकता ज्यादा है लेकिन हमारे पास कोई फीड बैक नहीं है। माननीय सदस्य ने अपना विचार रखा है वे लिख कर दे दें हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे।

कुमारी शारदा राठौर : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि आई०टी०आई० खोलते वक्त क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने आई०टी०आई० खोलें और शहरी क्षेत्रों में कितने आई०टी०आई० खोलें, क्या इस प्रकार का कोई क्राईटीरिया निर्धारित किया जाता है ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, आई०टी०आई० खोलने के लिए क्राईटेरिया है कि जहां पर इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ हो, बच्चों को ट्रेनिंग देने का प्रावधान हो, लैंड अवेलेबल हो, फंड की अवेलेबलिटी हो और बच्चों को ट्रेनिंग का प्रावधान हो और बच्चों की डिमान्ड भी हो।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यहां पर आई०टी०आई० का जिक्र किया है तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हांसी में जो आई०टी०आईज़० खुली हुई हैं, वहां पर नए ट्रेडज दर्ज करने का सरकार का कोई विचार है। इसके साथ ही मंत्री जी यह बताएं कि जो बच्चे यहां से डिग्रीयां लेकर निकलते हैं उनको नौकरियां दिलवाने का सरकार का कोई प्रबन्ध है।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी और सदन को यह बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि आई०टी०आईज़० में नए ट्रेडज़ शुरू किए जाएं। यह सिर्फ मैं हांसी की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि हरियाणा की सभी आई०टी०आईज़० में ये ट्रेडज़ शुरू किए जाएंगे। जहां तक नौकरी देने की बात है तो हम बच्चों को आई०टी०आईज़० में ट्रेनिंग देकर डिग्रीयां देते हैं और जो हमारे यहां पर इण्डस्ट्रीयल यूनिट्स हैं वे उनको आडप्ट कर रही हैं और उनको नौकरियां भी मिल रही हैं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद आबादी के हिसाब से हरियाणा में नम्बर वन जिला है और उद्योगों की दृष्टि से देखा जाए तो गुड़गांव और फरीदाबाद पहले नम्बर पर आते हैं । मंत्री जी फरीदाबाद में सिर्फ दो ही आई०टी०आईज० काम कर रही हैं। हमारा क्षेत्र इन्डस्ट्रीयली बहुत बड़ा क्षेत्र है और बैकवर्ड क्षेत्र माना जाता है तो वहां पर दो आई०टी०आईज० सफीशिंयट नहीं हैं। क्या सरकार फरीदाबाद में और आई०टी०आईज० खोलने के बारे में विचार करेगी। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 1991-1996 में या उससे पहले 1981-87 में वोकेशनल ट्रेनिंग सैन्टर्ज हरियाणा में खोले गए थे। पिछली सरकार के दौरान उन सैन्टर्ज को बंद कर दिया गया था, क्या आपकी सरकार उन वोकेशनल ट्रेनिंग सैन्टर्ज को दोबारा से खोलने के बारे में विचार करेगी क्योंकि वहां पर पहले से ही बिल्डिंग बनी हुई हैं।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि फरीदाबाद में दो ही आई०टी०आई० हैं, क्या वहां पर और आई०टी०आई० खोलने के बारे में सरकार विचार करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जो दो आई०टी०आईज० वहां पर हैं उनमें पहले ही बच्चे पूरे नहीं हैं और वहां पर बच्चों की संख्या कम है तो नई आई०टी०आईज० खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके अलावा जो वोकेशनल ट्रेनिंग सैन्टर्ज के बारे में इन्होंने कहा है तो इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग सैन्टर्ज ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनको ठीक करवाएंगे।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आई०टी०आई० लघु उद्योग को बढ़ावा देने का माध्यम हैं और हर सरकार की पालिसी होती है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान लघु उद्योगों के माध्यम से भी हो। मंत्री जी यह बताएं कि क्या इनकी सरकार ने ऐसी कोई स्कीम बनाई है, जिसकी तरफ बच्चे आकर्षित हो सकें। ताकि और ज्यादा आई०टी०आईज० खोल सकें।

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर सर, इनकी भावनाएं बहुत ही अच्छी हैं लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार के समय के मुख्यमंत्री ने 19 घोषणाएं की थी कि वहां-वहां पर आई०टी०आईज० खोलेंगे लेकिन बड़े दुख की बात है कि उन्होंने एक भी आई०टी०आई० नहीं खोली थी। स्पीकर सर, अगर बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे तो वे अच्छे काम करेंगे लेकिन उनकी ऐसी भावनाएं नहीं थी कि कोई पढ़ लिखकर अच्छा काम करे, उनकी भावना तो लूट-खसूट की थी। (विघ्न)

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जहां पर इन्डस्ट्रीज हैं, क्या इस सरकार की ऐसी कोई नीति है कि वहां पर आई०टी०आईज० खोलेंगे ताकि बच्चे वहां पर ट्रेनिंग ले सकें।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि आई०टी०आई० वहीं खोली जा सकती हैं जहां पर इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ हो, लैंड अवेलेबल हो, फंड की अवेलेबलिटी हो और वहां पर बच्चों की भी डिमान्ड हो।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे सवाल का पूरा जबाब नहीं दिया था। पता नहीं शायद उनको याद नहीं रहा है। मंत्री जी, कृपया इस बारे में ध्यान दें। मैंने

सवाल किया था कि पिछले शासनों के दौरान में दो वोकेशनल ट्रैनिंग सैंटर्ज चालू हुए थे। अभी जैसा माननीय साथी ने बताया था कि ये शायद 6 सैंटर्ज हैं। अगर ये मापदंड पूरे करते होंगे तभी वहां पर खुले होंगे। इन पर सरकारी पैसे का खर्चा वैसे ही नहीं हुआ है। वहां पर इनमें ट्रैनिंग देने का पूरा इंफ्रास्टक्चर है सारा सिस्टम उनमें मौजूद है इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि वे क्यों बंद किए और अगर ये गलत तरीके से बंद किये गये हैं तो क्या उनको दोबारा चालू करवाने का मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री फूलचन्द मुलाना : माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बुरी बात है कि जो इंस्टीच्यूशंज चल रहे थे अगर वे बंद किए गये, माननीय सदस्य अगर इस बारे में लिखकर देंगे तो हम उनकी जांच करवा लेंगे और अगर स्कोप होगा तो इनको दोबारा चालू करवा देंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, हमारा कलायत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां पर आई०टी०आई० खोलने की मांग रही है क्योंकि अभी तक न तो वहां पर कोई कालेज है और न ही वहां पर कोई आई०टी०आई० है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या माननीय मंत्री जी का वहां पर कोई आई०टी०आई० खोलने का विचार है ?

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि कलायत वाकई हाई ये पर है, इम्पोर्टैन्ट स्टेशन है, अगर वहां पर आई०टी०आई० खोलने का पोटेंशियल होगा, जमीन उपलब्ध होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो इस बारे में विचार कर लेंगे।

Providing of 80% Employment to Local Youth in Industries

***35. Shri Naresh Yadav :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to formulate any policy for providing of at least 80% employment to the local unemployed youths in the multinational or big companies which are being set up southern Haryana particularly in Ahirwal area (Gurgaon to Rewari) ?

Industries Minister (Sh. Lachhman Dass Arora) : No, Sir.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी हरियाणा में जब भी किसी चीज की बात आती है तो 'नो सर' का जवाब दे दिया जाता है। कल भी इस बारे में काफी लम्बी बहस हुई थी कि महेन्द्रगढ़ जिले में कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं है। मैंने मांग की थी कि जहां जहां पर अभी तक इंडस्ट्री सैटअप नहीं कि गयी हैं वहां वहां के लिए बजट में प्रावधान रखा जाना चाहिए। लेकिन बजट में महेन्द्रगढ़ में किसी भी इंडस्ट्री खोलने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज महेन्द्रगढ़, नारनौल या उसके आस पास के एरियाज में हैं उनमें हमारी धरती के लोगों को ही, हमारे जिले के लोगों को लिया जाना चाहिए, उनको मौका दिया जाना चाहिए।

Mr. Speaker : Delivering of speech is not permitted in the question hour. Please put the supplementary, Mr. Yadav.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई प्लान दक्षिणी हरियाणा के महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी जिलों के लिए इस बारे में बनाया है ?

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, सरकार जो नई इंडस्ट्रियल पोलिसी लायी है उसका मकसद एक ही है जगह-जगह बेरोजगारों को रोजगार मिले और सरकार को रैवेन्यू मिले। जहां तक महेन्द्रगढ़ जिले का सवाल है वहां अगर कोई इंडस्ट्री कल को इंस्टाल होती है तो उसमें हमारी यह कंडीशन होगी चूंकि इंडस्ट्री लगाने वाले के साथ हमारा ऐग्रीमैंट होता है कि 75 परसैंट बच्चे उनको उस एरिये के और हरियाणा के लगाने होंगे। अध्यक्ष महोदय, यही इनके प्रश्न का जबाव भी है। ये इंडस्ट्री लगवाएं हम इनकी हर तरह से इमदाद करेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, जो नई औद्योगिक नीति है यह मानेसर से आगे नहीं जाती । हमारे एरिये के अंदर रॉ-मैटीरियल के रूप में सबसे अच्छा मैटीरियल मिलता है। जैसे स्टोन क्रैशर के लिए स्टोन मिलता है। सरसों, गेंहू, बाजरा का जो वेस्ट मैटीरियल होता है जिसको तुड़ा कहते हैं वह वहां पर उपलब्ध है। मंत्री जी, प्राईवेट बातचीत में तो बहुत ही बढ़िया करते हैं लेकिन पोलिसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है ? मंत्री जी हमारे एरिये के रॉ मैटीरियल को ध्यान में रखते हुए क्या कोई टीम भेजकर इस बारे में सर्वे करवाएंगे जिससे हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके।

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो डिमांड रखी है। मैं इनसे यही कहूंगा कि या तो ये कोई ऐसी पार्टी तैयार कर लें जो मारथल का काम करना चाहती हो। हम 10.00 बजे उसको लैंड भी देंगे और पैसा भी देंगे और सारी तरह से ओब्लाइज करेंगे। माननीय सदस्य प्रपोजल बनाकर लिखकर भेज दें, सरकार उस पर गौर करेगी।

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वे सिरसा से हैं क्या वे सिरसा जिले में कोई इंडस्ट्री लगाने की कृपा करेंगे। सिरसा जिला पिछड़ा हुआ जिला है क्या वहां कोई बड़ा प्रोजैक्ट लगाने की कोशिश करेंगे ?

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिरसा जिले का सवाल है । माननीय सदस्य को शायद पता नहीं कि सिरसा को हमने इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया घोषित कर दिया है। जो भी इंडस्ट्री बड़ी से बड़ी वहां लग सकेगी उसको लगाने की चेष्टा करेंगे। जैसे इनके राज में वहां शूगर मिल लगी थी ऐसी इंडस्ट्री तो हम लगाते नहीं जिससे कि सरकार का दिवाला निकल जाए।

श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि हमारे यहां जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उनमें हमारे एरिया के कितने प्रतिशत बच्चे नौकरियों में लिए गए हैं जिन लोगों की जमीन ऐक्वायर की गई थी, उन बच्चों में योग्यता भी है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि उन इण्डस्ट्रीज में कितने प्रतिशत बच्चे हमारे एरिया के लिए गए हैं?

Mr. Speaker : It is not possible to reply. Please sit down.

डा० कृष्णा पंडित : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि यमुनानगर आई०टी०आई० में जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए होस्टल की सुविधा लड़के व लड़कियों के लिए अलग से बन सकती है ताकि वे उसमें सहूलियत से रह सकें। मेरा हल्का यमुनानगर इण्डस्ट्रीयल एरिया है और वहां जो आई०टी०आई०

है काफी प्रसिद्ध है मैं चाहूंगी कि उसमें से कोर्स करके निकलकर वहां के बच्चों को इण्डस्ट्री में नौकरी मिल सके और भविष्य बन सके ?

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : इस सवाल का मेरे डिपार्टमैंट से ताल्लुक नहीं है।

श्री रणधीर सिंह : बरवाला 50 हजार की आबादी का शहर है। वहां पर कालेज के लिए एक बिल्डिंग बनी हुई है जो शहीद भगत सिंह मैमोरियल कालेज के नाम से है। क्या सरकार वह कालेज चलाने में सक्षम है।

Mr. Speaker : Randhir Singh Ji, this is not the supplementary relating of this question.

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, जैसा उन्होंने बताया है कि सिरसा जिले को इण्डस्ट्रीयली बैकवर्ड घोषित किया गया है और कौन-कौन से जिले हैं और क्या करनाल को उसमें शामिल किया गया है।

(इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया।)

Reduction in the water Allowance

***43. Sh. Somvir Singh :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether the sanctioned water allowance of the Loharu Lift Irrigation system was reduced from 3.04 cuse per thousand acre to 2.40 cusecs per thousand acre by the previous Government; if so, the steps being taken to increase the authorized discharge of the system for the betterment of area under its command?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Yes, Sir. The Government, during the tenure of previous Ministry, had approved a proposal in July, 2003 to reduce the water allowance in J.L.N., Mahendergarh and Laharu Canal Commands from 3.05 to 2.4 Cs. per 1000 acres of culturable Command area. However, this decision remained unimplemented. The Government proposes to retain the water allowance at 3.05 Cs per 1000 acres of culturable command area.

श्री सोमवीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे कौन से ग्राउंडज हैं जिनकी बिनाह पर यह प्रोपोजल बनाई गई है। एग्रीकल्चर कमाण्ड ऐरिया तय करने का क्या क्राईटेरिया होता है, लोहारू क्षेत्र में पक्के खाले बनाने का प्रोग्राम क्या सरकार का है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय यह 3.05 क्यूसिक प्रति हजार एकड़ जल मात्रा को बनाने का इसलिए प्रस्ताव था क्योंकि उस समय यह संभावना थी कि एस०वाई०एल० का पानी मिलेगा और पानी ज्यादा मिलेगा। परन्तु वह पानी नहीं मिल पाया और कुछ पानी भाखड़ा से मिलना चाहिए था उसका ज्यादातर हिस्सा कुछ एरियाज में ही जाता था बहुत बड़ा पानी का इम्बैलेंस था इसकी वजह से उस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए हमने यह प्रयास किया है क्योंकि भिवानी, लोहारू और महेन्द्रगढ़ का एरिया रेतीला है इस बात को ध्यान में रखते हुए इस जल मात्रा को 3.05 क्यूसिक किया तथा और जगह यह 2.40 क्यूसिक प्रति हजार एकड़ किया था क्योंकि वहां वाटर लैस एरिया था इसलिए एज ए स्पेशल केस किया था, कमान क्षेत्र की जल मात्रा को प्रति हजार एकड़ के हिसाब से हमने 3.05 ही रखा है।

Smt. Kiran Chaudhary : Hon'ble Speaker, Sir, I would like to ask the Hon'ble Minister that whether 341 cusecs water or whatever is sanctioned for WJC system which is supplying water to Siwani Feeder and so why it has not been released and also the WJC System which has been supplying water, has not been started again ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय वैसे तो यह प्रश्न इससे रिलेटिड नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि यह जो हमारा टोटल सिस्टम है इसमें दिक्कत यह है कि जो एरिया नहर के हैड पर पड़ते हैं जैसे दादरी का एरिया हैड पर है उस एरिया के लोग पानी की चोरी ज्यादा करते हैं क्योंकि वहां इरीगेशन की इन्टैंसिटी ज्यादा है। जो टेल एण्ड एरिया है वहां पानी कम पहुंच पाता है इसलिए लोहारू और सिवानी के एरिया में यह दिक्कत है । इसमें वारबन्दी की समस्या है हम वारबन्दी को दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं उसके बाद यह दिक्कत कम हो जायेगी। बधवाना डिस्ट्रीब्यूट्री की इंटैंसिटी 21.26 है बहुत कम है वहां 1.77 और कहीं 5.20 की मात्रा है टेल एण्ड तक पानी पहुंचाने के लिए हमें काफी मशक्त करनी पड़ेगी, हम कोशिश करेंगे कि वहां पर पानी पहुंचा सकें।

श्री सोमबीर सिंह : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लोहारू की जमीन ऊंची नीची है क्या वहां पर पक्के खाले बनाने का सरकार का कोई प्रोग्राम है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, भिवानी में काडा डिवीजन है। जहां तक पक्के खाले बनाने का सवाल है माननीय सदस्य लिखित में दें दें। हम वहां पर जरूर पक्के खाले बनवायेंगे।

डा० शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भिवानी कांस्टीच्यूएंसी में 8 ऐसे गांव हैं जिनमें इरीगेशन का पानी है ही नहीं इनमें एक उमरावल, पूर्णपूरा, नांगल, ढाणा लाडनपुर आदि ऐसे 8 गांव है (विघ्न)

Mr. Speaker : It is not possible to remember the entire canal system. You should come towards the question.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि ये गांव टेल एण्ड पर पड़ते हों क्योंकि हैड एरिया में पानी की चोरी ज्यादा हो जाती है, हो सकता है कि इनके भी गांव टेल पर हों इसलिए ये लिखकर दे दें हम इनकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे।

Declaration of Hassanpur-Palwal as Industrially Backward Area

*** 53 Sh. Udai Bhan :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Hassanpur-Palwal area as Industrially backward area ; if so, criteria prescribed for the purpose alongwith the facilities which are provided in this regard ?

Industries Minister (Shri Lachhman Dass Arora) : Yes Sir ? Palwal block and Hassanpur block of Faridabad District have been declared as State backward areas under the New Industrial Policy, 2005. The economic condition and industrial

backwardness of the blocks has been considered while declaring the State backward areas. The details of the incentives and facilities admissible in backward areas under the New Industrial Policy, 2005 is given in annexure-I.

(a) Incentives for Mega Projects in Backward Areas :

(i) Mega project with investment of Rs. 100 crore and above or any project employing more than 500 persons irrespective of investment to be set up in the backward areas would be extended the facility of financial assistance to be quantified at, 50% of the tax paid on the sale of goods produced by such industrial units, under the Haryana Value Added Tax Act 2003 for a period of 7 years from the date of start of commercial production, as Interest Free Loan (IFL) repayable after a period of 5 years from the date of grant of IFL.

(ii) Exemption from LADT for a period of 5 years.

(b) Incentives for SSI in Backward Areas :

New SSI units in the backward areas would be extended the facility of financial assistance in the shape of Interest Free Loan to be quantified at, 50% of the tax paid on the sale of goods produced in such industrial units, under the Haryana Value Added Tax Act 2003 for a period of 5 years from the date of start of commercial production to be repayable after a period of 5 years.

(c) Incentives for Exporting Units :

In order to boost exports and enhance competitiveness of exporting units, subsidy upto 1% of the FOB value of exports subject to maximum of Rs. 10.00 lac per annum shall be given.

(d) Incentives for Food Processing Industries:

(i) Food Processing Industries except wheat & rice will be considered as seasonal industry and exempted from payment of minimum demand charges for electricity during closed period of more than 3 months.

(ii) No market fee will be levied on agriculture and horticulture produce used as raw material by food Processing Industries with in the State except rice, wheat mustard oil and cotton.

(iii) Interest Free Loan at the rate of 75% of the tax paid on the sale of goods produced in such industrial units under the Haryana Value Added Tax Act 2003 shall be given for a period of 5 years from the date of start of commercial production. This would be repayable after a period of 5 years.

(iv) Charges for Change of land use for food processing units shall be levied @ 50% of normal rates in State declared backward areas.

[Shri Lachhman Dass Arora]

(v) Wines/liquors/Brandy etc. made from 100% fruits produce in the State will be exempted from the Excise Duty.

e) Exmption from Electricity Duty

Exemption from Electricity Duty to the new industrial units for a period of 5 years from the date of release of electric connection.

Incentives & concessions shall be available only to those units which do not fall in the negative list of industries.

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सरकार का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने नई इंडस्ट्रियल पोलिसी बनाई है। मैं 3-4 बातें इस सम्बन्ध में पूछना चाहूंगा। पलवल होडल इसमें पुर का जो एरिया है, NCR रीजन में आता है, होडल को पार करते ही उत्तर प्रदेश ने कोसी कलां को इंडस्ट्रियल एरिया डिवैल्प किया हुआ है। हमारे यहां फरीदाबाद में बल्लभगढ़ से आगे कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। फरीदाबाद में बहुत बुरा हाल है, जैसा कि आप सबको पता है कि वहां बहुत प्रदूषण है, सरकार ने भी इस बात को माना है लेकिन हमारा जो एरिया है मैं इस बारे में दो तीन सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Please wind up, Udai Bhan ji. Put only one supplementary. You will get the opportunity for second supplementary.

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि HSIDC की तरफ से हमारे पलवल होडल के एरिया का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है जो आधारभूत ढांचा है उसको डिवैल्प करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है। जो यह एरिया है नैशनल ऐरिया है, मेन रेलवे लाईन है, दिल्ली के नजदीक है, सारा व्यापार दिल्ली से होता है, हर तरह से फिट है।

Mr. Speaker : Udai Bhan ji, you are replying the question. Please put the question. Minister will reply the question.

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं कि पलवल होडल एरिया के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए HSIDC की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है।

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने कोसी कलां उत्तर प्रदेश की बात की, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमने इनके एरिया को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया इसलिए घोषित किया था कि वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है और न वहां फाइनैंशियल पोजशन अच्छी है। जहां तक HSIDC की ये बात कर रहे हैं, ये लिख कर भेज दें हम सर्वे करवा लेंगे, जो हो पाएगा, हम जरूर करेंगे।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, पीछे जो एरियाज कांग्रेस के जमाने में इंडस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित हुए थे, 5-5, 6-6 सालों तक जनरेटर की सबसिडी के लिए लोग लाइन में लगे रहे, दूसरे साधनों के लिए सरकार जो सबसिडी देती है उसके लिए भी लम्बी लाइन लगी हुई थी, पिछली सरकार ने बगैर किसी कानूनी कारण के उस लाइन को खत्म कर दिया कि

हम यह सबसिडी नहीं देते। जिन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री लगाई थी उन्होंने यह सोचकर लगाई थी कि इतने प्रतिशत इसमें हमें सरकार से जनरेटिंग कैपेसिटी पर मदद मिलेगी। अब वह यूनिट ही अनवायेबल हो गई, उसके बारे में सरकार का विचार क्या है। जो गलतियां पिछलों ने की उनको सही करने का आज की सरकार का भी दायित्व है क्या मंत्री जी इसके लिए प्रयास करेंगे ?

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो मान साहब का प्रश्न है मैं इनको बताना चाहूंगा कि 1994 में भी मैं इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर था। उस समय सबसिडी हमने शुरू की थी और कई इण्डस्ट्रीज को दी थी लेकिन उसके बाद दूसरी सरकारों ने इण्डस्ट्रीज को सबसिडी का कोई पैसा नहीं दिया और आज तक उसमें कोई पेमैंट नहीं हुई है। हम उस पर विचार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि जितना अकोमोडेट हम इण्डस्ट्रीज को कर सकते हैं उतना करेंगे।

श्री भरत सिंह (सम्भालखा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि संभालखा औद्योगिक क्षेत्र है और उससे पहले सरकार ने उसे औद्योगिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया हुआ था। वहां पर 100 के करीब छोटी-छोटी इण्डस्ट्री लगी हुई थी लेकिन पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से उनमें से बहुत सी यूनिट वहां से प्लायन कर गई। अब वहां 40 के करीब यूनिट रह गई हैं और वे भी बंद होने के कगार पर हैं। अब जो लिस्ट औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित इलाकों की है उसमें मैंने देखा कि संभालखा का नाम नहीं है क्या मंत्री जी बतायेंगे कि संभालखा का नाम दोबारा से औद्योगिक पिछड़ा हुआ घोषित क्षेत्र इलाकों की लिस्ट में डाला जायेगा ताकि वहां पर औद्योगिक विकास हो सके।

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इण्डस्ट्रीज के प्लायन करने की बात है उसे रोकने के लिए ही हमारी सरकार ने इण्डस्ट्रियल पोलिसी बनाई है। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण संभालखा ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश से बहुत सी इण्डस्ट्रीज प्लायन कर गई। लेकिन हम उनको वापिस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक संभालखा को दोबारा से इण्डस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया में डालने का प्रश्न है यह बात मेरे नोटिस में नहीं है इसका पता करवा लेंगे। और जो ठीक होगा वह किया जायेगा ।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो पलवल-होडल का एरिया है जिसके लिए यह प्रश्न पूछा गया था वहां पर कोई बड़ा उद्योग लग सके, मल्टी नैशनल कंपनीज आ सके या कोई छोटा-मोटा उद्योग लग सके। उसके लिए उस एरिया को फ्री जोन करने का मंत्री जी प्रयास करेंगे कि उस एरिया को टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग से सी०एल०यू० की छूट मिल जाये या और कोई छूट मिल जाये।

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस पर हम विचार करेंगे और हमारी सरकार की यह चेष्टा रहेगी कि बैकवर्ड एरियाज में बड़ी से बड़ी यूनिट लगे और लोगों को रोजगार मिले।

आई०जी० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरियाणा में जो इण्डस्ट्रियल बैकवर्ड एरियाज हैं वे कौन-कौन से हैं ?

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी इस बारे में अलग से सवाल करेंगे तो इनकी लिस्ट दे दी जायेगी।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी इण्डस्ट्रियल बैकवर्ड एरियाज की बात चल रही है। मेरा हल्का अटेली है और वह भी बैकवर्ड है। अटेली से नीमराना जो कि राजस्थान में है 6 या 7 कि०मी० की दूरी पर है। नीमराना में इण्डस्ट्रीज डिवैल्प हो रही है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे नीमराना का दौरा करें और उसी आधार पर अटेली में भी इण्डस्ट्रीज लगाई जायें ताकि वहां के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके।

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम वहां का दौरा करेंगे और इनकी बात पर गौर करके माननीय साथी के हल्के को ओब्लाईज किया जायेगा।

C.B.I. Enquiry Conducted Against D.C. Karnal

*86. **Shri Tejinder Pal Singh Mann :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any enquiry/raid was conducted by the C.B.I. against the then Deputy Commissioner, Karnal during the regime of previous government ; if so, the details thereof ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, जुलाई, 1999 से फरवरी, 2005 तक के पूर्व सरकार के शासनकाल में उपायुक्त , करनाल के पद पर मई, 1999 से 31-12-2003 तक कार्यरत रहे। श्री देवेन्द्र सिंह, आई०ए०एस० के आवासीय स्थान पर सी०बी०आई० द्वारा दिनांक 2-11-2001 को छापा मारा गया था।

Allotment of Plots/Land to Institutions

*56. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the details of the policy ; if any, adopted for the allotment of plots/ lands to the Institutions by the Haryana State Industrial Development Corporation during the year 2000-2001 to 2004-2005; and

(b) whether any plot/land has been allotted to some Institution in violation of aforesaid policy during the period referred to in part (a) above ; if, so, the details thereof ?

Industries Minister (Sh. Lachhman Dass Arora) :

(a) Sir, to maintain uniform pattern in the State, the Haryana State Industrial Development Corporation adopted the terms and conditions of Haryana Urban Development Authority for allotment of the Institutional plots/lands on on-going basis as well as by inviting applications.

(b) No Institutional plot/land has been allotted by the Haryana State Industrial Development Corporation to any one till date.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने सवाल के पार्ट "ए" में जो जवाब दिया है और इन्होंने जो पॉलिसी बताई है, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि पिछली सरकार ने यूनिटैक कम्पनी को नियमों की उल्लंघना करते हुए मानेसर के एरिया में जो जमीन अलॉट की थी, उसके क्या कारण थे और जब वह अलॉट की गई थी तो फिर रद्द क्यों की गई थी ? अध्यक्ष

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जो जवाब दिया है कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है तो इण्डस्ट्रियल ऐरिया, मानेसर में राई यूनिवर्सिटी इण्टरनेशनल मैनेजमैंट इंस्टीच्यूट, टॉयटा क्लासिक का शो रूम, चौधरी देवी लाल के नाम से एक्सिलैंस सैंटर किस पॉलिसी के तहत वहां पर चल रहे हैं ?

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : स्पीकर सर, मैंने माननीय साथी को स्पष्ट बताया है कि हमने ऐसे किसी फाईनैंशियल इन्स्टीच्यूट के लिए कोई लैण्ड या प्लॉट नहीं दिया है और यदि ये इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो अलग से नोटिस देने की कृपा करें इनको बता दिया जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल के परिवार ने जन-संदेश ट्रस्ट के नाम से गुड़गांव में जमीन ले कर वहां पर अखबार छापने का काम किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एच०एस०आई०डी०सी० सैक्टर में प्राईवेट लोगों से जमीन को बदल कर सस्ते दामों पर गांव में लोगों से जमीन ली और एच०एस०आई०डी०सी० के प्लॉटों में तबदील किया और बहुत भारी मोटी रकम जमीन में फेर बदल करके कमाई जिसमें उन्होंने नियमों की उल्लंघना की, क्या मन्त्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करने का कोई विचार रखते हैं ? अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात चौधरी देवी लाल के नाम एच०एस०आई०डी०सी० के अन्दर जगह-जगह इन्होंने पार्क और न जाने क्या-क्या बना रखा है, वे कौन से नियमों के तहत बनाए गए हैं, उन पर जो पैसा खर्च हुआ है वह कौन सी नीति में आता था ? इन्होंने जो इण्डस्ट्रियल प्लॉट्स इण्डस्ट्रियलिस्टस को एलॉट किए उनका कमर्शियल यूज अलाउ किया वह कौन सी पॉलिसी है ?

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं समझता हूँ इस क्वैश्चन से मेरा कोई वास्ता नहीं है और मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता। (विघ्न) चौधरी देवी लाल पार्क किस तरह से बना था क्या हुआ इसके बारे में अगर ये पूछना ही चाहते हैं तो लिख कर दे दें मैं डिपार्टमैंट से वैरीफाई करवा लूंगा और इनको जवाब दे दिया जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से आश्वासन चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदय ने मेरे सप्लीमैंट्री के जवाब में कहा है कि इस तरह की बहुत सी अनियमितताएं एच०एस०आई०डी०सी० में की गई हैं। एच०एस०आई०डी०सी० में जो अनियमितताएं की गई हैं मैं उनके बारे में लिखकर इनके पास भिजवा दूंगा। माननीय मन्त्री जी बताएं कि लिखित शिकायत पर चाहे वे पिछली सरकार के मुख्य मन्त्री थे चाहे एम०डी० थे या कमिश्नर थे या और अधिकारी थे क्या वे उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ?

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : स्पीकर सर, बाकायदा कार्यवाही करेंगे। मैं आश्वासन देता हूं कि जब यह लिख कर देंगे तो मैं इन को जवाब भी दूंगा और जो गुनाह और पाप हुए हैं और जिन लोगों ने ये किए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे।

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय जो सवाल हमारे मैम्बर श्री कर्ण सिंह दलाल ने यूनिटैक के बारे में उठाया है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि an application from M/s Unitech South City Education Trust was received and examined by HSIDC. The HSIDC issued a letter of intent for allotment of 5 acre institutional plot at IMT Manesar to M/s Unitech South City Education Trust @ Rs. 2340/- per square metre but the allotment was declined by the Chairman of HSIDC before the issue of

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

final letter of allotment on the ground that the land use proposed in the project report did not completely tally with the uses specified for the allotment of the institutional plot.

Setting up of University in the State

***15. Shri Dharam Pal Singh Malik :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the government to set up any university on the pattern of Oxford/Cambridge University in the State; if so, the location thereof, togetherwith the date by which it is likely to start functioning ?

Education Minister (Sh. Phool Chand Mullana) :

(a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने तो साफ ही 'न' कर दी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि खानपुर में कन्या गुरुकुल इन्स्टीच्यूट उत्तरी भारत की सबसे बड़ी संस्था है और उसके पास पूरा इन्फ्रास्ट्रकचर है। अध्यक्ष महोदय, जैसे शान्ति निकेतन का नाम सारी दुनिया में प्रसिद्ध है क्या उसी तरह से कन्या गुरुकुल खानपुर को विश्वविद्यालय बनाने के लिए यह सरकार एग्जामिन करवाएगी।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में पहले से ही पांच विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, एक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में है, दूसरा महार्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक में है, तीसरा चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा में है, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार में है और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार में है। ये यूनिवर्सिटीज में, कृषि के क्षेत्र में, टैक्नीकल क्षेत्र में और सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं सदन में बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि हरियाणा में विश्व स्तर का एक विश्व विद्यालय खोला जाए और उसका नाम एजुकेशन सिटी रखा जाए। स्पीकर सर, उस विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए नगर एवं कल्याण निगम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर लिया गया है और उसमें किन-किन इन्स्टीचुएशंज को लाया जाए, उस बारे में एक कमेटी फाइनांशियल कमिशनर की अध्यक्षता में भी बनाई गई। यह विश्व स्तर की संस्था होगी। माननीय सदस्य समझ जाएगें कि इतनी यूनिवर्सिटीज होने के बाद कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हरियाणा में खोलने की जरूरत नहीं रहेगी।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो विश्व स्तर की संस्था स्थापित की जाएगी यह किस पैटर्न पर होगी। क्या इसका क्राइटेरिया होगा और किस पद्धति पर यह संस्था आधारित होगी ?

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर सर, यह एजुकेशन सीटी जो है, It is expected to attract large number of National and International institutions and it will impart technical education as well as research education of International standard.

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लेखा अनुदान के दौरान इन्होंने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि All Universities in Haryana would be made centres of excellence . मैं यह जानना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी जो सिरसा में है उसके साथ जितने भी सम्बन्धित कालेज जुड़े हुए थे उनको हटा लिया गया था। वहां पर जितना भी पैसा था वह वापिस ले लिया गया है। .....

Mr. Speaker: No-no, Indora ji, please take your seat. Hon'ble Members, now Question Hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Providing of Jobs to Terminated Police Constables

***65 Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to take back those police constables removed/terminated in the light of the judgment of the Court in the regime of previous Government ?

Chief Minister (Sh. Bhupinder Singh Hooda) : No Sir.

Medicine of T.B. Patients

***88 Shri Naresh Yadav :** Will the Minister for Health be pleased to state whether it is a fact that the medicine supplied by the Government free of cost to the T.B. patients are not being given in Narnaul Hospital to the T.B. patients; if so, the reasons therefore togetherwith the steps proposed to be taken to ensure the availability of such medicine in the aforesaid Hospital ?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहन करतार देवी) : नहीं श्रीमान् जी।

Replacement of Transformer of Atela Sub-station

***44. Shri Somvir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the capacity of transformer of 132 K.V. Atela Sub-station feeding the pump houses No. 2,3,4, and 5 of Loharu canal is inadequate due to which there is restriction in running the number of pumps in those pump houses and some time available water also can not be lifted ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to replace the aforesaid transformer with the adequate capacity ?

Chief Minister (Ch. Bhupinder Singh Hooda):

(a) No, Sir.

(b) In view of (a) above, question does not arise .

Construction of Pucka Bridge on Yamuna Canal

*54. **Shri Udai Bhan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the pantoon bridge pucka on the Yamuna canal in Hassanpur, if so, the details there of ?

Chief Minister (Sh. Bhupinder Singh Hooda): No, Sir.

Construction of Streets.

*92. **Shri Tejinder Pal Singh Mann :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the State Government has received any complaint in regard to the use of sub-standard material in the construction of villages streets in the State during the regime of previous Government; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to conduct any enquiry into the matter referred to part (a) above ?

Chief Minister (Sh. Bhupinder Singh Hooda) :

(a) No, Sir.

(b) In view of (a) above, question does not arise.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion No. 4 regarding the cyclone in the evening of the 9th and 10th June, 2005 causing casualities of human beings and damages to the property to the tune of crores of Rupees in Haryana State given notice of by Shri Dharam Pal Singh Malik, MLA, bracketed with calling Attention motion No. 6 given notice of by Dr. Sushil Kumar Indora and 5 other MLAs regarding heavy loss of human beings, animals, birds, private and public buildings and various crops particularly cotton crop and other infrastructure in the districts of Sirsa, Fatehabad, Hisar, Bhiwani and other parts of the State of Haryana on 9th June, 2005 due to unprecedented dust storm and calling attention motion No. 7 given notice of by Shri Karan Singh Dalal, MLA regarding the devastation caused by the storm in the State on 9th June, 2005. I admit it. It will be taken up on 20th June, 2005.

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, मेरा जो लास्ट क्वैश्चन था उसका जवाब आने से रह गया है (Interruptions)

Mr. Speaker : Dr. Raghubir Singh Kadian has to raise a point of order, Let him speak.

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिए। चाहे तो सी०एम० साहब खुद उसका जवाब दे दें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

Mr. Speaker : Gautam Sahib, you are always getting opportunities but unfortunately, you are not believing me. Please sit down.

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker: Whatever he is saying, that is not to be recorded. (Interruptions)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री उदयभान : स्पीकर सर, मैंने भी अपना एक कालिंग अंटेशन मोशन दिया था उसका क्या हुआ ?

Mr. Speaker: It will be taken up on 16th. Now, please sit down Udai Bhan Ji. Kadian Sahib, you please speak now.

जांच आयोग की नियुक्ति

डा० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, आज अखबारों में यह खबर आई है कि Haryana Government has ordered the Vigilance Enquiry into the recruitment of the Haryana State Industrial Security Force and suspended Shri M.S. Malik, DGP (Rules) for his involvement in the illegal act of omission and commission. But Sir, as the matter is serious and keeping in view the gravity and large scale bungling in this recruitment, a Commission of enquiry be ordered by the Government and the Commission be headed by some retired High Court Judge.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, अभी जो डा० रघुबीर सिंह कादयान जी ने प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बात के लिए इनको और सरकार को भी बधाई देता हूं कि यह बड़ा ऐप्रोप्रिएट ऐक्शन लिया गया है। लोग तो इस बात के पहले से ही इंतजार में थे कि जिन लोगों ने जबरदस्त तरीके से इतनी धांधलियां कीं, उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि हाई कोर्ट के सीटिंग जज या रिटायर्ड जज जो बिल्कुल अनडिसप्यूटिड हों, ऑनेस्ट हों, उन लोगों का कमीशन स्थापित किया जाए और जिन लोगों ने बगलिंग की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए चाहे वे कितने ही बड़े लोग क्यों न हों। They should be taken on task and serious notice of this matter should be taken.

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : Keeping in view the sentiments of the members and matter of utmost public importance, I concede to their demand. The Government shall appoint Commission of enquiry headed by the retired High Court Judge to probe and enquiry into the acts of omission and commission in the recruitment of Haryana State Industrial Security Force. However, terms of reference regarding the Commission shall be framed by the Government. The Commission shall be requested to submit the report within 6 months. The

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[Shri Bhupinder Singh Hooda]

High Court will be requested to name the person, who shall be heading this Commission.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस कमीशन के स्कोप में, टर्म एंड कंडीशन में राजनैतिक आदमियों का उस समय जो रोल था, उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे ? जितने भी स्कैंडल किये गये हैं उनके लिए इसमें अफसरों का रोल ही नहीं बल्कि राजनैतिक लोगों का रोल भी इंक्लूड होना चाहिए।

Shri Bhupinder Singh Hooda : Sir, I have already said that the terms of reference would be framed by the Government and every aspect would be taken into consideration.

वाक आउट

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, जिस बारे में आप यह चर्चा कर रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है।

श्री अध्यक्ष : सीताराम जी, आप बैठिए। कोई चर्चा नहीं है। आप नोटिस दो फिर देखेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, आप इस मामले को अभी देख सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनिए।

Mr. Speaker : It was the demand and the Government has acceded to it.

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गये।)

वर्ष 2005-2006 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members now, the general discussion on Budget Estimates for the year 2005-2006 will resume. Mrs. Kiran Chaudhary wanted to say something. (Interruption) Dangi Sahib please start. I will request every Member to take minimum time. I have extended the Session yesterday and do not give me an opportunity of extending today. So, please try to curtail your speech.

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, बात तो पूरी करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात तो आपकी सारा दिन नहीं होती । आपकी और प्रोफेसर साहब की बात तो पूरी होना बड़ी मुश्किल है। please try to curtail your speech.

श्री आनन्द सिंह डांगी (महम) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। 9 जून, 2005 को आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह जी हुड्डा की सरकार ने और चौधरी बीरेन्द्र सिंह, वित्त मंत्री जी ने जो एक शानदार बजट और हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास करने वाला बजट इस सदन में पेश किया, उसकी पूरे प्रदेश में अच्छी चर्चा है। पिछली सरकार ने जिस ढंग से इस प्रदेश को लूटकर बुरी तरह से खोखला कर दिया था अब प्रदेश को इस बजट के माध्यम से संभलने का और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री व अन्य अधिकारीगणों का धन्यवाद भी करता हूं और बधाई भी देता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए अच्छा बजट आने वाले साल के लिए दिया है। सबसे पहला काम सरकार ने जो किया है वह यह है कि प्रदेश की जनता भय, आतंक और असुरक्षा के वातावरण में जी रही थी उससे उसको मुक्त कराया है। पिछली सरकार के समय में किसी व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा नहीं थी, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, व्यापारियों और दुकानदारों का गल्ला सुरक्षित नहीं था। मात्र तीन महीने में अपने शासनकाल में इस प्रदेश की जनता को एक स्वच्छ कल्याणकारी और भयमुक्त शासन देकर प्रदेश की जनता में भाईचारा और स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार जनता को दिया है और सदन में भी ऐसा ही वातावरण है। आज सदन में पक्ष हो या विपक्ष हो सभी को समान रूप से खुले मन से बोलने का अवसर दिया जाता है। पिछली सरकार की तरह से नहीं है कि कोई बोलना चाहता था तो तुरंत सदन से बाहर कर दिया जाता था जिसका उदाहरण भाई रघुबीर सिंह कादयान जी हैं। जब भी इन्होंने प्रदेश की जनभावनाओं की बात उठाने की कोशिश की उन्हें सस्पैंड या नेम कर दिया गया। एक बात भी पूरे पांच साल में उनकी रिकार्ड में नहीं आई, यह एक उदाहरण है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जो तीन विधानसभाओं के उपचुनाव हुए उनमें सही प्रजातंत्र का स्वरूप देखने को मिला। हर व्यक्ति ने पूरी स्वतंत्रता से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिसमें ऐसा उदाहरण पेश किया गया जो कि पूरे देश में कहीं भी पार्लियामैंट, विधान सभा, पंचायत के चुनाव में ऐसा वातावरण देखने को नहीं मिला। तीनों हल्कों के लोग यह नहीं कह सकते कि मेरे को वोट डालने से वंचित किया गया। ऐसे चुनाव से पूरे देश में इतिहास बना है। अध्यक्ष महोदय, उपचुनाव तो इस प्रदेश में पहले भी हुए हैं और मुख्यमंत्री ने भी उपचुनाव लड़ा है पहले की सरकार के उपचुनावों में प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी, बूथों पर कब्जा करके लोगों को गोलियों से भूनकर **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** प्रजातंत्र पर डोरे डालने और छिपाने की कोशिश की लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उस समय के चुनाव में जो चुनाव माहौल उस धरती पर था जिस धरती से मैं संबंध रखता हूं आज के हालात के एकदम दूसरे हालात थे। वहां की जनता ने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपनी जिन्दगी कुर्बान करनी पड़ी और नादिरशाही ओमप्रकाश चौटाला को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, ऐसा अवसर उस चुनाव में ओमप्रकाश चौटाला ने पैदा किया था। उसके मुकाबले में जो उम्मीदवार खड़ा था वह आज आपके सामने है और इस सदन में खड़ा होकर बोल रहा है। मुझे दफ्तर खोलने की इजाजत भी श्री ओमप्रकाश चौटाला ने उस विधानसभा चुनाव में नहीं दी थी। लेकिन जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। उसका नतीजा यह हुआ कि ओमप्रकाश चौटाला को महम की धरती से भागना पड़ा और लगातार सालोंसाल सत्ता से बाहर रहना पड़ा लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने एक आदर्श चुनाव लड़कर

[श्री आनन्द सिंह डांगी]

हिन्दुस्तान की जनता के सामने एक उदाहरण पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, चौटाला सदन में यह कहता था, हमने तो सुना है कई साथी बता रहे थे कि जब तक जिऊंगा तब तक मुख्यमंत्री रहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा कि इस सदन का दूर्भाग्य है जो व्यक्ति कहता था कि जब तक जीऊंगा तब तक मुख्यमंत्री रहूंगा आज वह इस सदन में रावण के रूप में नहीं है।

डा० सीताराम : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे शब्द कार्यवाही से निकाले जायें।

डा० सुशील इन्दौरा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे शब्द कार्यवाही से निकाले जायें।

श्री आनन्द सिंह डांगी : इन्दौरा साहब, रावण तो एक महा पण्डित था अगर उसका नाम ले लिया तो क्या हो गया। आप बाद में अपनी बात कह लेना। इस समय मैं बोल रहा हूं। मेरी बात सुनिये।

डा० सुशील इन्दौरा : उपाध्यक्ष महोदय, बीमार तो कोई भी आदमी हो सकता है जैसे चौधरी भजनलाल जी भी बीमार हैं, इसलिए वे सदन में नहीं आ रहे। इसी प्रकार चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी भी बीमार हैं इसलिए सदन में नहीं आ सकते परन्तु ऐसे शब्द कार्यवाही से निकालने चाहिएं।

डा० रघुवीर सिंह कादियान : डिप्टी स्पीकर सर, जैसा कि माननीय सदस्य श्री डांगी साहब ने कहा यह रिकार्ड की बात है। इस सदन में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने यह बात कही थी कि मैं जब तक जिऊंगा हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहूंगा। डिप्टी स्पीकर सर, आज मुख्यमंत्री तो रहे नहीं तो झण्डा फहराने को दिल करता है इसलिए बाथ रूम में या ड्राईंग रूम में झण्डा फहराते हैं। (विघ्न)

डा० सुशील इन्दौरा : उन्होंने झण्डे फहराये नहीं जनता की भावना रही तो आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला होंगे किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह डांगी : उपाध्यक्ष महोदय, वे पता नहीं स्नान के लिए गए या कुछ और कारनामें करने के लिए गए यह तो वे ही जाने लेकिन वहां पर रिपोर्ट मिली है कि उस बाथरूम में जो रोशनदान लगा हुआ था उस पर एक रस्सी लटकी हुई मिली। बाल्टी जो कि बाथरूम में स्नान के लिए रखी जाती है वह बाथरूम में मूंदी पड़ी हुई थी, जैसे बाल्टी पर चढ़कर कोई और कुकृत्य करने की कोशिश की गई हो, लेकिन शुक्र है भगवान की दया से वह बच गया। (शोर एवं व्यवधान) एक इन्कवायरी के लिए तो आज जांच आयोग की नियुक्ति हो गई, अभी सैकड़ों इन्कवारियां और होंगी। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इस प्रदेश के बजट पर अपने विचार प्रकट करूंगा। बजट बड़ी सूझ बूझ के साथ इस प्रदेश की जनता के लिए दिया गया है। टैक्स फ्री बजट आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने इस प्रदेश की जनता को दिया है। मैं इसके आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि विस्तार से डाक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी ने आंकड़ों सहित बजट की तस्वीर सदन के सामने रखी है जो प्रदेश की जनता को हर तरह से बहुमुखी विकास की ओर ले जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। इसकी 75 प्रतिशत जनता खेती बाड़ी पर निर्भर करती है। किसान की हालत को सुधारना सरकार का कर्त्तव्य है। उपाध्यक्ष महोदय, हर वर्ग की रोजी रोटी

कृषि पर निर्भर है। चाहे वह मजदूर हो, चाहे दस्तकार हो, चाहे व्यापारी हो या फिर दुकानदार हो। अगर किसान के खेत में कुछ पैदा होता है तो हर व्यक्ति के हाथ को काम मिलता है, मजदूर को मजदूरी मिलती है, दुकानदार की दुकान चलती है, व्यापारी का व्यापार चलता है और हाथ से काम करने वाले को रोजगार मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार चाहती है कि किसान समृद्धशाली हो, किसान को विविध फसलों के विविधीकरण बारे शिक्षित किया जाए। मैं इस बारे में थोड़ा सा कष्ट की भावना से कह रहा हूं कि जिस तरह से इस प्रदेश की जनता को कृषि विभाग की तरफ से किसानों को आगे बढ़ने का रास्ता बताना चाहिए और कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो भी कृषि विभाग की नीतियां हैं, उस बारे में समय समय पर गोष्ठी करके किसानों को बताना चाहिए। लेकिन दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई गोष्ठी कृषि विभाग द्वारा नहीं की जाती। मैं अपने गांव का सबसे बड़ा किसान हूं लेकिन कृषि विभाग की तरफ से चाहे कोई ग्राम सचिव डैपुटिड हो या कोई और अधिकारी हो हमने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी, बड़े अधिकारियों की तो बात ही दूर है, लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं जिन का कर्त्तव्य और फर्ज है कि सरकार की तरफ से, यूनीवर्सिटी की तरफ से किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नये बीजों के बारे में और दूसरी उन्नत खेती के बारे में जानकारी दें लेकिन कृषि विभाग के किसी भी कर्मचारी ने किसी भी किसान के पास जाकर या किसी गोष्ठी में जाकर काम नहीं किया, बड़े अधिकारियों की तो बात ही दूर है। किसान पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित है। उसकी हर फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी रहती है चाहे कोई प्रकोप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे अधिक वर्षा हो, चाहे ओलावृष्टि हो और चाहे तूफान हो उसकी सारी फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी रहती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान की चाहे कोई भी फसल हो उसका निश्चित रूप से बीमा किया जाए ताकि उसकी किसी फसल का नुकसान हो जाए तो किसान के नुकसान की भरपाई की जा सके और किसान की फसल का बीमा प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। मैं श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आते ही जो प्राकृतिक प्रकोप से खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देने के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बढ़ोतरी करके किसानों को देने की बात की है, गेहूं की फसल खराब होती है तो जो मुआवजा पहले की सरकार में मिलता था उससे दुगना पैसा देकर उसकी भरपाई करने का सरकार ने सराहनीय काम किया है और दूसरी फसलों का 25 या 30 प्रतिशत मुआवजा दिया गया है और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया गया है। पिछली सरकार में हमने मुआवजों का हाल देखा, पिछली सरकार में सूखा पड़ा और सूखा राहत के लिए सरकार की तरफ से किसानों को मुआवजा दिया गया। मुआवजे की घोषणा हुई कि इंदौरा साहब के गांव में फलां तारीख को मुआवजा दिया जायेगा और इंदौरा साहब की बहन का नाम मुआवजे में था, इंदौरा साहब अपनी बहन को लेने के लिए उसकी ससुराल गये और आने जाने में 100-200 रुपये किराये के लगे तथा बहन को देने के लिए शहर से एक सूट भी खरीदा। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इंदौरा साहब की बहन को मुआवजे के रूप में 25 पैसे दिए गये। इस तरह से पिछली सरकार ने किसानों के साथ खिलवाड़ किया और उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाया। किसी किसान को 25 पैसे, किसी को एक रुपया, किसी को डेढ़ रुपये का मुआवजा पिछली सरकार ने दिया। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अब किसानों को और कमेरे वर्ग को जिनकी फसल खराब हो गई थी उनको पूरा मुआवजा दिया है जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। उपाध्यक्ष महोदय, अच्छी खेती के लिए पानी अतिआवश्यक है यह बात हम सब जानते हैं। लेकिन पानी के मामले में भी किसानों

[श्री आनन्द सिंह डांगी]

के साथ पिछले कई सालों से बड़ा भेदभाव होता रहा है। हमारे प्रदेश में जो एवेलेबल पानी है उसका 70 प्रतिशत केवल डेढ़ जिलों को ही जाता रहा और बाकी के प्रदेश के किसानों को 30 प्रतिशत पानी पिछले कई सालों से दिया जा रहा है। इस तरह से प्रदेश के किसानों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। यह सब राजनैतिक खोट के कारण होता रहा लेकिन चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और उनके साथियों ने प्रदेश में पानी के सम्मान बंटवारे के लिए लम्बा संघर्ष किया और जिस धरती को पानी की जरूरत थी उस धरती तक पानी पहुंचाने के लिए एक लिंक नहर 250 करोड़ रुपये की लागत से बनवा रहे हैं जो 6 महीने में बनकर तैयार हो जायेगी और प्रदेश के सूखे इलाके के किसानों को पानी मिलेगा जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में सभी को हर जगह, हर सुविधा लेने का अधिकार है और हमारे मुख्यमंत्री सभी को उनका हक दिलवायेंगे तथा पानी का सम्मान बंटवारा करवायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एस०वाई०एल० कैनाल की बात करना चाहूंगा। एस०वाई०एल० कैनाल हरियाणा की जनता के लिए जीवन रेखा है और कुछ लोग एस०वाई०एल० कैनाल के नाम पर अपना राजनैतिक स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं और साधते भी रहे हैं। 1985 में राजीव-लौंगोवाल समझौता हुआ था लेकिन चौधरी देवी लाल ने उस समझौते को ठीक नहीं माना और अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए चौधरी देवी लाल ने प्रदेश की जनता को संघर्ष में झोंक दिया। लोगों ने उनका साथ दिया और संघर्ष किया जिसमें तीन लोगों की जान गई। कई लोगों के ट्रैक्टर टूटे, किसी के सिर फूटे और किसी की हड्डी टूटी। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस संघर्ष के दौरान जान-माल का नुकसान हुआ और चौधरी देवी लाल मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उप-प्रधान मंत्री बने। उनका बेटा ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बना। लेकिन एस०वाई०एल० कैनाल का कोई हल नहीं निकला। यदि चौधरी देवी लाल राजीव-लौंगोवाल समझोते को मान लेते तो बहुत पहले एस०वाई०एल० कैनाल का पानी हमारे प्रदेश को मिल जाता लेकिन उन्होंने इस पर अपने स्वार्थ के लिए राजनीति की। उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरे कई साथी कहते हैं कि केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है इसलिए एस०वाई०एल० कैनाल के पानी का अब हल हो जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यदि उस समय राजीव लौंगोवाल समझौते का विरोध नहीं किया जाता और सही मायने में मान लेते तो आज दोनों प्रदेशों में अच्छा भाईचारा होता और हमें पानी मिल जाता। लेकिन चौधरी देवी लाल ने नहीं माना और अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए लोगों को संघर्ष में झोंक दिया। लोगों ने भी उनका पूरा साथ दिया। जिसका फायदा उन्हें यह मिला कि प्रदेश में ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने और सैंटर में चौधरी देवी लाल उप-प्रधानमंत्री बने। उप-प्रधानमंत्री तो कहने को ही थे असल मायने में तो वे प्रधानमंत्री ही थे। उस समय उनके मुख से निकला एक-एक शब्द कानून होता था और ओम प्रकाश चौटाला के पगड़ी बदल भाई प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे। लेकिन उन सब के मन में खोट था इसलिए उन्होंने उस समय भी एस०वाई०एल० का हल नहीं किया। जब सैंटर में चौधरी देवी लाल प्रधानमंत्री के बराबर थे और एस०वाई०एल के मुद्दे को लेकर वहां तक पहुंचे थे तो उन्होंने उस समय इसका हल क्यों नहीं करवाया। उन लोगों ने तो एस०वाई०एल० पर सिर्फ राजनीति की है यह रिकार्ड की बात है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनसे ही इस बात की हां भरवाऊंगा, डाक्टर इंदौरा जी जैसे पढ़े-लिखे लोग यहां बैठे हैं वे सही बात को सही मानेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल अढ़ाई साल तक देश के उप-प्रधानमंत्री रहे और उस समय उनकी जुबान से निकला एक-एक शब्द कानून के बराबर होता था इतनी उनकी चलती थी लेकिन

दुख की बात यह है कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश की जनता ने संघर्ष किया और चौधरी देवी लाल को देश की उपप्रधानमंत्री की बड़ी कुर्सी पर बिठाया और उनका लड़का प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा लेकिन सत्ता में बैठने के बाद उन्होंने एक बार भी एस०वाई०एल० का जिक्र नहीं किया। यदि किया हो तो इंदौरा साहब और सढ़ौरा साहब आप बतायें या चौटाला साहब बता दें या कोई और बता दे। हमारे साथ धोखा हुआ। अगर हमें उस वक्त इस बात का पता चल जाता कि राजनीतिक स्वार्थसिद्धि के लिए संघर्ष किया जा रहा है तो हम चौधरी देवी लाल को सदन के नजदीक भी नहीं आने देते। इस मुद्दे के ऊपर हम तेजा खेड़ा से मुर्दा लाश उठा कर लाए थे क्योंकि हमारे पेट भूखे थे और हमारी धरती प्यासी थी हमारे खेत सूखे थे। इस प्रदेश के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट मुद्दा था। इस प्रदेश की जनता के लिए हम उन्हें उठा कर लाए थे तथा इस प्रदेश का मुख्य मन्त्री और देश के उप-प्रधान मन्त्री की कुर्सी तक उन्हें पहुंचाया था, सिर्फ इस बात के लिए कि हमारी धरती प्यासी थी और हमें हमारा हक मिलेगा। लेकिन स्वार्थ में आ कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के अतिरिक्त उन्होंने कोई भी बात नहीं की। उस वक्त के उप-प्रधान मंत्री इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री होते हुए भी उन्होंने कभी इस बारे में कोई एफर्ट नहीं की यह हमारा दुर्भाग्य था और इस प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य था। उपाध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एस०वाई०एल० कैनाल निर्माण का जो फैसला दिया, वह फैसला क्या था। राजीव-लोंगोवाल समझौते को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। राजीव-लौंगोवाल समझौते के बारे में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि इस से बढ़िया फैसला नहीं हो सकता। इस फैसले की खुशी में इस प्रदेश की सरकारी इमारतों के ऊपर लाईटें जलाई गईं, लड्डियां जलाई गईं दीप जलाए गए और खुशियां मनाई गई और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बढ़िया फैसला दिया है। अगर यह फैसला इतना ही बढ़िया था तो 20 साल पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवी लाल को इसे मानकर इसे हर हाल में लागू करवाना चाहिए था। लेकिन प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा और विश्वासघात एस०वाई०एल० कैनाल मुद्दे पर उन लोगों ने किया। हरियाणा प्रदेश की जनता इसे कभी भुला नहीं सकती। आज वह एस०वाई०एल० का मुद्दा, वही एस०वाई०एल० का फैसला आज इतना बढ़िया हो गया और 20 साल पहले वह इतना खराब था। अगर उस वक्त इस समझौते को मान कर इसको लागू करवाया जाता तो एस०वाई०एल० का पानी आज हरियाणा प्रदेश की धरती पर आ गया होता। इस मामले में सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वह ये लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनके जैसे धोखेबाज, इनके जैसे स्वार्थी लोग अगर इस प्रदेश की राजनीति में इसी प्रकार से चलते रहे तो इस प्रदेश के अन्दर कभी भी एस०वाई०एल० का पानी नहीं आएगा। सच्ची नीयत से सही नीति से इस पर काम करना पड़ेगा और हरियाणा प्रदेश की जनता के हितों के लिए काम करना पड़ेगा। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने हरियाणा विधान सभा को मजाक बना रखा है एक सही बात को इन लोगों को सुनने की कोशिश करनी चाहिए, जो असलियत है वह सुनने की कोशिश करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अब बात आती है बिजली की। बिजली की समस्या इस प्रदेश की एक विकट समस्या है। (विघ्न) बिजली की समस्या प्रदेश की बहुत ही विकट समस्या है और इस विकट समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है बिजली के बिल न भरना। इस प्रदेश के किसान लगातार अपने बिल समय पर भरा करते थे लेकिन वही बात कि अपनी स्वार्थ की राजनीति में इन लोगों ने यह विकट समस्या पैदा की। मैं यह पूछना चाहता हूं कि किसानों को बिल भरने से किसने रोका। किस आदमी ने कहा मेरा राज आएगा मैं बिल माफ करूंगा, किसने कहा कि मेरा राज आएगा तो

[श्री आनन्द सिंह डांगी]

मैं बिजली पानी फ्री दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्दौरा साहब से पूछ सकता हूं, मैं डा० सीता राम जी से तथा सढौरा साहब से पूछता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किसने किया। (विघ्न)

Mr. Deputy Speaker : Please take your seat.

श्री आनन्द सिंह डांगी : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया गया और झूठ बोल कर वोट लिए और इस प्रदेश के लोगों को लूटने का काम किया गया और इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया गया जो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन कर खड़ी हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने किसानों को बिल भरने से रोका था उसके खिलाफ कार्यवाही हो। आज किसानों के सामने इतनी बड़ी रकम खड़ी हो गई है कि वे अपनी जमीन और मकान बेच कर भी अपने बिलों को नहीं भर सकते हैं इस सब का दोषी कौन है। इस सब का दोषी ओम प्रकाश चौटाला है जिसने कहा था कि मुझे वोट दो मेरा राज 11.00 बजे आएगा तो मैं बिजली पानी फ्री दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की अढ़ाई करोड़ जनता इस बात की गवाह है, प्रैस गैलरी में बैठी प्रैस गवाह है कि ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि आप मुझे वोट दो मैं आपके बिजली के बिल माफ कर दूंगा। आज उपाध्यक्ष महोदय, किसानों पर अरबों खरबों रुपए के बिल बकाया हैं। आज इस सरकार के काम काज को बढ़िया तरीके से चलाने के रास्ते में आर्थिक समस्या खड़ी हुई है। मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन है कि जितना भी बिजली के बिलों का मूल अमाउन्ट और ब्याज है वह सब ओम प्रकाश चौटाला से वसूल किया जाए, जिसने अपनी चल और अचल सम्पत्ति देश में और विदेशों में खड़ी कर रखी है। उसकी वैल्यू लगाई जाए। उस आदमी पर सही तरीके से जांच करके हरियाणा के कर्ज की और किसानों पर खड़े बिलों के अमाउन्ट को वसूला जाए। (विघ्न) इन्दौरा जी, आप सुनने की कोशिश करें। आज तेजा खेड़ा में जो फार्म हाऊस है उसमें पहले सिर्फ दो कोठड़े हुआ करते थे, उसकी आज की तारीख में वैल्यू 70 करोड़ रुपये आंकी जाती है। आज जो 20-20 और 50-50 लाख की गाड़ी में घूमते हैं वे कभी साईकल पर नहीं चल सकते थे। चौधरी देवी लाल जी को लोगों ने संघर्ष के दिनों में एक अम्बैसडर कार दी थी और ओम प्रकाश चौटाला वहां से महम तक बस में आया करता था कि महम में आनन्द सिंह डांगी जीप का अरेंजमैंट कर देगा। (विघ्न) लेकिन आज वे 20-20 और 50-50 लाख की गाड़ी में घूमते हैं। यह सब इन्होंने लोगों के खून पसीने की कमाई लूटी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस बारे में इन्कवायरी करके हरियाणा के किसानों के जो बिजली के बिल बकाया है वे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से वसूले जाएं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने जाट होने के बावजूद हरियाणा की जनता को इतना बढ़िया बजट दिया हैं। (विघ्न) हमारा हिसाब किताब वाला मामला खराब है। (विघ्न) लेकिन यह अच्छी बात है हम भी इतना बढ़िया काम करने लग गए हैं।

(वित्त मंत्री) श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कहा है इस बारे में मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं---

अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर,
पढ़ा जाट खुदा बराबर।

श्री आनन्द सिंह डांगी : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह बजट पेश करके बहुत ही बढ़िया काम किया है। (विघ्न) सर, हरियाणा प्रदेश जाटों ने ही चला रखा है। (विघ्न) इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बताना चाहूंगा कि हरियाणा में कमेरे वर्ग के साथ ज्यादती होने लगी तो किसानों ने संघर्ष की राह अपनाई थी। ओम प्रकाश चौटाला ने उनके संघर्ष को दबाने के लिए किसानों पर गोलियां चलवाई। उन पर राजद्रोह के मुकदमें चलाए। यह बहुत ही खेद की बात है कि उन्होंने अपने शासन काल में ऐसे ऐसे काम किए हैं हमें ऐसा कोई भी काम जनता के उपर नहीं थोपना चाहिए जिससे उसे परेशानी हो। पिछली सरकार की गल्त नीतियों का नतीजा है कि आज विधान सभा में उनमें से कोई नजर नहीं आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में दो तीन बातें कहना जरूरी है। एक बात सबसे बड़ी समस्या बिजली की कमी की हमें महसूस हो रही है। बिजली की कमी का मुख्य कारण लाईन लौसिज हैं। लाईन लौसिज पर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। इन पर तभी कंट्रोल किया जा सकता है जब बिजली की सभी पुरानी तारों को बदल दिया जाए। जो पुरानी तारे हैं, जो बहुत लम्बे समय से लगी हुई वे आज इतनी कमजोर हो गयी हैं कि थोड़ी सी तेज हवा से ही टूट कर गिर जाती हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में जितनी भी बिजली की पुरानी तारे हैं उनको बदला जाए ताकि लाईन लौसिज के हिसाब से जो बिजली खराब होती है उसको बचाया जा सके। इसी तरह से पावर हाउसिज के ट्रांसफार्मर्ज की क्षमता भी बढ़ायी जाए क्योंकि ये काफी पुराने पावर हाउसिज बने हुए हैं। पहले इतने बिजली के कनैक्शंज नहीं थे। जिस कैपेसिटी के हिसाब से ये पावर हाउसिज बने थे उसके हिसाब से आज काफी बिजली के कनैक्शंज हो गये हैं और उससे कहीं ज्यादा आज बिजली की खपत होने लग रही है। पावर हाउसिज के ट्रांसफार्मर्ज की क्षमता बढ़ायी जानी बहुत जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के के बारे में कुछ बातें वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं। मेरे गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है। वहां पर जो सब स्टेशन है उस पर छोटा ट्रांसफार्मर है उससे ही वहां के आस पास के इलाकों में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। आज से ढाई महीने पहले एस०ई०, रोहतक से मैंने निवेदन किया था कि उस ट्रांसफार्मर को बदलकर उसको अपग्रेड करवाकर लगवा दें। मैंने उनसे कहा था कि इसको आप चार एम०वी०ए० की जगह 6.3 के०वी०ए० का लगवा दें। उन्होंने इस बात का मुझे आश्वासन भी दिया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उस को बदल देंगे लेकिन आज ढाई महीने उस बात को हो गये हैं आज तक वह ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया है जोकि खेद की बात है क्योंकि ऐसी समस्याओं का समाधान तुरन्त करना चाहिए। चाहे कहीं से भी ये उपलब्ध करवाएं लेकिन उपलब्ध करवाए जाने चाहिएं क्योंकि बात जनता को सहूलियत देने की है। इसी तरीके से यदि और भी कहीं पर ट्रांसफार्मर्ज खराब हैं तो उनको भी बदला जाना चाहिए। इसी प्रकार से किसान की एक और विकट समस्या ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज की है। हजारों ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज इस इलाके में लम्बित पड़े हैं जिससे किसानों का बहुत घाटा होता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज हैं किसानों की सहूलियत के लिए, खेती के लिए जितना जल्दी हो सके, सरकार उनका इंतजाम करे ताकि किसान अपनी खेती को ठीक ढंग से आगे बढ़ा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जल संसाधन की बात है। यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी सरकार को तथा अपने साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि जो पानी की विषमता थी उसको समाप्त करके उन्होंने समान रूप से बंटवारा करने का काम किया है। इसके लिए सब के सब बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही साथ आज रजवाहों में पानी की समस्या भी है। जो रजवाहें हैं वह आज से दस या पन्द्रह साल पहले बने

[श्री आनन्द सिंह डांगी]

थे उस समय उनकी उस वक्त क्षमता बहुत कम थी, उस वक्त किसी माईनर में दस आउटलेट लगे हुए थे जबकि आज उसी माईनर में बीस आउटलेट लगे हुए हैं जिसकी वजह से पानी टेल पर नहीं पहुंच पाता। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो आउटलेट बढ़ गये और कुछ पीछे वाले लोग गड़बड़ी कर लेते हैं इसलिए टेल तक पानी नहीं पहुंचता। इसलिए नहरों की क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि टेल पर पानी पहुंच जाए और किसानों को पानी ठीक ढंग से मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : डांगी साहब, अब आप वाईंड अप करें।

श्री आनन्द सिंह डांगी : सर, अभी तो मैंने अपने हल्के की काफी बातें कहनी है। मेरे हल्के की बहुत लम्बित मांगें हैं। जितने भी माईनर्ज हैं सब की टेल महम हल्के के अंदर खत्म होती है। किसी भी टेल पर भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी पानी नहीं पहुंचता है। इसका कारण यही है कि भौगे बहुत ज्यादा हो गये हैं और पानी की क्षमता कम हो गयी है। जितने भी माइनर महम हल्के के अंदर हैं उनको वाइडन किया जाए, उनकी रेजिंग की जाए और उनकी पानी की क्षमता बढ़ाई जाए ताकि टेलों पर पानी जा सके। मेरे मेहम हल्के के अंदर दो नई माइनर बनानी हैं। एक माइनर तो ऐसी है जो कि तीन गांवों की बंजर जमीन पड़ी है उसको सिंचित करके बढ़िया जमीन बनाने का काम करेगी मदीना, मोखरा और खरखड़ा के बीच का एक माइनर है उस माइनर को बना करके इन तीन गांवों को लाभान्वित किया जा सकता है उस माइनर का सर्वे पहले 1990 से 1995 के बीच में हुआ था लेकिन उसके बाद वह बात ठप्प हो गई दोबारा से स्कीम को चालू करके इन माइनर्स को बनवाया जाए। एक मेरे हल्के में करसोला माइनर है जिसकी लम्बाई 15-16 किलोमीटर पड़ती है। हैड से लेकर टेल तक 15-16 किलोमीटर दूर जाती है। पानी की सप्लाई के हिसाब से अब उसकी कैपिसिटी बहुत कम हो गई है इसके बारे में लोगों की काफी मांग भी रही है। मुख्यमंत्री जी ने जब महम का दौरा किया था तो इनके सामने भी करसौला माइनर को डिस्ट्रीब्यूट्री का रूप देने की बात आई थी। इसके लिए मैं सिंचाई मंत्री महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि इस 15 किलोमीटर लम्बी माइनर को डिस्ट्रीब्यूट्री का रूप दिया जाए, जो नयी माइनर बनवानी है वह बनवाई जाए और जितनी भी माइनर्स महम हल्के में पड़ती हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए और उनकी रेजिंग की जाए ताकि पूरा पानी टेलों पर जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में जो बात बजट में कही गई है मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नाम मात्र की रह गई है। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते इसमें दोनों बातें हैं। पेरेन्टस भी मजबूर नहीं हैं। पेरेन्टस की मजबूरी नहीं है अध्यापकों की नीयत में खोट है। जो अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध पहले हुआ करता था आज वह नहीं रहा और उस संबंध को तोड़ने में अभिभावकों का भी बहुत बड़ा रोल है। शिक्षा में सुधार के लिए जो प्राइवेट स्कूल बने हैं वे इतनी कमर तोड़ फीस लेते हैं कि गरीब आदमी के बच्चे वहां नहीं पढ़ सकते और दूसरी तरफ सरकार पर इतना जबरदस्त बोझ अध्यापकों और स्टाफ का है आज कोई बच्चा बोर्ड में फर्स्ट आता है, मैट्रिक में फर्स्ट आता है तो वह प्राइवेट स्कूल का आता है, सरकारी स्कूलों के बच्चे फर्स्ट इसलिए नहीं आते क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि अब नयी सरकार बनी है अब हर अध्यापक की जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि जिसका जो सब्जैक्ट है उस सब्जैक्ट के आधार पर उसकी ए०सी०आर० लिखी जाए

उसके रिकार्ड के अंदर उसकी इंट्री होनी चाहिए ताकि वह लगन से काम कर सके और गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। देहात के अंदर टैक्नीकल ऐजूकेशन का प्रसार करना बहुत मुश्किल है इसके लिए कहना चाहूंगा कि - - - - (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

Mr. Speaker: Please wind up, Dangi Sahib.

श्री आनन्द सिंह डांगी : स्पीकर सर, हर स्कूल में अध्यापकों की कमी है चाहे वे प्राइमरी स्कूल हैं चाहे हाई स्कूल हैं चाहे जे०बी०टी० हैं चाहे मास्टर हैं चाहे हैड मास्टर हैं चाहे लेक्चरर है और चाहे प्रिंसिपल है। पूरे प्रदेश के अंदर अध्यापकों की बहुत भारी कमी है। और उस कमी को पूरा किया जाए ताकि शिक्षा बच्चों को ठीक ढंग से दी जा सके। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अनुसूचित जातियों व गरीबी से नीचे लड़कियों की शादी में जो - - - - (विघ्न)

Mr. Speaker : Dangi ji, please take your seat.

श्री आनन्द सिंह डांगी : स्पीकर सर, थोड़ा सा टाइम और दे दें।

Mr. Speaker : No. No. I am very sorry. Please conclude within one minute.

श्री आनन्द सिंह डांगी : स्पीकर साहब, मैं दस साल के बाद विधान सभा में आया हूं ! इतनी जल्दी आप मुझे बैठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके अभी 5 साल आगे रहते भी हैं। आज ही सारी कसर मत निकाल लो।

श्री आनन्द सिंह डांगी : स्पीकर साहब, जो इन्दिरा गान्धी प्रिय दर्शनी विवाह शगुन योजना में 5100 से 15000 रुपये किये हैं इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। पीले और गुलाबी कार्ड जो बनाये जाते हैं उनके लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वे आर्थिक आधार पर बनाये जायें। चाहे कोई आदमी किसी वर्ग या जाति से संबंध रखता हो ताकि गरीब आदमी को हर प्रकार से फायदा मिले जिससे वह अपना गुजारा कर सके। खाद, खासकर कृषि उपकरणों पर और ट्रैक्टर के इम्पलीमैंट्स पर भारत सरकार की तर्ज पर हमारी सरकार ने भी टैक्स फ्री कर दिया है, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। ट्रैक्टर के उपकरण को टैक्स फ्री करके किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इस प्रदेश के अन्दर शूगर मिल अधिक हैं। और गन्ना कम है ऐसी-ऐसी जगह शूगर मिल स्थापित कर दी गई जहां पूरे एरिया में गन्ने की एक धोरी भी नहीं होती।

Mr. Speaker : Mr. Dangi I am sorry, I may please be excused. I cannot extend your time. Please sit down.

Shri Anand Singh Dangi : Sir, I will take only one minute. अध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों के निर्माण के बारे में कहना चाहूंगा । किसी प्रदेश की तरक्की के लिए अच्छी सड़कें होना बहुत जरूरी है। सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने नेशनल हाईवे को सैद्रथान करने के लिए जैसे विशेष रूप से एन०एच० 10 को फोर-लेन करना प्रस्तावित है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको सरहद तक बढ़ाया जाये, जहां पाकिस्तान की सरहद लगती है उस दूरी तक इस सड़क को फोर-लेन बनाया जाये। इसी तरह परिवहन तंत्र आज हरियाणा में दूसरे नम्बर पर है। मेरा हल्का मेहम नेशनल हाईवे नं० 10 पर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, आज कचैश्चन आवर में भी रोड परमिट

[Shri Anand Singh Dangi]

बदलने के लिए एक प्रश्न आया था। पहले जो रोड़ परमिट दिये गये थे उनके बारे में सरकार प्रदेश में सर्वे करवाये क्योंकि पहले जो रोड़ परमिट दिये गये थे उनको लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार चेंज करवा लिया जिसके कारण जो बसें गावों में जाती थीं आज वे जा नहीं रही हैं, इस कारण आम जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए सरकार इसका सर्वे करवाकर रोड़ परमिट फिर से निर्धारित करे। अध्यक्ष महोदय, पेय जल व्यवस्था ठीक नहीं है इसको ठीक करवाया जाये। पानी की सप्लाई ठीक न होने के कारण गांव के लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता है। आपने मुझे टाईम दिया इसके लिए धन्यवाद।

Mr. Speaker: Please sit down Dangi Ji. If this type of speeches will be delivered then only 3 or 4 members will be able to speak. There are 20 other members to speak. Now, Smt. Kiran Chaudhary will speak.

Smt. Kiran Chaudhary (Tosham) : Hon'ble Speaker Sir, I welcome the Budget presented by the Hon'ble Finance Minister. It is a vibrant budget and indeed the Finance Minister needs to be congratulated because there are no fresh taxes in the budget, which have been levied inspite of the fact that the entire economy was left in shambles by the earlier regime and the way he has juggled with the depleting Finances is indeed a laudatory. Mr. Speaker Sir, sagacity and vision of Haryana are clearly visible in this Budget because we know that the previous Government had a very lackadaisical approach to the overall development of the State. Resources have been completely left at and end and in fact, I think this is indeed very laudable that inspite of shambles that have been left by the earlier regime, the Hon'ble Minister has struggled to recoup the resources, augment the resources and re-allocate the public funds for the overall balanced development of the State. Mr. Speaker Sir, by looking at the Budget, one can see that there is a substantial increase in the revenue deficit and fiscal deficit but after going through the entire form, which have been tabulated here, I see that for the first time, allocations for local bodies to the tune of Rs. 100 crores has been given, which is a major aspect and which will go a long way to strengthen these local bodies. Similarly, a sum of Rs. 160 crores has been allocated for the maintenance of roads, which is again a very major chunk and it will also strengthen the infrastructure of the State. The Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Bill, 2005, which is going to be passed in the Session will provide and ensure prudent fiscal management and fiscal suitability, which is the dire need of the hour. This year's State Plan outlay 2005-2006 at Rs. 3000 crores is a record increase from the last year and this shows the kind of confidence that the Hooda Government enjoys. As we know agriculture is the backbone of our economy and the need of the hour is to strengthen this sector also. To boost this sector, the deprived farmers can be given benefits. The increase in the corpus of calamity relief fund has been substantially increased to 224.37 crores, which indeed is very laudatory. Further our Government has provided the enhanced compensation for the land acquisition for public purpose. This will provide a great deal of relief to the farmers, who sometimes unsuccessfully indulge in lot of litigations. Major steps to alleviate the sufferings of the farmers have been taken. The assurance has been given to redress

the issue of pending dues and I am sure our Government is committed to it and an amicable solution is going to be arrived at this very important issue. Sir I would like to mention and would like to make a suggestion to our Hon'ble Chief Minister, who is present here that farmers have been given a lot of subsidy but unfortunately these subsidies do not percolate down to the farmers in the manner in which they were intended. For example, I just would like to give the example of the NABARD loans, which are being disbursed to the farmers. When this loan reaches to the hands of farmers, it remains only about 11%. So the poor farmer is again deprived of the subsidy for which the loans were meant to be given. Mr. Speaker Sir, I believe our neighbouring State Punjab has by an executive order, ordered that the local banks should not charge the more commission than 0.1% or 0.2% . If this is the situation in the neighbouring State, I am sure that this position can also be examined by the Hon'ble Finance Minister and these subsidies which are meant to benefit the deprived farmers, should be given in the manner is which they were intended. A major step taken by out Government is for the equitable distribution of water. Mr. Speaker, Sir it is very unfortunate that the earlier Government had completely disregarded the feelings of the people. Lot of areas were left completely unattended and there was no water at all. Sir, in fact, I would like to mention here that during the last elections when I was campaigning for my husband, Ch. Surinder Singh and I went to the villages. Women came to me in a large number and they removed their pallas from their heads. सिर से पल्ला उतारकर दिखाया करती थी कि बेटी देख कि हमारे सिर के ऊपर बाल खत्म हो गए हैं, इतनी दूर से पानी ढो ढो कर लाना पड़ता है। सारी उम्र हमारी इस तरह से निकल गई है। हमारे यहां लड़कों की शादियां नहीं हो सकती क्योंकि जो बहू शादी होकर आएगी तो उसको पानी ढोना पड़ेगा इसलिए यहां शादियां नहीं होती। So, this was the grim situation and today our Government has committed that equitable distribution is going to be made all over Haryana and I am sure when it is done, the people of Haryana will be Jubilant. Sir the Rajiv Gandhi Education City which has been announced by the Hon'ble Chief Minister is infact a dream project and I must commend him for it because as far as education is concerned I found in the debates, I have been hearing here, really a lot of work needs to be done in this sector. I would like to request the Hon'ble Chief Minister that the lines of this University should be on the lines of major Universities like Cambridge and Oxford so that this comes to an international standard and I believe today as during the question hour I was listening to Shri Phool Chand Mullana Ji that they have plans to make this as a famous University, it will not only benefit the people, the children of Haryana and not only, the people of India but also those people coming from abroad. If we can attract students then I am sure we will have a lot of prosperity all around. Mr. Speaker Sir, I do not know whether it is feasible. According to Shri Phool Chand Mullana Ji, there are six Universities already functioning and there is no scope of any private University, but Sir, any sector which comes up with private enterprises, colleges for example in different districts and different constituencies will also encourage the education and literacy of course, stringent norms can be applied so that they impart only quality education and if this is feasible, I think we should also look into this aspect so that more revenue can be generated and at the same time more education can be imparted to the people at the

[Smt. Kiran Chaudhary]

level where they are living. Mr. Speaker Sir, our Congress President Mrs. Sonia Gandhi and our Congress Government headed by Ch. Bhupinder Singh Hooda Ji is committed to the upliftment and empowerment of women and towards this aspect the measures which have been taken are indeed very-very laudatory because this is the Haryana as we know, where there has been a great discrimination against women and the steps which have been taken in this Budget and the policies which have been announced for women's upliftment will go a long way in establishing gender quality. We know for a fact that there is a tremendous alarming rate in female foeticide happening in Haryana and the amended Act of 1994 will curb this female foeticide. Sir, rupees five thousand which has to be given to the parents of girl child and also another five thousand for the next five years to be given to the parents for the second girl child will go a long way in establishing the fact that it will spread the message of quality. It is also a need of the hour to give the girl a rightful place in the society. Mr. Speaker, Sir, I will not want here to say that "it is the hand of the women that roads the world" and also 'behind every successful man is the hand of a woman' and I am sure all my erstwhile colleagues who are sitting here today will agree to it. Therefore, the participation of women in Haryana will go a long way towards this progress and 33% reservation which the Hon'ble Chief Minister has made in the educational institutions for teaching, for women will go a long way in empowering and lending them dignity and self employment. Mr. Speaker, Sir, similarly the Women Cooperative Banks run by women and fifteen thousand rupees which has been decided to be given to the girls at the time of marriage, from Rs. 5100 to Rs. 15,000 is a substantial increase and will ensure the much needed relief to the parents of the girl child Mr. Speaker, Sir, a nation which honours his freedom fighters and martyrs, honours itself. It is a fact that our Government has increased the pension of the freedom fighters from Rs. 1400 to 3500. It will go a long way in boosting their moral because these are the people who have sacrificed their lives for the independence of the State and whatever we are today is because of them. Disbanding the lottery and streamlining are some of the steps, which are taken in the interest of the common man and by discarding the earlier purchase policy followed by Chautala Govt. the honest and transparent intention of the Hooda Government is very perceptible and must be commended. Mr. Speaker sir, power is one area, in which we have been lacking for a long time and this is the major area, for which much is required to be done, as the former Government had completely neglected it. Providing Rs. 1708.21 crores to power sector will enhance the install generation capacity of the State and addition of 600 M.W. Thermal Power Project of Yamuna Nagar will substantially improve the situation in the State. Sir, I would also like to make a suggestion, which I feel that it should be explored by the Hon'ble Finance Minister and by our Hon'ble Chief Minister. Mr. Speaker Sir, all over the world Governments are exploring the possibility of power generation. Sir, we know about the scarcity of water in the State and it is difficult to generate power by these resources. To be an independent and progressive State it is very important that we should be self-reliant as far as power and energy are concerned. So, study regarding feasibility should be

conducted by the Government to see whether this is possible in our State in prevailing conditions or not. If it so, I think that it will be a long step in making yourself self reliant as far as power generation is concerned and it will make a firm foundation for the State in the future. Water augmentation and equitable distribution of water along with modernizing channels, canals and distributaries shall ensure this necessity of life. I feel the first priority which has been accorded by the Hon'ble Finance Minister in this year's budget, first of all to Education, Health and Drinking water and the second priority to irrigation, roads and transport definitely outline the intention of this Government that the Government is absolutely committed to give benefit to the common man and to bring Haryana State on the path of progress and development. Mr. Speaker Sir, as you know strong infrastructure provides development and strong infrastructure is the base of strong economy. Providing record increase of Rs. 141.92 crores in 2005-06 for roads infrastructure show that we are building stable structure for the future.

Similarly, in the transport sector lot has been done and a lot of policies have been announced in this regard. Here, I would request the Hon'ble Finance Minister to explore the possibility for adding revenue generation. Whether we can see the viable route which can be used by entrepreneurs for plying buses privately so that additional revenue can be generated and that revenue can be utilized in other areas of the State and the Government can ply their buses in those areas which are non viable routes. Mr. Speaker sir as you see on the roads that people are fully packed in the Maxi cabs. That is really very dangerous. If the State Government provides adequate transportation to the common man it will give lot of relief to them. Mr. Speaker sir, I know, you are looking at me with a great deal of apprehension about as to how long I am going to continue. Sir, I would like to end my speech by saying that this budget is indeed very vibrant. It looks to a future which will establish the honest intention of the Government. I am sure that coming next five years will be a showcase of development in the State under our Government.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई) : अध्यक्ष महोदय, इस समय वर्ष 2005-06 के बजट पर डिस्कशन चल रही है इस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वित्तमंत्री जी ने बजट में 34 प्रतिशत की बढ़ौतरी करके बहुत ही सराहनीय काम किया है। इस सरकार ने बजट के अन्दर ट्रांसपोर्ट में, बिजली में और पानी में बहुत ही सही ढंग से बढ़ौतरी की है। इसके लिए वित्तमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भी चण्डीगढ़ से कोई वीज फील्ड में जाती है तो उसके लिए गरीब आदमी को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

स्पीकर सर बजट स्पीच में क्रम संख्या 9 पर सोशल वैल्फेयर के लिए 442 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसमें वयोवृद्ध नागरिकों, विकलांगों, विधवाओं और निराश्रितों की पेंशन पर विशेष ध्यान दिया गया है और इनकी पेंशन को बढ़ाया भी गया है। जब हम गांवों में जाते थे तो हमें सुनने को मिलता था कि वयोवृद्ध नागरिकों, विकलांगों, विधवाओं और निराश्रितों को पेंशन नहीं दी जाती। यह पेंशन उन लोगों को दी जाती थी जो कि साधन सम्पन्न थे। मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि किनको पेंशन दी जानी चाहिए इस बारे में आंकलन करने की नीति को इस तरह से बनाया

[श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान]

जाए ताकि जरूरतमंदों को ही पेंशन मिल सके। इसमें पब्लिक के नुमायंदों की सिफारिश को भी मानना चाहिए। अगर उनकी सिफारिश गलत हो तो न माना जाए। स्पीकर सर, आम तौर पर जब पटवारी और शिक्षक इस बारे में सर्वे के लिए जाते हैं तो वहां पर बहुत भीड़ इक्ट्ठी हो जाती है और सर्वे करने वाले वहां से भाग जाते हैं। बाद में जब आकर वे आंकलन करते हैं तो उसमें गलती हो जाती है। इस बारे में सरकार को गौर करना चाहिए। इसके साथ ही सरकार ने विकलांगों को पेंशन देने के लिए 70 प्रतिशत विकलांग होने का क्राईटेरिया फिक्स कर रखा है। मेरा इस बारे में सरकार से निवेदन है कि जिस आदमी का एक हाथ नहीं है या एक पैर नहीं है वे 30 से 70 प्रतिशत विकलांगता में आते हैं। उनको यदि पूरी पेंशन न दें तो कम से कम 300 रुपए मासिक पेंशन देने के बारे में क्या यह सरकार गौर करेगी।

स्पीकर सर, देहातों में बिजली की बहुत भारी समस्या है। यहां पर जो आंकड़े आते हैं मुझे नहीं पता कि उन आंकड़ों को फीडर लॉग बुक में किस तरह से भरा जाता है। हम पब्लिक के नुमायंदे हैं और हमें पता है कि जगह-जगह बिजली की तारें ढीली हैं जिस कारण उस सैगिंग को दूर करने की जरूरत है। स्पीकर सर, पिछली सरकार के वक्त में हरियाणा में बिजली के कनैक्शन बहुत ही महंगे कर दिये थे। उन्होंने एक तत्काल कनैक्शन देने की स्कीम चलाई थी और उसके लिए लोगों ने बैंकों से, आढ़तियों से ब्याज पर पैसा लिया और कर्जे में आ गए लेकिन उस स्कीम के तहत भी लोगों को कनैक्शन नहीं मिल पाए और उसमें भी लम्बी लाईन लग गई है। लोगों ने मोटरें लगा ली हैं, ट्यूबवैल्ज लगा दिए हैं सिर्फ उनको कनैक्शन नहीं मिला है। अब लोग वहां पर कुंडी कनैक्शन से उनको चला रहे हैं। कई लोग तो एक-एक और डेढ़-डेढ़ किलोमीटर से केबल बिछाकर वे कनैक्शन चला रहे हैं यह सब पिछली सरकार की वजह से हो रहा है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जो सरकारी स्टोर हैं वहां पर छोटी-छोटी चीजें जैसे स्थूचीज, कंडक्टर आदि भी अवेलेब्ल नहीं होते हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त हैं कि इस सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए यह सरकार एक बार जहर का घूंट पीकर उन सभी कनैक्शनों को रिलिज करवा दे। इससे आपके लाईन लौसिज भी कम होंगे और लोगों को चोर न समझते हुए उनकी जरूरत को भी पूरा कर दें। एक और सरकार ने अच्छी बात की है। सरकार ने बिजली के बिलों को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। यह मामला बहुत दिनों से लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। पिछली सरकार के गलत प्रोत्साहन की वजह से लोगों ने बिजली के बिल नहीं भरे। पिछली सरकार ने कहा था कि हम बिजली के बिल माफ करेंगे लेकिन माफ नहीं किये गये। आज ये बिल करोड़ों/अरबों रुपयों तक पहुंच गये हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि इस कमेटी की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाए क्योंकि अब स्टेट के अंदर इस बारे में अनसर्टेन्टी पैदा हो रही है। जिन लोगों की क्षमता बिलों को देने की है वे भी यह सोचकर अपना बिल नहीं दे रहे हैं कि शायद इस कमेटी की कुछ घोषणा होगी और उनको कुछ कंसैशंज मिलेंगे और उसी के आधार पर हम अपने कदम उठाएंगे। मेरी बिल मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त है कि हमेशा से जब भी कोई कंसैशंज दिए गये तो जो हैव नॉटस हैं जिन्होंने कभी लेकर दिया ही नहीं, उन्ही को कंसैशंज मिलते रहे हैं लेकिन जो हमारे इलाके के गरीब लोग हैं, ईमानदार लोग हैं जो लेकर देने की प्रक्रिया जारी रखते हैं उनको ये कंसैशंज नहीं मिले हैं।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, अब आप वाईड अप करें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, इससे अच्छा तो आप मुझे बोलने के लिए टाईम ही न देते।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, आप जैसे मित्रों पर ही कुल्हाड़ा चलाना पड़ता है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, आपको मुझे 15 मिनट तो देने ही पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों का चरित्र पैसे देने के हिसाब से ठीक है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि आने वाले समय में लोग यह समझें कि यह सरकार उन लोगों का मान सम्मान करती है जो अपने बिल की अदायगी साल दर साल एवं महीने दर महीने ठीक करते हैं। उनका ध्यान सरकार को अवश्य रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की भावना और मुख्यमंत्री जी की भावना बहुत सही है। वे भय मुक्त सरकार देना चाहते हैं लोगों को सड़क पर चलने की इजाजत देना चाहते हैं। लेकिन पिछले पांच सालों में जिन अधिकारियों ने जुल्म ढाए थे, जिन्होंने स्टेट में टैरोरिज्म किया था, जिन्होंने कत्ल करवाये थे, जिन्होंने शरीफ लोगों के घरों के अंदर तीन तीन सौ सिपाहियों को बगैर कायदे कानून के घूसाया था, अगर आज भी वे लोग सरकार की प्रणाली के अंदर कहीं न कहीं हिस्सा ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से यह सरकार के लिए बहुत सोचने का विषय है। अध्यक्ष महोदय, उस समय सरकार के अंदर ऐसे व्यक्ति थे जिन पर जिले का डी०सी० और एस०डी०एम० होते हुए भी सी०बी०आई० की रेड पड़ी थी। वह रेड इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने आंतकवादियों को एक बंदूक का लाईसेंस दिया था। मैं मुख्यमंत्री जी का इस बारे में ध्यान आकृषित करना चाहूंगा। उसके घर में से 70 लीटर स्कोच व्हीस्की की बोटल्ज निकली थीं, दो दो लीटर के जार मिले थे लेकिन उसके ऊपर कोई कायदा कानून लागू नहीं होता था क्योंकि उसके बाद भी वह दो साल करनाल का डी०सी० रहा। उसके घर में एक हजार के करीब कारतूस निकले। वह लाईसेंसिंग अथोरिटी था बावजूद इसके उसने अपने लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया हुआ था। अध्यक्ष महोदय, वह जवाब देता है कि मेरे फादर इन लॉ का लाईसेंस था। जब घर डी०सी० का था तो ऐसे कैसे हो सकता है ? अध्यक्ष महोदय, डी०सी० के घर में नाजायज कारतूस होना, नाजायज शराब होना और स्मगलिंग शराब का होना अपने आप में कई-कई गुनाहों का सबूत देता है। लेकिन उस सरकार में अजीब हालात थे क्योंकि उस व्यक्ति ने हमारे जैसे शरीफ आदमियों पर कत्ल के मुकदमें बनाने में ओम प्रकाश चौटाला को सहयोग दिया था इसलिए उसको दो साल और वहां रखा गया ताकि उसकी सारी बुराईयां छिप जाएं और लोग डर के मारे कुछ न कहें। ऐसे ऐसे पुलिस के जुल्म ढाए गए, स्टेट टैरोरिज्म किया गया, घरों से पकड़कर शरीफ आदमियों को ले जाया गया और थाने में जाकर मुख्यमंत्री से पूछा गया कि साहब, हम पकड़कर ले आये हैं इन पर क्या मुकदमा बनाया जाए। थाने के अंदर बैठे-बैठ 302 का मुकदमा बना दिया जाता है। कत्ल कहीं होता है और मुकदमा कहीं बनाया जाता है। गजब की बात है। उन्होंने ऐसे आदमियों को मुठभेड़ में दिखाकर कत्ल किया जिनके साथ उनकी अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी थी। ऐसे पुलिस अधिकारी उन के राज में रहे हैं जिन्होंने सरकारी प्रोपर्टी का मिसयूज किया। उस समय वहां के डी०एस०पी० ने म्यूजिक डैक उठाकर अपने घर में रखा। डी०जी०पी० साहब की इस बारे में रिपोर्ट है उन्होंने कहा कि this officer should never be promoted in the interest of justice because as custodian of law, he has himself committed a theft. इतना लिख देने के बावजूद भी उसके केस का रिव्यू कराया गया। डी०जी०पी० साहब ने फिर लिख दिया कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसने कहीं न कहीं से जोड़ तोड़ करके दोबारा से रिपोर्ट ठीक करवा ली और पिछली सरकार में

[श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान]

मैडल भी हासिल कर लिया। जींद में किसान मारे जाते हैं और गोलियों से मरवाए जाते हैं। वे लोग उन जालिम लोगों से मरवाए। जब तक मुख्यमंत्री जी इस चीज को नोटिस नहीं लेंगे ऐसे व्यक्तियों को वीड आउट नहीं करेंगे तब तक आपका भयमुक्त शासन और स्वच्छ प्रशासन देने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। आज वे लोग अपनी गर्दन झुका कर यहां आए हुए हैं ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं से कोशिश करके दूध की नाल समझकर के कहीं न कहीं से कोशिश करके अधिकारी भी बने हुए हैं लेकिन ये थोड़े दिन के बाद आपको रंग दिखा देंगे। और मुख्यमंत्री जी ऐसे लोग आपकी आशाओं पर पानी फरेंगे क्योंकि ये बहुत भ्रष्ट हैं और बहुत जालिम हैं बहुत अच्छा आपने काम किया कि लॉटरी बंद कर दी। करनाल में एक एस०पी० थे, यह लॉटरियों का एक लाख रुपये हफ्ता लेते थे और जिन लोगों से लेते थे उनमें से एक आदमी मेहम का था, एक फतेहाबाद का था और एक फाजिल्का का था वे तीनों आदमी उनके घर पर बैठकर मुर्गा और दारू पीया करते थे, उनकी आदत थी। वहां उनका किसी बात पर कोई झगड़ा हुआ और उनको एन०डी०पी०एस० में नारकोटिक्स ऐक्ट के तहत बंद करा दिया। जब मैं जेल में था तब वे लोग भी जेल में आए। उन्होंने कहा कि हमें इस चीज का दुख नहीं है कि ताश बंद करा दिया लेकिन नारकोटिक्स तो हम नहीं करते थे, हमारा तो एस०पी० से झगड़ा हो गया था हमें अंदर कर दिया। फिर उन्होंने चौटाला साहब से तार खींचें उनकी कहीं से कोई रिश्तेदारी निकल आई तो 15 दिन के बाद उनको मैडीकल लीव पर भेज दिया गया, अगली पेशी पर 14 दिन का रिमांड होता है लेकिन अगली पेशी पर भेज दिया गया और पता यह लगा कि 14 दिन के अंदर वे बरी होकर चले गए। सरकार ने मिस्टेकन आइडैंटिटी के अंदर केस उठा लिया कि साहब, ये तो एन०डी०पी०एस० में थे ही नहीं। एन०डी०पी०एस० में तो रिकवरी भी होती है तो ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाए बहुत से लोअर रैंक के इतने शराबी, कबाबी भरे पड़े हैं, जब तक सरकार उनसे छुटकारा नहीं पाएगी तब तक सरकार जो स्वच्छ प्रशासन देने का इरादा रखती है उसमें बाधा पड़ेगी। मेरा एक और व्यक्ति की तरफ भी इशारा है। वे हरियाणा की एच०एस०आई०डी०सी० के एम०डी० थे, मैं जब 1991-96 तक वजीर था उससे पहले वे कैथल के डी०सी० थे। कैथल में शुगर मिल लगाने में उन्होंने बेतहाशा पैसा खाया था वे चौटाला के दलाल थे, जहां डंडा चुगा देते थे वह जगह मंहगी हो जाती थी। ऐज आई०ए०एस० अफसर पांच साल सस्पैंड भी रहे और जब सरकार बदली तो रीइंस्टेट हो गए और जब चौटाला सरकार आई तो महत्वपूर्ण भी हो गए, सारे लोग उनके नीचे से निकलने लगे। विदेशों की यात्राओं में भी उन्होंने बड़े भारी घपले किये। सर, इन्होंने इन्टरप्रेन्योर्स पर भी बड़ी भारी जुल्म ढाए। Sir, I am a graduate Engineer जब कभी पहली फेज के अंदर दुनिया का कोई आदमी कुण्डली में प्लाट नहीं मांगता था मैंने कुण्डली में फेज वन में एक प्लॉट हासिल किया। चौधरी देवी लाल जी आए और उन्होंने लिटिगेशन की और उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया उसे सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराया फिर ओम प्रकाश चौटाला आए उन्होंने बनी हुई बिल्डिंग में और उसमें चलती हुई इंडस्ट्री बंद करा दी और उसके महानुभाव डॉक्टर हरबक्श सिंह ने उसको रिज्यूम कर लिया विदाउट ऐनी पास्ट पावर वेस्टिड इन हिम। आज मैं दर बदर घूम रहा हूं। मुझे कहते हैं कि उसने तो बहुत ही गलत बात की है यह उसने नाजायज काम किया है यह उनका अधिकार नहीं था लेकिन रिस्टोर करने में समय लगेगा। यह मामला एच०एस०आई०डी०सी० बोर्ड के सामने ले जाया जाएगा, जब बोर्ड की मीटिंग होगी उस समय यह केस उसके अंदर डिस्कस होगा और बोर्ड की मीटिंग कब होगी उसमें समय

लगेगा। हाईकोर्ट से मैंने रिलीफ मांगा, हाई कोर्ट ने रिलीफ भी दिया और उनको लताड़ भी लगाई। हाई कोर्ट ने यह कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते लेकिन उसके बावजूद भी अभी हम उसमें कोई नया धंधा लगाने के लिए रूकावट के कारण बैठे हुए हैं सरकार की अनुमति लेने के लिए। स्पीकर सर, यह जो अधिकारी मैंने आपके सामने बयान किए हैं ये मानवाधिकार कमीशन के जस्टिस आनन्द के सामने पेश भी हुए थे Whole of the bureaucracy is sitting here, I am sorry to tell the comments of Hon'ble Mr. Justice, Anand whose comments were that Mr. Deputy Commissioner, it is unfortunate that people like you are today the Deputy Commissioner in Haryana, I have no hesitation in saying that Haryana is going to become another Bihar and when the S.P. stood, before the Commission he could neither speak Hindi nor speak English. D.G.P. who was a member of that Human Rights Commission, commented अरे S.P. Sahib कौन सी भाषा में बतलाऊं हिन्दी में या अंग्रेजी में बतलाऊं, Then that S.P. Said yes Sir, yes sir there was a case and speaker sir, that was instituted under section 302 against my son. The Sessions Judge has replied in the Judgment. He has said the prosecution should be ashamed of framing such charges against the youngesters. वह चीज जब आनन्द साहब के सामने आई तब उन्होंने यह कामैंट किया था। स्पीकर सर, क्लैमिटी रिलीफ फण्ड के तहत सरकार ने सराहनीय काम किया है, सरकार ने बहुत से लोगों के लिए बढ़िया काम किया है। लेकिन मेरी एक दरखास्त मुख्यमंत्री जी से है क्योंकि आंकड़ों से बात हल नहीं होती हेलस्ट्रोम आते हैं यह तो नेचूरल क्लैमिटी आती प्रसैंटवाईज वह बहुत थोड़े से एरिया में आती है लेकिन उसके लिए बजट काफी रखा हुआ है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आजकल इंटरनेशनल इन्श्योरैंस एजेन्सी देश के अन्दर आई हुई हैं, कहीं न कहीं उनसे कोई नेगोशिएशन करके, अगर हरियाणा सरकार की ओर से इन्श्योरैंस करवा दी जाये जहां हेलस्ट्रोम पड़े, ठीक है आपने मुआवजे का अढ़ाई-तीन हजार दिया है लेकिन मेरी फसल लुट जाये तो 14-15 हजार रुपये की होती है,चाहे गेहूं हो या जीरी हो हमारे यहां पर एकड़ ग्रोस 12-15 हजार का अनुमान होता है, अढ़ाई-तीन हजार रुपये में तो खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। बच्चों के लिए किसान आशाएं लगाकर रखते हैं उन पर पूरा पानी फिर जाता है। अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हमारी सरकार किसी इन्श्योरैंस कम्पनी से नेगोशिएट करके सारे हरियाणा के क्राप्ट ऐरिया का इन्श्योरैंस करे तो उससे पूरी फसल का मुआवजा मिल जाने की अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो सरकार की बड़ी भारी सराहना देश भर में होगी और प्रदेश में भी किसान को काफी फायदा होगा। स्पीकर सर, एस०वाई०एल० के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं यह मामला सब-ज्यूडिस है इसलिए इस पर ज्यादा कहने का कोई औचित्य नहीं। स्पीकर सर, वित्तमंत्री जी ने बेरोजगारों के लिए जो पैसा रखा है मैं इसकी सराहना करता हूं एक इम्प्लायमैंट के लिए मेरे विभाग में भी यह बात बहुत घूम रही थी इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं लेकिन अभी यह ख्याल है इसको डिवैल्प करना बाकी है हमारे रास्ते में तरह-तरह की एजैंसिज आयेंगी जैसे गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया और बाहर के मिशन आयेंगे। मेरी वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि यह बहुत एक्यूट समस्या है बेरोजगारी की हम फील्ड में जाते हैं तो नौजवान भटकते हुए कहते हैं कि मुझे यह लगवा दीजिए, मुझे वह लगवा दें। हमें टैम्पोरेरी लगवा दो इसी प्रकार की कोई कमिशन ब्यूरो बनाई जाये जिसमें आप इण्डस्ट्रियल वर्कर्ज की एनरोलमैंट करें। जो बच्चे आई०टी०आई० पास हों, वोकेशनल एजूकेशन से पास हों उसके अन्दर जो हरियाणा में इण्डस्ट्रीज स्थापित हैं उनको उनमें लगाने का सहयोग दे। आप इसको बढ़ावा दें आपकी बड़ी

[श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान]

मेहरबानी होगी। स्पीकर सर, स्पोर्ट प्राईस के बारे में मैं कहना चाहता हूं ठीक है आज किसानों की जो स्थिति है जो व्यवस्था है वह ज्यादा बिगड़ी है गरीबी इन्तहा पर है। पिछले चार सालों में जिस तरह से किसान को लूटा गया जो जीरी के उत्पादक थे 100-100 रुपये की लूट मण्डियों में दलालों के मार्फत हुई । मण्डियों से बोरी की बोरी मुख्यमंत्री और उसके बेटे लूट ले जाते रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने कहा कि हम उसकी क्रैडिट फैसिलीटी बढ़ा देंगे। मात्रा बढ़ा देंगे। मात्रा बढ़ाने से हमारा काम नहीं चलता कर्जा बढ़ाने से नहीं चलता कर्जे में तो दबे पड़े हैं। 1991 से 1996 तक की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस वक्त भी ऐसी स्थिति थी किसान की उस समय भी कोआप्रेटिव की सारी संस्थाएं बंद होने के कगार पर थीं। उस वक्त की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो टोटल कोआप्रेटिव लोन थे, उसका सात साल का सूद माफ किया था। मुझे खुशी है कि लोगों ने उस स्कीम को बड़ा अपनाया था और 98 प्रतिशत बैंक की रिकवरी हुई थी जोकि पहली बार जैनूयन रिकवरी हुई थी।

Mr. Speaker : Mann Sahab please wind up now.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मैं बाकी छोड़ देता हूं केवल अपने हल्के की बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के नोटिस में मैं एक बात लाना चाहता हूं कि मुर्रा बुफैलो प्रोजैक्ट बना है, मुख्यमंत्री जी हमारे माई हल्के में विशेषकर मुर्रा की बहुत प्राइज विनिंग है। मैं चाहूंगा कि जब आप इन्क्लयूड करेंगे तो इसको भी इंन्कलयूड कर लें।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, आप लिखकर दे दें, सारी बातें हो जायेंगी।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, हमारी कुछ सड़कें हैं जिनके बारे में मैं मुख्यमंत्री महोदय को लिखकर दे दूंगा। पाई में बस स्टैंड बहुत नीचे आ गया है वहां पानी भरा रहता है और सड़न रहती है, सरकार के अधिकारी वहां जाते हैं तो देखते होंगे कि वहां पानी खड़ा रहता है, इसलिए उस बस स्टैंड को नए सिरे से बनवाया जाए इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सदन की बैठक का समय बढ़ाना

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन है कि अभी हमारे 27 माननीय सदस्यगण बजट पर बोलना चाहते हैं। आज के बिजनैस में डिमांड पर भी चर्चा होगी और डिमांड पास भी होंगी। इसके अलावा मुझे भी रिप्लाई देना है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि डेढ़ बजे तक तो बजट पर ही रिप्लाई सम्भव नहीं। मैं यह चाहता हूं और आप भी चाहते हैं कि आज डिमांड पर भी सभी को बोलने का मौका मिले और जो बजट पर जनरल डिस्कशन पर नहीं बोल पाए उन्हें डिमांड पर बोलने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : जिनको बजट पर बोलने का मौका नहीं मिला वे डिमांड पर बोल लेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि डेढ़ बजे से 3 बजे तक लंच ब्रेक कर दें और 3 बजे दोबारा मैम्बर्ज को डिमांड पर बोलना शुरू करवा दें।

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the House may adjourn after the conclusion of the Finance Minister's reply and reassemble today at 3.00 P.M. and continue till 6.30 P.M. for discussion and voting and on the demands for grants on the budget for the year 2005-2006.

Voices : Alright, Sir.

Mr. Speaker : Alright, the House will adjourn after the conclusion of the Finance Minister's reply and will reassemble at 3.00 P.M. and continue till 6.30 P.M. for discussion and voting on the demands for grants on the budget for the year 2005-2006.

वर्ष 2005-2006 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। पिछली बार गवर्नर के अभिभाषण पर जो बहस हुई थी, मैंने ओपनिंग स्पीच दी थी, सरकार की जो उपलब्धियां थी, बहुत से नीतिगत फैसले सरकार उस वक्त कर चुकी थी, उन पर विस्तार से मैंने चर्चा की थी, मैं एक बार फिर इस बात के लिए सरकार को और मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में आज हाई कोर्ट के एक जज द्वारा इन्कवायरी की घोषणा की है। सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा सारे मैम्बर कर चुके हैं। हाउस का समय बचाने के लिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। हरियाणा की आबादी मार्च 2005 में 2 करोड़ 33 लाख के करीब थी और जब नवम्बर, 1966 में हरियाणा बना था तब हरियाणा में साढ़े 6 जिले थे एक पूरा और एक जींद का सब डिवीजन था जिसको बाद में जिला बना दिया गया। आज ये जिले बढ़कर 20 हो गए हैं। हरियाणा में हमारा बजट जो है उसमें आमदनी जो है वह है 16 हजार 130 करोड़ और खर्च है 16 हजार 137 करोड़। इसमें चिंता का विषय यह है कि सरकारी कर्मचारियों की जो तनख्वाहें हैं उसके ऊपर सालाना खर्च, यानि उनका पैकेज जो है वह है 5500 करोड़ रुपये और बाकी के और भी खर्चे है जैसे टेलीफोन के, टी०ए० के, गाड़ियों के,स्टाफ के आदि। यानि कुल मिलाकर इन्कम के आधे से ज्यादा खर्च सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों पर जाता है। आज हरियाणा में 203 IAS ऑफिसर्ज हैं और 219 HCS ऑफिसर्ज हैं। हरियाणा में टोटल एम्पलायज 3 लाख 11 हजार के करीब हैं।-जितने IAS और HCS अधिकारी 12.00 बजे हरियाणा में हैं, महाराष्ट्र और बंगाल जैसी बड़ी स्टेट्स में भी यह गिनती हमारे बराबर है । जबकि हमारी स्टेट तो छोटी सी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हरियाणा में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हैवी है। हरियाणा इतनी छोटी स्टेट है और यहां पर रिसोर्सिज की बहुत ज्यादा सकेयरसिटी है और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टॉप हैवी है जिसके कारण बजट का बहुत थोड़ा पैसा जनता की डिवैल्पमैंट के लिए बाकी बचता है। इसलिए, चिंतन का विषय है कि सरकार कैसे इस समस्या का समाधान करेगी। खेती के अभाव और व्यापार की कमी के कारण हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है। इसके अतिरिक्त एक कारण यह भी है कि सरकारी नौकरी में फिक्सड इनकम,सिक्योरिटी और सरकार के अंदर सत्ता में भागीदारी की वजह से भी हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है। चाहे किसी को छोटी-मोटी नौकरी ही मिल जाये, सब सरकारी नौकरी चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी केवल तनख्वाह तक ही

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

सीमित नहीं है। चाहे एस०पी० का ड्राईवर हो या डी०सी० के घर में खाना बनाने वाला कूक हो यदि उनके परिवार वालों को किसी किस्म की समस्या होगी तो उसको सरकार की तरफ से भरपूर मदद मिलती है। एक छोटे से छोटा सरकारी कर्मधारी अपने परिवार के दूसरे लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने में सक्षम है। सरकारी नौकरी में केवल तनख्वाह ही नहीं है इससे सरकार के अंदर सत्ता में भागीदारी भी मिलती है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हरियाणा प्रदेश के हर घर से एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाये ताकि सभी परिवारों को सत्ता में भागीदारी मिल सके। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश दिल्ली के नजदीक होने के कारण जो उच्च अधिकारी हैं वे भी हरियाणा में ही पोस्टिंग पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे बैनीफिट्स भी हैं। अध्यक्ष महोदय, जिलों के साथ-साथ तहसील और सब डिवीजन भी बढ़े हैं ये इतने ज्यादा एक्सपैंड हो चुके कि बहुत से सरकारी महकमें समय बदलने से रैंडर्ड हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर मैं चर्चा करूंगा कि जो रैवेन्यू डिपार्टमैंट है उसका कोई रोल पब्लिक के लिए नहीं है सिवाय VIPs को रैस्ट हाउस में अटैंड करने के, उनकी हाजरी भरने के जब से बिसवादारी सिस्टम खत्म हुआ है। तबसे तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के पास कोई काम नहीं है क्योंकि अब हर आदमी के पास अपनी मलकियत की कापी है इसलिए गिरदावरी की कोई जरूरत नहीं है और लैंड रैवेन्यू पहले ही माफ है। यह परजूम करना चाहिए कि जो मालिक है उसी का कब्जा है। यदि कोई डिसएप्रूव करना चाहता है तो वह सिविल कोर्ट में जा सकता है। जहां तक इंतकाल का सवाल है मैं समझता हूं गांवों में पंचायतें कर सकती हैं और शहरों में म्यूनिसीपल कमेटी इस रोल को अदा कर सकती हैं। मैं नहीं समझता कि अब इसमें रैवेन्यू विभाग का कोई रोल बचा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पटवारी से लेकर ऊपर तक यह महकमा अबोलिश हो जाये तो सरकार का पैसा भी बचेगा और दूसरी तरफ लोगों को रिश्वत से छुटकारा भी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपको भी मालूम है कि कोई भी रजिस्ट्री बिना रिश्वत दिए नहीं होती थी और अधिकारियों को जो आदत पड़ी हुई है, वह धीरे-धीरे छूटेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि रैवेन्यू विभाग रैंडर विभाग है इसको बंद कर दिया जाये।

एक आवाज : अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्री कौन करेगा ?

श्री एस०एस० सुरजेवाला : गांवों की रजिस्ट्री गांवों की पंचायतें करेंगी और शहरों की रजिस्ट्री म्यूनिसीपल कमेटियां करेंगी। रजिस्ट्रियों के लिए सी प्रताप सिंह कैरों ने असिस्टैंट रजिस्ट्रार लगा रखे थे। मुख्य मन्त्री जी, आपको भी याद होगा, यह कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसके लिए इतना भारी भरकम महकमा रखा जाए। इसके साथ ही साथ मैं कहता हूं कि डिवैल्पमैंट एण्ड पंचायत डिपार्टमैंट का पंचायतों के काम में रुकावट डालने के सिवाय और कोई भी फंक्शन नहीं है। पंचायतों की सुपरविजन पंचायत समितियां कर सकती हैं और पंचायत समितियों की सुपरविजन का काम जिला परिषदें कर सकती हैं। ओवर ऑल पंचायती राज के लिए उनकी एक इलैक्टिड बॉडी हो सकती हैं जिस तरह से बैंक के बोर्डज स्टेट लैवल पर बने हुए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि पंचायत डिपार्टमैंट एज ए डिपार्टमैंट टोटल रिडैशियेबल एबोलिश किया जा सकता है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्पीकर सर, को-आपरेटिव डिपार्टमैंट को यदि करप्शन डिपार्टमैंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सारे को-आपरेटिव मूवमैंट को पंगु बनाने का श्रेय या कुश्रेय यदि किसी को जाता है तो वह को-आपरेटिव डिपार्टमैन्ट को जाता है। इस को-आपरेटिव

डिपार्टमैंट को वाइंड अप कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि को-आपरेटिव ज्यादा फलौरिश कर सकता है और ज्यादा काम कर सकता है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट का एग्रीकल्चर में कोई रोल नहीं है। मेरे दोस्त डांगी साहब ने यहा पर बात कही कि कोई ए०डी०ओ० कहीं दिखाई नहीं देता। (विघ्न) मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुका हूं और मैं गांव में भी रहता हूं लेकिन मैंने ए०डी०ओ० को कभी नहीं देखा, यह बात हमारे डांगी साहब ने कही है। क्वालिटी कन्ट्रोल वालों का फर्टिलाईजर और बीज वालों से मन्थली इक्ट्ठा करने के अलावा और कोई काम नहीं है इसलिए मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट का किसानों और खेती में कोई रोल नहीं है इसलिए इस डिपार्टमैंट को बड़े आराम से वाईड अप कर सकते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण का बहुत महत्व मानता हूं लेकिन समाज कल्याण विभाग को जितना पैसा एलौट होता है उससे सिवाय तनख्वाहें देने के समाज कल्याण का और कोई काम नहीं होता है इसलिए सोशल एन०जी०ओज० और दूसरे लोग ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं समझता हूं कि एक्साईज डिपार्टमैंट का भी कोई रोल नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला साहब, 5-6 डिपार्टमैंट्स और रह गए हैं इनको भी वाइंड अप करने का प्रस्ताव दे दें। ताकि हुड्डा साहब भी फ्री हो जाएं।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक्साईज के जो ठेके दिये जाते हैं उनमें खूब धान्धली होती है। शराब की बिक्री कोई भी दुकानदार अपनी दुकान पर कर सकता है। कोई भी आदमी चाहे वह सब्जी बेचता है या उसका जनरल स्टोर है वह लाईसैंस लेकर शराब बेच सकता है और उससे आप एक्साईज ले सकते हैं। मिल, जहां से शराब निकलती है सरकार वहां से पूरा एक्साईज वसूल कर सकती है। यह महकमा सिवाय माफिया क्रिएट करने के और कोई काम नहीं करता है। जो वर्तमान में ठेकदार हैं उनका काम क्राईम बढ़ाना और एक्साईज और पुलिस महकमें को शराब और रिश्वत देने के और उनका कोई रोल नहीं है। ये लोग समाज को बहुत खराब कर रहे हैं इसलिए मैं कहता हूं कि इन महकमों को बन्द करके करोड़ों रुपया बचाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी अधिकारी जो कार और टैलीफोन रखते हैं मैं समझता हूं उनको सरकार को यह कहना चाहिए कि वे अपनी कार खरीदें और टैलीफोन लगाएं और सरकार से टी०ए० लें। सरकारी काम के लिए अगर कोई टेलीफोन करना है तो उसके लिए वे रजिस्टर मेनटेन करें और जहां पर जो भी काल की गई है उसको उस रजिस्टर में दर्ज करें। अध्यक्ष महोदय, इससे सरकार का करोड़ों रुपया बच सकता है और ऐसा हो सकता है। बैंकों वाले आज कल सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज देने के लिए तैयार हैं। और सरकार का रुपया बचाया जा सकता है। यह पैसा लोगों को सुविधाएं देने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि क्लास-III और क्लास-IV में नये आदमी को जिस दिन एप्वांयट करते हैं उसी दिन से उसकी पोस्ट को नॉन-ट्रांसफरेबल डिक्लेयर किया जा सकता है। इससे जहां सरकार का रुपया बचेगा वहीं पर सरकारी मन्त्रियों और राजनीतिक लोगों का समय भी बचेगा। क्लास-IV तथा क्लास-III कर्मचारियों को उनके घरों के नजदीक लगाया जाना चाहिए उनको दूर लगाने की नीति तो अंग्रेजों की थी जो कि सजा देने के लिए नीति थी। आज परिवार को दो-दो जगहों पर बांटा जा रहा है और इससे खर्चा बढ़ रहा है और वे लोग अपनी ड्यूटी पर नहीं जाते हैं और अपने घरों में बैठे रहते हैं। उनके ऊपर जो लोकल सोशल प्रैशर है अपने घर पर उनके ऊपर पड़ता है वह बाहर जा कर नहीं होता है और इससे क्रप्शन के भी चान्सिज कम होते हैं। इसलिए सरकार को ट्रांसफर नीति में मूलचूक परिवर्तन करके क्लास 3 और क्लास 4 को

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

उनके घरों के नजदीक पोस्टिंग दिलवानी चाहिए। अगर किसी स्टेट का डी०जी०पी० उसी स्टेट में लग सकता है और अगर किसी स्टेट का चीफ सैक्रेटरी उसी स्टेट में लग सकता है तो बेचारे मास्टर ने और वैटनरी कम्पाउन्डर ने क्या कसूर कर रखा है कि उसको 10 या 20 किलोमीटर दूर जाना पड़े। सरकार को इस गलत नीति को रिवर्स करना चाहिए अगर बिजली का ए०एल०एम०, वैटनरी का कम्पाउन्डर और पानी की टूटी चलाने वाला अगर वह अपने गांव में ही रहेगा तो रात को भी उसके गांव में चाचा, ताऊ उसको उठा सकेंगा और उस आदमी पर उनका प्रैशर रहेगा। स्पीकर सर, आज पटवारी से लेकर पानी चलाने वाले तक सभी शहरों में रहते हैं और उन पर आज कोई सोशल प्रैशर नहीं है। मैं हुड्डा साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि इन सारी बातों को देखने के लिए स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म सैन्टर के पैटर्न पर कमिशन बनाया जाना चाहिए। स्पीकर सर, ऐसा करने से 40 से 50 प्रतिशत का एक्सपैंडीचर बचाया जा सकता है और उससे लोगों की डिवैल्पमैंट के लिए जो जिन्दगी से जुड़े हुए खर्चे हैं वे पूरे किए जा सकते हैं।

स्पीकर साहब, इससे आगे मैं किसानों की आत्म हत्याओं की बात करूंगा। यह बात मैंने आज से 10-12 साल पहले भी सबसे पहले पार्लियामैंट में उठाई थी और वहां पर इस बारे में डिस्कशन भी हुई थी । सोनिया जी हरियाणा में आई और हुड्डा साहब भी वहां पर थे। वे चार गांवों में 100 परिवारों से मिली थीं। स्पीकर सर, एक साल में जितनी भी ब्रैड अर्नर्ज ने आत्म हत्याएं कर ली थी, सोनिया जी उनके बूढ़े मां-बाप से और बच्चों से मिली थीं, उनकी समस्याओं के बारे में समझकर आई थीं कि उनकी ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से नौजवान आदमी जान दे देते हैं। स्पीकर सर, मैं उस बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। आज खेती घाटे का धन्धा रह गया है। उनकी ऊपज बहुत ही कम हो गई है। आज लोगों के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। आज सरकार का किसी भी चीज पर नियन्त्रण नहीं है, चाहे वह एग्रीकल्चर के इनपूट्स हो, कोई मशीनरी हो चाहे कीड़े मार दवाई हो, बीज हो या खाद हो। सरकार का खेती की किसी भी चीज पर आज नियन्त्रण नहीं है। केन्द्र सरकार जो स्पोर्ट प्राईस देती है वह धीरे-धीरे चलती हैं, जबकि उनके खर्चे बहुत उपर चले गए हैं । मेरा कहना है कि सरकार को इस बारे में अपनी नीति बदलनी चाहिए। सरकार को ब्याज की दर को आठ प्रतिशत से घटाकर नीचे लाना चाहिए आज नाबार्ड से बैंकों को चार प्रतिशत पर खेती के लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन आज भी किसानों से लैंड डिवैल्पमैंट बैंकों द्वारा 10 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा की दर पर कर्ज दिया जाता है। स्पीकर सर, हरियाणा में दो काले कानून हैं और उनके बारे में मैंने बहुत बार चर्चा की है। एक काला कानून यह है कि को-आप्रेटिव एक्ट के तहत अगर किसान कर्जा वापिस न दे पाए तो उसको 40 दिन के लिए बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता है। उसकी रोटी का जो खर्चा होगा वह भी उससे वसूल किया जाएगा और इसके साथ ही जो जीप उसको लेकर आएगी उसका खर्चा भी उस पर ही डाला जाएगा। दूसरा काला कानून यह है कि कोई अगर कर्जा न दे सके तो बैंक उसके खिलाफ डिक्री लाकर उसकी जमीन को नीलाम कर सकता है। स्पीकर सर, जिसके पास थोड़ी सी जोत की जमीन है वह खर्चा ज्यादा होने की वजह से और ज्यादा कर्जा होने की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर है। अगर आप उस आदमी की जमीन नीलाम करेंगे तो मेरा आपको सुझाव है कि उसके पूरे परिवार को सल्फास की गोली दे देनी चाहिए क्योंकि जमीन नीलाम होने के बाद उनको तो मरना ही है। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन दोनों काले कानूनों को स्टैचुड बुक से उठा लेना चाहिए और कर्जे पर ब्याज की दर कम कर देनी चाहिए। सरकार ने किसानों के लिए,

खेती करने वाले मजदूरों के लिए बहुत सी रियायतें देने की घोषणाएं की हैं। इसलिए सरकार को व्यापक तौर पर इस पर भी विचार करना चाहिए और इस बारे में कोई उपाय करना चाहिए क्योंकि पिछले 5-7 सालों से आत्म हत्याओं की घटनाएं बढ़ी हैं। मेरा यह कहना है कि हर साल 5 से 10 हजार नौजवान हरियाणा में आत्म हत्याएं करते हैं। अगर सरकार चाहे तो इस बारे में सर्वे करवा सकती है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। स्पीकर सर, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि यह जो मार्किटिंग बोर्ड है, जिसका काम एग्रीकल्चर की मार्किटिंग करना है और इसके अलावा और भी दूसरे काम है जो कि उन्होंने आज तक नहीं किए हैं। क्राप की फोरकास्टिंग उसका काम है, वैदर की फोरकास्टिंग उसका काम है। किसान और खेत में काम करने वाले आदमी के लिए सुसाईड के केस में, डिसएबिलीटी के केस में और भी दूसरे तरह के केस में उनको मदद करनी चाहिए। भारी भरकम रुपया उसके पास होता है। दस बीस साल से सरकार क्या करती रही है जितना रुपया मार्केटिंग बोर्ड के पास है, मार्केटिंग कमेटी के पास नीचे से जो फीस आयी हुई है उसको या तो बिजली बोर्ड को घाटा पूरा करने के लिए दे देते हैं या हुडा को अपने काम करने के लिए पैसा दे देते हैं या किसी और महकमें को दे दिया जाता है। खेतीबाड़ी के लिए एक खास परपज के लिए रुपया इकट्ठा होता है उसको आप डायवर्सीफाई नहीं कर सकते हैं उस पैसे को आपको मार्केटिंग बोर्ड और मार्केटिंग कमेटीज के रियल कामों पर ही खर्च करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी, अब आप वाईड अप करें।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : सर, मैं बहुत समय नहीं लूंगा। मैं दो तीन प्वायंटस कहकर अपना स्थान ले लूंगा। अध्यक्ष महोदय, जो लेडीज हरियाणा की हैं। खास तौर से गांवों की और शहरों में गरीब घरों की, चाहे कोई बीमार है जैसे बुढ़िया है या कोई और है उनको शौचालय जाने के लिए रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है। इससे बड़ी खेद की और कलंक की बात नहीं है इसलिए प्राथमिकता के तौर पर सरकार को गांवों में गरीब आदमियों से शुरू करके सब घरों में ये शौचालय बनाने के लिए मदद करनी चाहिए। इस वक्त भारत सरकार इस तरह के शौचालय बनाने के लिए 600 रुपये प्रति शौचालय के हिसाब से मदद करती है, लेकिन इससे कुछ नहीं हो सकता। मेरा इस बारे में कहना यह है कि भारत सरकार से कहकर यह ग्रांट इंक्रीज करके दो हजार रुपये हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें मदद दे सकती है। इस बारे में टाईम बाउंड प्रोग्राम हर गांव में, हर घर में, हर गरीब के घरों में शुरू होना चाहिए ताकि लेडीज की जो स्थिति है उसमें सुधार हो और उनका उस कलंक से पीछा छूट जाए। इसी तरह से अवैध कालोनियों के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा। हालांकि पहले भी हाउस में यह बात आयी है। कि जो जमीनों के भू माफिया लोग हैं जो स्पैक्यूटेटर्ज लोग हैं वे जमीने खरीदकर बिना मंजूर करवाए भोलेभाले लोगों को जिनको इस बारे में पता नहीं होता, प्लाट्स बेच देते हैं। अज्ञानता की वजह से इन लोगों को पता नहीं होता क्योंकि ये लोग तो रोजगार के सिलसिले में आकर शहर में बसते हैं। वे समझते हैं कि शहर की इन अवैध कालोनियों में उनको पूरी फैसेलिटीज मिलेंगी। ये लोग हुडा की मंहगी जमीन नहीं खरीद सकते इसलिए ये शहर से थोड़ी दूर सस्ती जमीन खरीदते हैं। जिनमें सारी उम्र के लिए उनको बाद में कोई फैसेलिटीज नहीं मिलती है। आज भी बिजली बोर्ड की इस बारे में एक चिट्ठी है जिसमें कहा गया है कि अगर अवैध कालोनी में घर में बिजली का कनैक्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 15 रुपये प्रति गज के हिसाब से डिवैल्पमैंट चार्जिज देने पड़ेंगे। इन डिवैल्पमैंट चार्जिज में इन कालोनियों में न सड़क बनेगी, न नाली बनेगी न ही पानी आयेगा और न ही स्ट्रीट की लाईटिंग होगी। सिर्फ उसको घर में कनैक्शन लेने के लिए यह पैसा देना पड़ेगा। यह

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

कैसे 15 रुपये दे सकता है ? इसी तरह से ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज की और बिजली की भारी कमी स्टेट में है। जो पूरी दुनिया में किया गया है उसका अनुसरण हमको भी करना चाहिए। डीजल जैनरेटिंग सैट्स जो हैं वह हर कैपेसिटी के सस्ते हैं यूरोप के बहुत से देशो में मैनुफैक्चर होते हैं और मिलते हैं । पांच मैगावाट का, दस मैगावाट का, पन्द्रह मैगावाट का और बीस मैगावाट का मिल सकता है। ट्यूबवैल्ज का आप कलस्टर बना सकते है। 50 ट्यूबवैल्ज के लिए, 100 ट्यूबवैल्ज के लिए और वहीं पर एक कैपेटिव जैनरेटिंग यूनिट लगा दीजिए। इसी प्रकार से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए यह अलग से हो सकते हैं। इसी तरह से गांवों में रोशनी देने के लिए यह लग सकते हैं। इसलिए बिजली बोर्ड को और सरकार को नये तरीके अपनाने चाहिएं। कैथल में आज तक भी कोई सरकारी कालेज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके पड़ौस में यह इलाका है इसलिए यह आपको भी नुक्सान है। पूरे हरियाणा में एक मात्र यह जिला है जिसमें सरकार कोई भी सरकारी कालेज आज तक नहीं खोल सकी है । शिक्षा मंत्री यहां पर बैठे नहीं हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मैंने 12 किल्ले जमीन मुफ्त में दिलवायी है। यह जमीन मेन रोड पर है जो रोड कैथल से चंडीगढ़ आती है उस रोड पर यह जमीन है। सरकारी कालेज खोलने की मांग उन्होंने की थी। इसी तरह से होस्पीटल की दशा बहुत दयनीय है न बिल्डिंग है न डाक्टर्ज हैं। हमारी बहन जी हैल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने और इनके अधिकारियों ने इस बारे में वायदा भी किया था। सिविल अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन सैक्टर 18 में हुडा के अधिकारियों ने वहां पर रिजर्व कर दी है। यह उनका बहुत अच्छा निर्णय है। अगर एक मल्टी फैसेलिटी सुपर स्पैशिएलिटी होस्पीटल कैथल में बन जाए तो गांवों के लोगों को बहुत फायदा होगा। हमारे प्रदेश में 100-100 किलोमीटर दूर तक नेशनल स्टेडियम नहीं है। मैंने कैथल में नेशनल स्पोटर्स स्टेडियम बनाने के लिए बात की थी जिसके बारे में मंत्री महोदय ने वायदा किया था लेकिन आज वे मंत्री जी मौजूद नहीं है इसलिए सरकार को इस बारे में मदद करनी चाहिए। कैथल में एक स्पोट्र्स स्टेडियम इन्डोर और आउटडोर ऊंचे स्तर का बनाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का और सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने जो एक कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट के ऊपर घोटाला और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमें दर्ज करने का फैसला किया गया है। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में आज तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं उनमें से कुछ को छोड़कर कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे।. 4-5 जमात पढ़े हुए लोग मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने यूनिवर्सिटीयों के वाइस चांसलर भी वैसे ही लगाए। हिसार ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मुझे पर्सनल नॉलेज है वहां का वाइस चांसलर एक क्लर्क को लगाया गया था। बाकी जगहों पर भी कोई अकादमिक क्वालिफिकेशन नहीं देखी गई, कोई बैकग्राउंड नहीं देखी गई। मुझे सरकार से उम्मीदद है कि बहुत ही हाई क्वालिफिकेशन के लोग जो इस देश में मौजूद हैं, उनका फायदा शिक्षा के क्षेत्र में लिया जायेगा।

Mr. Speaker : Surjewala Ji, your time is over. Please sit down.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बात और कहकर अपना स्थान लेता हूं पिछले मुख्यमंत्री को तो यह भी पता नहीं था कि कांस्टीच्यूशन में और आम कानून में क्या फर्क है वे कहते थे कि मैं जो कहण लाग रहा हूं वही कानून है लोगों ने मुझे बनाया है ह्यूमन राइट्स में लिखने की आजादी और बोलने की आजादी में क्या फर्क है यह भी पता नहीं है। न यहां कोई कल्चर है न यहां तजवीज है। मुझे आज के मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों से उम्मीद है कि वे इन सारी

बातों को अपग्रेड करेंगे, लिफ्ट करेंगे और जो ऐजूकेशनल बैकवर्डनैस है। सोशल बैकवर्डनैस है उसको दूर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक ने तो 25 बैड का वैटरनरी अस्पताल भी डिक्लेयर कर दिया था।

प्रो० छत्तर पाल सिंह (घिराय) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने 9 जून, 2005 को इस सदन में जो बजट प्रस्तुत किया मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। डांगी साहब मुझे पीछे से आवाज दे रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है मैं भी उसका समर्थन कर दूं तो मैं बता दूं कि डांगी साहब की बात का तो मैं हमेशा ही समर्थन करता ही हूं क्योंकि जो आग वहां पर सामने बैठे लोगों के नेताओं ने लगाई थी और घिराय विधान सभा क्षेत्र की राजनीतिक लड़ाई को चौधरी देवी लाल को घिराय से हराकर मैंने शांत कर दिया था इसलिए मेरा समर्थन तो इनकी बात को स्वाभाविक ही रहेगा। अभी सुरजेवाला साहब ने जो रेवोल्यूशनरी चेंज की बात की वह काबिलेतारीफ है उसको भी इन्डोर्स करना जरूरी है, बाई एंड लार्ज इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं । मेरे सामने जो साथी बैठे हैं। इनकी पहले भी मजबूरी थी ये बोल नहीं सकते थे, अब भी इनकी मजबूरी है। अब हरियाणा प्रदेश की जनता के मन से एक बाप और दो बेटों का डर तो निकल चुका है लेकिन इनके दिमाग में आज भी डर है। (विघ्न) स्पीकर सर, कांग्रेस पार्टी जिसके हरियाणा के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा रहे हैं जो इन्होंने उस समय लोगों से वायदे किए थे अपने भाषणों में दूसरे नेताओं ने अपने भाषणों में जो वायदे प्रदेश की जनता से किए थे उनको इन्होंने आज मूर्तरूप दिया है मैं मुबारकवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और आज की सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को जिन्होंने पहले अपने कहे हुए वायदों को पूर्ण रूप से जनता की भावनाओं के अनुरूप ढाल दिया है यह तारीफ की बात नहीं है। (विघ्न) मैं तारीफ के लिए तारीफ नहीं कर रहा हूं बल्कि यह व्यवहारिकता है। स्पीकर सर, दूसरा कारण हिन्दुस्तान के अन्दर हमारी पार्टी की मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी है और हिन्दुस्तान के अन्दर काफी समय बाद लोगों को यह देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी की संरचना जिन विचारों को लेकर की गई थी उन विचारों को व्यवहारिकता के अन्दर ढालने में यदि आज किसी नेता ने पारदर्शिता दिखाई है तो वह श्रीमती सोनिया गान्धी हैं। स्पीकर सर, जनता के लिए सरकार ने बहुत उन्नत फैसले लिए हैं और हर कार्यकर्ता को हर नेता को आज वह उत्कृष्ट समझती है एनक्रेज करती है। स्पीकर सर, बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने कही हैं कि पिछली सरकार के अन्दर यह गलत हुआ। स्पीकर सर, फायनैंस मिनिस्टर ने एक फैसले के तहत हरियाणा के अन्दर लाटरी को खत्म किया जो एक बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि वे जो सट्टे लगाते थे उनमें हर पुलिस अधिकारी जो जिले में बैठता था थाने में बैठता था, चण्डीगढ़ में बैठता था या सरकार के मुखिया तक की जेबों में करोड़ो रुपये जाते थे। रिक्शा वाला, मजदूर, कमजोर से कमजोर आदमी सट्टा खेलता था और उसकी चमड़ी उतरने का काम होता था। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने बजट पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अन्दर बहुत अच्छा प्रकाश डालने का प्रयास किया है। The problem with intellectuals is that they do not have a synoptic view of economic development of the State. Cooperate Sector looks at the budget purely in terms of tax concessions. Service sector is worried about exemption limit and the tax slabs. Common man is worried about taxation on petroleum products and other consumables items. Finance Minister on the other hand get away with half backed proposals because opposition leaders do not do their home work properly and speak in the sense with an analytical approach and thrust.

[प्रो० छत्तर पाल सिंह]

Mr. Speaker, Sir, an honest presentation of the budget should consist of four parts. Part-I deals with coverage of milestones, revenue receipts, deficit financing and unutilized funds in the budget of previous year. Part-II to deal with national cash-book of receipts and expenditures for the next year and the fresh tax proposals. Part-3 should deal with appraisal of the five year plan, procrastination of projects, refixing of targets and addition of new proposals in the budget Part-4: should deal with new set of reforms in different department and ways to mop up financial resources. Speaker sir, but the Finance Ministers both at national and State Level do not adopt this mode and deliver speeches in roundabout and circumlacutory manners. Speaker sir, the basic problem is that every regime talks of 9% growth without explaining what it means in terms of end results for improving the quality of life of 37% population falling below poverty line and 28% just above it. Suppose the nation maintains 9% growth continuously for 10 years, will the prosperity level of the nation surpass the economy of the developed nations ? The answer is clear 'No' because India has a vast sea of poverty and the 6 to 7% growth witnessed during the last few years has not changed the situation much and just maintains economic status quo in the country and similar in Haryana. Speaker sir, to achieve 9% growth, the growth in agriculture sector has to be 4% which otherwise has tapered down to 1.8% और हरियाणा में तो 1.1 प्रतिशत है और यह स्टैगनेशन पर है, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा। इसके तो बहुत स्ट्रेंज रिप्रक्यूशन होंगे, इसको जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं हम अपने बजट और जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आदरणीय वित्त मंत्री जी अपने जवाब में इस चीज को देखेंगे कि कितना इन्वाल्व कर पाए हैं, इसको इम्पलीमैंट कर पाए हैं Mr. Speaker sir, Keeping in view this, the budget is heavily titled towards social sector projects than infrastructure problem with social sector projects is that full benefits hardly reach the poor and 50% get lost in the hands of intermediators. One cannot grudge against the desirability of these projects but the real key to economic development lies in providing basic infrastructure. If the Finance Minister wants to provide durable bricks for Haryana Nirman, he will have to place infrastructure at the central core of the dream budget and projects for rural development and social upbringing of poor people will have to form the main body. Otherwise any budget minus infrastructure projects would look like a pipe dream only. अध्यक्ष महोदय, आज जो हमारा फिसकल डैफीसिट है it is around 9.00 crores मैं वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि वह अपने जवाब में इसका खुलासा करें How it raised such a level. Mr. Speaker Sir, कल कुछ जवाब इंडस्ट्री मिनिस्टर के बिहाफ पर पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर दे रहे थे उसके अन्दर मुझे ऐसा लगा कि हरियाणा सरकार जो स्कीम बना रही है। उसमें चाहे गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, सोनीपत पानीपत अर्थात् जो दिल्ली के नजदीक के टाऊन हैं इनके अंदर एग्रीकल्चर सैक्टर की, इण्डस्ट्री सैक्टर की और एजूकेशन सैक्टर की डिवैल्पमैंट के लिए चाहे वह मोडल स्कूल्ज की बात है, चाहे राजीव गांधी जी के नाम पर Oxford University के लैवल का एजूकेशन इन्स्टीच्यूट बनाने की बात है सरकार विचार कर रही है इस बारे में मैं सरकार को यह सुझाव देता हूं कि रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में और डिसटैंस एरियाज में यदि इन इन्स्टीच्यूट्स को बनाया जायेगा तो देहात के अंदर विकास होगा और देहात के

लोग एग्रीकल्चर सैक्टर को छोड़कर शहरों की तरफ नहीं आयेंगे। इससे शहरों में जो भीड़ बढ़ रही है। वह भी कम होगी। कल मैंने देहात के अंदर एग्रीकल्चर सैक्टर में जो सैचूरेशन ऑफ लैंड बढ़ती हुई आबादी की वजह से हो रही है और एवेलेबल लैंड के अंदर किसान जिस तरह से बिजली और पानी की समस्या झेल रहे हैं उसके बारे में चर्चा की थी। मैंने जिक्र किया था कि जो किसानों के बच्चों के लिए जिस किस्म की टैक्नीकल एजूकेशन related to their products या उनकी employment in small scale industries or large scale industries में है। वह भी डबवाली और कुछ टाऊंज की बात थी । मैं यह चाहूंगा कि इस किस्म के जो इन्स्टीच्यूट्स हैं और जो small scale industries or large scale industries हैं वे भी देहात के क्षेत्रों की तरफ सरकार को देनी चाहिएं। ऐसा करने से देहात के अंदर जो बढ़ती बेरोजगारी टोटल पोप्यूलेशन की 80 प्रतिशत है वह भी कम होगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ बातें करना चाहूंगा और पांच मिनट में समाप्त करूंगा । मेरा विधान सभा क्षेत्र है, comprises of 40 villages only. वहां चाय की या पनवाड़ी की भी दुकान नहीं है। वहां पर किसान और मजदूर सिर्फ खेती पर ही निर्भर हैं। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे हल्के में सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको और उन्नत करने की आवश्यकता है। सिंचाई मंत्री जी अपने एक रिप्लाई में बता रहे थे कि किस इलाके में पहले ज्यादा पानी गया और कौन सा इलाका पानी से वंचित रहा । उसमें उन्होंने हिसार का जिक्र नहीं किया था। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर पिछली सरकार के समय में 40 दिन में एक हफ्ते से ज्यादा सिंचाई के लिए पानी किसानों को नहीं मिलता था। स्पीकर सर, इस बात को सरकार दिमाग में रखे कि हमारा इलाका पानी से deprive था इसलिए हमारे यहां भी पानी की उचित व्यवस्था की जाये। हमारे से आगे आदमपुर के कुछ एरिया में भी पानी की बहुत समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा जिक्र करता रहा हूं कि जो सिवानी सब फीडर है उसको जीरो प्रतिशत पानी दे रहे हैं और उसकी वजह भाखड़ा का पानी कहीं डाबड़ा गांव के पास लिंक करके आगे देने की बात है। पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूट्री का पानी भी कम किया जा रहा है। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इसमें चाहे लाडवा माईनर है या रायपुर माईनर है जो छोटे ओबस्ट्रक्स हैं उनके कारण पहले ही किसान पानी की कमी के शिकार रहे हैं। यदि उनमें पानी और कम कर दिया गया तो वहां पानी की बहुत किल्लत हो जायेगी। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि जो सिवानी फीडर और पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूट्री हैं इनके अंदर भी पानी कम नहीं किया जाना चाहिए जितना पानी इनमें है उसको मेनटेन रखना चाहिए क्योंकि वहां भी किसान को पानी की बहुत समस्या है। इसके अतिरिक्त हमारे यहां भधावड़ माईनर,सरसोद बालक माईनर, पाबड़ा ब्रांच स्टील, पी०एल०सी० लिंक जो फरीदपुर टेल है इनके अंदर भी हमेशा पानी की कमी रही है और हमारे सामने जो इण्डियन नैशनल लोकदल के साथी बैठे हैं इन्होंने हमारे गांव का पानी तो बिलकुल टेल पर ले आये और जो टेल बनी है वह किसानों का जो शेयर बनता है उसका पानी भी पूरा नहीं कर पाती । यदि गांव में तालाब के अन्दर पानी की आवश्यकता हो जाए तो अलग से आप उसके अन्दर पानी भरने की परमिशन दे दें तो फार्मर को पानी मिल जाएगा। अगर सरकार तालाब भर सकती है तो इस तरह से फार्मर्ज को पानी दे सकते हैं। इस स्कीम को चलाना बहुत जरूरी है इसका ऑगमैंटेशन बहुत जरूरी है अदरवाईज हमारे इलाके के किसान बर्बादी की कगार पर हैं। स्पीकर सर, बालसमन्द ब्रांच कैपेसिटी के हिसाब से पूरा पानी लेने की पोजीशन में नहीं है। अधिकारी हमेशा यह बात कहते हैं कि अगर इसमें पूरा पानी आएगा तो वह टूट सकती है। उसकी स्ट्रैंथनिंग के लिए खरखड़ी माईनर की स्ट्रैंथनिंग के लिए

[प्रो० छत्तर पाल सिंह]

हमें पैसे की आवश्यकता है। दिल्ली रोड पर बालसमन्द के ऊपर एक ब्रिज है वह हमेशा टूटा रहता है जिससे किसानों को पानी के लिए बहुत सफर करना पड़ता है। स्पीकर सर, इन सब बातों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है अदरवाईज़ किसान इन सुविधाओं से महरूम रह जाएगा। स्पीकर सर, रिपेयर एण्ड रि-मॉडलिंग ऑफ वाटर चैनल्ज़ मैंने इस के बारे में अधिकारियों से जिक्र भी किया है और मीटिंग के अन्दर यह चर्चा भी आई है। एक तो पहले डिजाईन ठीक नहीं किया गया या उन पर मसाला ठीक नहीं लगाया गया जिस के कारण वे जल्दी टूट गई और किसानों ने दोबारा से वाटर कोर्सिज के लिए अपना शेयर जमा करवा रखा है। पूरी स्टेट के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि का जो परपोजल है, वह पूरी स्टेट के लिए बहुत ही कम पैसा है। इस भद में और पैसा बढ़ाया जाए क्योंकि यदि हमारा शेयर हमारे जिले के लिए डेढ़ या दो करोड़ रुपये बनेगा तो उससे तो कुछेक वाटर कोर्सिज ही बन सकते हैं और हमारा किसान पानी से महरूम रहता चला जाएगा। अदरवाईज इस बात की तफर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्पीकर सर, जहां तक डि-सिल्टिंग का सवाल है, यह बहुत ही अच्छी बात है लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि there should be a continuous process अगर आप इसे एक बार करके छोड़ देंगे तो उसकी हालत फिर वैसी ही हो जाएगी। फिर छः महीने के बाद आपको इसकी डि-सिल्टिंग करनी पड़ती है।

Mr. Speaker: Please wind up. Now, Finance Minister will reply.

Prof. Chhattarpal Singh : Sir, within two minutes, I am winding up. स्पीकर सर, ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट का जिक्र किया गया है। यह बात ठीक है कि प्राईवेट बसें आज ट्रांसपोर्ट कर रही हैं और वे डेविऐट कर रही हैं। सरकार द्वारा वहां पर हरियाणा रोड़वेज की अपनी बसें नहीं लगाई हुई हैं जिसके कारण देहात के लोगों को बड़ी भारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। स्पीकर सर, अब मैं एजूकेशन के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। आर्ट्स फैक्लटी के अन्दर जो विद्यार्थी सरकारी कॉलेजिज के अन्दर दाखिला लेना चाहते हैं उनको वहां पर दाखिला नहीं मिलता है क्योंकि वहां पर अध्यापक और फेसिलिटीज़ सीमित हैं अगर वे प्राईवेट कॉलेजों में जाते हैं तो गरीब विद्यार्थी की यह प्रॉब्लम होती है कि उनका फीस स्ट्रक्चर in comparison of Govt. fees ज्यादा होता है और पैसे की कमी के कारण वह वहां पर ऐडमिशन नहीं ले पाता है, क्या सरकार इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देगी ? या तो उनका फीस स्ट्रक्चर ठीक किया जाए या गवर्नमैंट कॉलेजिज के अन्दर ज्यादा स्टुडैंट्स को एडमिशन की इजाजत दी जानी चाहिए। अब मैं टैक्नीकल ऐजुकेशन के बारे में एक प्वांयट कहना चाहता हूं। जब मैं मिनिस्टर था तो हमने 3800 विद्यार्थियों को एडमिशन दिया था। हमने उस समय एक पॉलिसी और एक स्कीम दी थी जिसके तहत 3800 एडमिशन यहां पर टैक्नीकल ऐजुकेशन में होंगे Guru Jambheshwar University is one of the part of our decisions.Education should be quality orientation लेकिन उसमें क्वालिटी मेंनटेन नहीं की जा रही है। मैं सरकार से चाहूंगा कि जिस मकसद के साथ जो कोर्सिज वहां पर चलाए गए थे उसको एचीव करने के लिए ऐजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए।

Mr. Speaker: Thank you very much. Please take your seat. No more time Now, Finance Minister will reply on the Budget. (विघ्न)

प्रो० छतरपाल सिंह : स्पीकर सर, बी० एण्ड आर० तथा हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे में मैंने थोड़ी सी बात कहनी है। मेरी कांस्टीच्यूएंसी में इस ओर पिछले 5-7 साल से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे कि धर्मपाल मलिक जी कह रहे थे कि खड्डों के अन्दर सड़क है मेरे वहां पर भी ऐसी ही पोजीशन है इसलिए वहां पर रोड्ज की रिपेयर भी वांछनीय है। स्पीकर सर, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में यहां पर प्रॉब्लम बताई जा रही है हाईजैनिक कण्डीशन के पानी की सप्लाई की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे। यह तो हम कह सकते हैं कि consumer has also to be disciplined क्योंकि यह देखा गया है कि कई बार वे पानी की तरफ ध्यान नहीं देते और पानी वेस्ट जाता रहता है। स्पीकर सर, मैं माननीय फाईनैंस मिनिस्टर से चाहूंगा कि वे अपने जवाब में इस बिन्दु पर भी ध्यान दें। स्पीकर सर, मैंने इस बारे में पहले भी जिक्र किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन के रौंग डिसिजन्ज की वजह से आज कोर्ट में हमारे बहुत से केसिज़ पैण्डिंग है। जब किसी भी कर्मचारी को और जनता को ठीक डिसीजन नहीं मिलता है तो उसको अपना हक लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है और उसके लिए उसको वकील करना पड़ता है और उसकी फीस देनी पड़ती है। इस बारे में मैंने पहले भी पूछा था लेकिन उसका सैटीसफैक्टरी जवाब नहीं आया था। इसलिए मैं अपनी बात दोबारा से कह रहा हूं कि सरकार इस बारे में कोई ठोस कदम उठाए। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker : Now, Finance Minister will give reply.

वित्तमंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, मैंने इस गरिमामय सदन में बजट प्रपोजल रखी थी उस पर लगभग 3 दिन हमारे सम्मानित साथियों ने अपने विचार रखे, चर्चा की और सरकार को अनेकों सुझाव दिए। इसके साथ ही बहुत से साथियों ने बजट के अन्दर जो उनके नजरिए से कमियां थीं उनको भी दर्शाने की कोशिश की है। मैं सभी साथियों का इस बात के लिए स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि एक नई परम्परा के साथ हरियाणा में पहली बार एक विस्तृत चर्चा बजट पर हुई । जैसा कि छत्तरपाल सिंह जी ने कहा है कि जब सम्मानित साथी बजट पर होमवर्क करके नहीं आते हैं तो बजट की बारिकियों को समझने में गलती लग जाती है। उनके भाषण की दिशा ही बदल जाती है। लेकिन इस बार बहुत से साथी बजट पर चर्चा करने के लिए तैयारी करके आए थे। स्पीकर सर, पिछले पांच सालों में अगर हम इस सदन का इतिहास देखें तो साल में साढ़े ग्यारह दिन की ही सीटिंग्ज हुई थीं। सारे हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं होगा जिसमें विधायकों को अपनी बात कहने का, अपने विचार प्रकट करने का, अपने हल्के के लोगों की जरूरतों और अपने एरिया के विकास के बारे में बात कहने का इतना कम समय मिला हो। स्पीकर सर,मैं तो यह कहूंगा कि 57 सालों के इतिहास में इतना कम समय जो कि पिछली सरकार के वक्त में विधायकों को सदन में बोलने के लिए मिला था, देश के किसी प्रान्त में नहीं दिया गया होगा, शायद ही इतिहास में किसी भी देश में ऐसी कोई घटना घटी हो। स्पीकर सर, चाहे बजट पर डिस्कशन हो, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डिस्कशन हो या जनता से जुड़ी हुई जरूरतों पर या बिलों पर डिस्कशन हो, पिछली सरकार ने उन पर बोलने के लिए किसी सदस्य को कोई समय नहीं दिया था। स्पीकर सर, आपने जब अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था तो उस वक्त हमारी सरकार ने खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया था कि पिछली सरकार की तरफ से जो भी गलतियां हुई हैं हम उनको ठीक करेंगे। सदन की कार्यवाही को

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

विचारों की अभिव्यक्ति का प्लेटफार्म बनाया है और बिना किसी इशारे और हड़बड़ाहट के हमने हमारे साथियों को सुना है। स्पीकर सर, एक अच्छी परम्परा का निर्वहन करते हुए आपके सहयोग से हमने यह सब किया है। अगर आपका सहयोग नहीं होता तो शायद हम ऐसा नहीं कर सकते थे। स्पीकर सर, हमने पूरा बजट अलग से रखा है। अभी भी 27 ऐसे हमारे माननीय साथी हैं जिनको बोलने का समय नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी उदारता की वजह फिर उनको डिमांडज पर बोलने का समय देने के लिए कहा कि जो साथी बजट पर नहीं बोल सके हैं उनको डिमांड पर बोलने का मौका मिलेगा और जो बजट से संबंधित उनके मुद्दे हैं उनको भी वे उस समय इस सदन में उठा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विधान सभा की जो गरिमा है जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि पहले वह एक किस्म से लौप हो गयी थी क्योंकि उस समय डेढ़ दिन के अंदर हाउस का सारे का सारा बिजनैस खत्म कर दिया जाता था तथा जो विपक्ष में सदस्य बैठते थे उनको बोलने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। जो सदस्य सरकार की खामियों को दर्शाना चाहते थे उनको सदन से बाहर कर दिया जाता था, नेम कर दिया जाता था। जिस प्रकार का तानाशाही का आचरण उस समय की सरकार ने दिखाया उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। आज हम प्रजातंत्र में पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी में रह रहे हैं। मुझे भी पांच साल तक लोकसभा का सदस्य रहने का मौका मिला, मुख्यमंत्री जी भी लोकसभा में रहे, शमशेर सिंह जी और दूसरे कितने ही सदस्य यहां पर ऐसे हैं जो लोक सभा में या राज्य सभा में रहे हैं। मैंने एक भी इन्सटान्स अपने तीस साल के राजनैतिक जीवन में नहीं देखा जब लोक सभा के अंदर किसी सदस्य को नेम कर दिया गया हो। विरोधी पक्ष के लोगों ने वहां कई कई दिन तक हाउस नहीं चलने दिया लेकिन सदन की गरिमा पर कभी आँच नहीं आयी। अध्यक्ष महोदय, इसी नियमावली को, इसी कन्वैशन को हम निभाते हुए यह कह रहे हैं कि विपक्ष को बोलने का समय मिलना चाहिए। विपक्ष को उन मुद्दों को उजागर करना चाहिए जिनमें सरकार की कमी नजर आए। मैं इस बात के लिए अपने साथियों को भी कहूंगा और मैंने बहुत से अपने साथियों से कहा भी है कि हमारे इस बजट में अगर उन्हें कोई कमी नजर आए तो मेहरबानी करके वे उनको बताएं ताकि हम उनका सुधार कर सकें। डांगी साहब ने तो प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि मैं खास बिरादरी से हूं तो हो सकता है कि मैं अच्छा वित्त मंत्री न होऊं। लेकिन जब से हरियाणा बना है मैं यह कह सकता हूं कि श्रीमती ओमप्रभा जैन जोकि लम्बे समय तक वित्त मंत्री रहीं, उनके कार्य की दक्षता का कोई मुकाबला नहीं रहा। मैं यह भी कह सकता हूं कि पिछली सरकार में अगर सम्पत सिंह वित्त मंत्री या मंत्री न होते तो वह सरकार और पता नहीं क्या क्या करती। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वे भी उसी बिरादरी से हैं जिससे मैं हूं। अगर मैं यह कहूं कि वे भी अच्छे वित्त मंत्री थे तो कोई अतिश्योक्ति नहीं है। फर्क उनमें और मेरे में यह है कि उन हालात में जब उनकी जुबान बंद कर दी जाती थी यह जब उनको मर्यादाओं का उल्लंघन करने के लिए कहा जाता था तो उनकी इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं होती थी। वरना इस्तीफा दे देते सरकार के अधिनायकवाद और मोनोपोली के खिलाफ। लेकिन अच्छा वित्त मंत्री होना और अपनी भावनाओं को दबाकर रखना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे हमारी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले अपनी प्राथमिकता तय कीं और हमने अपने बजट में उनका पूरा प्रारूप उतारने की कोशिश की । अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं उन प्राथमिकताओं का जिक्र करूं, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की पहले व्यवस्था थी उस व्यवस्था के खिलाफ एक जनमत हमें मिला और वह जनमत यह

था कि उस समय लोग आजादी से सांस नहीं ले सकते थे और लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। सिर्फ एक आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन ही नहीं हो रहा था बल्कि नौकरशाही भी बुरी तरह से दबी हुई थी। उस प्रशासन में पुलिस महकमें का मिसयूज करके, अपने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से हमारे दर्जनों जो राजनेता हैं चाहे इस तरफ बैठे हों या उस तरफ बैठे हों उनके खिलाफ गल्त मुकदमें बनाए गए थे। उस प्रशासन के खिलाफ यदि किसी पत्रकार ने अपनी कलम से आवाज उठाने का फैसला किया तो उनको भी जेलों में डाल दिया गया। यहीं नहीं, वे सरकारी तंत्र की गोलियों का शिकार भी हुए और सरकारी तंत्र जब इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ तो किराए पर लिए हुए बदमाश लोगों द्वारा पत्रकारों की जान ली गई। ऐसे वातावरण में जहां अधिकारियों का पूरी तौर पर हनन हो चुका था वहां हरियाणा प्रदेश की जनता ने फैसला किया कि हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां किसी को बिजली मिले न मिले या नौकरियां मिले या न मिलें लेकिन जीने का अधिकार तो मिले। जब अधिकार पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है तब फिर कोई बात बाकी नहीं रहती । यही वजह थी कि मेरे साथियों ने पिछली सरकार के कारनामों का जिक्र किया। इंदौरा जी ने भी कहा कि बजट में इतना घाटा बढ़ गया है। फलां मद में इतना पैसा था अब उसको इतना कर दिया है। नौकरियों और पेंशन पर ज्यादा खर्च बढ़ गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन पार्लियामैंट का चुनाव सम्पन्न हुआ तब जो सत्तासीन पार्टी थी जिसको पांच साल पहले लोगों ने बड़ा भारी बहुमत दिया था वह मात्र 18 प्रतिशत वोटों पर सिमट गई और जब उन्होंने देखा कि लोगों का झुकाव अब उनके विपरीत हो रहा है तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए ताकि आने वाले विधान सभा चुनाव में लोगों का मन जीत सकें लेकिन हरियाणा के लोगों ने यह समझ लिया था कि जो सरकार साढ़े चार साल तक दमनकारी नीतियां चलाती रही और लोगों को मौलिक अधिकारों का हनन करती रही, वह अब 6 महीने में उनको रियायतें देना चाहती है, सुविधायें देना चाहती है तो वह सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहती है। इसलिए जो पटकनी उनको लोकसभा के चुनाव में दी गई थी उसको दुरूस्त करने के लिए उनसे अगली इस सरकार पर जो 3 महीने पहले की सरकार है 700 करोड़ रुपये का वजन हमारे ऊपर पड़ा है और जिन कमियों के बढ़ने की बात करते हैं हमारी सरकार को तीन महीने का समय हुआ है हमने अभी तक भारत सरकार से एक रुपये का लोन भी नहीं लिया और किसी दूसरी संस्था से भी हमने कर्ज नहीं लिया। जो आपने बोला है वह आपके ही कारनामों का भुगतान हमें करना पड़ रहा है इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जब आपके बारे में चर्चा करूं तो हम आपकी बुराइयों को ठीक करने का ही यत्न कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने सुना था कि जो चोर, डाकू या लुटेरा है वह लोगों की धन संपत्ति को लूटता है लेकिन मैंने इतिहास में यह पहली बार देखा है कि जिस चीज की जिम्मेदारी वह खुद निभा रहा है वह अपने ही खजाने को लूटे यह पहली बार देखा है। इसका

13.00 बजे

सबसे बड़ा सबूत है चौटाला सरकार की एक्साइज पॉलिसी है। स्पीकर सर, पांच साल के शासन में इनका जो रेवेन्यू है जो एक्साईज से मिलना था उसमें 2 से 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई इससे ज्यादा वृद्धि क्यों नहीं हुई इस पर एक सवालिया निशान है क्योंकि सारे के सारे शराब के ठेके देने में मोनोपोली हो गई उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दिए । उनमें भी अपना हिस्सा कायम किया। यदि आज के मुख्यमंत्री यह सोचकर चलें कि यह जो सरकार है यह मेरी इण्डस्ट्री है तो उससे बड़े दुख की बात कोई और नहीं हो सकती । पिछली सरकार ने वही करके दिखाया, उन्होंने सारे तन्त्र को सारे सिस्टम को अपनी इण्डस्ट्री समझकर उसका दोहन और शोषण करना शुरू कर दिया। अब हम उसमें पारदर्शिता लायेंगे। सरकार की आमदनी को बढ़ाने के लिए हमने

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

उस एक्साईज पॉलिसी को बिल्कुल रिवर्स कर दिया है। उसी का परिणाम है कि 17 प्रतिशत के करीब हमारे को बढ़ौतरी मिली है। यही नहीं मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सोच में कितना फर्क होता है। पंचकूला में एक सैंड माईन्ज की आक्शन हुई उसकी जो मिनिमम स्पोर्ट प्राइस थी वह पहले 9 करोड़ थी उसको हमने बाद में 14 करोड़ रुपये किया था, लेकिन उस माईन्ज की बोली 35 करोड़ रुपये में छूटी। जिसने उस माईन्ज को लिया हमने उससे बात करने की कोशिश की कि इतना बड़ा जम्प कैसे है ? इसकी रिजर्व प्राईस 14 करोड़ रुपये है लेकिन आपने 35 करोड़ रुपये में ली तो उसने कहा कि वह इतने पैसे पहले भी दे सकता था लेकिन बिड लगाने की हिम्मत नहीं हुई। पिछली सरकार के समय में हरियाणा की जनता के साथ यह किया जा रहा था। मेरे साथी श्री अर्जन सिंह ने टोल टैक्स के बारे में कहा। मैं यह कहता हूं कि एक बार मैं दिल्ली से जीन्द आ रहा था तो जीन्द से पहले बैरियर पर चार लड़कों ने मेरी कार रोकी। उन लड़कों के साथ पुलिस भी खड़ी थी। उन्होंने कहा की पर्ची कटवाओं मैंने कहा कि किस बात की पर्ची तो पुलिस वाला मुझे जानता था वह तो पीछे चला गया और वह लड़का कहने लगा कि इस इलाके का ठेका हमने लिया हुआ है यहां से जो भी जायेगा उसको पर्ची कटवानी होगी यह मेरे साथ हुआ। ऐसे हालात थे हरियाणा को अपना फिफडम बनाकर, अपनी सम्पत्ति बनाकर राज करने की कोशिश की गई। इसलिए मुझे कई बार अफसोस होता है, उस सरकार में कुछ भले आदमी भी थे श्री सम्पत सिंह जी और श्री धीरपाल जी सिंह जैसे परन्तु उनमें बगावत करने की हिम्मत नहीं थी। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो हमारी कांग्रेस पार्टी में यह परम्परा रही है, ऐसे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की हममें हिम्मत है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस सारी चीज की जो परकाष्ठा है। The climax of the entire episode, I can put in two words, I want to quote. सर एक वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट की रिपोर्ट है। उसका नाम किल्स गार्ड है and that report is of the year 1996. उसने बहुत अच्छी बात कही है। वह बात अगर हरियाणा के संदर्भ में कही जाए तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। उसने कहा करप्शन, करप्शन का मतलब है मोनोपली प्लस डिसक्रीशन। करप्शन तब पैदा होती है जब मोनोपली भी हो और डिसक्रीशन भी हो। डिसक्रीशन तो उनकी यह थी कि सड़क का ठेका 10 करोड़ का या 12 करोड़ का हो उस बारे में एस०ई०, एक्सीयन को बोल दिया जाता था कि एक टैण्डर लेगें, दूसरा लिया तो तुम्हारी छुट्टी। पुलिस के लोग एस०ई०/एक्सीयन के ऑफिस के बाहर खड़े होकर जो टैण्डर्ज देने आते थे उनको सही माथनों में डंडे मार कर भगाते थे। इस तरह से करप्शन में मोनोपली और डिसक्रीशन आ गई अकाउंटेबिलीटी चौटाला सरकार की पहचान थी जैसे सत्यम शिवम सुन्दरम हैं यह उनका सत्यम था। उनका शिवम क्या था यह था ओम प्रकाश चौटाला, मोनोपली का प्रारूप मोनोपली के इम्बोडीमैंट और डिसक्रीशन किन को थी दोनों बच्चों को यानि दोनों बेटों को। एकाउंटेबिलिटी उस सरकार की क्या थी breaking the arms and legs of the MLAs ofI.N.L.D.

डा० सुशील इन्दौरा : वित्त मंत्री जी, आप इतने अच्छे ओहदे पर हैं, इसलिए ओहदे की गरिमा का तो ध्यान रखें।

Mr. Speaker : Indora Ji, please sit down.

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे अब समझ आता है कि सम्पत सिंह जी भी इसलिए नहीं बोले कि उनको भी टांग टूटने का डर था। अध्यक्ष महोदय, दूसरा एक असपैक्ट देखेंगे पिछली सरकार ने हरियाणा के लोगों से यह वायदा किया था, खासतौर से किसान भाइयों से कि आप बिजली के बिल मत भरो, हमारी सरकार आएगी तो हम माफ करेंगें और आगे बिजली पानी मुफ्त मिलेगा। अभी सढौरा जी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में ऐसा नहीं था। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि हरियाणा में 100 लोगों से सैम्पल सर्वे करवाएं, 100 में से 100 के 100 लोग यह कहेंगे कि चौटाला साहब ने यह कहा था कि बिजली के बिल मत भरो, माफ करेंगें और आगे बिजली पानी मुफ्त मिलेगा। अगर एक आदमी भी यह कहे कि ऐसा नहीं कहा तो हम अपनी सियासत, अपनी गद्दी छोड़ देंगें, इससे बड़ी गलत बात और क्या हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ...

Mr. Speaker : Indora Ji, please sit down. You fully know what were your powers when you were M.P. ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, इनकी स्थिति भी सम्पत सिंह जैसी हो रही है। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मरे सदन में यह कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बिजली के बिल माफ करने का वायदा नहीं किया लेकिन जब हम सत्तासीन हुए तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कैबीनेट मीटिंग में यह फैसला किया कि एक सब कमेटी बने और वह देखे कि आज का किसान, आज का गरीब आदमी खास तौर से गांव में रहने वाला हमारा भाई क्या उसकी हैसियत है कि वह बिजली के बिलों की अदायगी कर सके। इन्होंने एक कमेटी कंस्टीच्यूट की है। और उसका अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। भाई सुरेन्द्र सिंह और माननीय ओम प्रकाश जिंदल जी भी उस कमेटी के सदस्य थे लेकिन उनके अचानक निधन से हमारी कार्यवाही में थोड़ी सी अड़चन आ गई। वरना हम यह रिपोर्ट दो महीने पहले मुख्यमंत्री जी को सौंप देते। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने तो किसानों और गरीबों के बिल माफ करने के बारे में नहीं कहा था लेकिन हमारे मन में यह टीस जरूर है कि हम गरीब और किसानों की मदद करें। यह हमारी परम्परा रही है और हम उनकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी तीन महीने की सरकार ने कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं थी जिनके बारे में फैसला लिया है। चाहे ओलावृष्टि से फसलों के नुक्सान की बात है या कैथुरल क्लेमेटी की बात है। फसल के नुक्सान के लिए पहले 300 रुपये, 400 रुपये या 600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो मुआवजा दिया जाता था उसमें हमारी सरकार ने बढ़ोत्तरी की है। बढ़ोत्तरी भी 10 या 20 प्रतिशत की नहीं बल्कि गेहूं की फसल के लिए तो 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है और 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दूसरी फसलों के लिए मुआवजे में की गई है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि सदियों से किसानों की मांग थी कि उनकी जमीन अधिग्रहण का उन्हें उचित मुआवजा दिया जाये। किसानों की इस समस्या की तरफ भी हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां किसान सदियों से खेती करता आ रहा है। पहले उसकी जमीन अधिग्रहण कर ली जाती थी और उचित मुआवजा भी नहीं दिया जाता था। पिछली सरकार के लोग कहते थे कि कलैक्टर रेट पर मुआवजा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कलैक्टर रेट क्या है। बहुत से अधिकारी तो ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि किसान का धरती के साथ जुड़ाव कितना

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

अधिक है। एक-एक खूड के लिए किसान खून तक कर देते हैं। यदि उसकी पूरी जमीन अधिग्रहण कर ली जाये और उसे मुआवजा भी पूरा न दिया जाये तो हम सब सोच सकते हैं कि उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। पहले वाली सरकार के समय में 3 लाख रुपये, 3.50 लाख रुपये या 4 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को उनकी भूमि अधिग्रहण करने पर दिया जाता था और चौटाला साहब अपने को किसानों का सबसे बड़ा मसीहा कहलवाते थे। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं कहा, हम भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं। हमारी रगों में भी उन पूर्वजों का खून दौड़ रहा है जिन्होंने किसानों की सेवा की थी। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कहते कि हम किसानों के मसीहा हैं। अध्यक्ष महोदय, अब हमारी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे के मापदण्ड निर्धारित किए हैं। गुड़गांव और पंचकुला के आसपास के क्षेत्र में जिस किसान की भूमि अधिग्रहण की जायेगी उसको कम से कम 15 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस 15 लाख रुपये का मतलब यह नहीं कि 15 लाख से ऊपर मुआवजा नहीं दिया जायेगा। यह राशि 15 लाख की बजाय 20 लाख, 30 लाख या 40 लाख रुपये भी हो सकती है। इंदौरा साहब ने कहा कि इनकी सरकार के समय में भी 15 लाख रुपये मुआवजे के दिए गए। अध्यक्ष महोदय, हमने आंकड़े देखे हैं कहीं भी प्रति एकड़ के हिसाब से इनकी सरकार के समय में 8 लाख रुपये से ज्यादा मुआवजा नहीं दिया गया। कोई एक-दो एक्सैपशन गुड़गांव की हों तो पता नहीं। जबकि हमारी सरकार ने 8 लाख रुपये तो उस एरिया के लिए रखा है जहां सलम है। जिस जमीन पर किसान बिजाई नहीं कर सकता जो बंजर है। यदि इस तरह की जमीन एक्वायर की जायेगी तो भी 8 लाख रुपये तो एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा।

डा० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, बजट में तो पांच लाख रुपये लिखा हुआ है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि पांच लाख रुपये के अलावा 30 प्रतिशत सोलसियम है और 12 परसैंट इंट्रैस्ट इस तरह से टोटल करीब 8 लाख रुपये बनते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की तीन महीने की उपलब्धियों के बारे में बता रहा था। मेरे विपक्ष के कुछ भाई कह रहे थे कि हमने जो योजनाएं शुरू की हैं उनके नाम अपने नेताओं के नाम पर रखे हैं। जैसे जो हम एजूकेशन सीटी बना रहे हैं उसका नाम हमने हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम से रखा है। इसके अलावा गरीब लोगों के लिए जो स्कीम बनाई है उनका नाम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम रखा है। इनको इसका ऐतराज हुआ। (विघ्न)

डा० सुशील इन्दौरा : हमें कभी ऐतराज नहीं हुआ। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : इन्दौरा जी, आपको इस बात का भी अहसास होना चाहिए कि हमने कभी भी विपक्ष के नेताओं को इग्नौर नहीं किया है चाहे चौधरी देवी लाल जी थे और चाहे विपक्ष के दूसरे बड़े नेता रहे हों उनके प्रति कभी भी भद्दी भाषा अथवा गलत शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। हमने हमेशा उनको उचित सम्मान दिया है। इस सम्मान का ही मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सरकार पर इस बात का बड़ा दबाव था कि चौधरी देवी लाल जी के नाम पर सिरसा में जो यूनिवर्सिटी बनी है उसका कोई औचित्य नहीं है और उस यूनिर्सिवटी को खत्म किया जाए। उस यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी देवी लाल जी के नाम पर रख दिया गया और वहां पर मात्र एक

स्कैलटन बना दिया गया, एक ढांचा खड़ा कर दिया गया लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी की कोई एक्टिविटी नहीं है। हमने इसके बारे में माननीय मुख्यमन्त्री जी से बात की । उन्होंने मुझे खुद कहा कि हम वहां से कॉलेजिज को तो डिस-ऐसोसियेट करेंगे क्योंकि वहां पर कॉलेजों का चलाया जाना तर्कसंगत नहीं है लेकिन चौधरी देवी लाल जी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है, हम उनका नाम बरकरार रखेंगे और उसको सैंटर ऑफ एक्सिलैंस का दर्जा देने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारा सोचने का दायरा संकुचित नहीं है। हम फ्राखदिली से काम लेते हैं। हर व्यक्ति की विचारधारा अपनी है। कोई व्यक्ति चाहे वह सत्तापक्ष में है या विपक्ष में है लेकिन किसी व्यक्ति की विचारधारा अलग होने से उसके व्यक्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यह चाहते हैं कि ये लोग भी इसी भाषा को सीखें और इसी भाषा को अपनाएं। इन लोगों ने गलती की इसी लिए ये लोगों की नजरों से गिरे। अगर ये लोग हरियाणा की जनता की नजरों में उभरना चाहते हैं तो हरियाणा की जो संस्कृति है उसको अपनाएं। हरियाणा की अपनी कुछ संस्कृति है और खासकर कांग्रेस की जो संस्कृति है उसको अपनाएं। हमारे आनन्द सिंह जी डांगी इनके साथी थे डॉक्टर कादयान साहब इनके साथी थे और भी बहुत से इनके साथी थे जो इन्हें छोड़ कर इस तरफ आएं हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग इनको छोड़ कर आए हैं वे क्यों आएं हैं इस बात पर भी उनको गौर करना चाहिए। इन लोगों ने उनका निरादर किया है इस लिए वे उधर से इधर आए हैं। निरादर क्यों किया क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थोड़े पढ़े लिखे हैं और वे किसी ज्यादा पढ़े-लिखे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते । अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी कांग्रेस की संस्कृति यह नहीं है तथा कांग्रेस की छवि ऐसी नहीं है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने पढ़े-लिखे की बात कही है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब की बार सदन में पढ़े-लिखे सदस्यों की संख्या काफी है और अच्छे सदस्य इस बार चुन कर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आ गई। जब इनकी पार्टी के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह जी थे और एक दफा टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो उस समय उनको पार्टी ने इनके दो मैम्बरान की एक कमेटी बना दी। मेरे पड़ौस में डा० सरूप सिंह जी रहते थे। डा० सरूप सिंह और चौधरी देवी लाल जी की दो मैम्बरी कमेटी बना दी और कहा कि पार्टी के टिकट ये लोग बांटेंगे। एक व्यक्ति चौधरी चरण सिंह जी के पास टिकट के लिए चला गया। चौधरी चरण सिंह ने उस व्यक्ति को पूछा कि किस लिए आए हो तो उसने जवाब दिया कि मुझे टिकट चाहिए। उन्होंने कहा कि टिकट के लिए तो मैंने डा० सरूप सिंह और चौधरी देवी लाल की दो मैम्बरी कमेटी बना रखी है। वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं बी०ए० पास हूं तो चौधरी साहब ने कहा कि इसमें क्या बात है। वह व्यक्ति कहने लगा कि हमारे वहां पर तो एक बड़ी भारी समस्या हो रही है। डा० सरूप सिंह जी तो एम०ए० से नीचे किसी की दरख्वास्त नहीं ले रहे हैं और चौधरी देवी लाल जी दसवीं से ऊपर किसी की भी दरख्वास्त नहीं ले रहे हैं और मैं बीच में अटक गया हूं। (हंसी)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, बजट के जो मुख्य बिन्दु हैं उन पर हमारे सम्मानित साथियों ने जो सुझाव दिए हैं और क्रिटिसिज्म किया है उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूं इससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार जब बनी तो हमने यह मान कर अपना बजट निर्धारित किया है कि किसी राज्य को विकसित होना है तो उस राज्य के ढांचे के साथ-साथ उसकी जनता भी खुशहाल होनी चाहिए। अगर किसी प्रदेश की जनता कमजोर है उसकी जनता गरीब है तो

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

उसका विकास और ढांचे के सुदृढ़ होने का कोई अर्थ नहीं रहता । स्पीकर सर, हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम जी हैं उन्होंने जो केन्द्र में 2005-06 का बजट पेश किया है, उसकी कुछ लाईने मैं सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। स्पीकर सर, उसी दिशा में उन्हीं माप-दण्डों को लेकर हमारी सरकार ने डिसाईड किया कि हम भी उसी के आधार पर हरियाणा का बजट पेश करेंगे। स्पीकर सर, मैं उन लाईनों को कोट कर रहा हूं---

> "India is not a poor country, yet a significant proportion of our people are poor. Poverty is not only income poverty. Other indicators of poverty are illiteracy, disease, infant mortality, malnutrition, absence of skill and unemployment."

ये सारी चीजें मिलकर गरीबी बनती है इसलिए हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें हमारे यहां पर बेरोजगारी, उसमें हरियाणा की रैपिड इंडस्ट्रीयलाइजेशन में तीव्र गति से विकास हो जो कि अर्थहीन होकर रह गई है। आज हमारे बच्चों को जहां पर खड़े होने नहीं दिया जाता है। जिस चीज की हमें जरूरत है वह मीसिंग है। जिसके कारण आज हरियाणा में बेरोजगारी भयंकर रूप ले रही है। इन सब आधारों पर हमने अपनी वार्षिक योजना बनाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि चौटाला सरकार के पांच सालों के अन्दर पहली वार्षिक योजना में 1674 करोड़ रुपए रखे गये थे और वर्ष 2004-05 में वह राशि बढ़कर 2020 करोड़ रुपए हो गई थी। उनकी उन पांच सालों में उस बढ़ोतरी को लगाए और उस इन्फलेशन को लगाएं तो यह बढ़ोतरी नैगेटिव में जाती है। यह बढ़ोतरी 400 करोड़ रुपए की भी नहीं है। यह पांच-साढ़े पांच प्रतिशत की इन्फलेशन है, यह इन्क्रीज नैगेटिव है। स्पीकर सर, दूसरी तरफ हमारी वार्षिक योजना 3000 करोड़ रुपए की है। यह इन्क्रीज 800 करोड की है यानि कि 34 प्रतिशत इन्क्रीज है। स्पीकर सर, इसके लिए हमने कई साधन जुटाए हैं। स्पीकर सर, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं लेकिन यह पहला अवसर होगा जब मुख्यमंत्री जी और हम, प्लैनिंग कमिशन से मिले और उनसे हरियाणा के प्लान फाईनेलाईज करवाए। हमारे कहने से ही हमारी वार्षिक योजना में 3000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने यह कहा था कि यह जो हरियाणा की डिमाण्ड है यह जायज है और ये 34 प्रतिशत के जम्प के हकदार हैं। स्पीकर सर, एक किस्म से हमें उन्होंने इन्सैंटिव दिया है। This may be the first occasion in the 40 years of Haryana history that in the plan itself, we from our tresury are contributing about Rs. 180 crores, otherwise, the entire amount come from difference sources. Either we borrow from the Employees Provident fund or from the small saving, which has been a major component of the annual plan. This is for the first time. मैं यह कह रहा हूं कि प्लानिंग कमिशन ने हमारे काम को सराहा है और हमारे को 3000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। स्पीकर सर, इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे दूसरे क्षेत्र हैं, उनकी तरफ भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। जैसे इरीगेशन क्षेत्र को ही ले लें। सारा हरियाणा यह जानता था कि 1977 से लेकर जब तक हमारी सरकार नहीं आयी तब तक हरियाणा के लोगों को पानी का हिस्सा जिसको हम तर्क संगत, न्याय संगत बंटवारा कहते थे जिसके लिए हरियाणा के लोग ऐजीटेटिड होते रहे, नहीं मिला। कभी एस०वाई०एल० की आड़ लेकर, कभी दूसरी चीजों को कहकर कि कैरियर चैनल आएंगे तो यह पानी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जो हमें एस०वाई०एल० कैनाल के पानी का हिस्सा मिलना है उसका 1.66 मिलियन एकड़ फुट पानी हमारी नहरों में उपलब्ध था, लेकिन चाहे महेन्द्रगढ़ जिला हो, चाहे रिवाड़ी जिला

हो, चाहे झज्जर जिला हो, चाहे भिवानी जिला हो, चाहे गुड़गांव जिला हो, चाहे रोहतक जिला हो, चाहे सोनीपत जिला हो, चाहे पानीपत जिला हो और चाहे आधे से ज्यादा जींद जिले का हिस्सा हो या हिसार का बहुत बड़े क्षेत्र का हिस्सा हो, इनको इनके हक का पानी नहीं मिला । इनका हक उस पानी पर था लेकिन इनको वह पानी नहीं मिला । अध्यक्ष महोदय, इसके राजनैतिक कारण थे। इसी कारण यह पानी उनको नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं कहता हूं कि जिनको चौटाला साहब से टिकट लेना था चाहे वह बेशक नौलथा हल्के से पहले जो स्पीकर थे, एम०एल०ए० थे, उनकी भी यह हिम्मत नहीं होती थी कि वे यह कह सकें कि हमारे हल्के का पानी का हक मारा जा रहा है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठायी क्योंकि उनको टिकट चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, जिन जन प्रतिनिधियों की यह भावना रही हो तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 18 जिलों में से 12 जिलों का जिनका एक किस्म से संवैधानिक हक बनता था उनको पानी नहीं मिला। हमने यह फैसला किया कि हम तर्क संगत बंटवारा, न्याय संगत बंटवारा हरियाणा की जनता का पानी के लिए करेंगे और राजनैतिक कारणों को एक तरफ रखकर अगर इस सरकार की कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वह यही है कि हमने यह फैसला किया कि एक नहर बनेगी जिसके बारे में इंजीनियर भी मानते थे कि इसका लेवल नहीं बनता था क्योंकि उस समय सी०एम० कहते थे कि लेवल नहीं बनता तो वे भी कह देते थे। लेकिन आज वही इंजीनियर कहते हैं कि लेवल बनता है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी व्यथा है। मैंने उस समय देखा है कि किस तरीके से इस चीज की दलील दी जाती थी कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बनायी जाए। चूंकि इलैक्शन नजदीक थे और चौटाला साहब चाहते थे इसलिए ब्यरोक्रेटस भी वहीं रिपोर्ट बनाकर लाते थे और कहते थे कि जी हां, इससे बढ़िया प्रपोजल कोई और नहीं हो सकती । अध्यक्ष महोदय, आज वह लेवल कैसे बन गया? हरियाणा के लोगों ने इस बात के लिए भी कांग्रेस पार्टी को मतदान किया है और मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं क्योंकि इन्होंने एक हौसला दिखाया, एक हिम्मत दिखायी और सही बात को सही कहा। यही इस सरकार की उपलब्धि है। वरना तो हमने मुख्यमंत्री को भी दबते देखा है। यह ठीक है कि ये मेरे छोटे भाई हैं लेकिन मैं इनकी इस बात के लिए सराहना करता हूं, इनकी तारीफ करता हूं । ये अगर ऐसे ही निर्णय लेंगे तो ही कांग्रेस के लोग टिके रहेंगे। लोग भी यह देखते हैं कि हमारी परफोरमैन्स क्या है। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं मापदंडों को लेकर हमने अपना बजट पेश किया है। जैसा मैंने कहा कि बेरोजगारी पर झटका लगाने के लिए हम यह कहते हैं कि बेरोजगारी से लड़ना एक मुद्दा होना चाहिए। इसलिए हमने बेरोजगारी से लड़ने का निर्णय लिया।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the sitting of the House be extended till the conclusion of the Finance Minister's reply.

Voices : Yes Sir.

Mr. Speaker : The sitting of the House is extended till the conclusion of the Finance Minister's reply.

वर्ष 2005-06 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने निर्णय लिया लड़ने का। हमारी जो नई औद्योगिक नीति है वह इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि हरियाणा में अगर बेरोजगारी को खत्म करना है तो तीव्र गति से उद्योगों को बढ़ाना पड़ेगा और विदेशों से इन्वैस्टमैंट लानी पड़ेगी और दो लाख करोड़ रुपये की इन्वैस्टमैंट की अगले दस साल में हमारी प्रौजैक्शन है। उसके अंदर दस लाख लोगों को रोजगार मिलने की बात है और इस बारे में आज कई साथियों ने कहा भी है। मैं भी इस बात को कहता हूं बेशक कई बार I am go out of my text मैं मानता हूं पानीपत का विकास, गुड़गांव का विकास या फरीदाबाद का विकास हुआ है, लेकिन They are not the Haryana हरियाणा के ऐसे इलाके भी हैं जहां जीरो परसैंट इंडस्ट्री हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं है अब हमने उनको भी आईडैंटिफाई किया है। हम वहां भी जाएंगे जहां रोजगार की भूख है रोजगार की भूख वहां ज्यादा पनप रही है। कानून व्यवस्था कहां बिगड़ रही है, वह उन इलाकों में बिगड़ी है जहां खेती में कुछ नहीं होता । जहां पिछली सरकारों ने अन्याय किया है, नौकरियां, देने में, चाहे किसी की भी सरकार थी। कोई आदमी सिर्फ इसलिए चीफ मिनिस्टर बने कि वह अपने हल्के से 10 हजार या 15 हजार बच्चों को नौकरियां लगा दें ताकि वह जीत जाए चाहे उसकी पार्टी जाए भाड़ में, इस किस्म का ऐटीच्यूड रहा है। हमने इस चीज को बदला है हमने यह प्रतिज्ञा की है कि हम पूरा हिस्सा हर इलाके को देंगे, चाहे नौकरियों में है चाहे विकास की बात है सब जगह समान रूप से करेंगे। जब दस लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे तो बच्चों को मौका मिलेगा। इसके अलावा कृषि के बारे में भी हमने अपने विचार रखे हैं। मैं प्रोफेसर छत्तर पाल सिंह के विचारों से भी पूर्ण रूप से सहमति रखता हूं सर, आज कृषि में ठहराव है, किसानों की आमदनी घट रही है, बढ़ नहीं रही है, उनका उत्पादन घट रहा है, बढ़ नहीं रहा उसकी फसल का उचित मूल्य उसे नहीं मिल रहा है। उसका कारण है कि हम राजनीतिक स्वार्थों के कारण कई बार गलत फैसले कर देते हैं चौटाला जी की एक बात पर मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने एक बार गन्ने का भाव 110 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था और उसके बाद पांच साल तक बोले नहीं । किसानों को गन्ने के पेमैन्ट की बात छोड़ो। हर साल गन्ने की कीमत की बढ़ोतरी होनी चाहिए और पांच साल तक गन्ने के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं की। पांच साल में चीजों के भाव कितने बढ़े हैं लेकिन वोट की राजनीति करने के लिए उस समय 110 रुपये भाव कर दिया ताकि लोग उन्हें वोट दे दें। आज ऐसी परिस्थिति है कि हम किसान के धंधे को लाभकारी बनाना चाहते हैं और लाभकारी तब बन सकता है जब हमें नयी टैक्नोलॉजी बायोटैक्नोलोजी और नये अनुसंधान हों और उसकी उत्पादकता में बढ़ौतरी की आउटपुट जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक यह धंधा ठीक नहीं हो सकता और यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। मैं तो यह भी कहता हूं कि जब हमने ऐग्रीकल्चर के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि ऐग्रीकल्चर में दो परसैंट से ज्यादा इन्क्रीज नहीं हो सकती । अगर दो परसैंट की इन्क्रीज में ऐग्रीकल्चर रुक गई तो जिस पर 70 परसैंट लोगों की जीविका आधारित है वह समाज तो बिगड़ जाएगा, हालात और खराब हो जाएंगे। इसलिए हमने शुरुआत की है, मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है और ब्याज की दर 11 प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत कर दी है मैं तो यह कहता हूं कि समय आएगा जब आपको इस बात पर सोचना पड़ेगा कि क्या आज वह गरीब आदमी अपना ब्याज अदा कर सकता है क्या वह गरीब आदमी जिस पर ब्याज पर ब्याज हो गया है, जिसके कर्ज का वजन बहुत बढ़ गया है। जब हम बिजली के बिलों की माफी की बात कर सकते हैं तो हमारे को यह भी सोचना पड़ेगा कि गरीब को भी लैवल प्लेयिंग फील्ड की जरूरत है उसको भी वह अधिकार है

जो किसी उद्योगपति को होने चाहिए आज उसको भी लैवल प्लेयिंग फील्ड की इंतजार है और हम करेंगे, यह हमारे इरादे हैं। हम सत्ता भोगने नहीं आए हैं, मैं जानता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी को भी जानता हूं। इनसे ज्यादा मैं इनको जानता हूं कि हम किसी उद्देश्य के लिए सत्तासीन हुए हैं जब तक हमारे दम में दम होगा जब तक हमारी बुद्धि हमें इसके लिए प्रेरित करती रहेगी तब तक हम गरीब और किसान की भलाई के सिवाय दूसरी बात नहीं सोचेंगे। यह हमारा निर्णय है इसीलिए आज सुबह बात हो रही थी मेरे कई साथियों ने कहा कि एस०सी०, बी०सी० के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है जिसकी जरूरत होनी चाहिए। मेरी बहन जी मेरे पड़ोस में बैठती हैं कहती है कि भाई साहब आपसे और श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी से तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि आप हमारे लिए कुछ करोगे। स्पीकर सर, मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि सरदार प्रताप सिंह कैरों के समय में हरिजन कल्याण फण्ड के नाम से एक एक्ट बनाया गया था उसका नाम था Erstwhile Punjab a Temporary Taxation Act was passed in 1962. सर, आज जो गरीब समाज है जो धरती का मालिक नहीं है गांव में आज उसके पास काम नहीं है। आज गांव में लुहार के पास काम नहीं है, खाती के पास काम नहीं है, कुम्हार के पास काम नहीं है और न ही जुते बनाने वाले के पास कोई काम है आज उनके हाथ को काम देना हमारा फर्ज है। मैं कहता हूं कि करना है इसलिए यह कहता हूं कि इस किस्म का कोई एक्ट दोबारा से ला सकें जिससे हम जो हमारा समाज है उन भाईयों की हम कोई ठोस प्रकार से मदद कर सकेंगे उसका प्रयास करना है यह हमारी वचनबद्धता है यही नहीं हमारी वचनबद्धता यह भी है कि जिस प्रकार से पैंशन में बढ़ोत्तरी की गई है उसमें भी लोगों को छोड़ दिया गया है जो गरीब थे उनकी आवाज को दबाया गया है और जो बड़े लोग हैं जिनके घर ट्रैक्टर खड़ा है वे तो पैंशन के अधिकारी हैं और जिसके सिर पर छत नहीं वह ढूंढते फिरते हैं और कहते हैं कि जहां जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि तुम तो 40 साल के हो जबकि पैंशन तो 60 साल वाले की बनती है। गरीब आदमी तो 60 साल की उम्र तक वैसे ही नहीं पहुंचता, पहले ही खत्म हो जाता है। मेरा अपना यह मानना है कि पेंशन के लिए नए सिरे से सर्वे करायें ताकि हर ऐसे व्यक्ति को जो पैंशन का अधिकारी हो उसे पैंशन मिल सके। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि जो नेत्रहीन, विकलांग और दूसरे हैंडीकेप्ड की पैंशन बढ़ाई है मैं तो यह मानकर चलता हूं कि वह किसी भी जाति का हो अगर बिलो पावर्टी लाईन है तो उसको पैंशन का अधिकार होना चाहिए ताकि उसको समय पर खाना और दूसरा सामान मिल सके।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने चर्चा की यह ठीक है हमने एक योजना बनाई है कि जो ग्रामीण इलाके में जो एस०सी० बहन बेटियां हैं उनके लिए हम शौचालय बनायेंगे यह हमारी प्राथमिकता रहेगी।

श्री बीरेन्द्र सिंह : इसके अलावा मैं राशन कार्ड की भी बात जरूर करूंगा जो गुलाबी कार्ड बनते हैं उनमें भी भारी घांधली है उसमें गरीब का हक मारा गया है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि जिनके नाम से राशन बांटते हैं उन तक पहुंचता नहीं है बाजार में ही बिक जाता है, साफ हो जाता है और पिछली सरकार के समय में तो यह प्रथा थी कि आटा पीसने के लिए ज्यादातर कान्ट्रैक्ट एम०एल०एज० को दिये जाते थे। इन्होंने गरीब आदमी को भी नहीं छोड़ा। मैं यह कहता हूं कि हमने इस प्रथा को बदला है। स्पीकर सर, हमारे राज में कोई यह नहीं कह सकता कि मेरा टैण्डर लेने से इन्कार कर दिया। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि इसमें भी कुछ खामी है जैसा कि श्री मांगेराम गुप्ता बता रहे थे कि एक टैण्डर डिप्टी कमीशनर 18 रुपये के हिसाब से करता है

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

और 3 दिन के बाद वह टैण्डर रुपया हो जाता है, इस प्रकार 18 और डेढ़ में तो जमीन आसमान का फर्क है। डेढ़ वाली सच है या 18 वाली, these things are to be enquired into. These are the deficiencies in our system. We will have to short it out. ये कोई छोटी बातें नहीं हैं। हमें पारदर्शिता लानी होगी, वरना तो गल्त और बदमाश किस्म के व्यक्ति पहले भी टैण्डर के अधिकारी बन जाते थे और अब भी बन जाएंगे। हमारे राज में कोई गल्त या बदमाश अधिकारी होगा तो बीरेन्द्र सिंह उसका साथी नहीं होगा।

श्री मांगेराम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, 18 वाला टैण्डर डेढ़ का नहीं बल्कि डेढ़ वाला टैण्डर 18 का हो गया था।

श्री बीरेन्द्र सिंह : नहीं, पहले 18 से डेढ़ हुआ और फिर डेढ़ से 18 किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो गुलाबी कार्ड है उनके लिए हम चाहेंगें कि जिन लोगों को इन्साफ नहीं मिला उनको इन्साफ मिले, जो उनके लिए उपलब्धियां हैं वह उनके घर तक पहुंचे जिनका वह अधिकारी है तब हम समझेंगें कि हमारे राज में आने से गरीब आदमी को हमने आर्थिक राहत दी है जिसकी उसको जरूरत है। इसके साथ-साथ किसी साथी ने बात नहीं की, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूं कि जो शिड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासिज का बैक लॉग है उसको निर्धारित सीमा के अन्दर पूरा करना हमारा कर्तव्य है और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी और चौटाला की सरकार में कोई फर्क नहीं है। यह शिडयूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासिज भाइयों का मौलिक अधिकार है उसको पूरा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है और हमारी सरकार इस पर पूरा अमल करेगी। मेरे साथियों ने जो जो सुझाव दिए या हमारा क्रिटीसिज्म किया उसके बारे में मैं इन्दौरा साहब से शुरू करता हूं। इन्दौरा जी ने राजीव गांधी एजूकेशन सिटी के बारे में यह कहा कि 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इन्दौरा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो सिटी है यह कोई सरकार का नहीं होगा इसको बनाने के लिए जो उद्यमी हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीच्यूट कायम करना चाहते हैं, प्राइवेट सैक्टर के लोग हैं उनको इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसकी नोडल एजैंसी हुड्डा होगी, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं समझता हूं कि दूसरे हुड्डा के नाम की तबदीली करनी चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, 1987 में जो विधान सभा में सदस्य आए थे, उसमें हमारे साथी श्री कृष्ण हुड्डा भी थे और जब यह बात आई कि हुड्डा में यह करप्ट है वह करप्ट है तो हमारे साथी श्री कृष्ण हुड्डा कहने लगे कि हुड्डा ईमानदार है हुड्डा करप्ट बिल्कुल नहीं है। (हंसी)

श्री बीरेन्द्र सिंह : इन्दौरा जी, उसकी नोडल एजैंसी हुड्डा होगी वह सिटी एक सैन्टर आफ एक्सीलैंस होगा और वह भी इंटरनैशनल स्टैण्डर्ड का होगा जैसा कि किरण जी ने भी बात की है। उसमें हमारी सोच है कि उसमें जो रिजर्वेशन है वह 25 प्रतिशत हरियाणा के बच्चों के लिए हो ताकि उसके स्थापित होने का हमें लाभ हो यह हमारी मंशा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : इस हुड्डा नाम को रहने दो, कुछ लोगों में भ्रम रहने दो, क्योंकि जब मैं पार्लियामैंट में गया था तो मेरे बहुत से सांसद साथी कहने लगे, हुड्डा साहब हमें भी एक प्लाट

दे दो तो मैंने कहा कि मेरे पास कोई प्लाट थोड़े हैं तो कहने लगे आपकी सारे हरियाणा में प्रोपर्टी है इसलिए लोगों में यह हुड्डा का भ्रम रहने दो।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माडल स्कूल के लिए बजट में प्रावधान की बात कही गई है। यह साफ है कि हम हर जिले में एक माडल स्कूल स्थापित कर रहे हैं उसमें जैसा मैंने कहा कि गुणवत्ता जिस पढ़ाई में है उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और इसमें फंडस की कोई कमी नहीं रहेगी। जहां बिल्डिंग उपलब्ध है वहां बिल्डिंग का खर्चा नहीं होगा। जहां बिल्डिंग नई बनानी है। वहां बनायेंगे। जहां लैब की जरूरत है वहां लैब उलपब्ध करवायेंगे। हमारा मेन ध्येय यह है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें।

डा० सुशील इंदौरा : ये मॉडल स्कूल कब तक बनेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हर जिले में एक स्कूल के हिसाब से एक साल में 20 स्कूल बनाने हैं। जिनमें से एक बन चुका है, 18 को बनाने का प्रावधान किया हुआ है और मेवात अभी जिला बना है वहां भी एक स्कूल बनाना है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्ष के साथियों ने बजट के बारे में भी कुछ नुकते उठाये। इन्होंने कहा कि इनकी सरकार के समय में ब्याज की अदायगी 2166 करोड़ रुपये थी जो अब 2354 करोड़ रुपये हो गई। इस बारे में मैं इंदौरा साहब को बताना चाहूंगा जैसा मैंने शुरू में कहा यह हम इनके बोझ को ढोह रहे हैं। जब बजट चार-छः महीने बाद रि-एस्टीमेट होगा उसके बाद हमारी परफोरमैंस आयेगी। अध्यक्ष महोदय, ये जो सारे मद हैं जिनमें बढ़ोतरी का इन्होंने जिक्र किया है ये हमारी वजह से नहीं हैं। ये तो पहले वाली सरकार ने जो कर्जे लिये थे जिसकी वजह से बढ़ोतरी 28 हजार करोड़ रुपये हो गई । यह उनकी वजह से है कि हरियाणा फिस्कल रिसपोंसिबिलिटी एण्ड बजट मैनेजमैन्ट बिल, 2005 बल्कि हम तो इसी सैशन में (FRBM) के नार्म पर एक बिल लेकर आ रहे हैं जिस पर आप सब चर्चा कर सकते हैं। इस विधेयक के जो मापदण्ड हैं 12th वित्त आयोग के जब हम प्राप्त कर लेंगे तो पांच साल में हमें 1029 करोड़ रुपये मिलेंगे और इसी साल 179 करोड़ रुपये इसी मद से मिलेंगे जो बजट में नहीं दर्शाये हैं। इस बिल को हम परसों पास करेंगे इसलिए यह बात कह रहा हूं। इसके अलावा विपक्ष के साथियों ने राजस्व प्राप्तियों का जिक्र किया कि पहले राजस्व प्राप्तियां 11388 करोड़ रुपये थी जो अब बढ़कर 12037 करोड़ रुपये हो गई हैं। इसमें लगभग 5 प्रतिशत का इन्क्रीज है। स्पीकर सर, हमारे जो खर्चे हैं वे 12 प्रतिशत के करीब इन्क्रीज हुए हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये खर्चे पहली बार बढ़े हैं। आप एप्रिशियट करेंगे कि हमने अपने कैपिटल असैट्स को सट्रैन्थन करने के लिए 350 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया है और इस तरह का प्रावधान हरियाणा के बजट में पहली बार हुआ है ताकि हमारा जो इतना बड़ा स्ट्रैक्थर है जिसमें होस्पिटल, भिन्न सचिवालय और दूसरे अदारे शामिल हैं, इनको ठीक रख सकें। सड़कों के लिए हमने 160 करोड़ रुपये के लिए इन्क्रीज किया है जबकि पिछली सरकार के समय में सड़कों के लिए 75 करोड़ रुपये रखा गया था। हमने इसमें वृद्धि करके इसको 160 करोड़ रुपये किया है। अध्यक्ष महोदय, इंदौरा साहब कह रहे थे कि इनकी सरकार के समय में फसल का नुकसान होने पर मुआवजा प्रति एकड़ बढ़ाकर 600 रुपये से 2000 रुपये कर दिया गया था हमें तो पता नहीं ये इस तरह के आंकड़े कहां से लेकर आते हैं। इंदौरा साहब इस बात को मानेंगे कि हमने अपने तीन महीने के शासनकाल में एक प्राकृतिक आपदा का सामना किया है

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

और उसमें हमने 46 करोड़ रुपये तुरंत वितरित किए हैं इससे परोम्पट एक्शन किसी सरकार का हो नहीं सकता। इसके अतिरिक्त इनकी सरकार के समय में जो ओलावृष्टि हुई थी और उसमें जिन किसानों की फसल खराब हुई थी उनको भी हमनें मुआवजा दिया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कि एस०वाई०एल० के लिए बजट में एक करोड़ रुपये रखा है। स्पीकर सर, इन्होंने एक बड़ा ही रैलेवैन्ट सवाल उठाया है इसका जवाब देना मेरे लिए जरूरी है। इन्दौरा साहब ने कहा कि हमारे टाईम में इन्फ्रास्टक्चर के लिए 45% बजट रखा गया था, इनका कथन था। जिसको घटाकर हमने साढ़े 39% कर दिया। स्पीकर सर, अगर आप क्वांटम में चेंज देखें तो पिछले सालों के मुकाबले में 300 करोड़ से ज्यादा रुपया हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा है। पिछली बार 919 करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए था और अब 1180 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम यह मान कर चलते हैं कि हरियाणा में आने वाले पांच सालों में अगर हम एक मजबूत ढांचा खड़ा करने में सक्षम हुए तो हरियाणा की जो प्रगति है जो हमारे एजैंडे का सबसे बड़ा विषय प्रगति का था, वह इन्फ्रास्ट्रक्चर का है और वही हमारी प्राथमिकता का क्षेत्र है। अकेले बिजली पर बजट में जो प्रावधान है वह 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा है। हमने 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा एजूकेशन के लिए रखा है। स्पीकर सर, कैप्टन साहब की जो प्राथमिकता थी उनकी बात भी मैं यहां पर बता देता हूं। कल जब वे सवालों का जवाब दे रहे थे तो इन्होंने कहा था कि दक्षिणी हरियाणा की नहरों की गाद निकालने का काम, सफाई करने का काम और जो पम्पिंग सैट्स खराब पड़े हैं उनके ठीक करने का काम मैं दो साल में करूंगा तो हमारे एक साथी श्री नरेश यादव जी ने कहा था कि आप इन कार्यों को जल्दी करवाइये। स्पीकर सर, मैं कैप्टन साहब की तारीफ करूंगा ये इतने प्रॉमपट निकले कि शाम को ही पांच करोड़ रुपये की ऐडीशनल मांग ले कर मेरे पास आ गए और कहने लगे कि यह काम करना है और आप बजट में पांच करोड़ रुपये का और प्रावधान करें। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनको पूरा करने में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में इन्दौरा जी ने कहा कि सरकार ने एक करोड़ रुपये रखे हैं तो मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि इस नहर के निर्माण के बारे में चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो और चाहे इससे पहले का निर्णय था एस०वाई०एल० को बनाने की टोटल कॉस्ट केन्द्र सरकार वहन करेगी और राज्य सरकार को उस पर कोई पैसा खर्च नहीं करना है। हमने जो प्रोविजन रखा है इनकी सरकार के टाईम में भी एक करोड़ रुपये का ही प्रावधान था। इनके राज में 50 करोड़ रुपये या और अधिक प्रावधान होता और हमने एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया होता तो अलग बात हो सकती थी और तब ये इस बात को कह सकते थे लेकिन इन्होंने भी इसके लिए केवल एक करोड़ रुपये का ही प्रावधान रखा था और हमने भी एक करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। अध्यक्ष महोदय, हाउस की जानकारी के लिए मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि एस०वाई०एल० कैनाल को पूरा करने के लिए जितना भी पैसा खर्च होगा वह सारे का सारा पैसा केन्द्र सरकार वहन करेगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी गौतम जी, कभी किसी जमाने में मेरे सहपाठी और क्लासफैलो भी थे और माननीय मुख्य मन्त्री हुड्डा साहब के भी क्लासफैलो थे। इन्होंने कहा कि हरिजनों और पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए सरकार ने बजट में कुछ नहीं रखा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गौतम जी को बताना चाहूंगा कि हमने बजट में पिछड़ी जातियों, हरिजनों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए 640 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो एक किस्म से बड़ा भारी क्वांटम में

इन्क्रीज है। श्री धर्मबीर गाबा जी ने सवाल उठाया कि नगरपालिकाओं के विकास के लिए बजट में सिर्फ 18 करोड़ रुपये का प्रावधान है। स्पीकर सर, यह ऐसा नहीं है। (विघ्न) नगरपालिकाओं के विकास के लिए 18 करोड़ रुपये नहीं बल्कि शहरी विकास के लिए 168 करोड़ रुपये का प्रावधान है और पहली दफा यह हुआ है। नगरपालिकाओं को विकास कार्यों के लिए पैसा मिल जाता था लेकिन कभी भी किसी सरकार ने उनके रख-रखाव के लिए उनका जो ढांचा है उसको स्ट्रैंथन करने के लिए पैसे का प्रावधान नहीं किया। इस सरकार ने पहली बार 100 करोड़ रुपया नगरपालिकाओं को दिया है ताकि इस बात की शंका किसी को न रहे कि किसी को पैसा नहीं मिलता या कोई कहे कि हमने काम किया था लेकिन उसकी पेमैंट नहीं हुई या लोग ये कहें कि हमें पेंशन नहीं मिली। स्पीकर सर, इसी के साथ इन्होंने कहा कि पी०सी०आर० सिस्टम खासकर गुड़गांव में और पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण का प्रावधान किया जाए। पिछले वर्ष, पिछली सरकार के वक्त में इसके लिए 23 करोड़ रुपए का प्रावधान था और अब की बार हमनें 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। श्री के०एल० शर्मा जी ने कहा कि जी०टी० रोड के साथ औद्योगिक नगर बनाए जाएं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में कभी 10 साल पहले दो बड़े उद्योग नगर स्थापित किए गए थे ये उद्योग बावल और साहा में बनाए गए थे जो कि इनके पड़ोस में है। इसके साथ ही दादूपुर नलवी में नहर के लिए प्रावधान की बात कही है हमने उसमें 43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह दो सौ करोड़ रुपये में बनकर तैयार होगी, एक साल में यह बनकर तैयार हो जाए यह संभव नहीं है और इसके लिए बजट में स्प्रैडओवर करना पड़ेगा और इसको समय लगेगा। स्पीकर सर, इसके बाद धर्मपाल सिंह मलिक ने अपनी कांस्टीचुएंसी की टेलों में पानी पहुंचाने के बारे में भी बात कही है, इसके साथ ही जो इम्पलाई रिमोट एरिया में पोस्टिड हैं उनके लिए इन्सैंटिव हो। लेकिन हमारा इस बारे में एक्सपीरिएंस है कि हमने जब से यह निर्णय लिया है कि शहर के 8 किलोमीटर में वही सुविधा है जो कि शहरों में हो सकती है उससे हमारी ट्रांसफर पालिसी में नुकसान हुआ है। हर आदमी शहरों में जाकर ठिकाना बनाना चाहता है और उस ठिकाने से दो, चार और छः किलोमीटर के एरिये में ही रहना चाहता है। इस वजह से जो पिछड़े क्षेत्र हैं वे छूट जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज सभी पी०एच०सीज० का सर्वेक्षण किया जाए और वहां पर ऐसी, ऐसी पी०एच०सीज० मिलेंगी जहां पर सालों साल से डाक्टर्ज नहीं हैं वे तनख्वाह तो पी०एच०सीज० से लेते हैं लेकिन उनका पता नहीं वे हैं कहां पर। स्पीकर सर, मैं इस बात का पक्षधर हूं पता नहीं बहन जी इसे माने या नहीं माने। There should be two cadres for medical staff and doctors. There should be one rural cadre and the other urban cadre. If somebody wants to serve in the rural sector, he should remain in the rural area and some incentive should be given to him as Mr. Malik has said. That is the only way out. नहीं तो वे पी०एच०सीज० से तनख्वाह लेंगे और रहेंगे किसी और शहर में। इसके साथ ही कर्ण सिंह दलाल जी ने भी सदन में बहुत से सुझाव रखे हैं । वैट के बारे में, कृषि यन्त्रों और कीटनाशक दवाईयों के बारे में कहा है कि सरकार इस बारे में दोबारा से विचार करे। इस बारे में हमारे पास कई कम्पनियों की भी रिप्रैजेन्टेशंज आई हैं जिसमें किसी ने कहा है कि टैक्स को कम करो या किसी ने तो यहां तक कह दिया है कि टैक्स बिल्कुल ही खत्म करें। स्पीकर सर, इस बारे में हमने सभी के सभी सुझाव कमेटी को रैफर कर दिए हैं और यह कमेटी सभी के सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी क्योंकि पड़ोसी राज्य जो हैं उनमें ऐसा नहीं है, हरियाणा में ही यह लागू है। स्पीकर सर, चौटाला साहब, की सरकार के वक्त में दो साल पहले वैट लागू हो गया था और

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

अब उसको तीसरा साल लग गया है। उसमें कुछ मिसडायरैक्शंज थी और वहीं चलती रहीं, जो अब वैट में 12 प्रतिशत है वह 10 प्रतिशत पर चलती थी और अब जो 4 प्रतिशत है वह 8 प्रतिशत पर चलती थी। उन सारी की सारी मिसडायरैक्टिड को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। स्पीकर सर, इसी के साथ हम एक कुण्डली मानेसर-पलवल सुपर एक्सप्रैस हाईवे बनाने जा रहे हैं। यह हरियाणा के लिए बड़ा ही प्रैस्टीजियस प्रोजैक्ट है। मैं यह भी समझता हूं कि जो टोटल इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसमें यह बड़ा भारी कम्पोनैंट होगा। इसके द्वारा हम दिल्ली में जो संसाधन हैं उनको एक्सप्लायेटेशन करने का, वहां के पैसे को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। स्पीकर सर, आज जो दिल्ली है वह पहले वाली दिल्ली नहीं रही है। पहले मुम्बई को फाईनांशियल सिटी कहा जाता था और आज उसके मापदण्ड बदल गए हैं। आज दिल्ली जो 14.00 बजे है, in certain respects, it is more and more economical than Bombay. सर उन संसाधनों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हमने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बनायी है। इसमें आप देखेंगे कि आने वाले समय में इस कुंडली मानेसर हाईवे पर गुड़गांव जैसे पांच गुड़गांव और उभरकर आएंगे जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था को और बड़ा भारी बूस्ट मिलेगा। रणबीर सिंह महेन्द्रा ने भी एक सवाल उठाया कि करनाल के अंदर मल्टीपरपज स्टेडियम कल्पना चावला के नाम से बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो 2010 के कॉमन वैल्थ गेम होने जा रहे हैं उसके मद्देनजर हम देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे गेम हैं, कौन कौन सी स्पोर्टस की इवैन्टस है जो हरियाणा में हो सकती है उसी हिसाब से हम इंफ्रास्टक्चर तैयार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि फरीदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में पोल्यूशन की वजह से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मैच नहीं हो रहे हैं इसलिए एक स्टेडियम गुड़गांव में बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये तो खुद बी०सी०सी०आई० के अध्यक्ष हैं पता नहीं यह सच है कि नहीं कि बी०सी०सी०आई० दुनिया की सबसे अमीर स्पोर्टस की संस्था है तो अगर ये भी कुछ अपनी जेब ढीली करें तो सरकार इस बात पर गौर करेगी। सुमिता सिंह जी ने भी कुछ मुद्दे उठाए, उनके कुछ लोकल इश्यूज थे। इसी तरह से शारदा जी ने भी अन अथोराइज्ड कालोनीज के बारे में कहा। सुमिता जी ने ट्रामा सैंटर के बारे में भी कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं कि जो ट्रामा सैंटर नेशनल हाईवे के साथ स्थापित हुए हैं उन की गाड़ियों में लगने के लिए हमारे पास बहुत से पुलिस के सिपाही आते हैं कि मेरे को ट्रामा सैंटर वाली गाड़ी में ड्राईवर लगवा दो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में वहां स्टाफ की दिक्कत होगी यह तो it is becoming lucrative sort of appointment सर, इसके अलावा मैं आपसे एक प्रार्थना और करना चाहूंगा कि हमने जो बजट के अंदर आंकड़े दिए हैं उसके अलावा भी कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिनको हमने अपने बजट में दर्शाया नहीं है। हमने कुछ और भी स्टैप्स लिए हैं। हमने मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक रिसोर्स मोबलाइजेशन कमेटी का गठन किया है कि जहां पर लीकेजिज है उनको हम कैसे प्लग करें और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा हम रिसोर्सिज को इकट्ठा कर सकें। इसके अलावा भी हमारे कुछ अदारे ऐसे हैं जैसे ट्रांसपोर्ट के अंदर गुड्ज टैक्स की बात है या रैवेन्यू स्टैम्प्स की बात है आज अगर किसी से पांच रुपये लेते हैं तो इसके बजाए आप अगर उससे पांच सौ रुपये ले लो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अध्यक्ष महोदय, आज पावर ऑफ अटार्नी गरीब आदमी तो करवाता नहीं है यह तो अमीर आदमियों का खेल है। इस तरह से कई चीजे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। मैं यकीन से यह बात कह सकता हूं।

Speaker sir, I can not quote the figures but I can claim that we would mop up a substantial amount through these extra resources, which will give a boost to the economy of the State. Our Budget Estimates, have shown, which we have indicated; those are the estimates or those are indicators only of the performance of the last Government and when we would add our resources in this, you would find that this would be a most viable budget, which is for the poor, which is for the needy and which is to create a viable infrastructure in Haryana. इसी उम्मीद के साथ सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। (विघ्न) वैसे शमशेर सिंह सुरजेवाला जी की एक बात से मैं सहमति रखता हूं कि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। After the introduction of privatisation, liberalization and globalisation, we are undergoing a change. Now, regarding the concept of socialistic pattern of the Government, there is a question mark. A time may come when the Government would come out only to see the law and order problem. That is all. जो हम किताबों में पढ़ते थे, वह एक युग है उसमें किसको कितनी इम्पोर्टेंस होगी लेकिन इनके तर्जुबे से इनके जो ख्यालात हैं, इनकी जो सोच है वह कभी न कभी अवश्य प्रैक्टिकल शेप लेगी। आज तो हम यह नहीं कहते लेकिन जब चौटाला साहब एम०आई०टी०सी० को बंद कर सकते हैं, इनफैड को बंद कर सकते हैं, 26 हजार कर्मचारियों की छुट्टी कर सकते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो सरकार की फंक्शनिंग हैं उसमें जो एक एन्टरप्राइजिंग का आस्पैक्ट था जो कार्मिशियल आसपैक्ट था वह धीरे धीरे कम हो रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आए हमारी आने वाली पीढ़ी सुरजेवाला साहब की इस बजट स्पीच को निकालकर पढ़ें they may act accordingly. इसके साथ ही मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बजट को पारित करने में एक राय रखेंगे।

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned and will reassemble at 3.00 P.M.

*14.10 hrs (The Sabha then *adjourned at 2.10 P.M. and re-assembled at 3.00 P.M.)

वर्ष 2005-2006 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on Demands 15.00 बजे for Grants on Budget Estimates for the year 2005-2006 will take place.

As per past practice and in order to save the time of the House, all the demands for grants (No. 1 to 25) on the order paper will be deemed to have been read and moved together. Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

> That a sum not exceeding **Rs. 9,51,75,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 2,52,00,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 1-Vidhan Sabha.**

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding **Rs. 150,61,93,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 34,00,60,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 2-General Administration.**

That a sum not exceeding **Rs. 649,77,98,000 for revenue expenditure and Rs. 19,66,50,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 182,19,54,000 and capital expenditure amount of Rs. 5,33,50,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 3-Home.**

That a sum not exceeding **Rs. 211,01,96,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 65,10,32,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 4-Revenue.**

That a sum not exceeding **Rs.44,01,99,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 13,46,14,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 5-Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding **Rs. 881,43,61,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 223,95,48,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 6-Finance.**

That a sum not exceeding **Rs.24,15,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 184,24,70,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 7-Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding **Rs. 277,58,83,000 for revenue expenditure and Rs. 297,17,03,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 53,75,37,000 and capital expenditure amount of Rs. 67,71,47,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 8-Buildings & Roads.**

That a sum not exceeding **Rs.1632,02,99,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 446,25,67,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 9- Education.**

That a sum not exceeding **Rs. 645,38,14,000 for revenue expenditure and Rs. 270,48,28,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 181,88,44,000 and capital expenditure amount of Rs. 54,51,72,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 10-Medical & Public Health.**

That a sum not exceeding **Rs.150,67,42,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 17,03,01,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No.11-Urban Development.**

That a sum not exceeding **Rs.168,33,36,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 27,76,42,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 12-Labour & Employment.**

That a sum not exceeding **Rs. 573,28,33,000 for revenue expenditure and Rs. 5,05,25,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 150,23,09,000 and capital expenditure amount of Rs. 48,75,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 13-Social Welfare & Rehabilitation.**

That a sum not exceeding **Rs. 23,17,43,000 for revenue expenditure and Rs. 26,10,95,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 7,40,66,000 and capital expenditure amount of Rs. 1253,00,00,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 14-Food & Supplies.**

That a sum not exceeding **Rs. 1446,43,88,000 for revenue expenditure and Rs. 511,20,22,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 417,53,00,000 and capital expenditure amount of Rs. 111,74,78,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 15-Irrigation.**

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding **Rs. 58,29,41,000 for revenue expenditure and Rs. 2,18,14,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 14,36,95,000 and capital expenditure amount of Rs. 55,65,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 16-Industries.**

That a sum not exceeding **Rs.245,09,82,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 70,25,07,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 17-Agriculture.**

That a sum not exceeding **Rs.120,89,55,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 34,30,97,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 18-Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding **Rs.11,65,45,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 2,61,91,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 19-Fisheries.**

That a sum not exceeding **Rs.120,74,39,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 26,46,21,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 20-Forests.**

That a sum not exceeding **Rs. 332,00,23,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 65,20,32,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 21-Community Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 29.84,89,000 for revenue expenditure and Rs. 6,64,75,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 5,97,25,000 and capital expenditure amount of Rs. 2,73,25,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 22-Co-operation.**

That a sum not exceeding **Rs. 507,19,86,000 for revenue expenditure and Rs. 63.79,50,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment

for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 155,03,51,000 and capital expenditure amount of Rs. 13,91,50,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 23-Transport.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,28,89,000 for revenue expenditure and Rs. 5,62,50,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 40,52,000 and capital expenditure amount of Rs. 1,37,50,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 24-Tourism.**

That a sum not exceeding **Rs.93,23,32,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 82,27,08,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 25-Loans & Advances by State Government.**

श्री बच्चन सिंह आर्य (सफीदों) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांड पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं डिमांड नं० 11 नगर विकास के मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बजट के बारे में बोलने के लिए भी हम सभी ने इधर से मांग रखी थी मगर समय नहीं मिल पाया। मैं अपनी बात इसके माध्यम से कहना चाहूंगा। नगर विकास के बारे में बजट के अन्दर काफी कुछ रखा गया है इसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं नगर में या छोटे शहरों में जहां म्युनिसिपल कमेटियां हैं उनके बारे में भी काफी अच्छे बजट का प्रावधान किया गया है। जैसा कि मेरे सफीदों विधान सभा क्षेत्र को कोई बड़ा शहर तो नहीं कह सकते, मगर वहां म्युनिसिपल कमेटी है अभी उसको बी क्लास का दर्जा सरकार ने दिया है, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। हमारा इलाका काफी पिछड़ा हुआ और बैकवर्ड इलाका है। वहां पर बहुत सी सुविधाएं होनी चाहिएं थी लेकिन वहां है नहीं। इन 9-10 सालों के कार्यकाल में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ और न ही म्युनिसिपल कमेटियों को किसी भी तरह का बजट दिया गया है। एक भी कार्य का उल्लेख नहीं किया जा सकता जो कि पिछली सरकार ने किया हो। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सफीदों विधानसभा क्षेत्र के विकास के कार्यों की तरफ ध्यान दिया जाए, वहां की म्युनिसिपल कमेटी की मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा। जैसे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय सफीदों विधान सभा क्षेत्र में हुड्डा के सैक्टर कटने की बात आई थी। 3 सैक्टरों की वहां डीमार्केशन भी हुई थी पता नहीं, पिछली सरकार के समय में वह योजना लुप्त हो गई। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के 90-90 विधान सभा क्षेत्रों में से सफीदों में जनगणना के आधार पर बैकवर्ड लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के हिसाब से उन सैक्टरों का पता नहीं लगा जबकि उसके अन्दर हाउसिंग कालोनी का भी प्रावधान था। गरीब तबका वहां रहता है जहां उनको आसान किस्तों में मकान दिए जा सकें। लेकिन वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब हुड्डा ने वहां पर तीन सैक्टर बनाने थे, वे क्यों नहीं बनाये गये। इसके अतिरिक्त वहां पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा भी मकान बनाने की पूरी योजना बन गई थी वे भी नहीं बने। यह तो मुझे मालूम नहीं कि वे मकान आवास बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहीं बने या हुड्डा की लापरवाही के कारण नहीं बने। हो सकता है पिछली सरकारों ने सफीदों के साथ भेदभाव किया हो। मुझे तो इसमें

[श्री बच्चन सिंह आर्य]

विभागीय अधिकारियों की कारगुजारी लगती है। स्कीमें मंजूर हुये कई-कई साल हो जाते हैं लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा उन पर ध्यान नहीं दिया जाता । सफीदों में आज तक कोई भी मकान आवास बोर्ड ने नहीं बनवाया है। मेरे हल्के सफीदों में हुड्डा के सैक्टर और आवास बोर्ड के मकान आज तक नहीं बने हैं। मुझे तो अंदेशा है जैसे गुड़गांव के सैक्टर 43 में आवास बोर्ड द्वारा नौ मंजिली बिल्डिंग बनानी थी और वे मकान लोगों को देने थे जो आज तक नहीं बने हैं वैसा ही हमारे सफीदों में हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सैक्टर 43, गुड़गांव में क्या हुआ यह जानकारी सदन को देना चाहूंगा क्योंकि यह मामला मेरे सफीदों शहर जैसा ही है। आवास बोर्ड ने अगस्त, 2003 में हुड्डा से जमीन मकान बनाने के लिए सैक्टर 43 में ली। जून, 2003 में उस जमीन की आवास बोर्ड ने कुछ पेमैंट भी कर दी और सितम्बर, 2003 में आवास बोर्ड ने उस जमीन का पोजैशन भी ले लिया था। उस जमीन पर हुडा ने यह शर्त रखी थी कि यदि तीन साल में आवास बोर्ड उस जमीन पर मकान बना लेगा तो हुडा लैंड कोस्ट में 20 प्रतिशत की छूट देगा और बोर्ड तीन साल में मकान नहीं बनायेगा तो बाकी की पेमैंट 11 प्रतिशत इंट्रस्ट के साथ देनी पड़ेगी। जिसकी राशि ब्याज समेत 3 करोड़ रुपये बनती है। उसके बाद आवास बोर्ड के मकानों की पंजीकरण अक्तूबर, 2003 में की गई और मार्च, 2004 तक वे मकान बनने थे लेकिन आज तक नहीं बने हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ ही सफीदों के साथ हुआ है। इसमें तीन करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई है। लोगों को एप्लाई किए हुए दो साल से अधिक समय हो गया लेकिन आज तक मकान नहीं मिले हैं और न ही उन मकानों का निर्माण शुरू हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है जो मकान 2003 की कीमतों पर बनने थे वे आज तक नहीं बने हैं। आवास बोर्ड पर तो इसका असर नहीं पड़ेगा इसका बोझ तो आम जनता पर ही पड़ेगा। यदि ये मकान तीन साल में हुडा की शर्तों के अनुसार बन जाते तो 20 प्रतिशत की छूट मिलती लेकिन अब तो ब्याज भी देना पड़ेगा। जिसका बोझ आज जनता पर ही पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आवास बोर्ड के अधिकारियों ने इस स्कीम की तरफ ध्यान नहीं दिया इसीलिए यह स्कीम अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछली सरकार के समय में जो वित्त सचिव आवास बोर्ड के थे वे आज भी यहीं कार्य कर रहे हैं। क्या वे इसके लिए जवाब देय नहीं हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस सारे प्रकरण की जांच कराई जाये ताकि लोगों को तीन करोड़ रुपये का खामियाजा न भुगतना पड़े, सरकार को न भुगतना पड़े अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही एक मामला सैक्टर-10 का है जैसा मेरे सफीदों का है। सैक्टर-10 में भी आवास बोर्ड ने मकान बनाने के लिए एप्लीकेशन पंजीकरण कर ली और उनके पास जमीन थी नहीं, जब जमीन नहीं थी तो पंजीकरण क्यों किया गया। इसमें ऑफिसर्ज से जवाबदेही मांगी जाए। इसी तरह से मेरे सफीदों में इसने जमीन और सारा कुछ दे दिया है मगर विभाग की लापरवाही की वजह से पिछले कितने ही वर्षों से पता नहीं हुड़ा डिपार्टमैंट के अधिकारी क्या करते रहे और हाउसिंग विभाग के अधिकारी भी न जाने क्या कार्यवाही करते रहे। मुझे जो जानकारी मिली वह यह है कि उनका झगड़ा सिर्फ ठेकेदारी की वजह से रुका रहा कि दो नम्बर में कितना पैसा सरकार को जाए और कितना पैसा किस अधिकारी को जाए। इस वजह से बार-बार ठेकेदार हटते चले गए और हमारा यह कार्य यूं की ही अधूरा पड़ा रहा जिसकी वजह से मेरा पिछड़ा हुआ इलाका और भी पीछे चला गया। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था। दैनिक भास्कर अखबार में खबर छपी है जिसका शीर्षक है छोटे काम में बड़ा घोटाला । आज से पिछली सरकार ने 10 लाख रुपये के कार्य में 4 लाख 53 हजार रुपये की गड़बड़ी की

चार छोटे अधिकारी और कर्मचारी जिसमें सैक्रेटरी, चीफ एकांउटैंट ऑफिसर, चीफ रैवेन्यू ऑफिसर, सीनियर आर्किटैक्ट और टाउन प्लानर को तो चार्जशीट थमा दी गई लेकिन किसी बड़े ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस सरकार ने जो वर्तमान सी०ए० लगाया है उसने पीछे किये गये कार्यों की चैकिंग की। पीछे जो जो काम एलॉट हुए थे उसका मुआयना किया तो यह पाया कि जो काम 10.00% लाख में किया गया उसी कार्य के लिए दूसरे ठेकेदारों ने भी ऐप्लिकेशन्ज़ दी थीं और वे लोग उसी काम को पांच लाख रुपये में भी करने को तैयार थे। हुडा डिपार्टमैंट के पास और आवास विभाग के पास अब भी सबूत हैं मगर पता नहीं किस वजह से 4 लाख 53 हजार का चूना सीधे सरकार को लगा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए यह कहना चाहता हूं कि उन छोटे कर्मचारियों को तो चार्जशीट दे दी गई लेकिन पिछले 3-4 साल से पिछली सरकार के समय जो सीनियर अधिकारी बैठे हुए थे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब सामने दिखाई पड़ रहा था कि लापरवाही हुई है तो उन्होंने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जबकि चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर ने उस लापरवाही को पकड़ लिया कि दूसरे ठेकेदार उसी काम को 5-5 लाख रुपये में करने के लिए तैयार थे। 4 लाख 53 हजार का जो चूना सरकार को लगाया गया है उसमें किसी बड़े अधिकारी को क्यों नहीं पकड़ा गया। मुझे यह भी विदित हुआ है कि उस समय जो कमिश्नर थे वही कमिश्नर इस समय हाउसिंग डिपार्टमैंट में कार्यरत हैं इस तरह की लापरवाही और अनियमितताएं जगह जगह पर की गई हैं। मेरे विधान सभा हल्के में भी जो सबसे मेन कार्य हुडा तथा आवास विभाग में मन्जूर पड़े हुए थे लेकिन आज तक वहां पर यह कार्य शुरू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में सरकार को कहना चाहता हूं कि उनकी लापरवाही के कारण मेरे हल्के के लोगों का नुकसान हुआ है और जिस भी अधिकारी ने लापरवाही से कार्य किया है उनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसी डिमाण्ड पर चर्चा करते हुए अपने हल्के सफीदों की कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं सदन में रखना चाहता हूं कल बजट पर तो हम ज्यादा बात नहीं कर पाए मैं इसी दायरे में रह कर अपनी बात कहूंगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जैसे मेरे सफीदों क्षेत्र के लोग पिछड़े हुए हैं और वह पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं आपको बता रहा हूं कि पीलू खेड़ा मण्डी ब्लॉक भी है। स्वास्थ्य मन्त्री जी इस समय हाउस में नहीं बैठी हुई हैं मुझे उम्मीद है कि वे मेरी बात को सुन रही होंगी। अध्यक्ष महोदय, पीलू खेड़ा मण्डी में पी०एच०सी० तो दूर की बात अभी तक वहां पर कोई छोटी सी डिस्पैंसरी तक नहीं है। वहां पर एक बड़ी अनाज मण्डी है और वह ब्लॉक भी है वहां की जनसंख्या की काफी ज्यादा है। आज हरियाणा के छोटे -छोटे गांवों में डिस्पैंसरीज और जगह जगह पर पी०एच०सी० खुली हैं मगर मेरे हल्के के अन्दर तो डिस्पैंसरी भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां पर एक पी०एच०सी० खुलवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरे इलाके के अन्दर सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है, वे बुरी तरह से टूटी हुई हैं। दो तीन सड़क तो ऐसी हैं जो कि 10 सालों से अधूरी पड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इसराना से लेकर गोल्सी तक की सड़क 3 किलोमीटर लम्बी है। कांग्रेस की पहली सरकार के वक्त में उस पर गिट्टी डाल दी गई थी और आधी सड़क पर तो रोड़ी भी डाल दी गई थी लेकिन पिछली इनैलो की सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण वह मेरा पैतृक गांव है उस सड़क पर कोई काम नहीं करवाया। वह सड़क वैसी की वैसी है जिसकी वजह से वहां पर से जाने वाले किसानों के ट्रैक्टरों के टायर और बुग्गी के टायर खराब हो जाते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस सड़क को पूरा

[श्री बच्चन सिंह आर्य]

करवाने का कष्ट करें। इसके साथ ही रजाना गांव से कालवा गांव की सड़क अढ़ाई किलोमीटर लम्बी सड़क है, उस सड़क का भी निर्माण करवाया जाए, हरिगढ़ से लेकर ओरहाट तक की सड़क का भी निर्माण करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : आर्य जी, आप वाइंड अप करें।

श्री बचन सिंह आर्य : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि यहां पर हाऊसिंग बोर्ड, हुडा का और आई०टी०आई० का जिक्र किया गया है तो मेरे हल्के सफीदों से जींद और पानीपत 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, कैथल भी लगभग 45 किलोमीटर दूर है। स्पीकर सर, मेरे हल्के सफीदों में कोई भी आई०टी०आई० नहीं है। वहां पर आई०टी०आई० खोलने का कष्ट करें। स्पीकर सर, आपने कहा है कि मेरे और भी साथियों ने बोलना है इसिलए मैं आपका धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, अपनी सीट लेता हूं।

Mr. Speaker : Thank you very much. Dharambir ji, you may start.

श्री धर्मबीर (बाढ़ड़ा) : स्पीकर सर, 9 जून को वित्तमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि लगभग 15-20 सालों से कर्ज लेकर स्टेट को चलाने की जो प्रथा पिछली सरकारों ने हरियाणा में डाल रखी थी वह खत्म हो गई है। स्पीकर सर, पहली बार लगभग 3000 हजार करोड़ रुपए वार्षिक योजना पर खर्च होंगे। इसलिए आज प्रदेश की जनता की आशाएं थोड़ी ज्यादा जाग गई हैं। स्पीकर सर, जहां हमारा पैसा लोन की रिपेमैंट में जा रहा है। वह 14.89 प्रतिशत इन्ट्रस्ट है और लोन में 9.81 प्रतिशत है, यानि की साढ़े 24 प्रतिशत या 25 प्रतिशत हमारा पैसा तो रिपेमैन्ट में चला जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और बीरेन्द्र सिंह जी की सलाह से वार्षिक योजना में 34 प्रतिशत प्लानिंग कमिशन ने प्रदेश के विकास के लिए दिया है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है।

स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने 40 वर्ष बनाम 40 महीने वाली बात कही है यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम सभी मिलकर काम करेंगे। यह जो कैंसर रूपी भ्रष्टाचार का रोग कई सालों से लगा हुआ है अब इस पर अंकुश लगेगा। इन तीन महीनों में मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने हैड आफ दि डिपार्टमैंट के आफिसर्ज, जिलों में भी चाहे वे डी०सी० हैं या एस०पी० हैं के बारे में पूर्ण रूप से कोशिश की है कि ईमानदार आफिसर्ज ही लगाएं। लेकिन चूंकि कई साल से प्रदेश भ्रष्टाचार से जकड़ा हुआ था और कुछ लोग जो जिलो में कई सालों में बैठे हैं उदाहरण के तौर पर कोई पुलिस का सब इंसैक्टर है या कुछ और लोग हैं तो इन्हीं लोगों ने अपनी जान पहचान बना रखी है। मेरा सुझाव है कि कम से कम इन लोगों को दूसरे जिलों के दूर दराज के इलाकों में बदला जाए ताकि उनका लिंक टूट जाए और सरकार भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। इस सरकार ने बनते ही जिस प्रकार से पानी के समान वितरण का फैसला किया। जिस तरह से हमारे इरीगेशन मिनिस्टर ने यह भी दिया है कि लगभग दो साल में एक नई लिंक नहर बनाकर मेन भाखड़ा नहर का पानी डब्लयू०जे०सी० में डालकर उस लिंक नहर के माध्यम से पानी की कमी वाले इलाकों में पानी देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में एक सुझाव है खासकर नहर विभाग के अधिकारियों से, इरीगेशन मिनिस्टर से और वित्त मंत्री जी से कि वे कुछ पोलिसी बदलें। उदाहरण के तौर पर जहां मेन फीडर हैं उनमें कहीं पर भी आउट लैट्स नहीं होने चाहिएं क्योंकि यह लकरीबन इल्लीगल हैं। इनकी वजह से ही पानी आगे नहीं पहुंच पाता। मेन फीडर का काम है पानी को आगे ले जाना। कई माईनर्ज ऐसे हैं जिनमें एक महीने में तीन दिन पानी जाता है अगर पैरलल माईनर और फीडर होते

हैं तो कई लोग कोशिश करते हैं कि उनको फीडर से मौगे दिए जाएं ताकि उनको पानी मिलता रहे। इसके अलावा मेरा सुझाव यह भी है कि जिस तरह से फॉरेस्ट ऐक्ट के तहत अगर कोई लकड़ी काटता है या कोई पेड़ काटता है तो इनके लिए अलग से कोर्टस बना रखी हैं। जैसे भिवानी के आदमी ने पेड़ काटे तो उसको फरीदाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में जाना पड़ता है, अम्बाला के आदमी को सिरसा में जाना पड़ता है। इसी आधार पर मैं आपके माध्यम से नहरी मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं कि जो लोग नहरी पानी की चोरी करते है तो इनके लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। यदि भिवानी का आदमी पानी की चोरी करता है तो उसकी कोर्ट अम्बाला में लगनी चाहिए ताकि वह तंग होकर पानी की चोरी करने का नाम न ले सके। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके बारे में सोमवीर सिंह ने भी, आदरणीय महेन्द्रा जी ने भी कहा कि एक हजार प्रति एकड़ के ऊपर जो 3.4 क्यूसिक पानी था उसको घटाकर 2.40 क्यूसिक किया। मैं कहता हूं कि 2.40 क्यूसिक पानी करने के बाद भी उस इलाके में पानी इरीगेशन के लिए नहीं बल्कि केवल मात्र जोहड़ भरने के लिए और पीने के लिए ही मिलता है और पीने के लिए भी कई बार नहीं मिलता है। जब से हरियाणा प्रदेश पंजाब से अलग होकर बना है तब से लेकर आज तक कई गांव ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं मिला है। मैं ऐसे बहुत से गांवों का नाम बता सकता हूं। उदाहरण के तौर पर मकड़ाना है। खासकर वे इलाके जो तोशाम से लेकर बहल, सिवानी और झूप्पा जो राजस्थान के चुरू जिले तक लगता है, वहां पर आप भी यह जानकर हैरान होंगे कि वहां के लोग आज भी पीने के पानी के लिए इस बात की मांग करते हैं कि हमारे तालाब में पानी डाल दो ताकि हमें पीने का पानी तो मिल जाए यह तभी संभव होगा जब इरीगेशन महकमा पुरानी पोलिसीज को बदले। एक तो मेन कैनाल के ऊपर जितने भी आउटलेट्स हैं वह उखाड़े जाएं। दूसरे जितने पम्प हाउसिज हैं वे सब बहुत साल पहले बनाये गये थे किसी भी पम्प हाउस की कैपेसिटी आज तीस परसैंट से ज्यादा की नहीं है। चाहे वह जे०एल०एन० कैनाल का सिस्टम हो, सिवानी फीडर हो, लोहारू कैनाल हो, जुई कैनाल हो, सतनाली फीडर हो या दूसरे जितने भी सिस्टम हैं उनके बारे में आप भी जानकर हैरान होंगे कि वहां आज भी पूरी कैपेसिटी से पानी नहीं मिलता। लोहारू कैनाल जिसकी 1450 क्यूसिक की कैपेसिटी है जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक हमने उसमें 500 क्यूसिक से ज्यादा पानी चलते नहीं देखा है। अगर थोड़ा बहुत पानी दे भी देते हैं तो बिजली के जितने पम्प हाउसिज हैं जो केवल मात्र लिफ्ट कैनाल के लिए बने थे लेकिन बड़े दुख की बात है कि पिछली सरकार के दौरान उनसे डोमैस्टिक कनैक्शंज भी दे दिए गए। जिन पम्प हाउसिज में फाल्ट होता है वे पानी नहीं उठा सकते। इस तरह से फीडर पर दूसरे कनैक्शंज नहीं दिए जाने चाहिए चाहे वे ऐग्रीकल्चर सैक्टर के हों या डोमैटिस्क कनैक्शंज हों वे तुरंत वहां से हटाए जाने चाहिएं। इसी तरह से जिस प्रकार से सिवानी फीडर है जिसके बारे में हमारे विधायक छत्तर पाल जी ने एक ऐलराज उठाया था इसमें पहले पानी डब्ल्यू०जे०सी० की हांसी ब्रांच से चलकर पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी के माध्यम से 200 क्यूसिक और लगभग 130 क्यूसिक न्यू सिवानी फीडर से देते थे लेकिन पिछले बीस साल से वहां पर कभी भी इतना पानी नहीं आया क्योंकि लोगों ने पीछे पानी की चोरी करके सौ या सवा सौ क्यूसिक से ज्यादा पानी आगे नहीं जाने दिया। इसलिए हमारी मांग है कि बालसमंद डिस्ट्रीब्यूट्री जिसमें भाखड़ा का पानी आता है उसकी टेल से 100 परसैंट पानी सिवानी फीडर में दिया जाए क्यों कि सिवानी फीडर 3200 क्यूसिक की नहर है जिसमें कभी पानी नहीं जाता । उसी नहर से माध्यम से चाहे वह मिट्ठी का टैंक है, जितना भी सिस्टम राजस्थान से लगा हुआ है उससे जुड़ता है।

राजस्व मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि जो नहरें हैं उनमें काफी ज्यादा सिल्ट आ गई थी जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी कम हो गई थी। नहरों की सफाई का कार्य चल रहा है। अभी पिछले दिनों से जे०एल०एन० की सफाई का काम चल रहा है। आने वाले दो महीनों के अंदर नहरों की कैपेसिटी बढ़ा देंगे और 75 प्रतिशत तक की जो आपकी कैपेसिटी है उसको वहां तक ले जाएंगे।

श्री धर्मबीर : इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 75 प्रतिशत की भी नहीं कहता। जितना हमारा सिस्टम है, लोहारु कैनाल का सिस्टम है, जतनाली कैनाल का सिस्टम है वह सारे जे०एल०एन० सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये सिस्टम 1450 क्यूसिक्स के हैं अगर आप हमें बारिश के समय में 800 क्यूसिक पानी भी दे देंगे तो हम आपका आभार व्यक्त करेंगे क्योंकि पिछले 20-25 साल से नहरों की सफाई नहीं हुई। जब 1995 में बाढ़ आई तो बहुत से पम्प हाउसेज के पम्प उतार कर बाढ़ का पानी निकालने के लिए बाढ़ की जगह पर ले कर गए थे उनको वापस नहीं लाया गया। अगर बारिश के दिनों में भी वहां पानी जाएगा तो वह पानी रीचार्ज होकर ऊपर आ सकता है। नयी सरकार से बहुत सारी आशाएं हैं। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के बनने के बाद पहली बार ऐसी सरकार का गठन हुआ है जो पूर्ण रूप से ईमानदार है। इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र सोनियां गांधी जी भी हैं जिन्होंने हमें एक बेहद ईमानदार मुख्यमंत्री दिया जिसके कारण खासकर किसान और मजदूर और हमारा इलाका, मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने बिजली के बिलों के लिए सब कमेटी वित्तमंत्री जी की अध्यक्षता में बना दी उससे काफी खुश हैं। सामने बैठने वाले विपक्ष के लोगों ने जनता की आशाओं को मार रखा था। अब उनके हौंसले बढ़े हैं। आज हरियाणा की आम जनता की सरकार बनी है। इस प्रकार ऐग्रीकल्चर में हमारे सीमित बजट में से हमारे मुख्यमंत्री जी ने गेहूं की फसल का जहां औलावृष्टि की वजह से नुकसान हुआ। उसका मुआवजे का पचास प्रतिशत से ज्यादा पैसा दिया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे यहां सरसों ज्यादा पैदा होती है आज यह सारी की सारी फसलें घाटे का सौदा है। यह बात हर विधायक ने मानी है कि हमारा पहाड़ी इलाका है इसलिए वहां पर सर्दी से बचाव हो जाता है जिसकी वजह से वहां पर टमाटर की फसल ज्यादा होती है यदि वहां फूड प्रौसेस का कारखाना जैसे टमाटर का सौस बनता है ऐसा यदि लगा दिया जाए तो किसान को फायदा होगा। वैसे भी सरसों में कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिसको हम अलग नाम दे देते हैं यह बीमारी रेतीले इलाके में ज्यादा पाई जाती है जहां सरसों की पैदावार फिफ्टी परसैंट से डाउन आई है। ऐग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी से उस बीमारी की जांच करवा करके उस बीमारी को पकड़ कर खत्म किया जा सके। जहां विकलांगों के लिए इस सरकार ने पैंशन की राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी है वैसे तो यह राशि पिछली सरकार को बढ़ानी चाहिए थी जिसको ज्यादा ऐक्सपीरियंस था खासकर हैंडीकैप्ड के बारे में, क्योंकि वे लोग खुद भुक्तभोगी थे लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने यह बढ़ाकर स्वागत योग्य काम किया है। आदरणीय हुड्डा साहब की सरकार ने बनते ही करप्शन को कंट्रोल करने का काम किया है। आप हैरान होंगे कि पिछले पांच साल के दौरान जब भी पी०डब्लू०डी० के टैंडर होते हैं, चाहे इरीगेशन के टैंडर थे, चाहे बी० एण्ड आर० के हुए थे या पब्लिक हैल्थ के टैंडर होते थे यदि एक काम 5 करोड़ का था तो उस पर 20 परसैंट ऐक्स्ट्रा सरकार के ऊपर खर्च पड़ता था और सिंगल टैंडर मंजूर करवाए जाते थे। ये लोग निचले अधिकारियों पर दबाव डालकर ऐसा करते थे। आदरणीय हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री बनते ही सख्त आदेश दिए जिसके कारण आज टैण्डर का काम कम्पीटीशन में होता है। पहले जिस काम का खर्चा 20 प्रतिशत से ऊपर जाता था आज उसी काम पर 10 और 15 प्रतिशत से

कम खर्चा आता है जिससे सरकार का करोड़ो नहीं बल्कि अरबों रुपया बचता है। अगर यह सरकार इसी प्रकार से फैसले लेती रही, जिन्होंने केवल तीन महीने में ही ये फैसले लिए हैं, वह दिन दूर नहीं जहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी 40 साल बनाम 40 महीने कहते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि 40 महीने की बजाए एक साल में ऐसा उदाहरण पेश हो जायेगा कि हिन्दुस्तान में हरियाणा ईमानदारी के तौर पर नम्बर एक पर आ जायेगा। इसी प्रकार से बिजली बोर्ड के मामले में मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि इसमें लम्बी लाईनों के फीडर ज्यादातर हैं उन लाईनों को घटाकर छोटी लाईनें बनाई जायें ताकि जो सिस्टम ओवर लोडिड हो चुका है वह सिस्टम सही हो सके। पिछले कई सालों से सब-स्टेशन अपग्रेड नहीं किए गए जिसके कारण वे सभी अढ़ाई गुणा से तीन गुणा ओवरलोडिड हैं। उनको छोटे सब-स्टेशनों में तबदील किया जाये या छोटी लाईनों के फीडर बनायें जायें। इसी के साथ-साथ जहां से कैनाल निकली है वहां पानी ऊपर आया है। इसी के साथ जो तीन फेस की मोटर है उसको सिंगल फेस के कनैक्शन में तबदील किया जाये क्योंकि सिंगल फेस की मोटर लगाकर लोग 10-10 स्प्रिंकलर सैट्स चलाते हैं जिससे थोड़ा खर्चा आता है इसलिए 3 फेस के कनैक्शन को सिंगल फेस में बदला जाये। पिछले सालों में बागवानी कनैक्शन दिये गये थे, जिनमें बिजली का रेट कमर्शियल रेट पर लगता है उनको एग्रीकल्चर सैक्टर में तबदील किया जाये। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बिजली और पानी के मामले को एक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये जिसे छठी कक्षा से शुरू किया जाये ताकि बिजली और पानी की बचत हो सके। क्योंकि आज घर में अगर 70 साल का आदमी होगा जब वह घर से बाहर जायेगा तो बिजली को बन्द करके जायेगा अगर पानी की टूटी खुली है तो उसको बन्द करेगा लेकिन आज के बच्चे चाहे घर में ए०सी० चल रहा है तो चलता रहेगा अगर गीजर चल रहा है तो चलता रहेगा उनमें बन्द करने की आदत बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार से पानी की जो टूटी चल रही है तो चलती रहेगी उसको कोई बंद करने की कोशिश नहीं करता। इसलिए इस बात को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये और जिस प्रकार पी०टी० की क्लास लगती है उसी प्रकार से इसकी भी आधे घण्टे की क्लास लगे जिसमें बच्चों को बिजली पानी की बचत के बारे में बताया जाये। स्पीकर सर, आपके माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पिछले सालों में प्रचार किया गया कि पंचायतों के माध्यम से एच०आर०डी०एफ० का पैसा खर्च करके गलियां पक्की बना दी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से एक मांग करता हूं कि गलियां जब बनाई जाती हैं। तो वहां डी०सी० रेट जाकर देखा तो ईंट का भाव उन्होंने 1500 रुपये प्रति हजार के हिसाब से फिक्स कर दिया लेकिन अगर भट्ठे पर पता किया जाए तो पता चलेगा वह वहां 2200 या 2300 रुपये प्रति हजार ईंटों का भाव है अगर यही रेट रहेगा तो आपको नम्बर 1 की ईंट नहीं मिलेगी इस प्रकार घटिया ईंट लगाई गई जिसकी वजह से बदनामी हुई कि यह तो 3 या 4 नम्बर की ईंट है जबकि नम्बर एक ईंट का भाव ज्यादा है। इससे अच्छा तो कंक्रीट या सीमेंट की बनाई जायें या ईंटों के रेट को बराबर किया जाए ताकि क्रप्शन न फैले। इसी प्रकार से जो गांवों में गलियों में टूटियां लगी हैं उनमें पानी चलता रहता है और गलियां खराब हो जाती हैं इसलिए पानी को बचाने के लिए पंचायत और पब्लिक हैल्थ दोनों मिलकर हर गांव में 5-4 या बड़ा गांव है तो 10 टंकियां बनाई जाएं और उस टंकी को कनैक्शन दिया जाये इससे पानी भी बचेगा और गलियां भी नहीं टुटेंगी। जहां तक पब्लिक हैल्थ है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि अण्डर ग्राउंड वाटर जो बोर करके लिया जाता है दूसरा कैनाल बेस्ड स्कीम प्रदेश भर में ऐसी कई जगह वाटर कैनाल बेस्ड स्कीम है जिनको इरीगेशन विभाग ने पता नहीं कैसे पास कर दिया उन टैंकों में बनने के बाद नहर का पानी नहीं

[श्री धर्मबीर]

डाला गया है इसलिए सरकार उनके लिए पानी का प्रबन्ध करे। 1996-97 में तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफीडेविट दे दिया था। कि हमारे पास टैक्नीकल स्टाफ नहीं है अगर गांव का आदमी मोटर को चलाता है तो वह मोटर हर तीसरे दिन जल जाती है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि कोई टैक्नीकल आदमी वहां लगाया जाए। इसी प्रकार से हैल्थ के बारे में मेरा मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि जहां-जहां पर भी नए होस्पिटल बनें चाहे वह PHC बने, चाहे CHC की डिमांड हो लेकिन जहां सरकार B&R से उनकी बिल्डिंग बनवाने की कोशिश करती है, उससे पहले उन गांवों को प्राथमिकता दी जाए जहां पर लोकल सेठ साहुकार अपने पैसे से बिल्डिंग बनाना चाहेंगें वहां PHC पहले खुल जाए तो लोगों को फायदा हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, एनीमल हस्बैंडरी भी एक महत्वपूर्ण सब्जैक्ट है अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो वह गाड़ी में बैठकर, बस में बैठकर इलाज करवाने अस्पताल जा सकता है। पशु धन आज बहुत जरूरी है, कोई पशु बीमार हो जाता है तो उसको दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता । इसलिए कोशिश की जाए कि 5 किलोमीटर के दायरे में पशुओं का अस्पताल बनाया जाए। अन्त में मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो धर्मबीर जी ने पशुओं की बात की है उस बारे में मैं हाउस को बताना चाहता हूं और हमें इस बात की खुशी है कि केन्द्र से मुर्रा ब्रिड के लिए 557 करोड़ का पैकेज हरियाणा को मिलने जा रहा है।

श्री देवेन्द्र बंसल (अम्बाला छावनी) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं बजट पेश करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय, का आभार प्रकट करता हूं । इंडस्ट्रीयल पोलिसी के तहत करीबन 20 हजार करोड़ रुपये की पानीपत के आस पास और दूसरी जगहों पर इन्वैस्टमैंट करने की बात की गई है। यह बहुत अच्छी और शोभनीय बात हरियाणा की डिवैल्पमैंट के लिए की गई है। मेरी गुजारिश है कि अम्बाला छावनी इंडिया में साइंटैफिक इन्स्ट्रमैंट के एक्सपोर्ट के लिए, मैनुफैक्चरिंग के लिए सबसे बड़ा हब रहा है। पिछले 10-12 सालों से यह इंडस्ट्री में नम्बर वन नहीं रहा क्योंकि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली और न ही कोई हैल्प किसी इंडस्ट्री को मिली जिससे घर-घर में जो साइंटैफिक इंडस्ट्रीज थी वे बन्द हो गई हैं, मेरी इस बारे में सबमिशन है कि अगर 20 हजार करोड़ रुपए की इन्वैस्टमैंट में से कुछ इन्वैस्टमैंट अम्बाला छावनी की साइंटैफिक इंडस्ट्रीज में की जाए तो उससे इंडस्ट्रीज अपलिफ्टमैंट बहुत बड़े लैवल पर हो सकती हैं। यह हरियाणा के लिए बहुत बड़ा क्रैडिट होगा। पहले भी अम्बाला छावनी हिन्दुस्तान में नम्बर वन पर था। Being a getaway of three States, a special care should be given to Ambala Cantt. तो इसलिए मेरी एक बार फिर सबमिशन है कि कुछ न कुछ इन्वैस्टमैंट अम्बाला छावनी में इंडस्ट्रीज पर की जाए। अम्बाला छावनी की तरफ से थोड़ी सी हमें शिकायत भी है कि रोजगार और व्यवसायिक शिक्षा के बारे में जितने भी शहर लिए गए हैं उनमें गुड़गांव, यमुनानगर और सोनीपत को लिया गया है लेकिन उसमें अम्बाला छावनी को कहीं नहीं रखा गया। इसलिए मैं चाहूंगा इंडस्ट्रीज के बारे में और इम्पलायमैंट वगैरह के बारे में अम्बाला कैंट की तरफ भी देखा जाए। अम्बाला छावनी का बस स्टैंड जिसका कई सालों से निर्माण शुरू हुआ और वह बीच में रह गया है अभी तक अधूरा पड़ा है, इसके अलावा अम्बाला छावनी का एक लोकल बस स्टैंड है, 10 साल पहले उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तब से लेकर आज तक उस लोकल बस स्टैंड का निर्माण नहीं हुआ। अम्बाला कैंट के मेन बस स्टैंड का निर्माण न होने से

जितनी भी बसें हैं These buses are remain standing on the roads due to that enormous accidents take place there. इसके बारे में स्पैशल केयर की जाए। मेरी NOC के बारे में एक और सबमिशन है जो सिर्फ अम्बाला कैंट में ही इम्पलीमैंट कर रखी है Not any part of the Haryana. NOC - प्रोपर्टी सेल और परचेज के लिए अम्बाला छावनी में लेना पड़ता है और वह केवल अम्बाला छावनी में लेना पड़ता है इसलिए इसको हटाया जाए। except creating hardships इसका कोई भी पर्पज नहीं है क्योंकि जितना भी रिकार्ड है वह म्युनिसिपल कमेटियों के पास है दूसरा किसी भी दूसरे डिपार्टमैंट से इसका कोई कंसर्न नहीं है। काफी समय से NOC जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने लगाए थे, उसकी वजह से हजारों लोगों को अम्बाला छावनी में प्रोब्लम फेस करनी पड़ रही है इसलिए इसको तुरन्त हटाया जाए। एक जो स्पेशल पावर ऑफ एटोरनी हरियाणा में किसी ने जमीन सेल, परचेज करनी है Then that person has to take the Special Power of Attorney after going out of Haryana. यह कंडीशन खत्म की जाये ताकि लोगों की समस्याएं दूर हों। इसके अतिरिक्त दूसरी जो मेन बात है अम्बाला छावनी में 35 प्रतिशत they are residing in the Cantonment area of Ambala Cantt., और उनकी वजह से जो आर्मी आफिशियल हैं they are several times creating problems to them. They are several times disconnecting the electricity. They are disconnecting the water connections. They are breaking upon the houses of those persons as well as upon the fields of those persons. कुछ दिन पहले भी आर्मी आफिसर्ज ने अम्बाला छावनी के जो आर्मी एरिया में जितने भी निवासी हैं उनकी प्रोपर्टी पर कब्जा कर लिया था जिसको केन्द्रीय मंत्री से कहकर छुड़वाया था। इसमें ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास ऐसी इन्फार्मेशन हो जो हम उनकी वर्किंग में इंटरफियर कर सकें। जितना भी पैसा सैंटर से डिफैंस कंट्रोल एरिया में सिविलियंज की डिवैल्पमैंट के लिए आता है कोई ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जिसकी हमें भी जानकारी हो कि वह पैसा जिस काम के लिए आया था वहां खर्च हुआ भी है या नहीं हुआ। दूसरा यह भी होना चाहिए कि जो वे सिविलियंज के काम में इंटरफियर करें उस मामले में हम भी इंटरफियर कर सकें । अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं पानी की बात करना चाहूंगा कि अम्बाला छावनी में पानी की बहुत समस्या है। Ambala is not connected with any river. It is entirely based upon the tubewells for two months. There is a big problem of the water and atleast 10 tubewells are immediately required and no doubt a big amount is kept in the Budget for the purpose making improvement in the water. उनकी रिक्वायरमैंट है ताकि अम्बाला छावनी के लोगों को हैल्प मिल सके। धन्यवाद।

श्री जय सिंह राणा (नीलोखेड़ी) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे डिमांड पर बोलने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब की सरकार ने जो बजट सदन में रखा है उससे इस सरकार की नीयत और सरकार के नेताओं की नीयत का पता चलता है कि प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए यह सरकार कार्य करना चाहती है। बजट पर लम्बी बहस के बाद आज वित्तमंत्री जी ने सभी साथियों ने जो जो सवाल उठाये थे उन सबका बड़े अच्छे ढंग से जवाब दिया उससे भी सरकार की अच्छी नीयत का पता चलता है कि यह सरकार प्रदेश में खुशहाली लाने की तरफ आगे बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मांग संख्या 17 पर बोलना चाहूंगा जो कृषि से संबंधित है। हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है जिसकी 75 से 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। इसलिए कृषि को आय का साधन बनाने के लिए सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बिजली और पानी का उचित प्रबन्ध करना

[श्री जय सिंह राणा]

पड़ेगा। जिसके लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है लेकिन हमें और मजबूती के साथ इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, बिजली कृषि के क्षेत्र में ही नहीं आज हर व्यक्ति की जरूरत बन चुकी है, चाहे वह किसी भी कार्य से संबंध रखता हो। यदि दस मिनय बिजली नहीं आती है तो हा-हा कार मच जाता है। इसलिए बिजली की सप्लाई को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत कुछ कार्य करने की जरूरत है। आज बिजली बोर्ड में Assistant Linemen से लेकर J.E. तक पोस्टें खाली हैं। अध्यक्ष महोदय, लाईनमैन, फोरमैन, जे०ई० उनकी संख्या बहुत कम है और उससे ऊपर के रैंक के जो लोग हैं वे बहुत हैं। परन्तु आज प्रदेश में जो बिजली उपलब्ध है उसे प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने की जहां तक बात है, तो बहुत पुराना ढांचा है, पुरानी तारें हैं, पुराने खम्भे हैं उस ढांचे को बदल कर मजबूत करना बहुत जरूरी है। असिस्टैंट लाईनमैन लाईनमैन, फोरमैन और जे०ई० आदि की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत से लाईनमैन और असिस्टैंट लाईनमैन पता नहीं कब भर्ती हुए और वे लोग अब खम्भे पर नहीं चढ़ सकते हैं। वे किसान को कहेंगे तथा किसान अपने नौकर को बुलाएगा और जब वह आएगा तो वह खम्भे पर चढ़ कर फ्यूज लगाएगा। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि लाईनमैन वगैरह की भर्ती की जाए, नये लोग आएंगे और उनके सहयोग से लोगों तक बिजली पहुंचाने में सहायता मिलेगी। इसी तरह से बिजली की चोरी की बात है। सदन में बार-बार साथियों ने कहा है कि कुछ लोग बिजली की चोरी करते हैं और उसका खामियाजा हरियाणा प्रदेश के सभी लोग भुगतते हैं, इसलिए चोरी रोकने के लिए यह नहीं देखना चाहिए कि इससे कोई राजी होगा या इससे नाराज होगा। बिजली की चोरी को रोकना चाहिए और इस बारे में सरकार को हर सम्भव प्रयास करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन पावर हाउसिज की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है उनकी क्षमता बढ़ाने का कार्य जल्दी से जल्दी किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में शामगढ़ सब-स्टेशन निर्माणाधीन है उस पर कार्य पिछले पैडी सीजन में शुरू हो चुका है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उसका कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करके लोगों को बिजली दी जाए। तरावड़ी में 33 के०वी० का सब-स्टेशन है और वह स्थान राईस का बहुत बड़ा सैंटर है। वहां पर बहुत सी राईस मिल्ज हैं और वहां पर 33 के०वी० का सब-स्टेशन है उसकी क्षमता बढ़ा कर वहां पर 132 के०वी० का सब-स्टेशन बनाया जाए जिससे सारे हल्के में बिजली की समस्या हट सके। इसी प्रकार से सीता माई में 10-15 किलोमीटर तक कोई भी सब-स्टेशन नहीं है। वहां पर एक 33 के०वी० का एक नया सब-स्टेशन लगाया जाए। किरमच गांव में 33 के०वी० का सब-स्टेशन है जिसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है लेकिन उसका काम अधूरा है, वहां पर 66 के०वी० का सब-स्टेशन बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि पैडी सीजन से पहले उनका काम पूरा करवाने की कृपा करें ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके जिससे जीरी के ऐरिया में लोगों को सीजन के समय पर अच्छी बिजली मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार कृषि से सम्बन्धित कीटनाशक दवाइयां, खाद और कृषि यन्त्र हैं, मेरे से पूर्व बोलते हुए मेरे माननीय साथियों ने कहा है कि इन चीजों को वैट प्रणाली के दायरे से बाहर रखा जाए और मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी से एक विशेष बात के लिए निवेदन करूंगा। मार्कीटिंग बोर्ड हरियाणा में बहुत पहले एक स्कीम बनी थी जो अभी भी चल रही है और लोगों को उस स्कीम का फायदा भी पहुंच रहा है। खेती का काम करते हुए किसी भी किसान या मजदूर की दुर्घटना से मृत्यु हो जाए चाहे वह मृत्यु बिजली का करण्ट लगने से हो या कहीं हौदी में दबने के कारण या किसी और

कारण से किसी की मृत्यु हो जाए। तो उसके परिवार वालों को 50 हजार रुपए देने का प्रावधान मार्किटिंग बोर्ड ने रखा हुआ है। यह प्रोवीजन मुख्यमंत्री जी बहुत पहले का रखा हुआ है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे तत्काल ही इस अमाउन्ट को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दें और बाद में अगर जरूरी समझे तो इस बारे में विचार करके इस अमाउन्ट को और बढ़ा दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मरने वाले के परिवार को कुछ तो सहायता मिलेगी। स्पीकर सर, मेरा मुख्यमंत्री जी से कहना है कि यह बहुत ही जरूरी है और आप इस अमाउन्ट को तुरन्त बढ़ाएं क्योंकि आज किसान यह कहता है कि सरकारी आफिसर्ज की तनख्वाह भी बढ़ गई है, एम०एल०एज० भी अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं। लेकिन किसान को एक सहायता है जो उसके जाने के बाद ही उसके परिवार वालों को मिलती है उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी इसको आप तुरन्त बढ़ाए। स्पीकर सर, कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के लिए बहुत बड़ा योगदान आज नहरों के पानी का है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। जो पूरे हरियाणा में पानी का बराबर बंटवारा करवा दिया है। आज हरियाणा में क्षेत्रवाद का भेदभाव नहीं है। हम सब आपस में भाई भाई हैं। यह जो इस सरकार ने किया है वह जहां पर किसी के साथ अनदेखी हो रही थी उसको दूर किया है। एक तरफ तो पानी की वजह से जमीन में सेम आ गई थी और वहां पर कोई फसल न हो रही हो और दूसरी तरफ सूखे की वजह से कोई फसल बोई ही नहीं जा रही थी। यह बहुत ही खराब बात थी इसलिए मुख्यमंत्री जी ने पानी के बंटवारे के बारे में जो फैसला लिया है यह बहुत ही सराहनीय कदम है।

स्पीकर सर, मेरे हल्के में एक बहुत ही पुराना भुतंग सिस्टम डब्ल्यू०जे०सी० से आता है। पहले जब बारिश होती थी तो धान की फसल की बोआई होती थी। जब से टयूब्वैल आए हैं और लेटस्ट बीज आए हैं तो उनकी बोआई लोगों ने पहले ही करनी शुरू कर दी है। आजकल हमारे यहां पर जीरी की बोआई बहुत ही जोरों से चल रही है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर नहरों में अभी तक सफाई नहीं हुई है उनकी सफाई करके वहां पर जल्दी से पानी छोड़ा जाए।

श्री अध्यक्ष : आप वाईड-अप करें।

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर सर, यह भुतंग सिस्टम काफी पुराना सिस्टम है उसकी सफाई पानी आने से पहले करवाई जाए। वहां पर सफाई सिर्फ नीचे तक नहीं होनी चाहिए उसकी सफाई बरम तक होनी चाहिए, उसके किनारे अच्छी तरह से छीलें जाएं ताकि वहां पर पानी टेल तक पहुंचे।

Mr. Speaker : Please wind up.

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं ; मुख्यमंत्री चले गये हैं और वित्त मंत्री जी आ गये हैं। इनको मेरी बात पर ध्यान देना चाहिए। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बड़ी भारी उम्मीद हर वर्ग को है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं तब गरीब लोगों को, भूमिहीन लोगों को तीन-तीन मरले के प्लाटस दिए गये थे लेकिन उसके बाद किसी भी सरकार ने उन गरीबों की तरफ नहीं देखा है। वह टकटकी बांधकर सरकार की तरफ देख रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इस बात पर सरकार गौर करे। इसमें जाति बंधन को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए बल्कि इसका आधार गरीबी बनाया जाना चाहिए चाहे वे किसी भी जाति से संबंध रखते हों। अगर वे भूमिहीन हैं तो उनको प्लाटस दिए जाने चाहिएं। जब हम चुनाव के समय जाते थे तब हम देखते थे कि छोटे से एक घर में चार-चार बेटों के साथ गरीब लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर उनको प्लाट्स दे दिए जाएं तो वे कर्जा लेकर अपने मकान बना लेंगे, धन्यवाद।

श्री नरेश यादव (अटेली) : स्पीकर सर, इस साल का जो बजट आया है वह बहुत ही बढ़िया बजट है सभी ने इसकी तारीफ की है। विपक्ष की तरफ से भी इसका कोई खास विरोध नहीं हुआ है। आदरणीय वित्त मंत्री जी, हमारी भी एक पार्टी थी जिसका नाम था हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति। इस पार्टी के बैनर तले ही हमने विधान सभा का चुनाव लड़ा और इसके बैनर तले ही हम पिछले दस साल से हरियाणा की धरती पर संघर्ष कर रहे हैं। स्पीकर साहब, हमारी पार्टी के कुछ मुख्य मुद्दे थे। वही मुद्दे कांग्रेस पार्टी के भी थे। जब इनैलो सत्ता में था तो कांग्रेस के वही मुद्दे होते थे और जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती थी तो इनैलो और भारतीय जनता पार्टी के भी वही मुद्दे होते थे । सभी पार्टियों की जब भी सरकार बनी तो बंसीलाल जी की पार्टी की सरकार को छोड़कर जो शराबबंदी के नाम पर बनी थी, बाकी सभी पार्टियों की सरकारें पानी के मुद्दे पर ही बनीं। चाहे वह 1987 में सरकार बनी हों या उसके बाद सब ने यही कहा कि एस०वाई०एल० कैनाल का निर्माण करवाया जाएगा और हरियाणा में जो उपलब्ध पानी है उसका बंटवारा समान रूप से करवाया जाएगा। मैं इस सरकार को मुबारिकबाद देता हूं कि कम से कम इसने पानी के समान बंटवारे के बारे में यह तो माना है कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं था और इसका सही बंटवारा किया जाएगा। इन्होंने इसकी कोशिश की भी है और पानी नहरों के टेल तक हमारे इलाकों में पहुंचा भी है लेकिन अभी इस बारे में बहुत काम होना बाकी है। सारी नहरे अटी पड़ी हैं, उनकी सफाई करवानी जरूरी है। आज ही मुख्यमंत्री जी ने दो करोड़ रुपये के बजाए पांच करोड़ रुपये बढ़ाकर कहा है कि नहरों को ठीक किया जाएगा। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सदन में इस समय सभी सदस्य बैठे हुए हैं मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि हरियाणा में जो पानी उपलब्ध है उसका समान वितरण हुआ है और हो रहा है इसके लिए मैं सरकार को मुबारिकबाद भी देता हूं। अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार ने पानी के सभी समझौतों को रद्द करके शुरू कर दिया कि एक बूंद पानी की हरियाणा को नहीं देंगे। उसके बाद इस पर हरियाणा की उस समय की विधान सभा के मौजूद सदस्यों ने कोई निर्णय लिया या नहीं लिया इसका हमें पता नहीं है क्योंकि उस समय हम सदस्य नहीं थे। लेकिन अगर कोई भी उस समय का मौजूद, सदस्य हमें इस बारे में बता दें। चाहे वे कांग्रेस के हो, चाहे वे इनैलो से हों या चाहे वे भाजपा से हों यह एस०वाई०एल० का मुद्दा बहुत अहम है इसको आसानी से छोड़ नहीं देना चाहिए । जो हमारा पानी का हक है उसको लेने केलिए प्रयास किया चाहिए, यह ऐप्रोप्रिएट टाईम है। पीछे जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इनैलो और भाजपा की सरकार थी तब कांग्रेस के लोग और किसान संघर्ष समिति के लोग सड़कों पर आवाज उठाते थे और ये लोग विधान सभा में आवाज उठाते थे कि पंजाब में भाजपा और अकाली दल की अलायंस सरकार है और सैंटर में एन०डी०ए० भाजपा की सरकार है और हरियाणा में चौटाला की सरकार है तब भी एस०वाई०एल० का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। पानी का सबसे ज्यादा तकलीफ हमारा इलाका ही भुगत रहा है। रिवाड़ी भिवानी जो दक्षिणी हरियाणा का इलाका है जहां आज भी 1400 फुट गहरी खुदाई होने पर भी पानी नहीं है। पानी की असली तकलीफ हमारा इलाका झेल रहा है और पानी पर चारों तरफ से राजनीति हो रही है। मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि एस०वाई०एल० कैनाल का मामला सारे देश में सबसे चर्चित मामला है आज इस मामले को आसानी से कैसे छोड़ दिया गया है जब केन्द्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार है और सदन में भी यह मेन मामला है कि पानी आना चाहिए इसके ऊपर जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहले साल का टाइम दिया जब बादल की सरकार थी उसके बाद 21 दिन का टाईम

दिया कि 21 दिन के अंदर-अंदर पंजाब सरकार एस०वाई०एल० के निर्माण का कार्य शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारी तकलीफ को समझकर 21 दिन का टाइम दिया है तो जब तीनों जगह कांग्रेस की सरकार है तो फिर इस अहम मुद्दे पर समय क्यों लिया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं चूंकि इन्होंने भी एस०वाई०एल० के बारे में काफी संघर्ष किया था और हमने भी इस बारे में पदयात्रा निकाली थी हमने किसान संघर्ष समिति ने भी पद यात्रा निकाली थी वह पदयात्रा बेकार नहीं जानी चाहिए इसके लिए सोनिया गांधी जी पर दबाव डालना चाहिए और एस०वाई०एल० का जो मामला है वह टेबल पर आना चाहिए। कोर्ट कचैहरी में नहीं रहनी चाहिए। इसको सीरियसली लेना चाहिए। एस०वाई०एल० का पानी हर कीमत का प्रदेश की जनता तक पंहुचाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा हमारे इलाके में वाटर टेबल भी नीचे जा रहा है मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि राजस्थान सरकार ने हमारे दक्षिणी हरियाणा के बार्डर के चारों तरफ बांध बनाए हैं के चारों तरफ हमारे बांध बने हैं मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि उसके लिए राजस्थान सरकार से बातचीत कर कोशिश की जानी चाहिए कि जो उन्होंने ऊंचे बांध बना लिए हैं एक तो बारिश कम होती है फिर उनके ऊंचे बांधों की वजह से बारिश होती भी है तो एक बूंद भी पानी हमारी तरफ नहीं आता है। कॉपर में डीप माइनिंग हुई है। उनकी वजह से भी हमारे इलाके का वाटर लैवल नीचे गया है इसलिए किन्हीं भूगर्भ विशेषज्ञों की टीम वहां लगाकर जांच की जानी चाहिए। सदन में यह भी चर्चा चली कि महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को इण्डस्ट्रीयली बैकवर्ड घोषित कर दिया है मैं सदन से जानना चाहूंगा कि वर्षों से बैकवर्ड हमारा जिला है उसको फौरवर्ड बनाने के लिए क्या कोई प्रयास इस सरकार ने किया है यदि किया है तो क्या कदम उठाए गए हैं जब सरकार ने पानी के मामले में मान लिया है कि अहीरवाल के क्षेत्र के साथ मेदभाव हुआ है तो मैं कहना चाहूंगा कि केवल पानी के बारे में नहीं बल्कि पिछले मुख्यमंत्री जो बने वे सभी चीजें अपने इलाके में ले गए। तीन तीन यूनिवर्सिटी हिसार में दो फिलोमीटर के एरिया में हैं रोहतक के अंदर मैडिकल कालेज और यूनीवर्सिटी बनी हुई है और आप लोगों के चारों तरफ बढ़िया-बढ़िया इंस्टीच्यूट्स हैं लेकिन जब हम मांग करते हैं, जैसे कल मैंने जब एक सवाल उठाया कि मेरे क्षेत्र में क्या कोई यूनिवर्सिटी का प्रावधान है तो मंत्री जी ने सिम्पल कहा नो नैवर । मंत्री जी नो नैवर कहने से काम नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : आप कौन सी डिमाण्ड पर बोल रहे हैं।

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, मैं शिक्षा पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं यह पूछ रहा हूं कि आप कौन सी डिमाण्ड पर बोल रहे हैं।

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, मैं शिक्षा पर बोल रहा हूं। डिमाण्ड के बारे में बताया नहीं, कि कौन सी पर और कैसे-कैसे बोलना है।

Mr. Speaker : Come to the point. यादव साहब आपने तो एजिटेशन किए हैं यहां तो एजिटेशन न करें, टू दि प्वाईंट बात करें।

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, मंत्री जी ने कहा नो नैवर मेरी हरेक मांग पर नो ही आया है। मैंने सदन में बात की कि हमारे क्षेत्र का विकास करने के लिए वहां पर इण्डस्ट्रीज स्थापित की जाएं। अटेली से 7 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान का क्षेत्र है वहां नीमराणा फस्से को औद्योगिक क्षेत्र डिवैलप किया हुआ है। अगर वित्त मंत्री जी हमारे इलाके को कुछ सबसिडी और दूसरी

[श्री नरेश यादव]

सुविधाएं दे दें तो वहां के व्यापारियों को हम हरियाणा में भी बुला सकते हैं। हमारे इलाके का विकास करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, वहां पर कोई मैडिकल कालेज खोलने का प्रावधान नहीं किया गया है।

Mr. Speaker : Thank you, Yadav Ji, Thank you, very much.

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, मैं कह रहा था कि हमारे एरिया का विकास करने के लिए यूनिवर्सिटी, मैडिकल कालेज, सैनिक स्कूल, भर्ती दफ्तर आदि खोलने के लिए इस बजट में किसी भी चीज का प्रावधान नहीं किया गया है। कल इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर हाउस में मौजूद नहीं थे उनके जवाब परिवहन मंत्री जी दे रहे थे सारे हरियाणा का जिक्र आ गया लेकिन हमारे इलाके के बारे में उन्होंने बताया कि कोई प्रावधान नहीं है लेकिन महेन्द्रगढ़ और रेवाड़ी में कोई फैक्टरी लगाने का प्रावधान नहीं किया गया।

Mr. Speaker: Thank you, very much. Please take your seat. पहले आप एक सैकिण्ड कह रहे थे अब एक मिनट कह रहे हैं, मैडम आनेता जी आप शुरू करें।

श्रीमती अनिता यादव (साल्हावास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व की सरकार में हमारे काबिल वित्त मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने जो बजट पेश किया है सर, मैं उस पर बोलना चाहती थी लेकिन आपने उस समय मुझे समय नहीं दिया। अब बजट अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे समय दिया मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। स्पीकर सर, पिछले चुनाव में तीन दशकों के बाद इनैलो का गढ़ कहे जाने वाले साल्हावास हल्के को जनता ने कांग्रेस की झोली में डाल दिया यह हरियाणा की राजनीति में बदलाव था । लेकिन जनता ने कांग्रेस की नीति में आश लगाये रखी और इस बार एक ऐतिहासिक जीत में साल्हावास ने अपना नाम दर्ज कराया । माननीय स्पीकर महोदय, इनैलो की सरकार ने इस हल्के के साथ बहुत भेदभाव किया तथा जनता ने कांग्रेस को वोट देने के लिए विकास के नाम पर भेदभाव करके लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में चौटाला की सरकार ने तंग किया अब क्षेत्र की जनता भय एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन के मूलमंत्र में अमन तथा चैन की सांस ले रही है। तथा विकास कार्यों की बाट जोह रहे हैं। हमें अपने मुख्यमंत्री महोदय पर विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाला हमारा साल्हावास जो हल्का है जो इनैलो गवर्नमैंट की चपेट में था, पिछली सरकार में इसका बहुत बुरा हाल रहा और विकास कार्य नग्न रहे। अब लगभग 100 दिनों की उपलब्धियां जो कांग्रेस की रही वे बड़ी बेमिसाल हैं, हर वर्ग को राहत देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने की है। वैसे तो इतने थोड़े अर्से में सरकार ने जनता के हित में जो फैसले लिए हैं जिन्हें मैं गिनाऊं तो काफी समय लग जाएगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी सुख की हवा में सांस ले रहा है, खुद को अपने आप में आजाद महसूस कर रहा है। इस गरिमामय सदन में अपने आप को सारी उम्र मुख्यमंत्री और तानाशाह कहने वाले मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को जनता ने ऐसी मार मारी कि वह विपक्ष में बैठने के काबिल ही नहीं रहा। पिछली सरकार ने किसानों पर जो मुकदमें दर्ज किये थे उनको हमारी सरकार ने वापिस लिया है जो कि एक ऐतिहासिक फैसला है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी बधाई

के पात्र हैं। चौटाला के साथ-साथ उनके राज में मौज लेने वाले अलायंस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी थे वे भी राज बनाने की बात कहते थे, वे आज सिमट कर 2 रह गए हैं। वे कहते थे कि SYL पर राजनीति करेंगे और बाद में इस्तीफा दे दिया और आज ये 2 में सिमट कर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस बजट पर मांग करने के लिए खड़ी हुई हूं, मेरे हल्के की जो समस्याएं हैं वे पिछली सरकार के समय से मुंह बाएं खड़ी हुई थीं। हालांकि मेरे से बोलने वाले पूर्व वक्ताओं ने इंडस्ट्री का जिक्र किया, किसी ने हाईवे का जिक्र किया। मेरा साल्हावास विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है इसकी छोटी छोटी डिमांड्स हैं, मैं चाहूंगी कि इस बजट के माध्यम से इन डिमांड्स को पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में खेड़ी नांगल गांव ब्लाक नाहड़ तहसील कोसली जिला रिवाड़ी में कस्टोडियन की जमीन शामलात देह बंजर भूमि है। पंजाब सरकार ने 1962 में 110 प्लाट डेढ़ किला प्रति परिवार गरीब हरिजन भाइयों को दिए थे। यह जमीन उस समय बड़ी उबड़ खाबड़ थी उन सभी हरिजन भाइयों ने इस जमीन पर मजदूरी करके 6-7 सालों में इसको समतल किया था और बोने के काबिल किया था, इसमें हरिजन भाइयों ने 5 ट्यूबवैल भी लगाए थे लेकिन खारा पानी होने की वजह से वह जमीन कलर बन गई और वहां के पटवारी जो थे उन्होंने इस जमीन को कहीं रिकार्ड में नहीं दिखाया। अब तहसीलदार बार बार इस जमीन की नीलामी करके इन गरीब लोगों को, हरिजन भाइयों को तंग कर रहे हैं। मैं हरिजन भाइयों का नाम बार बार इसलिए ले रही हूं क्योंकि खेड़ी नांगल गांव पूर्णतया हरिजन भाइयों का है। वह हरिजन भाई इस जमीन को नीलामी में तो नहीं ले सकते थे। 1962 में सरकार ने इस जमीन को 886 रुपये एक एकड़ के भरवाने के लिए बोला था लेकिन वह रुपया आज भी सैन्ट्रल बैंक झज्जर में जमा है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी गरीबों और किसानों के हित की बात करने वाली पार्टी है। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र के इस गांव के गरीब हरिजनों को 1962-63 की कीमत के रेट रखकर आसान किस्तों पर वह जमीन दी जाये। ताकि उनका आशियाना बना रह जाये। मेरा एक बार फिर से अनुरोध है कि सरकार कम से कम पैसा भरवाकर उनको यह जमीन दे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा की बात है मेरे हल्के में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो अपग्रेडेशन के सभी नार्म्ज पूरे करते हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन के नार्म पूरे करने के लिए अपनी जमीन भी स्कूलों को दी है। लीलोड़ गांव के स्कूल को दसवीं से अपग्रेड करके जमा दो का बनाना है। अध्यक्ष महोदय, यह बड़े गजब की बात है कि आज तक हरियाणा में स्कूल अपग्रेड होते आये हैं लेकिन पिछली सरकार ने मेरे हल्के के गांव बहू का स्कूल जो 1962 से जमा दो का था उसको डिग्रेड करके दसवीं तक कर दिया। क्यों किया यह तो पिछली सरकार ही जानती है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि यह स्कूल अपग्रेडेशन के सभी नार्म्ज पूरे करता है इसलिए इसको दोबारा से जमा दो तक बनाया जाये। इसके अतिरिक्त कानड़वास के स्कूल को आठवीं से अपग्रेड करके दसवीं तक, बध्वा गांव भी काफी बड़ा गांव है और इसके आसपास 50 गांव लगते हैं। इन गांवों के लोगों ने पिछली सरकार के समय में एक प्रस्ताव पास करके दिया था कि बध्वा गांव में कन्या महाविद्यालय या को-महाविद्यालय बनाया जाये। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां के लोगों की यह डिमांड सरकार मान ले और बध्वा गांव में महाविद्यालय बनवाया जाये। इसके अतिरिक्त कोहला गांव में आठवीं से अपगेरड करके दसवीं तक, सुनारैटी गांव में पांचवीं से 8वीं तक स्कूल अपग्रेड किये जायें। पिछले अधिवेशन में सरकार ने कहा था कि जो स्कूल पांचवीं कक्षा तक हैं वे एटोमैटीकली आठवीं कक्षा तक अपग्रेड हो जायेंगे। इसलिए सुनारैटी गांव का स्कूल आठवीं तक अपग्रेड किया जाये।

Mr. Speaker : Anita Ji, you have already taken 15 minutes. 20% Members are still to speak and time of the House will be over on 6.30 p.m. So, please take your seat.

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं एक गजब की बात और बताना चाहती हूं कि श्रीमती बाला देवी पत्नी गोपीराम, गांव-भाला, तहसील कौसली, जिला रेवाड़ी की रहने वाली है। यह औरत सिविल होस्पिटल नारनौल में गाल ब्लेडर की पथरी का आपरेशन करवाने गई थी लेकिन पता नहीं डाक्टर बृजलाल गुप्ता जिसने यह आपरेशन किया कहां सो रहा था उसने इस औरत का यूट्रस ही निकाल दिया। इस औरत की ऊमर भी अधिक नहीं है। अब वह मातृत्व से वंचित हो गई है। मैं चाहती हूं कि उस डाक्टर के खिलाफ इन्कवायरी हो और उस औरत को न्याय मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं नगरपालिका की बात करना चाहूंगी। मैं सब डिविजन कौसली में रहती हूं और कौसली सब डिवीजन में नगर पालिका नहीं है इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि कृपा करके कौसली को नगर पालिका बनाया जाये। इसके अतिरिक्त कौसली में सब्जी मण्डी बनाने के लिए पैसा आया हुआ है इसलिए वहां पर बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन के बीच जल्दी से सब्जी मण्डी बनवाई जाये।

Mr. Speaker : Thank you, Anita ji, please take your seat. अब महेन्द्र प्रताप सिंह जी बोलेंगे। महेन्द्र प्रताप जी, आप टाईम का ख्याल रखें। (विघ्न) बोलने वाले बहुत से मैम्बर हैं। (विघ्न) I will definitely give you time, I assure you Mr. Nirmal Singh (विघ्न) every body will get time. I will extend the house, You will get the time. (विघ्न) पुरानी सारी बातें बदल जाएंगी। (विघ्न) आपका जब नम्बर आएगा तो आपको भी टाईम मिलेगा। जो मैम्बर पहले बोल चुके हैं उनको टाईम नहीं मिलेगा। (विघ्न)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार बनने के बाद वित्त मन्त्री जी ने पहली बार बजट पेश किया है और उस पर पिछले दो दिन से चर्चा हो रही है। हमारे महानुभाव साथियों ने बजट की सामान्य तौर पर काफी विस्तार से चर्चा की है और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिये हैं। डाक्टर साहब और डांगी जी ने तो पिछली सरकार का पोस्ट मार्टम भी काफी अच्छे ढंग से किया है उसपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सामान्य बजट पर हमें चर्चा करने का समय नहीं मिला लेकिन डिमाण्डज पर बोलते हुए अगर मैं थोड़ा सा समय बजट पर बोलने के लिए ले लूं तो मेरे ख्याल से आप मुझे माफ करेंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पिछले बजट की अगर हम तुलना करें तो पिछले बजट ने हर साल 2,4,5,10 फीसदी की जो योजनागत व्यय है उसमें इससे ज्यादा का इजाफा नहीं हुआ है। अगर इस इजाफे को इन्फलेशन के अनुसार देखें तो मैं समझता हूं कि वह बढ़ौतरी न के बराबर है। माननीय मुख्य मन्त्री जी की रहनुमाई में वित्त मन्त्री जी ने यह पहला बजट पेश करने की कोशिश की है। इस बजट को संतुलित और विकासशील बजट की संज्ञा दी जाए तो मैं समझता हूं कि वह गलत नहीं होगा। 34% योजनागत व्यय में बढ़ौतरी करके वित्त मन्त्री जी ने सूझ-बूझ का परिचय दिया है। हर क्षेत्र में हर मद में सन्तुलित ढंग से उसको फालतू पैसा देने की कोशिश की है जिससे जो पिछली सरकार के राज के दौरान सत्ता का दुरूपयोग हुआ है और सन्तुलित विकास नहीं हो सका है उसको पटरी पर लाने के लिए एक प्रयास किया है मैं समझता हूं कि उन्होंने यह एक सराहनीय कदम उठाया है जिसके लिए वे एक बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार

के दौरान जैसे कि माननीय साथियों ने जिक्र किया उसको कहने की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि भय और निराशा का वातावरण तो प्रदेश में रहा है और जनता का उत्पीड़न भी हुआ है। उन सबका क्या नतीजा हुआ उसको मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने कांग्रेस की नीतियों में और सोनिया जी के ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास के तौर पर इतना प्रचण्ड बहुमत कांग्रेस पार्टी को दिया। मेरे ख्याल में आज तक इतना अधिक बहुमत कांग्रेस को पहली बार मिला है। सन् 1991 में कांग्रेस पार्टी को 51 सीटें मिली थीं और अब की बार 68 सीटें मिली हैं जो उसी का नतीजा है उस विश्वास और साख का नतीजा है। उसके बाद माननीय मुख्यमन्त्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने एक सरकार दी। उन्होंने जनापेक्षा, जनभावना, सम्मान और विकास की दृष्टि से पारदर्शी फैसले लेकर जनता को एक मैसेज दिया है कि कांग्रेस सरकार वाकई में पापूलर सरकार है। उसका जन भावना और जन विकास के अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। उनके बारे में मैं जिक्र डिमाण्ड पर बोलने से पहले करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं एस०एस० बोर्ड के बारे में कहना चाहूंगा उसके बारे में जनता में बहुत चर्चा होने लग गई थी और अखबारों में भी उसकी काफी चर्चा होने लग गई थी, उस बोर्ड पर उंगलियां उठने लग गई थीं। इस सरकार ने सत्ता में आते ही उस संस्था को सबसे पहले भंग करने का काम किया। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक भी था। जो संस्था जनता का विकास नहीं कर रही थी तो ऐसी संस्था को भंग करके मुख्यमंत्री जी ने हिम्मत का काम किया है।

स्पीकर सर, इसके बाद मैं लाटरी के बारे में कहना चाहूंगा। पहले की सरकार में हो सकता है यह उसकी आमदनी का साधन हो और इसलिए उन्होंने इसको बंद नहीं किया था। वित्तमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने आते ही इसको भी बंद करने का काम किया है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि लाटरी से स्टेट को जो पैसा आता है वह दूसरी किस जगह से लाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि स्टेट के नौजवानों के चरित्र को सुधारने के लिए इस लाटरी को बंद करके हरियाणा की जनता पर उपकार किया है। तीसरे किसानों के ऊपर जो झूठे मुकदमें पिछली सरकार के वक्त में दायर किए गए थे उन सभी मुकदमों को तुरन्त मुख्यमंत्री जी ने वापिस लिया है और ऐसा करके इस सरकार ने किसानों की भावनाओं की कदर की है।

इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के लिए पिछली सरकार की तरफ से किसानों को बहुत ही कम मुआवजा दिया जाता था। हमारी सरकार ने आते ही उस मुआवजे में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। ऐसा करके मुख्यमंत्री जी ने किसानों को एक सम्मान दिया है और उनको आर्थिक दृष्टिकोण से सम्भालने की कोशिश की है।

स्पीकर सर, इसके अलावा मैं सदन में आपके माध्यम से गुड़गांव और फरीदाबाद का भी जिक्र करना चाहूंगा। ये दोनों क्षेत्रों में इन्डस्ट्री होने के नाते और दिल्ली के नजदीक होने के नाते यहां पर किसानों को बहुत ही भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर उनकी जमीन से रिलेटिड कोई मुकदमा होता है तो उनको सालों सालों तक कोर्ट में लड़ना पड़ता था। अब इस सरकार ने गुड़गांव में किसानों को 15 लाख रुपए कीमत प्रति एकड़ के हिसाब से दी है और इसमें दूसरी चीजें मिलाएं तो यह तकरीबन 22 या 23 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से रेट पड़ता है और इसके विपरीत फरीदाबाद में यह रेट साढ़े 12 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया है। ऐसा करके सरकार ने उन किसानों के साथ न्याय किया है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि फरीदाबाद में जो प्राईवेट डीलर्ज हैं वे एक एक किले का

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

50-50, 70-70 लाख रुपए के हिसाब से खरीदते हैं और कई बार तो यह अमाउन्ट एक करोड़ रुपए तक भी पहुंच जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार ने फरीदाबाद में और गुड़गांव में जो फर्क रखा है उसको बराबर करना चाहिए और फरीदाबाद में भी साढ़े बारह लाख प्रति एकड़ की बजाय 15 लाख रुपए प्रति एकड़ कर देना चाहिए। स्पीकर सर, दोनों जगहों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों के विवाह पर 5100 रुपए की बजाय 15,000 रुपए की राशि देने की योजना शुरू की है जिसे इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना कहा जाएगा। चाहे वह गरीब आदमी की लड़की हो या चाहे हरिजन या बैकवर्ड क्लासिज की लड़की हो इससे लिंगानुपात की समस्या पर भी कंट्रोल होगा लेकिन इसके पीछे जो मुख्य भावना सरकार की रही वह यह थी कि जहां पहले इन लोगों की लड़की की शादी के लिए 5100 रुपये दिए जाते थे वहीं अब इसको बढ़ाया गया है। हालांकि यह बात सही है कि गरीब आदमी के लिए इतनी राशि क्या मायने रखती है क्योंकि शादी के लिए कम से कम दस बीस हजार रुपये तो गरीब से गरीब लोगों के भी खर्च हो जाते हैं। सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा है, उनके सम्मान का ख्याल रखा है इसलिए इसको बढ़ाया गया है। निस्संदेह सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांडज पर बोलना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बिजली के बारे में बात करना चाहूंगा। बिजली आज हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति है कि कोई भी व्यक्ति आज बिजली के बिना दस मिनट भी नहीं रह सकता । अगर कृषि और इंडस्ट्रियल विकास समाज के उत्थान की, विकास की धूरी है तो बिजली को अगर हम उसकी आत्मा कहें तो गलत नहीं होगा। इंडस्ट्रीज भी बिजली पर आधारित है और कृषि भी बिजली पर आधारित है। अध्यक्ष महोदय, आज की सबसे बड़ी समस्या जहां लाईन लौसिज है वहीं इसके साथ ही चोरी भी एक मुख्य समस्या है। हमारे पास डिमांड और जैनरेशन दोनों में एक गैप है। जैनरेशन की अगर कमी है तो हमें सबसे पहले गैस बेस्ड या पन बिजली योजनाओं की तरफ ध्यान देना होगा क्योंकि यह बिजली सस्ती पड़ेगी । मैं बल्लभगढ़ गैस प्लांट का जिक्र करना चाहूंगा। हमारे पास बिजली है। वहां पर प्रथम चरण में जो यूनिट लगाई थी वह 400 मेगावाट की थी। एन०टी०पी०सी० वहां बिजली का उत्पादन करती है। मेरे ख्याल में उसकी क्षमता 90 परसैंट तक है लेकिन वहां के लोग कहते है कि हमारे पास और क्षमता इसकी है लेकिन हमसे बिजली लेने वाले तो हों। अध्यक्ष महोदय, हम बिजली क्यों नहीं ले पाते यह तो एक टैक्नीकल मामला है इसलिए शायद मुख्यमंत्री जी या बिजली मंत्री जी इस बारे में ज्यादा जानते होंगे। हमारे पास ज्यादा बिजली संभालने के लिए सब स्टेशन नहीं है अगर हम बिजली की पुरानी लम्बी तारों पर ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि हम ज्यादा अच्छे तरीके से बिजली की जैनरेशन का उपयोग कर सकेंगे। हमें दोनों तरफ देखना होगा। कृषि की उपज अब आखिरी प्वायंट पर है और इंडस्ट्रीज लगातार बढ़ रही है तो इसके लिए बिजली की भी ज्यादा आवश्यकता है। हमें दूरगामी नीति के बारे में सोचना होगा। जैनरेशन और सप्लाई के बारे में हमें दूर दृष्टि के साथ विचार करना होगा। चूंकि फाईनेंस की भी इन्वाल्वमैंट इसमें है इसलिए प्राईवेट कम्पनीज को या एन०आई०आर० को या इंडस्ट्रियलिस्टस को इसमें शामिल करना पड़ेगा। हमें उनसे बात करनी पड़ेगी कि अगर वे कोई अपना प्लांट लगाना चाहें तो हमें काफी नरम शर्तों पर उनको इजाजत देनी होगी जिससे आने वाले वक्त के लिए इस समस्या से निजात मिल सके।

Mr. Speaker: Thank you very much. Do not take more time.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट और लूंगा। मेरे हल्के की समस्याएं रह गयी हैं। अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। किसी समाज के उत्थान के लिए, एक शिक्षित व्यक्ति के पुरुषार्थ के लिए लक्ष्य आवश्यक है। शिक्षा के बारे में मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आते ही इस बारे में एक नया कन्सैप्ट देने की कोशिश की है। जब तक हम प्रदेश में अपने नौजवानों को गुणवत्ता के तौर पर शिक्षा नहीं देंगे तब तक हम पिछड़ते ही रहेंगे। यह अच्छी बात है कि राजीव गांधी के नाम से एक एजूकेशन सिटी स्थापित करने की बात हो रही है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी सोचना पड़ेगा जैसे वित्त मंत्री जी ने मॉडल स्कूल खोलने की बात कही है। नयी पौध को तैयार करना तथा उनको उच्च शिक्षा देना अच्छी बात है लेकिन एक मॉडल स्कूल खोलना मैं समझता हूं नाकाफी है। हमें इसके लिए एजूकेशन इंफ्रास्टक्चर को मजबूत करना होगा। जब तक एजुकेशन को हम इकौनामी ओरिएन्टेड एजूकेशन नहीं बनाएंगे तब तक हम इसमें पिछड़ते चले जाएंगे, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट पढ़ी है उसमें जो नवीं पंचवर्षीय योजना शायद वह 2002 तक की है उसमें उन्होंने लिखा है कि 5 जिलों में ढाई हजार स्कूलों का टैस्ट चैक किया गया उसमें 225 से 250 स्कूल्स देहातों में ऐसे हैं जहां पर कमरे नहीं हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है 1500 और 650 के बीच में स्कूल ऐसे हैं जहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है शौचालय का प्रबन्ध नहीं है जब तक हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर ही इतना कमजोर होगा तो हमारे स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चे तैयार नहीं होंगे।

Mr. Speaker : Thank you very much, please take your seat.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। हमारे यहां तकरीबन 8-9 कालेजिज हैं। होडल से लेकर पलवल और फरीदाबाद तक दो गवर्नमैंट कालेज हैं। गवर्नमैंट कालेज में इस साल एम०ए० की क्लासिज बंद की जा रही हैं। फर्स्ट ईयर के ऐडमिशन नहीं किए गए हैं । एक तरफ तो हम उच्च शिक्षा और गुणवत्ता की कल्पना करते हैं और दूसरी तरफ फरीदाबाद जिला जो आबादी के हिसाब से बड़ा है। औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां कालेजिज हैं वहां एम०ए० की क्लासिज के ऐडमीशन किए जा रहे हैं, वहां ला कालेज नहीं हैं मेरा मुख्यमंत्री जी से यह भी अनुरोध है कि वहां लॉ कालेज की भी व्यवस्था की जाए।

Mr. Speaker : I will be very glad to hear you but the time is very short.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : मैं सिर्फ अपने हल्के की 2-4 बात कहकर अपना स्थान लेता हूं। हैल्थ के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि हैल्थ का ढांचा हमारे प्रदेश में देश के और प्रदेशों से अच्छा है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा फरीदाबाद जिला होने के बावजूद एक ही गवर्नमैंट हास्पीटल वहां पर है और वहां भी आई०सी०यू० की सुविधा नहीं है और वहां कैट स्कैनिंग और एम०आर०आई० की सुविधा भी नहीं है। वहां बिल्डिंग की हालत यह है कि प्रथम फेज की बिल्डिंग बहुत पहले बन चुकी है, दो फेज में और बननी है, वह अब तक नहीं बन पाई, बहन जी उसकी तरफ भी ध्यान दें।

Mr. Speaker : Thank you very much. Udai Bhan Ji please start.

श्री उदय भान (एस०सी०, हसनपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, चाहे दो तीन दिन के प्रयास के बाद दिया। मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार को कि उन्होंने जो हरियाणा में भय, आतंक और भ्रष्टाचार का माहौल था और अघोषित इमरजैंसी थी, उसको उन्होंने दूर किया है। हरियाणा की जनता ने उन्हें बागडौर सौंपी तो उन्होंने कई सराहनीय निर्णय लिये। सरकार बनने के बाद चाहे वह लॉटरी बंद करने की बात है, चाहे किसानों पर देशद्रोह के मुकदमें जो लगे थे वह वापस लेने की बात है और भी कई कल्याणकारी वायदे पूरे किए हैं। उसके लिए हमारी सरकार बहुत ही सराहना की पात्र है। उद्योग नीति जो घोषित की है वह बहुत ही सराहनीय है। उसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब बजट पर हुई चर्चा के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी रिप्लाई दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि बैक लॉग के बारे में किसी भी सदस्य ने कोई बात नहीं कही। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में उनको बताना चाहता हूं कि केवल इनेलो के एक एस०सी० मैम्बर को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के और इन्डिपैंडेंट सदस्य जो एस०सी० कैटेगरी के हैं उनको आपने बोलने का समय ही नहीं दिया। इसी लिए एस०सी० और बी०सी० से संबंधित जो समस्या है उनके बारे में कोई बात नहीं हो सकी। मैं सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह कहा कि हम जल्दी ही बैकलॉग को पूरा करेंगे उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस भावना के साथ उन्होंने यह बात कही है वे शीघ्र समयबद्ध और कारगर कदम उठाकर इस बैक लॉग को शीघ्र पूरा करेंगे। इस संबंध में मैं हमारी पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में जो घोषणाएं की थी उनका थोड़ा उल्लेख करना चाहूंगा। श्री चौटाला के निरंकुश शासन में प्रदेश का कमजोर तबका खासकर महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही थी। महिला तबका सुरक्षित महसूस करे इसके लिए प्रयास किया जायेगा। भूमिहीन अनुसूचित जाति के परिवारों में फालतू जमीन बांटने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे। अन्य कमजोर तबकों को जमीन दी जायेगी, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों और कमजोर तबकों को आवासीय प्लाट उपलब्ध किये जायेंगे। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सरकारी नौकरी में लम्बित कोटे को निश्चित समय-सीमा के अन्दर निपटाया जायेगा। आरक्षण नीति को पूरी भावना के साथ लागू किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं सरकार का कि बहुत अच्छी भावना के साथ इस कार्य को लिया गया है। जिस तरह से सरकार ने निर्णय लिया है चाहे वह बी०पी०एल० हो उसका दोबारा से सर्वे किया जायेगा और बैक लॉग को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाये जायेंगे। इस बारे में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने जनवरी 2002 में 85वां संविधान संशोधन पास किया था और 21 जनवरी 2002 को सभी प्रदेश सरकारों को और चीफ सेक्रेटरीज को पत्र लिखा था कि इस 85वें संविधान संशोधन को जिसमें क्लास-1 और क्लास-2 के प्रोमोशन में भी रिजर्वेशन का प्रावधान है और उसको एक संवैधानिक दृष्टि से लागू किया जायेगा। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंज दी हैं सभी राज्यों को शामिल करके उसमें यह कहा गया था कि यह 6 महीने के अन्दर-अन्दर सभी राज्य सरकारें लागू करें। लगभग 18 प्रदेश सरकारें इसको लागू कर चुकी हैं। हमारी सैंटर गवर्नमैंट लागू कर चुकी है, दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकारें लागू कर चुकी हैं और हमारे साथ लगती सभी राज्य सरकारें लागू कर चुकी हैं लेकिन हरियाणा प्रदेश में इसको लागू करने में चौटाला साहब की सरकार की नीयत नहीं थी तो अब मैं यह उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार गरीब,

तबके, मजदूर तबके और पिछड़े तबके ने सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा की है उस पर विचार करते हुए 85वां संविधान संशोधन शीघ्र अति शीघ्र लागू करें। इसको रोकने के लिए और गुमराह करने के लिए कई प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं कि यह मामला अदालतों में विचाराधीन है। परन्तु जब तक अदालत से स्टे नहीं मिल जाता तब तक सरकार का कोई केस रुकता नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाये। जिस तरह से हमने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया है, मैं मुख्यमंत्री महोदय जी का आज आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने घोषणा की है कि जो भूमिहीन दलित हैं चाहे वे गांव में बसते हैं या शहर में बसते हैं, BPL में आते हैं उन सभी को 100-100 गज के आवासीय प्लाट आवंटित किए जाएं। जहां पर जिस गांव की पंचायत की जमीन नहीं है, नगरपालिका की जमीन नहीं है वहां जमीन एक्वायर करके उनको 100-100 गज के प्लाट दिए जाएं। अध्यक्ष महोदय, शौचालयों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी। किसी गांव में शौचालयों की व्यवस्था नहीं थी लोगों को दिक्कत होती थी और खास तौर से दलित महिलाओं को दिक्कत होती थी। आज सरकार ने और मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंस किया है कि सभी गांवों में शौचालय बनाए जाएंगे जो कि सराहनीय काम है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करूंगा। मैं एक उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि BPL का दोबारा से सर्वे किया जाए क्योंकि उसमें अनियमितताएं हैं, वृद्धावस्था पैंशन के लिए भी दोबारा से सर्वे कराया जाए उसमें भी काफी अनियमितताएं है। टैक्नीकल एजूकेशन के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। इंजीनियरिंग कालेज और पोलीटैक्निक कालेज और जो दूसरे प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज हैं उनका कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी में और हिसार यूनीवर्सिटी में एडमिशन के लिए जब कामन टैस्ट होता है, तो प्राइवेट कालेज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता जबकि सारा काम गवर्नमैंट के शू होता है। पहले यह रिजर्वेशन दिया जाता था, चौटाला के टाईम में यह बन्द हो गया, इसलिए इसका रिव्यू करके उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के बारे में बोलना चाहूंगा। फरीदाबाद में समान पानी के बंटवारे की बात की गई यह बहुत अच्छी बात है। इससे दूसरे महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, झज्जर, रोहतक और सोनीपत इन जिलों को लाभ होगा लेकिन जो हमारे फरीदाबाद और गुड़गांव के साथ बेइन्साफी हो रही है उस तरफ भी मैं अपने सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। गुड़गांव और फरीदाबाद में इरीगेशन के लिए जो पानी आता है वह आगरा और गुड़गांव कैनाल के जरिए आता है। पहले दिल्ली को पानी 200 क्यूसिक दिया जाता था उसकी एवेज में हरियाणा सरकार दिल्ली से पैसा लेती थी लेकिन वह पानी अब बढ़कर 200 क्यूसिक से 800 क्यूसिक कर दिया गया है। 400 क्यूसिक वजीराबाद ट्रीटमैंट प्लांट में जा रहा है और 400 क्यूसिक हैदरपुर ट्रीटमैंट प्लांट में जा रहा है। जो 200 क्यूसिक से 800 क्यूसिक पानी दिल्ली को दिया गया है, दिल्ली को पानी पूरा देकर हमारा पानी काट लिया गया है। हमारे जो रजबाहे हैं हसनपुर, होडल, हथीन और पलवल के जहां 250-250 क्यूसिक पानी चलता था और आज 50-50 या 60-60 क्यूसिक पानी चल रहा है। किसी रजबाहे में टेल तक पानी जाने का प्रश्न ही नहीं होता। हमारा पानी अगर दिल्ली को देना है तो पीछे से WJC से पानी ले आओ, दिल्ली सब ब्रांच के खुबरों हैड से जो पानी आ रहा है उसमें आप सरप्लस पानी लेकर आओ, हमारा पानी क्यों काटा जा रहा है। हमारे फरीदाबाद और गुड़गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। फरीदाबाद में जो पानी आ रहा है वह पूरी तरह से प्रदूषित है और इतना प्रदूषित है कि पीने का पानी अगर आप कहीं भी टैस्ट करा लें तो पीने के लायक नहीं है, पूरी फसलों के लिए हानिकारक है। आम आदमी के लिए और पशुओं के लिए पीने के मतलब का पानी नहीं है।

Mr. Speaker : Udai Bhan Ji, please wind up. I am to accommodate many members. Everything is important.

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, 22 गन्दे नाले यमुना में जाते हैं, 22 में से 3 में ट्रीटमैंट प्लांट लगे हुए हैं। मेरी मांग है कि एक पब्लिक लिटिगेशन दायर करवाई जाये, सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से जिससे दिल्ली सरकार को कोर्ट से इस बात के लिए बाउंड हो कि वह पानी ट्रीट करके डालेंगे, उनके यहां ट्रीटमैंट प्लांट लगे हुए हैं। जिससे स्वच्छ पानी हमें मिलेगा। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद जिले में जो चिंता का विषय है वह बाढ़ का है। क्योंकि यू०पी० सरकार की तरफ से 28 कि०मी० लम्बा केवल टेप्पल मार्जिनल नाम का बांध 97 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है जो 12 कि०मी० बन चुका है और 16 कि०मी० बकाया है जो जल्दी ही बन जायेगा। इसके आसपास मेरे हल्के के गांव, बल्लबगढ़ हल्के के गांव, पलवल हल्के के गांव और कुछ गांव मेवलामहाराजपुर हल्के के भी लगते हैं उन गांवों में 20 गांव ऐसे हैं जो इसी बरसात में उजड़ सकते हैं। जो हमारे छोटे रिंग बांध हैं उनसे वह बांध 20 से 25 फीट ऊंचा है और 20 फिट चौड़ा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह बहुत मज़बूत बांध है। जो यमुना की क्षमता है वह 70 हजार क्यूसिक है और बरसात के दिनों में 1.50 से 2.50 लाख क्यूसिक पानी यमुना में ताजेवाला हैड वर्क्स से छोड़ा जाता है। वह पानी आगे नहीं जायेगा क्योंकि आगे उत्तर प्रदेश में बांध बना हुआ है तो वहां आसपास के गांवों में उस पानी से तबाही होगी। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उदयभान जी, आप बैठिये। अब श्री निर्मल सिंह जी बोलेंगे।

श्री निर्मल सिंह (नग्गल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इरीगेशन पर चर्चा करना चाहूंगा। पिछले तीन दिनों से इरीगेशन पर काफी चर्चा हुई है और नहरों के पानी के बंटवारे के बारे में विशेष तौर से चर्चा हुई है। कई सदस्यों ने उस पर चिंता भी जताई । कैप्टन साहब ने सदन में यह बात मानी है कि पहले पानी के बंटवारे में नाइन्साफी हुई है। लेकिन कैप्टन साहब ने जब जिलों का नाम गिनवाया उस समय ये अंबाला का नाम भूल गये । अध्यक्ष महोदय, नग्गल लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम आपके समय की बनाई हुई है। उसकी कैपेसिटी 165 क्यूसिक पानी की है और 65 क्यूसिक पानी उसमें इस महीने और उससे पिछले महीने से लिफ्ट किया गया है तथा पिछले 5-7 साल से इस नहर में 65 क्यूसिक पानी ही आता है। यानि अंबाला का नहरी पानी में 65 क्यूसिक हिस्सा ही है क्योंकि अंबाला में इसी नहर से पानी आता है। बहुत सी नदियां-नाले और नहरें अंबाला से होकर गुजरती हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश ने पानी के समान बंटवारे के लिए संघर्ष किया है कि पानी के बंटवारे में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि आज उन्होंने जो पानी उपलब्ध है उसकी समान बंटवारे की बात कही है। मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी इस नहर की पानी की कैपेसिटी बढ़ाई जाये ताकि हमें भी अपने हिस्से का पूरा पानी मिले। इसके अतिरिक्त हमारे यहां एक लिफ्ट इरीगेशन स्कीम मंजूर हो चुकी है उस पर पिछले पांच साल से अर्थ वर्क हो चुका है लेकिन वह अब तक अधूरी पड़ी हुई है। उसे भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाये। दादूपुर नलवी नहर को बनाने के लिए बजट में पैसे का प्रावधान हो गया है। इस नहर को बनवाने के लिए बहुत समय से लोग मांग कर रहे थे। अब हमें आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस नहर को बनवा देंगे। इस बारे में मेरी मुख्यमंत्री जी से एक प्रार्थना है मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री जी को मीटिंग में भी सुझाव दिया था कि इस नहर को थोड़ा और लम्बा

किया जाये ताकि मेरे हल्के के लोग भी इसका लाभ उठा सकें। यह नहर टांगरी नदी को छूती है और उसके नीचे से निकलेगी । इस नहर का मेन मकसद यही है कि ग्राउंड वाटर के लैवल को ठीक रखा जाये। इलाके का वाटर लैवल बहुत नीचे तक जा गिरा है उसको बढ़ाया जाए तथा उस नहर को जल्दी बनाया जाए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि हमारे साथी अभी बता रहे थे कि बरसात के मौसम में यमुना से पानी बह कर वैसे ही चला जाता है। बादशपुर नलवी भी बरसाती नहर है और उसी से ही नारायणगढ़ तक रेनी सीजन के लिए कोई नहर निकाली जाए ताकि हमारा वाटर लैवल कुछ ऊपर आ सके। स्पीकर सर, जैसे कि हमारा अन्दाजा था कि 20-30 साल के बाद ड्रिंकिंग वाटर के लिए लोग यहां पर लड़ेंगे तो वैसी ही स्थिति अब हो रही है। आज वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है और 400 फुट से कम नीचे पीने का पानी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप एक भी ऐसी जगह नहीं दिखा सकेंगे जहां 400 फुट से कम गहराई पर लोग पानी न पी रहे हों और यही नहीं आप देखें कि 1100-1100 फुट की गहराई पर ट्यूबवैल लग रहे हैं। हमारे यहां बबियाल में एक ट्यूबवैल में 1100 फुट की दूरी पर पानी मिला है। यह सम्भव नहीं है कि लोग 1100 फुट नीचे से पानी निकाल कर पीयें और उस पानी से सिंचाई का काम भी चलायें। यह जो खतरे की घण्टी 25-30 साल के बाद बजनी थी वह खतरे की घण्टी अब बज चुकी है। इन गर्मियों में जब हम लोगों ने इन इलाकों का दौरा किया तो हमें यह लगा कि लोगों को पीने के पानी के लिए लड़ना पड़ेगा और लोग पीने के पानी के लिए झगड़ना शुरू हो जाएंगे। आज सरकार को इस बात के लिए चौकन्ना हो जाना चाहिए। अम्बाला में नैक्सिनन कैनाल बेसड वाटर सप्लाई स्कीम का पानी देना पड़ेगा इसलिए सरकार को अभी से इसकी कोशिश करनी चाहिए। अम्बाला कैंट में 15 करोड़ रुपये की परियोजना नहरी पानी की दी जा रही है। अम्बाला सिटी में थोड़ा सा पानी नहरी मिलता है। इसी तरह से नारायणगढ़, शाहजादपुर, बोह, बबियाल जैसे ऐसे बड़े कस्बे हैं जहां पर हमें कैनाल बेसड पानी देना चाहिए। अल्टीमेटली सभी गांवों में कैनाल बेस्ड पानी के साथ ही हमारा काम चलेगा क्योंकि हमारा वाटर लैवल बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता जा रहा है। इसके इलावा पानी के बंटवारे की बात है। स्पीकर सर, कैप्टन साहब ने पहली बार इस बात को माना है कि अम्बाला के साथ पानी के बंटवारे में नाइन्साफी हुई है। हमारे पास पानी का हिसाब ही नहीं । 65 क्यूसिक पानी आज हम ले रहे हैं और आज पानी के लिए इतना शोर है। हर बात का समान विभाजन होना चाहिए। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ बिजली की समस्या है। कई साथियों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जो गांवों में छतों के ऊपर से तारें जा रही हैं उनसे भयंकर हादसा कभी भी हो सकता है और इसमें इफस एण्ड बटस न लगा कर सरकार को इस बारे में ठोस फैसला कर लेना चाहिए कि हम यह सारी दिक्कत रिमूव करेंगे। जहां पर भी छत के ऊपर से तार निकलती है उसको हटाना सरकार की जिम्मेदारी है पूरे हरियाणा के बारे में सरकार को इस प्रकार का निर्णय ले लेना चाहिए। इसके साथ ही हमारी जो डोमैस्टिक बिजली की सप्लाई है उसको भी अलग से करना चाहिए। जैसे अभी पिछले दिनों गांवों में दोपहर को बिजली नहीं थी, रात को बिजली के कद्दू थे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कई जगह से इस प्रकार की शिकायतें मिली कि शहरों में रात को बत्ती जल रही है और गांव में बिजली नहीं है। जब हम इस बारे में अफसरों से पूछते थे तो हमें बताया जाता था कि वह शिड्यूल ऐसा है । स्पीकर सर, अब ऐसा चलने वाला नहीं है इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें समान बिजली सब को देनी है। अब डोमैस्टिक बिजली के बिना भी काम चलने वाला नहीं है। (इस समय चेयरपर्सन्ज की सूचि में से एक माननीय सदस्य श्री रघुबीर सिंह कादियान पदासीन हुए) हैल्थ के

[श्री निर्मल सिंह]

बारे में मैं माननीय हैल्थ मिनिस्टर बहिन करतार देवी जी से कहना चाहता हूं । इस समय वे यहां पर बैठी हुई हैं इसलिए उनसे यह आश्वासन दिलवा दें। सभापति महोदय, आपने तो यह सारा इलाका देखा हुआ है। बबियाल कितना बड़ा गांव है आज वहां पर 24 हजार की आबादी है और साथ में दस हजार की आबादी दिलीपगढ़ में है। बोह में 20 हजार की आबादी है इन तीनों गावों में कोई भी डॉक्टर नहीं है और न वहां पर कोई डिस्पैंसरी या छोटा अस्पताल ही है। आज वहां पर इस बात की जरूरत है कि इन तीनों गांवों में बबियाल में खासकर छोटा होस्पीटल बनाया जाए। वहां पर कम से कम एक डॉक्टर का प्रावधान हो और भविष्य में इस बात का भी ख्याल रखना है कि देहात बहुत गन्दे हो चुके हैं और वे बढ़ भी रहे हैं। इसलिए जो भी विकास का कार्य किया जाए वह किसी प्लानिंग के साथ होना चाहिए। सभापति महोदय, मुझे इस बात की आशंका है कि 20-30 साल के बाद ये सभी चीजें उखाड़ कर दोबारा बनानी पड़ेंगी चाहे वह गांव हो और चाहे वह शहर हो। मैं आशा करता हूं कि बहिन जी हमें इस बात का आश्वासन देंगी कि बबियाल में एक डिस्पैंसरी बनाई जाएगी। सभापति सर, एग्रीकल्चर सैक्टर में किसानों को इन्सैंटिव देने की जरूरत है। सभापति सर, लकड़ी की खेती का, बागवानी, फिशरिंग और गोट पालने का काम है, लोगों को उस तरफ ले जाना चाहिए । सरकार उस बारे में अच्छे तरीके खोजे जिससे किसान गेहूं और जीरी की फसल को छोड़ कर उन कामों की तरफ ध्यान दे। आज पापूलर की खेती हमारे इलाके में होती है लेकिन उसका भाव देखें तो किसी भी तरह से किसान भविष्य में उसकी तरफ नहीं आएगा। अल्टीमेटली वह गन्ना, जीरी और गेहूं ही बिजेगा, जिसमें उसको पानी की जरूरत होती है जिसकी आजकल बहुत ही समस्या है। सभापति सर, मैं डिमान्ड पर भी बोलना चाहता हूं लेकिन मेरे बहुत से दूसरे साथी भी सदन में बोलने के लिए बैठे हुए हैं। मेरी एक मांग और है कि हमारे इलाके में एस०वाई०एल० कैनाल पर साईफन बनना चाहिए और यह हमारी बहुत ही पुरानी मांग है। पिछली बार जब फल्ड आया था तो मुख्यमंत्री हुड्डा जी वहां पर गए थे और वहां पर बाढ़ से हुई तबाही को अपनी आंखों से देखकर आए थे। वहां के लोगों की भी मांग है कि एस०वाई०एल० पर साईफन बनाया जाए और उसके बनने से उस पानी की निकासी आखिर तक हो सकती है।

चेयरमैन सर, इसके अलावा मैं एजूकेशन पर बोलना चाहता हूं और मेरे से पहले बोलते हुए कई साथियों ने भी इस बारे में बात कही है। आज के बच्चे 10वीं और 12वीं पढ़ने के बाद भी शायद ही एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसका कारण हमारे टीचर्ज हैं। पिछली सरकारों ने टीचर्ज की बहुत सी ऐसी नियुक्तियां करी हैं जो टीचर्ज के पदों पर लगने के योग्य ही नहीं थे, वे क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। जब उनको निकालने की बात की जाती है तो हमारे अपोजिशन के साथी शोर मचाते हैं कि अध्यापकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन ये इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि जिस टीचर को पढ़ाना नहीं आता है वह अकेला टीचर कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आने वाले समय में करेगा। इस बात का आप सबको अन्दाजा होना चाहिए। सर, जो भी जे०बी०टी० के डिप्लोमा होल्डर्ज डिप्लोमा लेकर निकले थे और डिप्लोमा लेने वाले हैं, उनकी जे०बी०टी० में एडमिशन मैरिट बेस पर नहीं हुई थी। उन बच्चों ने अपने पेपरों में कुछ नहीं लिखा था और उनकी एडमिशन जे०बी०टी० में हो गई थी। अब ये बच्चे जे०बी०टी० का डिप्लोमा लेकर भविष्य में बच्चों को पढ़ाएंगे। चेयरमैन सर, जब हरियाणा में चौधरी बंसी लाल जी की हकुमत थी, उस वक्त भी मैंने इस सदन में जो बिल पेश किया गया था उसके खिलाफ अपनी बात कही थी। मैंने उस वक्त सदन में यह भी कहा था कि हमारे यहां पर अंग्रेजी की शिक्षा पहली

कक्षा से शुरू होनी चाहिए । आज हम चाहे कुछ भी कहें लेकिन आज अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल पाता है और अंग्रेजी कम आने की वजह से हमारे बच्चे कम्पीटीशंज में पीछे रह जाते हैं। अंग्रेजी महज एक लैंग्वेज है लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सरकार ने फैसला किया है कि अंग्रेजी पहली क्लास से पढ़ाई जाएगी, यह सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। चेयरमैन सर, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार को एजूकेशन सिस्टम को टैलिविजन के थ्रू शुरू करना चाहिए। हमारी सरकार को एक ऐसा सिस्टम अपनाना चाहिए कि सारे हरियाणा में एक ही सिलेबस हो और सारे हरियाणा में एक ही टीचर के लेक्चर को सुना जा सके। इस प्रोजैक्ट पर हमने पहले एक्सरसाईज भी की थी और इस प्रोजैक्ट पर 50 या 100 करोड़ खर्च होंगे। चेयरमैन सर, पैसे एक बार तो खर्च होंगे लेकिन इससे हरियाणा के बच्चों को बहुत लाभ होगा। चेयरमैन सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़) : चेयरमैन सर, आपने मुझे डिमान्ड पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। चेयमैन सर, मैं डिमान्ड पर बोलने से पहले बजट पर बोलना चाहता हूं। 9 जून को जो बजट सदन में पेश किया गया है मैं उसके कुछ विषयों पर बात करूंगा।

चेयरमैन सर, वैसे तो हरियाणा के इस गरिमामय सदन में हर वर्ष बजट पेश किए जाते हैं और आगे भी पेश किये जाते रहेंगे। सदन में बजट रखना महज एक औपचारिकता नहीं थी, यह संविधान की जरूरत है। लेकिन यह जो बजट चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने सदन में जिस कुशलता से रखा है, वह बहुत ही सराहनीय है। हमारे विपक्ष के जो सदस्य हैं वे चाह कर भी इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। हां अगर अपोजिशन वाले सिर्फ अपोज just sake of अपोजिशन करें तो अलग बात है। यह बजट ऐसा है जिस से प्रदेश के हर क्षेत्र को और हर वर्ग को छूआ गया है। इसमें किसी व्यक्ति को और किसी भी क्षेत्र को उपेक्षित नहीं रखा गया है। वरना मैं स्मरण करवाना चाहता हूं मेरे विपक्ष के उन साथियों को जो सामने की बेंचों पर बैठे हैं जब यहां पर बजट पेश किया जाता था तो मात्र शब्दों की हेरफेर करके और आंकड़ों के बदलाव के बाद पेश किया जाता था। उस समय ऐसा अनुभव होता था कि पुरानी शराब को नयी बोतल में डालकर पेश किया गया है क्योंकि वे बजट जनता की आशाओं, आकंक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, प्रदेश की जरूरतों के अनुसार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की इच्छाओं के अनुसार पेश किए जाते थे। अब जिस तरह का बजट पेश हुआ है वह अपने आप में उदाहरण है जिसने पूरे प्रदेश के अंदर अपनी छाप छोड़ी है। चाहे अम्बाला के अंदर अर्बन रैनीवल स्कीम के तहत विकास की बात कही गयी हो, चाहे दक्षिणी हरियाणा के उस छोर महेन्द्रगढ़ और नारनौल की प्यासी भूमि की प्यास के बुझाने के लिए नई नहरों के निर्माण की बात की कही गयी हो, चाहे सिरसा के अंदर सेम की समस्या को दूर करने की बात कही गयी हो, चाहे मेवात के अंदर रैनीवल स्कीम की बात हो, चाहे फरीदाबाद जैसी औद्योगिक नगरी के विकास के लिए 47 करोड़ की व्यवस्था करके उसके विकास की बात हो यानी सभी एरियाज की बात इस बजट में कही गयी है। इस बजट में हरियाणा के चहुंमुखी विकास की बात कही गयी है। यह कुशल नेतृत्व चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का था जिन्होंने विशेष तौर पर दक्षिणी हरियाणा के साथ उस भेदभाव को मिटाने के लिए, जिस दिन शपथ ली थी, उसी दिन इस सदन के पटल पर कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा का हूं, 36 वर्गों का हूं, 36 जाति का हूं लेकिन जो भेदभाव और सौतेला व्यवहार किसी के साथ भी हुआ है तो उसे मैं अवश्य ही स्वीकार करूंगा

[राव दान सिंह]

और आज से ही मैं यह फैसला करता हूं कि जो भेदभाव नहरी पानी का हुआ है वह अब नहीं होगा और यदि एक बूंद भी पानी का मिलेगा तो बीस के बीस जिलों में समान रूप से बंटवारा किया जाएगा। हम मुख्यमंत्री जी के आभारी है जिन्होंने इतनी उदारता से और साहसिक कदम उठा करके हमारी एक ज्वलंत समस्या का समाधान किया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। अगर मैं पिछले बजट का जिक्र करूं तो मैं बताना चाहूंगा कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी, प्रावधान किया था सिरसा के अंदर सेम की समस्या को मिटाने के लिए जबकि हमारे यहां तो 1700 फुट तक पानी की बूंद नहीं मिलती है फिर भी हमारे यहां के लिए एक पैसे का प्रावधान नहीं किया गया। सभापति महोदय, अगर मैं एक पंथ दो काज की बात कहूं तो अलग नहीं है। अब दो बातों का समाधान हो गया है। उधर तो सेम की समस्या का समाधान हो जाएगा और इधर हमारे क्षेत्र की प्यासी धरती को पानी मिलेगा। इसलिए मैं पुन: उनको बधाई देता हूं। हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है यहां की आजीविका मुख्य तौर पर कृषि पर निर्भर करती है। और आज भी 75 प्रतिशत जनता कृषि के ऊपर ही आधारित है। इसीलिए आज नयी औद्योगिक नीति के साथ ही हमारी सरकार ने कृषि की नीति भी पेश की है जिसमें फसलों का विविधीकरण, आधुनिकीकरण और फसलों के चक्र के बदलाव की बात की गयी है। आज किसान कृषि को जो घाटे का व्यवसाय देख रहा है तो इस नीति से उसको भी लाभ मिल सकेगा। इस बारे में बहुत सारी स्कीम्ज और बहुत सारे चैलना अभियान चलाने की बात की गयी है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक समय था जब इसी सदन के अंदर एक नेता अपने को किसान का बेटा, किसानों का नेता कहता था और किसानों को सत्ता सीढ़ी बनाकर सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद उसने कालिदास की कहावत को चरितार्थ किया था कि जिस पेड़ पर चढ़ा उसी पेड़ को काट दिया जाए। जो आन्दोलनकारी थे उनके ऊपर राजद्रोह के मुकदमें बनाये लेकिन आदरणीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने एक क्षण में ही सत्ता पर काबिज होते ही दूसरे क्षण में वह मुकदमें वापस लेने का फैसला कर दिया कि जिन किसानों ने आन्दोलन किया था उनको आज से ही इन केसिज से बरी किया जाता है। सभापति महोदय, यह है एक सच्चे किसान की कहानी । इसी तरह से प्रदेश के चहुमुखी विकास का संकल्प जिसने लिया वह औद्योगिक विकास की बात अवश्य करेगा। आज खाली कृषि पर निर्भर होकर हम नहीं चल सकते। इसलिए एक नई औद्योगिक नीति, 2005 प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री महोदय ने घोषित की है इससे दो लाख करोड़ रुपये के निवेश के आने की संभावना है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यही प्रदेश अब है और यही प्रदेश तब था। इसी प्रदेश के अंदर यहां के उद्यमी यहां से पलायन करने के लिए मजबूर होते थे लेकिन आज तरह-तरह से प्रपोजल मल्टी नेशनल कम्पनीज लेकर आ रही हैं। ताकि इस प्रदेश में अपने उद्योग स्थापित कर सकें और हमारे यहां जो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खतरे के रूप में मंडरा रही है। उसका समाधान वे कर सकें। सभापति महोदय, यह आप भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है कि हर एक व्यक्ति को सरकारी सेवा में नहीं लिया जा सकता। जब तक अपना कृषि न हो जब तक अपने उद्योग न हों तब तक प्रदेश की तरक्की के अंदर लोगों को समा नहीं सकते। जो नयी औद्योगिक नीति घोषित की गई है मुझे पूर्ण विश्वास है कि उससे प्रदेश के लोगों को बेरोजगारी से निपटने में सहायता मिलेगी। जहां पर मांग की बात आती है मांगें बहुत सारी हैं। मेरे से पहले बोलने वाले सभी सम्मानित सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी है लेकिन एक पक्ष ऐसा रहा जिसको सब लोगों ने छुआ है यह है पंचायती राज। स्वर्गीय राजीव गांधी इसके सूत्रधार थे उन्होंने पंचायती राज के

माध्यम से सत्ता के विकेन्द्रीकरण और हस्तांतरण की बात की थी। पिछली सरकार के मुखिया ने सत्ता अपने हाथ में पूरी तरह से केन्द्रित करके रखी थी। राजीव गांधी जी ने इस बात को भांप लिया था कि पंचायती राज के माध्यम से ही समाज के ढांचे को ऊपर उठाया जा सकता है आम आदमी के छोटे-छोटे कामों को और झगड़ों को जिला परिषद् और ब्लॉक समिति के माध्यम से निपटाया जा सकता है। आज के मुख्यमंत्री जी ने भी ग्रामीण विकास के लिए काफी पैसे का प्रावधान बजट में रखा है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक धरोहर के रूप में माना जाता है पहला सुख निरोगी काया को माना जाता है यदि मनुष्य के शरीर में किसी तरह की पीड़ा हो तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। इस बात पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है। पहले सरकारी अस्पताल सिर्फ एम०एल०आर० काटने के अड्डे रह गए थे। अब उनमें गुणात्मक चेंज करने की बात की गई है इसके लिए मैं काबिल मुख्यमंत्री जी और काबिल स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। उन्होंने तीन महीने के अल्पकाल में इस दिशा में काफी कार्य किया है। अब मैं खेलों की बात भी करना चाहूंगा। उनके विकास के लिए मिनी स्टेडियम और दूसरी सुविधायें उपलब्ध करवाई जाएं। ताकि हमारे यहां के जो बच्चे हैं जिनमें कि बहुत प्रतिभा भी है लेकिन अवसर न मिलने की वजह से वे पीछे रह जाते हैं उनको निखारने में सहायता मिल सके। इस बारे में रणबीर महेन्द्रा जी ने भी बोलते हुए कहा है। अगर उनको सुविधायें मिलें तो वे इस प्रदेश और देश का नाम खेलों के मामले में ऊंचा कर सकते हैं। अब मैं अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ बातें रखना चाहूंगा। हमारा क्षेत्र कृषि पर आधारित है लेकिन हम यह भी समझते हैं कि जब तक उद्योगों की स्थापना नहीं होगी तब तक हम निश्चित तौर पर तरक्की और विकास की राह पर नहीं जा सकेंगे। हमारे क्षेत्र को भी औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि बाहर से आने वाले उद्योगपति वहां आकर भी उद्योग लगाएं। इससे हमारे यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सभापति महोदय, बिजली एक बहुत बड़ी समस्या है कृषि के लिए ट्यूबवैल बिजली पर आधारित हैं हमारे दो तीन सब-स्टेशन हैं जहां बिजली की सख्त जरूरत है मेरे हल्के में पाथेड़ा और सेहलंग में 33 के०वी० के सब-स्टेशन की बहुत जरूरत है इससे हमारे क्षेत्र को बिजली की समस्या से निजात मिल सकेगी। मेरा क्षेत्र वैसे तो कस्बे के रूप में जाना जाता है लेकिन सुविधाओं के लिहाज से ग्रामीण क्षेत्र से भी पीछे रहता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एक हुडा जैसी कालोनी विकसित की जाए ताकि जो लोग वहां रहकर अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वे प्लॉट लेकर रह पाएं। सभापति महोदय, महेन्द्रगढ़ से एक रोड़ राजस्थान को जोड़ता है जो जयपुर जाने वाले नेशनल हाई-वे नम्बर 8 पर कोटपूतली के पास जाकर मिलता है। उस रोड़ पर एक फलाई-ओवर की सख्त आवश्यकता है। कम से कम 8-10 बार वहां पर जो गाड़ियां दादरी से आती हैं उनको उस रेलवे क्रॉसिंग पर घण्टों खड़े रहना पड़ता है अगर वहां पर फलाई ओवर या ओवर ब्रिज सैंक्शन कर दिया जाये तो निश्चित रूप से लोगों को जयपुर से हिसार जाने में बहुत सुविधा होगी।

Mr. Chairperson : Please wind up, Dan Singh ji.

राव दानसिंह : सभापति महोदय, बागोत से सेहलंग वाया बहालावास, महेन्द्रगढ़ से मांदौला, नांगल सिरोही से खेड़की, गुडाह से नांगल मोहनपुर, खेड़ा से बूचावास, नांगल हरनाथ से रसूलपुर इन सड़कों को अगर जोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के विकास के लिए काफी गति होगी।

Mr. Chairperson : Thank you very much, Dan Singh ji. Please take your seat.

राव दान सिंह : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी ने पानी का समान बटवारा किया इसके लिए उनको भी धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र सिंह जून (बहादुरगढ़) : चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इतना शानदार बजट पेश किया। जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनको यह बजट इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि इनको यह पता है कि हमारे रोहतक जिले के मुख्यमंत्री बन गये हैं इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला का एलटनेटिव हमारे श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा मुख्यमंत्री बन गये हैं ये जैसा 40 साल से राज कर रहे थे अब वह 40 साल रोहतक जिला के श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा करेंगे और जिन सीटों पर-आज ये बैठे हुए है अगली बार यहां कांग्रेस के विधायक बैठेंगे और ये लोग सदन से बाहर नजर आयेंगे। (विघ्न)

Dr. Sushil Indora : Chairperson sir (Interruptions)

Mr. Chairperson: Indora ji, take your seat. This is not the way. Please continue, Joon Sahib.

श्री राजेन्द्र सिंह जून : चेयरमैन सर, अब मैं अपने हल्के की कुछ समस्याएं रखने जा रहा हूं मेरे हल्के के 5-6 गांव ऐसे हैं जो लोकसभा सीट के लिए तो सोनीपत जिले में पड़ते हैं और विधान सभा क्षेत्र में बहादुरगढ़ में पड़ते हैं इनमें छोटी पाई, परमपुर, किड़ोली, प्रहलादपुर और बरोना है। इनके लिए न तो सोनीपत में कोई सुनवाई होती है और न ही बहादुरगढ़ में कोई सुनता है इनकी सारी सड़कें टूटी हुई हैं। इन गांवों में न लाईट है, न पानी की सुविधाएं हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि इन विषयों पर विचार किया जाए। दूसरा जसराना माईनर की रिमाडलिंग की जाए जिसका 7-8 गांवों को पानी टेल एण्ड तक नहीं पहुंचता इससे इन गांवों को लाभ हो सकेगा। तीसरा इरीगेशन का एक्सियन दिल्ली में बैठता है इसलिए अगर कोई काम हो तो लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है कई बार वह एक्सियन वहां पर नहीं मिलता। इसलिए मेरी विनती है कि दिल्ली की बजाए कोई छोटा अधिकारी बहादुरगढ़ में बैठाया जाए ताकि लोगों की समस्या की सुनवाई हो सके। अब मैं हैल्थ मिनिस्टर से विनती करना चाहूंगा। सभापति जी, बहादुरगढ़ में 7 बैड का होस्पिटल है उसको अपग्रेड करके 100 बैड का करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा हुआ है। मेरी बिनती है कि उसको अब 100 बैड का करने बारे विचार करें। नगर परिषद् में बिना तकनीको राय के अवैध कालोनियों के नक्शे पूर्व विधायक ने पास करवाए 4-5 अवैध कालोनियां वहां बसी हुई हैं । उनकी जांच कराई जाए और जो दोषी पाया जाए उस पर कार्यवाही की जाए। पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर से मैं बिनती करूंगा कि हमारे शहर में पानी की बड़ी प्रोब्लम है, पुरानी मशीनें लगी हुई हैं, वे 2-4-5-10 दिन में फुंक जाती है इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि वहां नई मशीनें लगाई जाएं। पिछली सरकार के समय में कुछ जमीनें हमारे गांव बहादुरगढ़ की, नए गांव की पूर्व विधायक ने एक्वायर करवाई थी। हमारे बहादुरगढ़ में सैक्टर 6, 2 और 9 आलरेडी हैं। अभी उनमें पूरी जनता नहीं बसी है, इसमें सैक्टर 10,11 और 12 और 12ए, की जमीन जानबूझकर एक्वायर करवाई गई क्योंकि वह जमीनों को खरीदना चाहते था इसकी दोबारा से जांच कराई जाए और जो लोग वहां बसे हुए हैं उसमें उस एक्वीजिशन में उनका नाम भी लिखवा रखा है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ एक इंडस्ट्रियल टाउन है और उसमें कम से कम 500 फैक्ट्रियां होती थी, पिछले राज में पूर्व विधायक ने आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां बन्द करा दी थी। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि बहादुरगढ़ को भी कम से कम इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर

करें। ताकि अच्छी से अच्छी फैक्ट्रियां वहां आएं और खुलें । सभापति जी, बहादुरगढ़ में नाहरा-नाहरी पर लाइन पार आधे से ज्यादा बहादुरगढ़ बसता है वहां पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है। वहां रेलवे फाटक पर आधा आधा या 45-45 मिन्ट तक ट्रैफिक जाम रहता है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उस पर एक ओवर ब्रिज बनाने का प्रावधान करें। जैसा कि मैट्रो रेल जागलोई तक आ रही है, इस बारे में मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इसको बहादुरगढ़ तक लाने की कोशिश करें। बहादुरगढ़ में हाइवे नं0 10 है उस पर भी एक ओवर ब्रिज बनाने की व्यवस्था करें। सभापति जी, मेरी आपसे विनती है कि हमारे हरियाणा में 4-5 यूनीवर्सिटीज हैं, मेरी विनती है कि सैल्फ फाइनैंस स्कीम पर यूनीवर्सिटीज खोलने पर विचार किया जाए। सभापति जी, आपने मुझे डिमाण्डज पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

Maj. Nirpender Singh Sangwan (Dadri) : Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Budget. I had almost given up the hope. I would congratulate the Finance Minister and the Hon'ble Chief Minister for giving such a balanced budget inspite of serious financial constraints. The State debt has reached to Rs. 30,000/crores as on date. Rs. 2400/-Crores is the interest liability per year. Rs. 1600 crores is the principal repayment liability per year. All these constraints have arisen on account of the mis-management, corruption and bad planning of the previous Government. The previous Government did not generate enough resources. Therefore, resorted to reckless borrowings, which resulted in the mess, with which the present Government is saddled with. It was no doubt a challenging task how to balance the development commitments made to the electorate and at the same time reign in the mounting debt. But our Finance Minister has overcome this remarkably. It is heartening to learn that the State has constituted a Committee under the Chairmanship of the Hon'ble Chief Minister for additional resources mobilization. This Committee will look into the aspect of revenue leakages and how to pluck them. The good results have already started coming and we have seen it in the excise auctions. Similarly the auction of mines at Panchkula, has shown a threefold increase. The objective of the present Government is to generate its own resources of the State to meet its expenses rather than burdening the people of Haryana with huge debts, which they may never be able to repay. Sir, from times immemorial, troops from Haryana Heartland have been sought by all armies. Troops from Haryana have been the forefront of the British Army from times immemorial. In both the great wars, the troops from Haryana have achieved remarkable results. Even the renowned German General Rommull said the result of the North African compaign could have been different, had it not been the 4th Indian Division. This Division comprised largely of troops from Haryana, the erstwhile greater Punjab. Keeping the commitment of these valiant soldiers in mind, serving soldiers and ex-servicemen in Haryana, have never had it so good as in the present Government. This is largely due to the bold initiative taken by our Hon'ble Chief Minister. In our Fauji Biradari, being a 60% Fauji having had its schooling at Sainik School, Kunjpura. All army and ex-servicemen canteen in the State have been exempted of VAT. Twenty five percent excise rebate for all canteens has been promised. Equal compensation to the next

[Maj. Nirpender Singh Sangwan]

of kin of Martyrs from the Armed forces or paramilitary forces has been given out. Bomb blast victims of the Armed forces or paramilitary forces hailing from Haryana in disturbed areas are being given compensation, as those killed in disturbed areas also. But Sir, I must say that maintenance of all the Sainik Rest Houses in the State, Zila Sainik Board offices in the State are in a State of utter neglect. There is a shortage of staff.

सभापति महोदय, जो फौजी रिटायर होता है वह अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दर-दर भटकता है। कई जगह चक्कर काटने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी रजिस्ट्रेशन कहां पर होगी। जब वह जिला सैनिक बोर्ड के आफिस में जाता है तो उसे वहां न स्टाफ मिलता है, न अधिकारी मिलते हैं जो उसका काम कर सकें। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमें इनकी मेनटीनैंस के लिए और पैसे देने चाहिएं। इसके अतिरिक्त जो हमारे यंग सोल्जर 15 या 18 साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर आ जाते हैं उनकी रिहैबलीटेशन के लिए कोई न कोई सिक्योरिटी फोर्स खड़ी करनी चाहिए ताकि सिक्योरिटी का जो काम हमारी पुलिस कर रही है ये लड़के अच्छी तरह से कर सकते हैं जिससे हमारी पुलिस और काम कर सकेगी। Private agencies exploit these young boys very much. Therefore, it is requested that rehabilitation of these ex-servicemen, which is the utter necessity, should be taken on priority.

सभापति महोदय, अब मैं बिजली बोर्ड के बारे में सदन को बताना चाहूंगा। सभापति महोदय, बिजली बोर्ड के जो ट्रांसफारमर्ज हैं उनकी रिपेयर इतनी ज्यादा फॉल्टी है कि आज ट्रांसफार्मर लगाया और तीसरे दिन खराब। जो लोग इनकी रिपेयर करते है अगर वे ठीक रिपेयर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए और यदि वे ट्रांसफारमर्ज रिपेयर के काबिल नहीं हैं तो उनको रिपेयर ही नहीं करवाना चाहिए क्योंकि हर तीन दिन के बाद वे खराब हो जाते हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। उन लोगों को पूरी छूट है और वे अपने पैसे बना रहे हैं। हर तीसरे दिन वे खराब हो जाते हैं जो लोग उनकी रिपेयर करवाते हैं उनकी भी कोई न कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे इतनी जल्दी रिपेयर क्यों मांग रहे हैं। Sir, the Electricity Board is unable to supply quality electricity in the villages and the towns. This is mainly due to the wire conductors which for the last 30 years have not been changed. They are hanging loosely and it results in lot of accidents. Cattle, men, women and children lose their lives due to this. They can not be tightened because as you try to tighten them, they break. They need replacement urgently for all practical purposes. Sometimes we are told that on the papers they have been replaced a couple of times but I do not know what is the reality. Now, I request the worthy Chief Minister to look into this aspect at once.

Drinking water in Dadri, I would request, it is of prime importance. Everything depends upon drinking water. There are road blockades and the villagers fight with each other. Neighbours quarrel among themselves, there are lot of cases in the Police Stations and all are because of water; somebody has taken over a hand pump, somebody is not letting the other persons to fill up water. Water is not coming in the taps. Sometimes Public Health staff is beaten up, there are gheraos.

Therefore, I would request the Minister of Public Health and Minister for Irrigation to give Dadri and other towns in Southern Haryana more water so that drinking water problem is taken care of immediately.

The teachers of today as we say, are going to shape the Haryana of tomorrow. But, Sir, where is their commitment and where are their qualifications. So many times when you go and see in a village school, the teacher who is posted there, is teaching the children songs from the films. Once, I happened to ask a teacher why are you not teaching them the text, you are supposed to teach them mathematics. उस मास्टर ने मुझे बताया, साहब, गणित तो मैंने कभी सीखा ही नहीं मुझे खुद ही गणित नहीं आता तो मैं बच्चों को गणित क्या पढ़ाऊंगा। So Sir, in this kind of situation, I am to request Education Minister to put a very stringent criteria when the recruitments of the teachers are made whether it is of primary, secondary or higher education stage. Besides their qualifications, the biggest problem being faced by the Government is their placement. Everybody wants to be on the main roads. Where the villages are on the roads, there is surplus staff and where the villages are off the roads, there is no staff. Sir, I would request that some incentives should be given to those teachers who are teaching in the rural areas placed off the main roads.

Mr. Chairperson : Please wind up within two minutes.

Maj. Nirpender Singh Sangwan : Sir, one big thing is the accommodation at Haryana Bhawan. There is no accommodation for the staff at Haryana Bhawan. Whosoever is accompanying the MLA/Minister, his staff faces this problem. The staff is lying on pavement or lawns of Haryana Bhawan or in other Rest Houses or is in the cars. So, I am to request you that like Punjab Bhawan, we should also have some accommodation earmarked for the staff. I am sure that with the commitments with which our Government is working, the Government will succeed in presenting a deficit free Budget in future. Thank you very much Sir.

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : चेयरमैन सर, मेरा सबमिशन है कि डिमान्डज पर बोलते हुए अढ़ाई घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। अगर आप ठीक समझें तो 17 तारीख को एप्रोप्रिएशन बिल पर भी डिस्कशन होनी है That is the final reading of the Appropriation Bill and in the agenda for that day this is the only item i.e. introduction, consideration and passing/voting of the Bill. So, most of the friends can have a lot of time on 17th June, If we strict it to 6 O'Clock then rest of them can speak on the Appropriation Bill and they will have ample time to speak.

श्री सभापति : ठीक है।

श्रीमति गीता भुक्कल (कलायत, एस०सी०) : माननीय चेयरमैन सर, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं सदन में जो बजट पेश किया गया है उसका स्वागत करती हूं और समर्थन करती हूं। मेरा बजट पर बोलने का विचार था। मैं आपके माध्यम से सदन में अपनी कुछ मांगे रखना चाहती हूं। सबसे पहले मैं आधुनिक और प्रगतिशील राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को स्वच्छ एवं पारदर्शी बजट पेश

[श्रीमति गीता भुक्कल]

करने के लिए बधाई देती हूं । इन्होंने मात्र तीन महीने के कार्यकाल में गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए और किसानों के लिए जो विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, वे बहुत ही सराहनीय हैं और यह ऐतिहासिक फैसला है । ऐसे कदम केवल कांग्रेस पार्टी या इसके मुख्यमंत्री जी ही उठा सकते थे। इसके लिए हमारी सरकार और हम सब बधाई के पात्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरा कलायत हल्का है। मेरा हल्का आजतक पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। 45 वर्षों से विकास की दृष्टि से सभी सरकारों ने इस हल्के की अनेदेखी की है। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री का हल्का नरवाना था। वह हल्का मेरे हल्के कलायत के साथ ही लगता है। लेकिन उन्होंने न वहां पर कभी विकास की बात कही और न ही कोई विकास का कार्य किया है। अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो सिर्फ विनाश ही विनाश किया होगा। चेयरमैन सर, मैं इस सरकार से पूरी आशा और उम्मीद रखती हूं बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला कल्याण व अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए एक स्पैशल पैकेज मुख्यमंत्री जी वहां पर देंगे। सबसे पहले मैं वूमैन सैक्टर की बात करूंगी। हरियाणा में पुरूषों का साक्षरता का स्तर 78.5 है और महिलाओं का 56 प्रतिशत है। लेकिन मेरे कलायत क्षेत्र में महिलाओं की 50 प्रतिशत से भी कम साक्षरता की दर है। इसके अलावा कलायत में बहुत समय से सरकारी कालेज की मांग की जाती रही है। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि कलायत में सरकारी महिला कालेज खोला जाए। चेयरमैन सर, हमारे माननीय सदस्य श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने कहा था कि कैथल जिले में सरकारी कालेज नहीं है इसलिए मेरा यह कहना है कि कलायत हल्के में महिलाओं के लिए सरकारी कालेज दिया जाए और इसके लिए मुख्यमंत्री जी मैं और मेरे हल्के के लोग आपके आभारी रहेंगे। इसके साथ ही हमारे इस बजट में कहा गया है कि एक एक जिले में माडल स्कूल खोलने की व्यवस्था की जाएगी। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कलायत में भी एक माडल स्कूल खोलने की मांग करती हूं । चेयरमैन सर, हमारे हल्के में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिनको अपग्रेड किया जाना चाहिए, मैं इसलिए यह कह रही हूं कि हमारे हल्के में शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे है। इसी के साथ वूमैन सैक्टर के साथ शौचालयों की बात भी जूड़ी हुई है। ग्रामीण आंचल की महिलाओं की रक्षा के लिए उनके मान सम्मान के लिए शौचालयों का शीघ्र निर्माण करने की मांग थी जो कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही इस बात को कहा कि जल्द से जल्द ग्रामीण महिलाओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूं। चेयरमैन सर, मैं और मांग करती हूं कि इस कार्य के लिए एक कमेटी गठन किया जाए और वह जल्द से जल्द अपनी पूरी रिपोर्ट दे कि कहां कहां पर ये शौचालय बनाने की जरूरत है ताकि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और हमारी महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा की जा सके। महिला विधायक होने के नाते हमें मालूम है क्योंकि जब हम हल्के में जाते हैं तो हमें महिलाओं की समस्याओं को सुनना पड़ता है। इसके अलावा एक समस्या और हमारे यहां पीने के पानी की है। हमारे कलायत क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत कमी है चाहे शिमला गांव हो, चाहे भाणा गांव हो या चाहे बालू गांव हो सब जगह पीने के पानी की कमी है। अगर कुछ जगहों पर पानी की टंकियां बनी हैं तो वे ठीक काम नहीं कर रही हैं। पिछली सरकार में करोड़ों रूपयों का बजट आया था टंकियों के और दूसरे निर्माण के लिए लेकिन उनमें अंडर कंस्ट्रक्शन ही पानी चौने लगा है। आज वे इस हालत में है कि वह कभी भी ढह सकती है। मैं मांग करती हूं कि एक ऐसी इंक्वायरी कमेटी बिठायी जाए तो यह जांच करे कि जितने भी फंड्ज कलायत में पानी की समस्या

को दूर करने के लिए आये थे वह सही ढंग से वहां क्यों नहीं यूज किये गये हैं। इस बारे में जो घोटाला हुआ है। उसकी जांच की जाए। जहां तक हैल्थ की बात है। हमारा कलायत क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। सी०एच०सी० कलायत में पी०एच०सी० बालू और बाता में स्टाफ की बहुत कमी है। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, स्टाफ की कमी के बारे में हमने बार-बार अपनी माननीय हैल्थ मिनिस्टर से बात की है कि जल्द से जल्द स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। वहां पर एक्सरे मशीन तो है लेकिन कोई रेडियोग्राफर नहीं है। इसी तरह से कुछ इंस्ट्रूमैंटस की भी कमी है। हमारे बजट में मैटरनिटी हटस के लिए बहुत ही अच्छा प्रावधान किया गया है। मैं मांग करती हूं कि हमारे यहां मैटरनिटी हटस बनाये जाएं ताकि हमारी जो महिलाएं हैं बहनें हैं उन्हें जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान वहां पर हो सके। दूसरी बात मैं नहरी पानी के बारे में कहना चाहूंगी। नहरी पानी का न्यायोचित बंटवारा नहीं हुआ है। हमारी सरकार ने बनने से पहले हमारे क्षेत्र के किसानों और लोगों को वायदा किया था। हमारे यहां सिरसा ब्रान्च पड़ती है इसमें पहले से ही पानी की बहुत ज्यादा कमी है। वहां पर सिंचित क्षेत्र में भी मरूस्थल की स्थिति पैदा हो गयी है। इसलिए मैं मांग करती हूं कि पानी का जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो हमारे साथ जो शुरू से भेदभाव होता रहा है वह आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं मांग करती हूं कि जो शाला और बाता माईनर्ज हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ायी जाए क्योंकि जो भी सरकार आयीं शुरू से लेकर आज तक हर सरकार ने हमारे इलाके के साथ भेदभाव किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से इस सरकार की कमान संभाली है मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि अब तक इस क्षेत्र से जो भेदभाव होता रहा है उसको वे जरूर ठीक करेंगे, वर्षों से हमारे किसान जो पानी की कमी की वजह से मार झेल रहे हैं तो अब टेल तक पानी पहुंच सके। अगली बात मैं तालाबों के पानी के बारे में कहना चाहूंगी। आबादी बढ़ने के कारण जोहड़ों का पानी बहुत ही गंदा हो चला है। इन जोहड़ों की सफाई के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। गंदे पानी की वजह से पशु बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। पशुओं के बीमार होने की वजह से आम किसान को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे कलायत हल्के में कुछ पशु चिकित्सालय तो हैं लेकिन उनमें डाक्टर नहीं है इसलिए मैं मांग करती हूं उनमें डाक्टर भेजे जाएं क्योंकि अस्पतालों की बिल्डिंग से कोई कार्य नहीं चल सकता जब तक उनमें डाक्टर न हों। इसी तरह से सीवरेज की एक बहुत पुरानी मांग कलायत की है। इस बारे में हमने प्रपोजल बनाकर भेजी है। इसी तरह से बिजली आपूर्ति की भी हमारी मांग है कि इसके पावर हाउसिज की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। कर्मचारियों की भी बहुत कमी है। मैंने इस बारे में लिखकर भी दिया है कि वहां पर कर्मचारी ही नहीं है । कई बार मांग करने के बाद भी हमारी यह मांग पूरी नहीं हुई है। खास तौर से हमारी यह मांग भी है कि पुरानी बिजली की जो तारें लटकी पड़ी हैं उनको बदला जाए। हमने इनके फोटो तक खिचवाएं लेकिन उन पुरानी तारों को अभी तक नहीं बदला गया है। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि हमारे यहां बस स्टैंड को भी खोलने की मांग थी। हमारे माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको मान लिया है इसके लिए मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूं। आई०टी०आई० खोलने की मांग को आज ही हमने उठाया है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि यह बनेगी। इसी तरह से बुढ़ापा पेंशन की अनियमितता हमारे यहां बहुत ज्यादा रही है। गांव बाता के लोगों की पेंशन चोरी हो गयी थी। हमने बहुत बार शिकायत की लेकिन बजुर्गों को पेंशन नहीं मिली। सात तारीख से पहले जो हमारी सरकार ने आश्वासन दिया है कि पेंशन जमा हो जाएगी और उनको मिल जाएगी तो मेरा इस बारे में कहना है कि इस बारे में सख्ताई से काम करें और निर्देश दें कि हमारे बजुर्गों को सात तारीख

[श्रीमति गीता भुक्कल]

से पहले पेंशन मिल जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री दूडा राम (फतेहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार ने जो बजट पेश किया है उसका स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जो कर रहित बजट दिया है इसमें हर वर्ग का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। यह जनकल्याणकारी बजट है और यह बजट हरियाणा को तरक्की और विकास की राह पर ले जाएगा। मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन देने की एक अनूठी शुरूआत की गई है तथा कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बहाल किया गया है। जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए विकास और जनकल्याण के कई कदम उठाए गए हैं यह एक सराहनीय काम है। सरकार ने सबसे पहले प्रदेश में भय और आतंक का शासन खत्म किया है और लोगों में एक विश्वास की भावना पैदा की। कांग्रेस पार्टी का 120 वर्ष का पुराना इतिहास है और इसने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं लेकिन यह पार्टी गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों से कभी भी विमुख नहीं हुई। अनुसूचित जातियों के परिवारों की लड़कियों के विवाह पर 5100 की बजाय अब 15000 रुपये की राशि देने की योजना इंदिरा गांधी प्रिय दर्शनी विवाह शगुन योजना शुरू की गई है। विकलांगों को दी जाने वाली मासिक पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई है। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 1400 से बढ़ाकर 3500 कर दी गई है। ब्याज की दरों में एक प्रतिशत की कमी की गई है। इस वर्ष फरवरी-मार्च में हुई ओलावृष्टि से नुकसान की भरपाई के लिए गेहूं के लिए 50 प्रतिशत और अन्य फसलों के लिए 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 9-5-2005 को फतेहाबाद और सिरसा में जो भीषण तूफान आया था उसमें फतेहाबाद जिले में भी 7 लोग मारे गए थे तथा सम्पत्ति व पशुओं को काफी नुकसान हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन परिवारों के दुख दर्द को बांटने के लिए स्वयं तुरन्त फतेहाबाद तथा सिरसा गए तथा उन परिवारों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया तथा हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को रखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि उन समस्याओं का समाधान सरकार अवश्य करेगी। मेरे हल्के की अधिकांश आबादी ढाणियों में रहती है। ढाणियों में बिजली की काफी समस्या है क्योंकि गांव की ढाणियों में बिजली पहुंचाने के प्रयासों में सरकारी नीति आड़े आ रही है। नियमानुसार जिस ढाणी में बिजली पहुंचाई जाती है वहां तक बिजली की तारों, खंभों, ट्रांसफार्मरों तथा अन्य खर्चों को ढाणी के लोगों को ही वहन करना पड़ता है। इस नियम के चलते ढाणियों में रहने वाले लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि लोगों को पहले की तरह बिजली कनेक्शन सरकारी खर्च पर दिए जाएं। मेरा मुख्यमंत्री जी से यह भी अनुरोध है कि पीले, गुलाबी कार्ड और पेंशन का दोबारा से सर्वे जल्द से जल्द करवाया जाए। फतेहाबाद में एक 60 बिस्तरों का अस्पताल है तथा फतेहाबाद के जिला मुख्यालय बनने के बाद सी०एम०ओ० कार्यालय की स्थापना की गई है जो अस्पताल में प्राइवेट वार्डों में स्थित है जिस कारण मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि सी०एम०ओ० कार्यालय के लिए अलग से बिल्डिंग की स्थापना की जाए। अस्पताल में स्टाफ की कमी है। कृप्या स्टाफ की कमी को दूर किया जाए व फतेहाबाद में जिला मुख्यालय होने के नाते एक ब्लड बैंक की स्थापना की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की सड़कों का वर्णन कर रहा हूं। ये सड़कें हैं गोरखपुर से काजलहेड़ी, भूथनखुर्द से नाढोडी तक, ढिब्बी से धोलू तक, भोघी से जाण्डली कलां तक, धौल्टू से नाढोड़ी तक, चन्दोकलां से सुखलमपुर तक, इन सड़कों का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोय, फतेहाबाद के जिला मुख्यालय बनने के बाद भी फायर बिग्रेड में स्टाफ व गाड़ियां उपमण्डल स्तर की हैं कृप्या उसमें स्टाफ व गाड़ियों की संख्या जिला मुख्यालय के आधार पर की जाए। अध्यक्ष महोदय, फतेहाबाद में लड़कों का कोई राजकीय कालेज नहीं है कृप्या वहां राजकीय कालेज लड़कियों के लिए स्थापित किया जाए। गांव में हर स्कूल में स्टाफ की कमी है जिसके कारण परीक्षा परिणाम काफी निराशाजनक आए हैं मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि स्कूलों में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए ताकि परीक्षा परिणाम अच्छे आ सकें। हमारे यहां नहरों की टेल पर पानी की काफी समस्या है। कृप्या नहरों की सफाई करके टेलों तक पानी पहुंचाने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त पीने के पानी की काफी समस्या है ट्यूबवैल लगाने काफी आवश्यक हैं व पुराने ट्यूबवैलों को दोबारा बोर कराने की आवश्यकता है। पब्लिक हैल्थ के पास बजट की काफी कमी है उनको अधिक से अधिक बजट देने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, फतेहाबाद के जिला मुख्यालय बनने के कारण वहां वाहनों का काफी आवागमन है जिसके कारण प्रतिदिन काफी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए फतेहाबाद शहर का बाईपास बनाया जाए। फतेहाबाद में अभी नगरपालिका को अपग्रेड करके नगर परिषद बनाया गया है। मैं गुजारिश करूंगा कि नगर परिषद को अधिक से अधिक बजट मुहैया करवाया जाए ताकि शहर का विकास हो सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो बोलने का अवसर प्रदान किया है इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्रीमती मीना मण्डल (जुण्डला, एस०सी०) : स्पीकर सर, इस सम्मानित सदन में मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूं। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सम्मानित सदस्यों को, वित्त मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अब तक का सबसे बढ़िया और शानदार बजट पेश करने के लिए बधाई देती हूं। मैं आभार प्रकट करती हूं। सरकार का, वित्त मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने जनता का ध्यान रखते हुए कर मुक्त और बोझ रहित बजट हरियाणा की तमाम जनता को दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी सरकार दी है जो पहले कभी नहीं बनी। यह सरकार सभी के हितों का ध्यान रखने वाली सरकार है चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो और चाहे प्रदेश भर की जनता हो सभी की भलाई के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार हाउस के अन्दर विपक्ष को भी पूरा मान-सम्मान और बोलने का अधिकार दे रही है। जब सदन चलता है तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार के मुक्कमल तौर पर ट्रान्सपेरैंसी है सब इस बात को समझते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने महिलाओं के प्रति मान-सम्मान और इस बजट को अपने दिलो-दिमाग से बढ़िया और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बनाया है जिसे मन ही मन विपक्ष के साथी सराह रहे हैं। भले ही हाउस में कुछ भी कहते हों क्योंकि यह तो उनकी मजबूरी है कि ऑन दि फलोर ऑफ दी हाउस उन्होंने विपक्ष में ही बोलना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए सही बात को टालना नहीं चाहिए। इसमें कोई दो राय

[श्रीमती भीना मण्डल]

नहीं कि इस बजट में संतुलन है और यह बहुत ही सन्तुलित बजट है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास की अच्छी स्कीमें हैं। यह सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लोगों के प्रति बढ़िया और सकारात्मक सोच का नतीजा है। इसके लिए सरकार, वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। स्पीकर सर, शिक्षा आज की सबसे ज्यादा बुनयादि जरूरत है। बजट में प्रदेश के हर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल स्कूल खोलने की बात कही गई है और शिक्षा के ढांचे में सुधार की व्यवस्था की बात कही गई है। शिक्षा से जुड़ी अन्य बातों पर जोर दिया गया है। इससे साफ झलकता है कि हमारी सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश को पूर्ण रूप से साक्षर करने की सोच रखते हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाले हैं और हरियाणा प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में केरल प्रदेश की साक्षरता से भी ऊपर ले जायेंगे। यही नहीं हमें पूरा विश्वास है कि नक्शे में हरियाणा हर मामले में विश्व में सबसे ज्यादा गतिशील और विकसित होगा। अध्यक्ष महोदय, यह सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कामों से जाहिर हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आज हरियाणा प्रदेश की किस्मत जागी है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा की जनता के रक्षक के रूप में निर्मल स्वभाव वाले रहनुमा मिले हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने से हरियाणा प्रदेश के लोगों को ऐसा लगता है जैसे उजड़े चमन में बहार आ गई हो। इस बारे में मैं दो लाइनें कहना चाहूंगी --

कुछ वक्त पहले जी रहे थे हम सुनसान के वीराने में,
रहनुमा हमें अब ऐसा मिला कि वीराने में आ गई हो बहार जैसे।

अभी मैंने अपने हल्के की डिमांडज पर बोलना है। मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की हैं जैसे हजलाइयों पर लगने वाला भट्ठी टैक्स खत्म करना, किसानों के लिए ट्रक मंडीकरण शुल्क खत्म करना, शगुन योजना के लिए कन्यादान की राशि 5100 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये करना इसके अलावा लगभग 100 से भी ज्यादा काम और घोषणाएं काबिले तारीफ हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक ऐसे उपेक्षित और पिछड़े क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहती हूं जो हमेशा पिछड़ेपन का शिकार रहा है और हमेशा इनैलो का गढ़ रहा है जोकि इस बार कांग्रेस के पास आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के जुंडला की बात कहना चाहूंगी कि उस पिछड़े हल्के में बुनियादी सहूलियतों के अलावा हर सुविधा की जरूरत है। सबसे पहले तो वहां पर महिला कालेज निर्माण की जरूरत है ताकि उस क्षेत्र के आस पास के गांवों की लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिल सके और आज के उस दूषित माहौल से वे बच सकें। जो माहौल उन्हें अपने घर से शहर के कालेज तक जाते हुए परेशान करता है क्योंकि आज जो दूषित माहौल है उसको देखते हुए कोई माता-पिता अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेजना मुनासिब नहीं समझता। इसलिए जुंडला में एक कन्या महाविद्यालय की जरूरत है। दूसरा हमारे जुंडला में एक बस स्टैंड के निर्माण की जरूरत है। तीसरा जुंडला में एक होस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गांव के लोगों को इमरजैंसी में असुविधा का सामना न करना पड़े क्योंकि कई बार मरीज शहर के अस्पताल तक पहुंचते-2 दम तोड़ देता है। जुंडला के किसी भी गांव में कोई ITI नहीं है इसलिए हमारे इलाके में एक ITI की जरूरत है। हमारे हल्के के स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्स व अन्य स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। स्कूलों में टीचिंग स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए ताकि अच्छे रिजल्ट आ सकें। मैं पिछले

दिनों गांव के एक स्कूल में गई। वहां मिडल क्लास के 68 बच्चे हैं। बड़े खेद की बात है कि 68 में से केवल 8 ही बच्चे पास हुए। अध्यक्ष महोदय, सड़कों की हालत भी हमारे इलाके में बहुत खस्ता है। पानी के लिए ट्यूबवैल नाम मात्र हैं, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे यहां पावर स्टेशन की भी जरूरत है। इसलिए वहां पावर स्टेशन खुलवाया जाए इसके अलावा मेरे हल्के की जो दूसरी जरूरतें हैं उनको भी पूरा किया जाए। (शोर)

18.00 बजे **Mr. Speaker :** Take your seat. No time is left now. Sita Ram Ji, please start.

डा० सीता राम (डबवाली, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन के लम्बे इंतजार के बाद आज अंत में आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है इसका मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं डिमांड संख्या 12 पर बोलना चाहता हूं जो श्रम और रोजगार से संबंधित है। माननीय वित्तमंत्री महोदय ने अपनी बजट स्पीच में जिक्र किया कि आने वाले दस सालों में दस लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इसके लिए इतना पैसा कहां से आयेगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि सरकारी महकमे में कितना रोजगार दिया जायेगा और नये कौन से उद्योग लग रहे हैं जिनमें रोजगार दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की प्रथा रही है कि इन्होंने लोगों को सदा शब्दों के भ्रमजाल में उलझाये रखा है। यह आज की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 40 साल तक देश पर राज किया है। जो समस्याएं आज से बहुत पहले हल हो जानी चाहिए थीं वे आज तक भी हल नहीं हुई हैं। इसका मेन कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी लोगों को शब्दों के भ्रमजाल में उलझा कर रखती है। जो समस्याएं आज हमारे सामने हैं ये सब कांग्रेस पार्टी की ही देन हैं। अगर ये अपने काम के प्रति सजग होते तो आज जो ये अपने बजट में दोहरा रहे हैं वे बातें दोबारा नहीं दोहरानी पड़ती । लोगों को इस सरकार पर बड़ी आशा और उम्मीद है कि यह सरकार कोई ऐसा चमत्कार करेगी जिससे उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन बजट स्पीच के अंदर ठोस कारण नहीं दिए गए कि किस तरह से लोगों की समस्याओं को दूर किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त एस०वाई०एल० के हल के बारे में भी बजट में कुछ नहीं कहा गया। अपनी आदत के अनुसार इससे इन्होंने बचने की कोशिश की है। वित्तमंत्री जी ने बजट पर कहीं जिक्र नहीं किया कि एस०वाई०एल० नहर का निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा और कब तक पूरा करने का प्रयास है। गोलमोल करके एक दूसरे पर इन्होंने पहले भी थोपा और अब भी यह जवाब गोलमोल कर गये। एस०वाई०एल० का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के हक में हुआ है। आज के दिन हरियाणा, पंजाब और केन्द्र तीनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कहीं कोई मंशा इन्होंने अपनी जाहिर नहीं कि कि ये एस०वाई०एल० के बारे में क्या निर्णय ले रहे हैं, कब तक इसको पूरा किया जायेगा। बल्कि एक नई नहर बनाने का जिक्र करके लोगों को भ्रमजाल में फंसाने का काम किया है। जो कभी नहीं बनेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि पानी की समस्या का तो समाधान तभी होगा जब एस०वाई०एल० का पानी आयेगा। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूंगा जैसा वित्त मंत्री जी की स्पीच से आभास होता है कि ये किसानों को बिजली के बिलों में कोई न कोई छूट या उनको माफ करने की नीयत रखते हैं । इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बिजली के बकाया बिलों की राशि 2500 करोड़ रुपये के करीब है। यदि सरकार यह पैसा माफ करना चाहती है तो इसके पैसे का सरकार को बजट में तो कहीं इंतजाम करना चाहिए। यदि सरकार ऐसा करेगी तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा जायेगी। यदि सरकार माफ करती है तो बहुत अच्छी बात है हम भी सरकार

[डा० सीता राम]

की तारीफ करेंगे। लेकिन यह समस्या कांग्रेस पार्टी की ही देन है क्योंकि जिस समय किसानों के साथ हमारा समझौता होने जा रहा था उस समय किसानों को कांग्रेस पार्टी ने भड़का कर ऐसे काम किए जिसकी वजह से यह समस्या पैदा हुई। (विघ्न) दूसरी बात वह है कि आज भयमुक्त प्रशासन की बात ये लोग करते हैं लेकिन आज मैं क्राईम की बात करना चाहता हूं। इस सरकार के आने के बाद इस प्रदेश के अन्दर क्राईम बढ़े हैं। एक सवाल के जवाब में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने माना है कि राज्य में क्राईम रेट बढ़ा है। जब स्टेट में क्राईम रेट बढ़ रहा है तो उससे ये कैसे कह सकते हैं कि यह भयमुक्त प्रशासन देने जा रहे हैं। लोग कैसे इनसे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, कैसे इस प्रदेश में उद्योग धन्धे लग पाएंगे और लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें स्वच्छ प्रशासन दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था सही दिशा में न जा रही हो वहां पर प्रदेश का विकास कैसे होगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की कृपा करें। पिछले शासन के अन्दर जनता को बिल्कुल अच्छा प्रशासन दिया गया था और अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यह बात बिल्कुल सही साबित होगी। ये कहते हैं कि वित्त मन्त्री महोदय ने एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। इस अच्छे बजट का श्रेय भी पिछली सरकार को जाता है। इस सरकार ने पिछले 100 दिन के शासन में ऐसा कोई योगदान नहीं दिया जिससे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ हुई हो। पिछली सरकार ने प्रदेश में सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था कायम की थी जिसकी वजह से ये ऐसा अच्छा बजट पेश करने में सक्षम हो सके।

Mr. Speaker : Please be relevant. Sita Ram Ji, try to wind up.

डा० सीता राम : पिछली सरकार की नीति की वजह से यह सरकार ऐसा बजट पेश करने में सक्षम हुई है। नहीं तो प्रदेश में बहुत कठिनाईयां और दिक्कतें होती और लोगों को अनेकों प्रकार की समस्यों से जूझना पड़ता क्योंकि इनके पास पैसे का प्रबन्ध नहीं हो सकता था। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वैट का जिक्र किया। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया था। ये लोग कहा करते थे कि जिस दिन इनकी सरकार आएगी वैट प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा। (विघ्न)

Mr. Speaker: Sita Ram ji, now you take your seat. Finance Minister wants to speak Please take your seat.

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल मैम्बर से यह जरूर कहूंगा कि वे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर न रखें। हमने कभी यह नहीं कहा कि हमारी सरकार आने के बाद हम वैट प्रणाली खत्म कर देंगे। हमने हमेशा एक ही स्टैंड रखा है। दो साल पहले जब चौटाला साहब की सरकार ने वैट इन्ट्रोड्यूस किया था तब हमने यह जरूर कहा था कि in isolation यह लागू नहीं होना चाहिए अगर सारा देश वैट की परिधि में आता है तो हम सहयोग करेंगे और हमारा आज भी वही स्टैंड है। स्पीकर सर, 21 राज्यों ने वैट प्रणाली को अपनाया है और हमने यह फैसला किया है कि हम उनके साथ चलेंगे।

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, इसके बाद इन्होंने फूड पार्क बनाने का जिक्र किया है। यह फूड पार्क पिछली सरकार के समय में मन्जूर हुआ था और उस के ऊपर काम चल रहा था। इन्होंने इसका बड़े जोर शोर से प्रचार किया कि फूड पार्क बनाने जा रहे हैं। ऐसी ही बात एक्सप्रैस हाईवे के बारे में भी है।

Mr. Speaker : Sita Ram Ji, wind up now, time is running against you.

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि एक्सप्रेस हाईवे का जिक्र आया यह भी पिछली सरकार के समय में मन्जूर हुआ था और उसी के ऊपर यह कह रहे हैं कि वहां बड़ा बिजनैस सैंटर बनेगा। गुड़गांव और फरीदाबाद में बड़ा बिजनैस सैंटर बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। (विघ्न) अगर आप उद्योग धन्धों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर वहां पर जैसे सरकार ने छूट दी हुई है, इन्कम टैक्स में और दूसरे टैक्सिज में कुछ समय के लिए शायद 8-10 साल के लिए कुछ छूट दी हुई है यदि आप राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो वैसी ही सुविधाएं आप भी स्टेट में दें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक प्रदेश में उद्योग धन्धे फल फूल नहीं सकते हैं।

Mr. Speaker : Thank you very much please take your seat now.

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथियों ने आज कुछ प्वायंट्स रेज़ किये हैं। चौधरी धर्मबीर जी ने यह प्वायंट रेज किया था कि जो मेन फीडर्ज हैं वहां से पानी नहीं दिया जाए। मैं इस बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि वहां पर हमने पहले ही इस आशय की हिदायतें दे रखी हैं कि मेन फीडर्ज पर अगर कोई पानी का मोघा हो तो उसको बन्द करना है। इसके साथ ही साथ जहां तक नहरों की कैपेसिटी बढ़ाने की बात है, तो मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि आजकल जे०एल०एन० ऐरिया की सफाई का काम चल रहा है। इनके समय में यह एक नाला था लेकिन आज वह नहर बन गई है और उस पर बाकायदा सफाई का काम चल रहा है। इसी प्रकार से हमारे एरिया में जितने भी पम्प हाउसिजज हैं उनके रिहैब्लीटेशन का कार्य भी चल रहा है। इससे कैपेसिटी बढ़ेगी और जो बात धर्मबीर जी ने कही थी कि नहरों की कैपेसिटी बढ़ाई जाए और पम्पों की कैपेसिटी ठीक की जाए तो वह हम करने वाले हैं। दूसरा मुद्दा खासकर श्री उदय भान जी ने उठाया था रिगार्डिंग, दिल्ली को ज्यादा पानी दिया जा रहा है। यह बिल्कुल सही बात है। सुप्रीमकोर्ट ने पब्लिक इन्ट्रस्ट लिटिगेशन पर एक आदेश दे दिया कि जो दिल्ली की रिक्वायरमैंट है उसको पूरा किया जाए, जिसकी वजह से ओवर एंड अबव हम उनको उनकी रिक्वायरमैंट के हिसाब से 500 क्यूसिक पानी दिया करते थे। अब हम उनको 900 क्यूसिक पानी दे रहे हैं। हमने इस बारे में प्वांयट रेज भी किया था। स्पीकर सर, वजीराबाद में जो ट्रीटमैंट प्लांट है वहां से भी दिल्ली के लोग पानी चोरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से फरीदाबाद के लोगों को बहुत नुक्सान हो रहा है। जो कन्टेमिनेटिड वाटर की बात इन्होंने की है वह बिल्कुल सही है, वहां पर बहुत गन्दा पानी आ रहा है क्योंकि उसमें गंदे नालों का पानी आ जाता है। उसके बारे में भी हमने कई बार मामला टेकअप किया है और प्रोटैस्ट भी किया है। इसके बाद इन्होंने यू०पी० में टेपला बांध के बारे में जिक्र किया है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बांध बनाया गया है वह हरियाणा की स्टैंडिंग कमेटी से पूछे बिना ही बना लिया गया है। इसके बारे में कल एक कालिंग अटैंशन मोशन भी लगी हुई है और इसके बारे में मैं कल जवाब दे दूंगा। स्पीकर सर, इस बारे में मैं अभी यह जरूर कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी यू०पी० के काउन्टर पार्ट से बात करेंगे और हम उस पर जरूर कार्यवाही करेंगे। हमारे साथी निर्मल सिंह जी ने कहा है कि इनका जो नग्गल का एरिया, अम्बाला का एरिया है यहां पर पानी के बारे में बड़ा डिस्क्रीमिनेशन हो रहा है। यह सही बात है इनकी रिक्वायमैंट तो 165 क्यूसिक वाटर की है लेकिन वहां सिर्फ 65 क्यूसिक वाटर ही दिया जा रहा है। स्पीकर सर, इस बारे में मैं इनको यह कहना चाहूंगा कि मैं अपने

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

आफिसर्ज से इस विषय में बातचीत करूंगा। साथ ही मैं इनको यह भी बताना चाहूंगा कि जो दादूपुर नलवी नहर की स्कीम है उसको मुख्यमंत्री जी ने मंजुर कर लिया है। उस पर 167.62 करोड़ खर्चा आएगा और उसके लिए जमीन की इक्वीजिशन का काम शुरू हो गया है। इससे अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की 43,370 एकड़ जमीन को फायदा मिलेगा। इसके अलावा नरेश यादव जी ने एस०वाई०एल० का भी जिक्र किया है। मैं इनको केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि इसका फैसला 15 जनवरी, 2002 को आ गया था और इसको पंजाब सरकार ने एक साल में बनवाना था। स्पीकर सर, 15 जनवरी, 2004 तक एन०डी०ए० की सरकार थी जिसमें हमारे ये साथी जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनकी हरियाणा में सरकार थी इन्होंने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की । यहां पर उस समय विधान सभा में जो बी०जे०पी० के एम०एल०एज० थे उन्होंने इस्तीफा देने का एक ड्रामा किया था। (विघ्न)

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, on a point of order.

Mr. Speaker : Don't interrupt. Please take your seat Indora ji. (Interruptions)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, उनका वह ड्रामा काम नहीं आया और उस वक्त जो 6 व्यक्ति बी०जे०पी० के एम०एल०एज० थे, उनमें से कोई भी जीत कर नहीं आया बल्कि सिर्फ दो नए एम०एल०एज० ही चुनकर इस विधान सभा में आए। (विघ्न)

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, on a point of order., I want to clarify.

Mr. Speaker : What do you want to say ? Under which provision you want to speak. Quote the provision.

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कैप्टन साहब यह कह रहे हैं कि हमारी सरकार और बी०जे०पी० के टाईम में कोई काम नहीं हुआ है। स्पीकर सर, यह तो आन रिकार्ड है, ये उस रिकार्ड को देख लें।

Mr. Speaker : Indora ji, take your seat. Don't interrupt. Please, continue Capt. Sahib. This is not the time. You can take up this matter when we will discuss Appropriation Bill. (Interruptions) Nothing to be recorded what Mr. Indora is saying.

Dr. Sushil Indora : * * * * *.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, 15 जनवरी, 2003 से लेकर और फरवरी, 2004 तक के समय में इनके द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। (विघ्न)

Dr. Sushil Indora: * * * *.

Mr. Speaker : Indora Ji, please take your seat. Nothing to be recorded. Capt Sahib go ahead.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में हमारी सरकार ने आते ही सी०पी०डब्ल्यू०डी० को काम दे दिया । लेकिन पंजाब ने अपने काउंटर पार्ट पर एक पंजाब टर्मिनेशन एक्ट पास कर

* Not recorded as ordered by the Chair.

दिया। उसके अगेन्स्ट भी हमारी केन्द्र की सरकार ने प्रेजेन्ट रैफरैंस दिया है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूं कि एस०वाई०एल० कैनाल को बनवाएंगे और इसके लिए सुप्रीमकोर्ट का फैसला भी हमारे हक में ही आया हुआ है। (विघ्न)

Mr. Speaker : All right, Indora Ji you are master and we are appreciating you. Please sit down.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मेरे कहने का मकसद यह है कि जो नरेश यादव जी ने बात कही थी मैंने उसका जवाब दिया है। एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में सरकार सिंसियर है और इस बारे में हम अवश्य ही उचित कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो प्वाइंटस दूसरे साथियों ने कहे थे उनका भी मैंने जवाब दे दिया है। धन्यवाद।

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० 10 और 13 के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए बिन्दुओं का जवाब देने के लिए खड़ी हुई हूं। सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों के साथ मिलकर माननीय वित्त मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूं कि पहली बार उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दी है। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि विजन पेपर के माध्यम से जितना भी हमने बजट मांगा था उससे कुछ ज्यादा ही बजट उन्होंने अलौट किया है। माननीय सदस्यों की जो भावना है उसके अनुरूप ही हम काम करने का प्रयास करेंगे। महेन्द्र प्रताप जी ने फरीदाबाद के होस्पीटल के बारे में कुछ सवाल उठाए हैं। यह ठीक है कि उस होस्पीटल की हालत कुछ अच्छी नहीं है। हमारे पुराने टाईम में ही उसका एक फेज बनाया गया था लेकिन उसके बाद इन नौ सालों में उस पर एक ईंट भी नहीं लगी है। पुरानी बिल्डिंग ज्यों की त्यों ही पड़ी है। हम जल्दी ही प्रायोरिटी बेसिज पर उसकी पुरानी बिल्डिंग का और जो वहां पर इक्विपमैंट्स वगैरह की समस्या है उसका समाधान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बहन गीता ने भी अपने यहां की पी०एच०सी० के बारे में और वहां पर स्टाफ की कमी के बारे में बताया है। हम उसको भी देखेंगे। सबसे बड़ी गंभीर बात बहन अनिता जी ने सदन के सामने रखी है। मैं उनको बताना चाहती हूं कि यह सूचना मुझे माननीय सदस्य राधे श्याम शर्मा जी द्वारा बहुत पहले मिल गयी थी तभी हमने उसके खिलाफ जांच करवाकर उस डाक्टर को सस्पैंड कर दिया है तथा और भी उसके खिलाफ सख्त से सख्त ऐक्शन सरकार लेगी। नरेश यादव जी ने मुझे टी०बी० की दवाई न मिलने के बारे में लिखकर भी दिया है और व्यक्तिगत तौर पर भी कहा है मैं उनको बताना चाहूंगी कि दूसरी दवाईयों की तो कमी हो सकती है लेकिन पूरे प्रदेश में किसी भी जगह पर टी०बी० की दवाई की कमी नहीं है क्योंकि टी०बी० कंट्रोल करने का यह जो प्रोग्राम है वह वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन चलाता है और वही यह दवाई प्रोवाइड करवाता है। अब तो इस बारे में नया सिस्टम शुरू हो गया है। अब तो मरीज को अपने सामने ही दवाई खिलायी जाती है। जैसा उन्होंने कहा कि डाक्टर हेराफेरी करता है अगर ऐसी बात है तो जरूर आवश्यक कार्रवाई होगी। निर्मल सिंह जी ने भी एक गांव में पी०एच०सी० की सुविधा देने के बारे में कहा। मैं उनको बताना चाहूंगी कि इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनी हुई है। पांच हजार की आबादी पर सब सैंटर, तीस हजार की आबादी पर पी०एच०सी० और एक लाख बीस हजार की आबादी पर सी०एच०सी० बनायी जाती है। अगर इनकी मांग इनमें से किसी नोर्म में आती होगी तो हम जब नई पी०एच०सी० बनाएंगे तो उस समय इनकी यह मांग कंसीडर कर लेंगे। इसके अलावा प्रश्नों के द्वारा या दूसरे तरीकों से डाक्टर्ज की कमी का सवाल भी उठाया गया है। मैं बताना

[करतार देवी]

चाहूंगी कि 162 डाक्टर्ज की कमी है। अभी जो हमारे हैल्थ कमिश्नर हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इन सभी पदों को जल्द से जल्द भरने का प्रयास किया जाएगा। ट्रांसफर करते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा। जहां एक्सरे मशीन है वहां पर रेडियोग्राफर अवश्य लगाया जाएगा और जहां पर सर्जन की जरूरत होगी वहां पर उनको लगाया जाएगा। ट्रांसफर करते वक्त अवेलेवल स्टाफ को उचित जगहों पर लगाने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। जिस तरीके से हमारी नेता सोनिया गांधी की मंशा है और जिस भावना को लेकर प्रधानमंत्री जी ने रूरल हैल्थ मिशन की घोषणा की है, प्रोग्राम को चालू किया है और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार चाहती है तो मेरा यह पूर्ण प्रयास होगा कि हम उनकी मंशा पर खरा उतरें चाहे इसके लिए हमें कितनी ही मेहनत करनी पड़े। हर दूर दराज के इलाके में हैल्थ कैम्प के द्वारा और किसी मोबाइल वैन के द्वारा हर आदमी को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की सरकार कोशिश करेगी। सर, मैं समझती हूं कि माननीय सदस्यों की यही भावना थी इन भावनाओं को पूरा करने में समय तो जरूर लगेगा लेकिन उनकी भावनाओं का पूरा ख्याल जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।

Finance Minister (Shri Birender Singh): Speaker Sir, before I put all the demands for the approval of the House, first of all, I would congratulate the entire House and especially you Sir. When the demands were to be taken up, one of the senior members, who has been the member of the previous House, was telling me that demands are never discussed in the House and it is supposed to be passed when the reply is given by the Finance Minister on the General Discussion on budget. So, to streghthen the record and for the knowledge of the Hon'ble Member, I would say whether there is a discussion guillotine is applied when there is a shortage of the time or constraint of the time. So, I must congratulate the entire House that we are moving towards the direction which was the commitment of the Congress Party that we would like the institutions which are being degraded or their authority was eroded in the past, may be Public Service Commission, may be Staff Selection Commission, may be Universities or may be the august House. (Interruptions)

श्री अध्यक्ष : 41 मैंबर बोले हैं।

श्री नरेश मलिक : उनमें से मैक्सिमम कांग्रेस के बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंबर तो बोले हैं । रेशो के मुताबिक आपको टाईम मिला है। आप दो मैम्बर हैं। आप अपने साथी को कह देना अगली बार वे नहीं बोलेंगे, आप बोल लेना।

Mr. Birender Singh : Hon'ble Members should not feel disturbed when Appropriation Bill would come up for discussion day after tomorrow. You would have ample time by the courtesy of the Speaker to speak on the Budget. That is a part of the Budget. So Sir, I have said that the credibility of the Institutions, which are enshrined in the Constitution of the country, those are to be restored back. Their authorities should be restored back. The erosion of the authority should be

restored back. Sir, you would not believe that this is a fact, a stage has come when in the presence of the Deputy Commissioner, the so-called activities of the last Government, they used to put mobile on the ear of the Deputy Commissioner कि भाई साहब से बात करो This was the kind of system, which was prevailing and it was our utmost duty to restore back that authority and have been repeatedly asking the Chief Minister. the moment he took over as the head of the Government. The first instruction was that we want that there should not be any insterference. Even if some work is to be put before the administration, that should be in a systematic way. We do not belong to that culture, which they used to have. They used to dictate the terms of the administration. Our first priority is to see that their confidence is, built up. So, Sir, with this I have put it to straighten the record and that is with your blessing Sir. Now, I would like to say about the pouls raised by various members, who have participated in the discussion on Budget. Most of the members while discussing the demands, actually they were not referring to the Budget. They were confined to their local demands. My Hon'ble colleagues, Irrigation Minister and the Minister for Health have give already their replies. The Questions which were related to the Education Department, should be answered by the Hon'ble Education Minister on the day of the Appropriation Bill. But as far as one or two members, those who have pointed out about the Budget, one is Dr. Sita Ram. He said that we have not explained in detail the problem of unemployment and how to sort out the problem of unemployment. Sir, if you go through the budget speech of mine, we have made it clear that there are avenues, where we can send our boys on foreign assignments. There are placements for our boys and for that we were planning to have a society because Mr. Tejinder Pal Singh Mann was very right when he pointed out that there may be some administrative hustles to sort out from Government to Government. We are not a sovereign. We are the State of a Sovereign Country. So, for that purpose, we are going to constitute a society, which would be authorized to give guidance to facilitate our boys, those who want to get their passport, prepared those who want to get a visa, those who are in search of placements. With this we hope that there would be a tremendous scope for our boys to go to other countries, especially to the Gulf countries and developed countries in Europe and America. Sir, you would not believe, it has been a fact that when we try to get the data of the Punjab, how much remittance comes from the other parts of the world to Punjab, we found that about Rs. 1200 crore are remitted annually to the state exchequer compared to Punjab we only get Rs. 50 crore only. So, how are we moving forward to see that the boys and the skilled workers of Haryana, those who want to go abroad, they should be given these facilities. He has also made it a point to talk about SYL. Capt. Ajay Singh has already replied for that. But I must say that as far as Chautala Government is concerned, there was no contribution for the last two years. When Supreme Court passed a specific order and it directed the Punjab Government, you would be recalling that when the order of the Supreme Court came atleast for three months Shri Parkash Singh Badal Government, Chautala's Government here and the NDA's Government were together but at the Centre, nothing came out.

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time of the House be extended for 10 minutes.

Voices : Yes Sir

Mr. Speaker : The time of the House is extended for 10 minutes.

वर्ष 2005-06 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

Shri Birender Singh : Speaker Sir, ultimately another judgement came from the Supreme Court and that too went in favour of Haryana and the Central Government was authorized to construct. When the agreement was abrogated by Punjab Assembly, it was the Congress Party which agitated on that. We went to our Congress President Smt. Sonia Gandhi Ji, we went to the Prime Minister of the country and we made it a point. What would have been done by Chautala Government. They should have moved to the Supreme Court. (Interruptions) Dr. Indora Ji, it is a fact. You refused to move. When Punjab Assembly abrogated the water agreement, it was the duty of the State Government of Haryana which was headed by Shri Om Parkash Chautala to move to knock the door of the Supreme Court, but they did not. He wanted to make the use of the situation. So, he was anticipating that this issue can be clinched politically to get the votes because his father and Shri Chautala both were playing the same tactics for the last 30 years. They were never serious about the completion of the canal and it was the Congress Party, which has really done something. (Interruptions)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो यहां SYL की चर्चा हुई, इन्दौरा जी भी बोल रहे थे, हमारे वित्त मंत्री जी भी कह रहे थे। कांग्रेस के हमारे सभी साथियों का यह स्टैंड रहा है कि SYL का मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा या वोट लेने का मुद्दा नहीं है बल्कि यह हमारी जीवन रेखा है। लेकिन SYL इतने सालों से नहीं बनी इसके लिए कौन दोषी है, मैं आन दि फलौर आफ दि हाउस कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और इनैलो ही पूर्ण रूप से इसके लिए दोषी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हरियाणा के हित में आया था उसका आधार इन्दिरा गांधी अवार्ड और राजीव लौंगोवाल समझौता माना है, राजीव लौंगोवाल समझौते का विरोध किसने किया है, उस समय इनकी पार्टी का नाम कुछ और था, शायद लोकदल था। ये हर साल अपनी पार्टी के नाम बदलते रहते हैं, उस समय इनकी पार्टी के अध्यक्ष देवीलाल जी थे और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष डा० मंगल सैन जी थे, दोनों ने इस्तीफे दिए और इसका विरोध किया, उसका विरोध अगर न किया होता तो हरियाणा को कभी का पानी मिल गया होता इसलिए इस बात के लिए यह दोनों पूर्ण रूप से दोषी हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker : Birender Singh Ji. you may proceed. Further

Shri Birender Singh : Sir, I do not find any querry by any Hon'ble member which basically relates to Budget but still Maj. Nirpender Singh, he raised certain very relevant issues. One of them was repair of the transformers. A transformer which costs Rs. 54,000, but its repair cost comes to Rs. 23,000.. So we are seized of the problem and we are sorting out these things not only of the transformers but also how to streamline the entire power utility sector. That would be our prime consideration and this has been entrusted by the Cabinet, by the Chief Minister to a Sub-Committee which is going to take certain decisions very soon. Sir, Smt. Geeta Bhukal also raised certain points, I do not think there is any reply needed on my side because nothing is concerned with the Budget but still she was pleading one thing that this is the most neglected area. This has been unfortunate on the part of Kalayat area that whenever some Government was formed, the decision of the electorate was never right. They were on the other side of that, but now for the first time Congress Party has come to power and the MLA is also from the same party. So every aspect of backwardness of this area would be taken care of, that is our commitment and not only to Geeta Bhukal Ji but all the areas of Haryana where the areas were discriminated on political consideration. That would be our main aim to remove that discremination. Sir, other Members also spoke. Shri Dura Ram Ji made certain points, Smt. Meena Mandal also talked about a women college in Judla, Dr. Sita Ram was also replied about the questions whatever he raised. Naresh Yadav Ji's questions were replied by the Irrigation Minister. Sir, in the last, Shri Rajender Singh Joon was very much right, he was of this opinion and of the cofirm view that in the next elections the entire lot would be wiped out. (Interruptions) Shri Dan Singh Ji talked about any industrial unit in the backward area of Mahendergarh district. Sir, this has already been replied that 84 spots have been identified where there would be industrial activities so that no area is left without industry. It will be our main thrust that no area is left without industry and in the remote areas where there is zero industry zone, there activity should also be to a substantial extent.

In the last, I would thank all the Members and Sir, the way you conducted the House and the way the Members got the opportunity to speak out, this would go a long way to see that the very important institution i.e. the Legislative Assembly is now again reviving to a place which it deserves and where the expressions of the entire State as Shri Shamsher Singh Surjewala Ji had put up that now the population of State had gone to about 2 crore and 33 lac, So, this is the platform, this is the area. Mr. Chautala used to say that I am the only man because there is no Opposition. Congress Party does not know how to act as an Opposition. He used to say that there are so many groups in Congress Party. They fight themselves. They can not give a fight to Chautala as a united Party. Sir, now the entire situation has proved it to the hill that Congress Party is a united Party. We are committed to our philosophy. We are committed to our manifesto. Sir, Mr. Chautala should also remember that this is the Congress Party which the People of Haryana has opted as their political party and not any other political party bacause Congress fought for the rights of the citizens of the State for five years together. It was his misgiving, it was his misconception that Congress does not know the role of Opposition. We

[Shri Birender Singh]

played our role and people reposed confidence in us. With these words, Sir, the time would prove that we stand for the welfare of the State, we stand with every citizen. Those who have been deprived of their due rights, they should get their rights. We stand for the administration whose authority was totally eroded, the authority of the administration should be restored. With these words, I thank you, Sir and I thank all the Members of the House.

Mr. Speaker : Hon'ble members, now the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 9,51,75,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 2,52,00,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 1-Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding **Rs. 150,61,93,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 34,00,60,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 2-General Administration.**

That a sum not exceeding **Rs. 649,77,98,000 for revenue expenditure and Rs. 19,66,50,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 182,19,54,000 and capital expenditure amount of Rs. 5,33,50,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 3-Home.**

That a sum not exceeding **Rs. 211,01,96,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 65,10,32,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 4-Revenue.**

That a sum not exceeding **Rs.44,01,99,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 13,46,14,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 5-Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding **Rs. 881,43,61,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 223,95,48,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 6-Finance.**

That a sum not exceeding **Rs.24,15,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 184,24,70,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 7-Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding **Rs. 277,58,83,000 for revenue expenditure and Rs. 297,17,03,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 53,75,37,000 and capital expenditure amount of Rs. 67,71,47,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 8-Buildings & Roads.**

That a sum not exceeding **Rs.1632,02,99,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 446,25,67,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 9- Education.**

That a sum not exceeding **Rs. 645,36,14,000 for revenue expenditure and Rs. 270,48,28,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 181,88,44,000 and capital expenditure amount of Rs. 54,51,72,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 10-Medical & Public Health.**

That a sum not exceeding **Rs.150,67,42,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 17,03,01,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No.11-Urban Development.**

That a sum not exceeding **Rs.168,33,36,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 27,76,42,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 12-Labour & Employment.**

That a sum not exceeding **Rs. 573,28,33,000 for revenue expenditure and Rs. 5,05,25,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 150,23,09,000 and capital expenditure amount of Rs. 48,75,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 13-Social Welfare & Rehabilitation.**

[Shri Birender Singh]

That a sum not exceeding **Rs. 23,17,43,000 for revenue expenditure and Rs. 26,10,95,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 7,40,66,000 and capital expenditure amount of Rs. 1253,00,00,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 14-Food & Supplies.**

That a sum not exceeding **Rs. 1446,43,88,000 for revenue expenditure and Rs. 511,20,22,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 417,53,00,000 and capital expenditure amount of Rs. 111,74,78,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 15-Irrigation.**

That a sum not exceeding **Rs. 58,29,41,000 for revenue expenditure and Rs. 2,18,14,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 14,36,95,000 and capital expenditure amount of Rs. 55,65,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 16-Industries.**

That a sum not exceeding **Rs.245,09,82,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 70,25,07,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 17-Agriculture.**

That a sum not exceeding **Rs.120,89,55,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 34,30,97,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 18-Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding **Rs.11,65,45,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 2,61,91,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 19-Fisheries.**

That a sum not exceeding **Rs.120,74,39,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 26,46,21,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 20-Forests.**

That a sum not exceeding **Rs. 332,00,23,,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 65,20,32,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 21-Community Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 29.84,89,000 for revenue expenditure and Rs. 6,64,75,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 5,97,25,000 and capital expenditure amount of Rs. 2,73,25,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 22-Co-operation.**

That a sum not exceeding **Rs. 507,19,86,000 for revenue expenditure and Rs. 63,79,50,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 155,03,51,000 and capital expenditure amount of Rs. 13,91,50,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 23-Transport.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,28,89,000 for revenue expenditure and Rs. 5,62,50,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 40,52,000 and capital expenditure amount of Rs. 1,37,50,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 24-Tourism.**

That a sum not exceeding **Rs.93,23,32,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2005-06 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 82,27,08,000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 25-Loans & Advances by State Government.**

(The motion was Carried)

Mr. Speaker : Now, the House stands *adjourned till 9.30 A.M., tomrrow the 16th June, 2005.

*18.40 Hours (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. Thursday, the 16th June, 2005).

40072—H.V.S.—H.G.P., Chd.